Union Budget (2025-26) ? Demands for Grants ? Ministry of Jal Shakti ? Contd.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है ।

सभापति महोदय, आज देश क्या, बल्कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण विषय, जो पूरी दुनिया के सामने है, वह जल संकट का विषय है । पूरे विश्व में हर देश का हर राज्य कहीं न कहीं जल के इस संकट से जूझ रहा है । माननीय मंत्री जी ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया है । मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदय, कल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बात को कहा था । महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों के समागम के अवसर पर नदियों के महत्व को, नदियों के उत्सव को मनाया गया था । वहां से एक स्प्रिचुअल पावर निकली थी, जिससे पूरा देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से भी कुल 66 करोड़ लोग महाकुंभ में आए । यह कहीं न कहीं हमारी आध्यात्मिक शक्ति है और शायद पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है ।

सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं कि चाहे सत्तापक्ष के लोग हों या प्रतिपक्ष के लोग हों, सभी यह मानते हैं कि जल ही जीवन है । लेकिन, आज जल ही जीवन नहीं रह गया है, क्योंकि जहां जल जीवन है, वहीं जलीय विकास है । अगर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है । इसलिए, मैं आज उस जल के महत्व को देखते हुए उसके बारे में कहना चाहता हूं । आज लोगों को जल की बहुत आवश्यकता है, हर घर के हर व्यक्ति को सेफ ड्रिंकिंग वॉटर, स्वच्छ जल मिले ।

यह देश इस बात का गवाह रहा है कि हर राज्य में कहीं न कहीं जल का संकट रहा है । आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, हमारे मिथिला के सारे साथी यहां बैठे हैं । मिथिला के 22 जिले ऐसे हैं, जहां छः महीने सूखा रहता है और छः महीने बाढ़ रहती है । यही पूर्वी उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां हैं । महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, जो जिले नेपाल के फुटहिल्स में हैं, वहां हमेशा बाढ़ आती रहती है । चाहे गुजरात हो या राजस्थान हो, आज जीरो आवर में एक माननीय सदस्य इस बारे में कह रहे थे । जिस तरीके से ईस्टर्न राजस्थान की बात हो रही थी, जिसमें काफी जिले आते हैं । ? (व्यवधान) ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) है, जिसके जिले भी आपको बता दूं

। ये जिले हैं ? झालावाड़, बारां, कोटा-बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर ।

यह 40,000 करोड़ की परियोजना है । ? (व्यवधान) आप इतने दिन सरकार में रहे, इतने जनपद पानी से जूझते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी यह परियोजना स्वीकृत नहीं हुई । निश्चित तौर पर यह परियोजना यदि आज स्वीकृत हो रही है, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के इतने जनपदों के संकट दूर हो रहे हैं ।

मैं कहता हूँ कि चाहे आपने राजस्थान की बात की, जब उस समय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उस समय गुजरात में एक बड़े इलाके में पानी के लिए संघर्ष होता था । चाहे सौराष्ट्र का इलाका हो, जिसमें मेहसाणा हो, राजकोट, जामनगर, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा, गाँधीनगर आदि, इन सारे इलाकों में पानी की दिक्कत थी । आप गवाह होंगे कि उत्तर प्रदेश में राजस्थान के लोग गर्मियों में पलायन करते थे, गुजरात के लोग पलायन करते थे । चाहे भरतपुर हो, आगरा से लेकर पूरे यूपी में लोग अपने जानवरों को लेकर आते थे । वहाँ ऊँट के लिए पानी नहीं रहता था । ऐसी परिस्थितियाँ थीं, तो आज उस पानी का कितना महत्व है? पानी का महत्व क्यों न हो, आखिर भारत की आबादी दुनिया की पूरी जनसंख्या की 18 प्रतिशत है । आज भारत में विश्व की 18 प्रतिशत आबादी के लिए जो स्वच्छ जल है, वह मात्र 4 प्रतिशत उपलब्ध है, तो स्वाभाविक है कि भारत के सामने भी जल का संकट है । जब विश्व की 18 प्रतिशत पॉपुलेशन के लिए केवल 4 परसेंट पानी उपलब्ध है, ऐसी परिस्थिति में आखिर कहाँ से पानी का इंतजाम होगा । पहली बार आपने देखा कि जिस तरीके से जल शक्ति मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, क्योंकि जब वे गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में थे तो वह देश में पहला राज्य था, जिसने अपने उन 11 जिलों, राजकोट, जामनगर, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ आदि, जहाँ पर पूरे साल पानी का संकट रहता था, उन्होंने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण योजना यानी सौनी योजना 12,166 करोड़ रुपये की स्वीकृति देकर बनायी और आज उससे गुजरात का वह इलाका न केवल खुशहाल हो रहा है, वहाँ केवल फसलें ही नहीं हो रही हैं, बल्कि आज गुजरात विकास का एक मॉडल भी बन रहा है । जिस तरह से उन्होंने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण योजना को स्वीकृत किया, फिर एक सुजलाम सुफलाम योजना शुरू की, जिसका इनिशियल एलोकेशन 6,237 करोड़ रुपये था । मेहसाणा, पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा, गाँधीनगर आदि जिलों को इस सुजलाम सुफलाम योजना से जोड़कर पानी उपलब्ध कराया । फिर सरदार सरोवर परियोजना में 52,600 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, जिसमें कच्छ, सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात जैसी ऐतिहासिक योजनाओं को साकार करके एक तरह से

गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में जल क्रांति करने का काम किया था । जहाँ सूखा रहता था, आज वहाँ के खेत लहलहा रहे हैं, उद्योग फल-फूल रहे हैं और हर घर में जल पहुँच रहा है । मुझे लगता है कि उनका जो वह संकल्प मुख्यमंत्री के रूप में था, वह आज प्रधानमंत्री बनने के बाद भी है । देश की आजादी के बाद कौन सा राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश में महिलाएँ दूर पानी लेने के लिए जाती थीं, चाहे आदिवासी इलाका हो, कई-कई मील दूर लोग पानी लेने के लिए जाते थे, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, देश के अन्य हिस्सों में, लोगों के गाँव में पानी उपलब्ध नहीं रहता था ।

घरों में तो पानी की कल्पना ही नहीं थी । प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2019 में, एक तरह से अभी तक जो अलग-अलग मंत्रालय थे, पहले कांग्रेस यूपीए की सरकार में एक वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट का मंत्रालय था, एक गंगा रेजुवेनशन डिपार्टमेंट था, जिसमें कितना काम हो रहा था और ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन डिपार्टमेंट था । इन सबमें आपस में कोई कोआर्डिनेशन नहीं था । कोई एक सम्यक रूप से काम नहीं था । देश के घरों में नल से जल की तो कल्पना छोड़ दीजिए, लोग इंडिया मार्क टू हैंडपंप के लिए तरसते थे । इन सारे मंत्रालयों को एकत्र करके उन्होंने वर्ष 2019 में फैसला किया कि हम इन मंत्रालयों के एकीकरण से, चाहे वाटर कंजर्वेशन हो, इरीगेशन हो, रिवर हो, रिवर रेजुवेनशन हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन हो, फ्लड मैनेजमेंट हो, इन सबके लिए उन्होंने एक जल शक्ति मंत्रालय बनाने का काम किया है और आज उसके परिणाम आ रहे हैं । जल शक्ति मंत्रालय बनने के बाद आपने देखा कि जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनमें एक जल जीवन मिशन की योजना शुरू हुई, दूसरी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई, नमामि गंगे योजना शुरू हुई और अटल भू-जल योजना शुरू हुई ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्राय: किसी भी मंत्रालय का आप बजट देखिए, मंत्रालयों के पिछले साल के बजट में प्राय: 10,12,15 या 20 परसेंट तक का इजाफा होता है ।

महोदय, आज हमारे लिए जल ही जीवन है, हर घर में नल से जल पहुंचाना है, इसलिए जल शक्ति मंत्रालय के लिए 2025-26 में बजट का आबंटन 99503 करोड़ रुपये का किया है । यदि हम वर्ष 2024-25 से तुलना करें तो 51558 करोड़ रुपये का आबंटन था और यह पिछले वर्ष की तुलना में 93 प्रतिशत इस मंत्रालय के बजट को इंक्रीज किया है । यह वृद्धि अपने आपमें अभूतपूर्व वृद्धि है जो भविष्य के लिए जल को सुरक्षित रखने के संकल्प को पूरा करने के प्रयत्न को दर्शाती है । जल जीवन मिशन में हमने तय किया है कि जम्मू-कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गांव के हर घर में टैप वॉटर उपलब्ध कराएंगे । कभी यह सिर्फ

कल्पना थी लेकिन आजादी के बाद हमारी सरकार ने चाहे नार्थ-ईस्ट की पहाड़ियां हों, चाहे झारखंड का आदिवासी इलाका हो, चाहे राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका हो या देश का कोई भी भाग हो, हर घर जल पहुंचाने के 67 हजार करोड़ रुपये के बजट का आबंटन किया है ।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यहां बैठे हुए साथियों के साथ-साथ पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि हर घर नल से जल मिले, यह संकल्प किया और पिछले साल की तुलना में हमने 195 परसेंट बजट को इंक्रीज किया है । प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में 8260 करोड़ रुपये के बजट को एलोकेट किया है । पिछले साल की तुलना में यह 25 परसेंट की वृद्धि है । नमामि गंगे में 20 परसेंट इंक्रीज करके 2400 करोड़ रुपये दिए हैं । अटल भू-जल योजना में 1780 करोड़ रुपये आबंटित करके 197 परसेंट इंक्रीज करने का काम किया है । पूरा देश याद करता है कि यदि धरती पर गंगा आई तो हम भगीरथ जी की तपस्या को याद करते हैं । जिस तरह से राजा भगीरथ अथक तपस्या करके स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाए और आने वाले समय में देश ही नहीं, पूरी दुनिया मानेगी कि भारत के हर घर में यदि नल से जल पहुंचा है तो नरेन्द्र मोदी जी ने यह काम किया है । आज निश्चित रूप से आधुनिक भगीरथ के रूप में भारत के हर गांव के हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम हुआ है । यह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही है । अभी तक तो यह नारा ही था कि ?हर घर जल? ?हर खेत को पानी? लेकिन आज यह सपना नहीं है और हर घर जल और हर खेत को पानी वास्तविकता के धरातल पर उतारने का काम मोदी सरकार करेगी । यह केवल पानी की व्यवस्था नहीं है, यह विकास की धारा है और जो मोदी जी की दूरदृष्टि और संकल्प है और जब भी आधुनिक भारत में जल क्रांति की बात होगी, तब नरेन्द्र मोदी जी को याद किया जाएगा । जैसा हमारे राजस्थान के साथियों ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट है । इसमें भी 26 नदियों को जोड़ने की बात की गई है । 26 नदियों को जोड़कर 13 जिले झालावाड़, बारा, पोटा, बूंदी, सवाईं माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा और करौली में पानी पहुंचाने की बात है । कांग्रेस यूपीए की सरकार में जयराम रमेश जी थे ।? (व्यवधान) माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब नदियों को जोड़ने की बात कही, फिर कांग्रेस यूपीए की सरकार आई । आप सहमत होंगे, गौरव जी आप सहमत होंगे, उस समय यूपीए-1 और यूपीए-2 में कभी भी नदियों को जोड़ने की परियोजना को गंभीरता से नहीं लिया । उस समय के तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश जी ने कहा कि इन नदियों को जोड़ना विनाशकारी होगा? (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में नदियों को जोड़ने की परियोजना 161 साल पुरानी है ।? (व्यवधान) ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने वर्ष 1858 में कहा था कि इस देश में किसी नदी में ज्यादा जल है और किसी नदी में अगर कम

जल है, तो उन दोनों नदियों को लिंक किया जाए, नहर से जोड़ा जाए । इससे आवागमन भी होगा और व्यापार भी बढ़ेगा । उस समय न तो इतनी सड़कें थीं, न रेल की सुविधा थी । 161 साल पहले ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने नदियों को जोड़ने की परियोजना की बात कही, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद इतने वर्षों तक सरकार में रहने के बाद भी कभी उस योजना को वास्तविकता के धरातल पर लाने का प्रयास नहीं किया गया । जब अटल बिहारी वाजपेयी ने केन-बेतवा को जोड़ने की परियोजना को शुरू किया, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस-यूपीए की सरकार आयी तो फिर वह काम ठंडे बस्ते में चला गया, जबकि जल समस्या थी, सूखे की स्थिति थी ।

वर्ष 2014 में, जब नरेन्द्र मोदी जी सरकार में नहीं आए थे, उसी समय उन्होंने बिहार के पटना में यह कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो नदियों को जोड़ने का अटल जी का जो सपना है, वही हमारी सरकार का सपना होगा और उनके सत्ता में आते ही वह काम शुरू हो गया । सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने यही किया । उन्होंने 23 सितम्बर, 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के तहत एक विशेष समिति का गठन किया । विशेष समिति ने फिर अप्रैल, 2015 में एक स्वतंत्र कार्य बल का गठन किया । कार्य बल का गठन करने के बाद यह तय हुआ कि हम इंटरलिंकिंग करेंगे और इसी से उन्होंने इस काम को शुरू किया । आज आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार की जो योजना थी, उन्होंने न केवल इसको साकार किया, न केवल केन-बेतवा का काम ही हुआ, बल्कि हमारी सरकार ने नॉर्थ-ईस्ट में भी काम किया । आज नॉर्थ-ईस्ट में सबसे बड़ी परियोजना कोसी-मेची परियोजना है । इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? 4,900 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी और उस पर काम हो रहा है ।

इसी तरीके से, गंगा, ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों को जोड़ने के लिए काम चल रहा है । महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई को जोड़ने के लिए भी योजना की स्वीकृति हो गयी है । यह राष्ट्रीय हित का मुद्दा है ।? (व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं जब फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर बात करूंगा तो फिर खीरी, लखीमपुर, सिद्धार्थनगर की बात करूंगा, अभी आप जल संसाधन की बात सुन लीजिए ।? (व्यवधान)

राष्ट्रीय हित के मुद्दे, जैसे जल संकट, बाढ़ नियंत्रण, कृषि विकास के लिए कार्य हैं, इनके लिए हमें चारों तरफ से काम करना होगा । जब हम इस काम को करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम उसके लिए बजट निर्धारित करेंगे । जल जीवन मिशन में ग्रामीण हाउसहोल्ड्स को नल

जल से जोड़ने का काम किया गया है । उसमें वर्ष 2025-26 तक 67,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है । उसका परिणाम देखिए कि 21 जनवरी, 2025 तक, जबकि हम मार्च में बजट सेशन में मिल रहे हैं, लेकिन 21 जनवरी, 2025 तक 15 करोड़ गरीब परिवारों के घरों को इससे जोड़ दिया गया है । पहले वे इसकी कल्पना भी नहीं करते थे कि उनके घरों में कभी नल के माध्यम से पानी आएगा । पहले वे किसी कुएँ या किसी नल से अपना घड़ा भरने जाते थे, परन्तु आज 15 करोड़ ग्रामीण परिवार, जो देश के 80 प्रतिशत लोग हैं, उनके घरों के कनेक्शंस नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में एचटीसी के माध्यम से जुड़ चुके हैं ।? (व्यवधान) यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जल सुरक्षा में एक क्रांति है । हमने 6 वर्षों में योजना की शुरुआत कैसे की और दूसरी सरकार ने पिछले 7 दशकों में कितना किया, यह देखने की बात है । आज़ादी के बाद से अगर हम पिछले 7 दशकों को जोड़ लें और अगर बस हमारे 6 साल के काम को जोड़ लें, पूरे सात दशक के काम को मिला दें तो उससे 5 गुना ज्यादा नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने हर घर तक नल से जल को पहुंचाने का काम किया है । आज कौन-से राज्य पीछे हैं, यह तो आंकड़ा है । आज भी जब हम हर घर को नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो निशिकांत जी, आज भी सबसे पीछे झारखंड है, आज भी सबसे पीछे केरल है, आज भी सबसे पीछे पश्चिम बंगाल है ।? (व्यवधान) आखिर ये कौन-से राज्य हैं? You do not have any commitment to provide safe and drinking water to every common man.

अवधेश जी, मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करूंगा । अभी आप बैठ जाइए ।? (व्यवधान)

इसमें केरल, झारखंड और पश्चिम बंगाल पीछे हैं । वर्ष 2019 में हमने 100 पर्सेंट नल से जल योजना को लॉन्च किया था । वर्ष 2019 में केवल 3.23 करोड़ लोगों तक, केवल 17 पर्सेंट लोगों के घरों में नल से जल की व्यवस्था थी । लेकिन आज वर्ष 2024 में 11 करोड़ 99 लाख लोगों तक जा रहा है । वर्ष 2025 में 15 करोड़ लोग तक हो गए हैं । हम केवल पानी ही नहीं दे रहे हैं, उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रख रहे हैं । मैं स्टेंडिंग कमेटी ऑन वॉटर रिसोर्सेज़ की बात बताता हूँ । इसी हाउस में 11 मार्च को स्टेंडिंग कमिटी ऑन वॉटर रिसोर्सेज़ के चेयरमैन, रूड़ी साहब ने ही उस रिपोर्ट को ले किया है । उसमें यह है कि आज यह सरकार न केवल घरों को पानी सप्लाई कर रही है, बल्कि पानी की क्वालिटी के लिए, उसके परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं बना रही हैं । 2160 सक्रिय प्रयोगशालाओं में से 1571 प्रयोगशालाओं को नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज़ के द्वारा जोड़ा गया है, मान्यता मिली है, स्वीकृति मिली है ।

माननीय अखिलेश जी, अवधेश प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश में 138 लैब्स में से 75 एनएबीएल मान्यता प्राप्त लैब्स मौजूद हैं । आज आपको सेफ और सुरक्षित पानी मिल रहा है । आपके घरों में मिल रहा है । पानी की जो निगरानी है, सर्विलांस है, उसको राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिल कर कर रहे हैं । हम गांव में केवल टंकी बना कर लोगों को पानी नहीं दे रहे हैं । 23.10.2024 तक पांच लाख सात हज़ार गांवों में 24.72 लाख महिलाओं को फील्ड टेस्टिंग किट्स दिए गए हैं ताकि वे टेस्ट कर सकें कि गांव का पानी भी शुद्ध है कि नहीं । हमने 24.72 लाख महिलाओं को एफटीके जिसको फील्ड टेस्टिंग किट्स कहते हैं, उनका उपयोग कर के पानी की गुणवत्ता चेक करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए कहा है । इस तरह से भारत सरकार ने जल-जीवन मिशन किया है । इसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन की बात करता हूँ । वर्ष 2019 में जो हुआ, कभी आपने पहले देखा, आजादी के बाद, हम दुनिया के विश्व गुरू बनना चाहते हैं । किस तरीके से लोग खुले में शौच करने जाते थे । पहली बार मोदी जी ने संकल्प किया कि हम ओपन डेफिकेशन फ्री करेंगे, खुले में शौच से मुक्त करेंगे । हर घर में हम टॉयलेट देंगे, हर गांव में कम्युनिटी टॉयलेट देंगे । आज 96 पर्सेंट प्लस ओडीएफ हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पा चुके हैं । आज वे महिलाएं जो सुबह से शाम का इंतज़ार करती थीं, अगर तबियत खराब हो गई तो वह सूरज ढलने का इंतज़ार करती थीं कि घर से बाहर निकल कर कैसे जाएं । आज हमने केवल टॉयलेट नहीं दिया है, आज हमने गांव में केवल कम्युनिटी टॉयलेट ही नहीं दिए हैं, आज गांव में वेस्ट मैनेजमैंट का भी काम शुरू किया है । जो कि गांव में कभी सोचा भी नहीं गया था । आज 4.94 लाख गांवों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है । 5.19 लाख गांवों में यह लिक्विड बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है । समग्र ग्रामीण में सैनिटेशन का काम हो रहा है । उत्तर प्रदेश में भी 51,746 गांवों में हो रहा है । हमने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण शुरू किया है । 95.1 पर्सेंट सर्वेक्षण किए गए । परिवारों को जो टॉयलेट की सुविधा प्राप्त हुई, कचरे का बायोडिग्रेशन के लिए ऑर्गेनिक किया । इस तरह से 92.7 पर्सेंट किया है ।

मान्यवर, अब मैं आपसे प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कहना चाहता हूँ । वर्ष 2015 में इरिगेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने इस योजना को लॉन्च किया । सिंचाई परियोजनाएं पड़ी रहती थीं । सरयू नहर परियोजना पिछले 37 सालों से पड़ी हुई थी । कई योजनाएं 50-50 सालों से पड़ी हुई थीं । आज मुझे सदन में बताते हुए खुशी हो रही है कि देश की जो 99 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं थीं, उनमें से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 62 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा कर चुकी है । इसीलिए आज हर खेत को पानी मिल रहा है । 55 पर्सेंट माइनर इरिगेशन परियोजनाएं चल रही हैं । इन सब की दुनिया में चर्चा हो रही है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो पानी के संकट पर हो सकता है । ? (व्यवधान) इसी तरह से जेपीसी

ऑन वक्फ पर भी ये डिटर्स्ब करते थे । इस सदन में भी कर रहे हैं । वहां भी हमको बोलने नहीं देते थे । आप इस बात के खुद गवाह हैं ।

आप इस बात के खुद गवाह हैं । आखिर वे कब तक बैठे-बैठे बोलते रहेंगे? वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2021-22 तक हमने 9.7 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि की है । यह कमिटमेंट है कि किस तरीके से हम सिंचाई क्षमता की वृद्धि करेंगे ।

महोदय, आप नमामि गंगे प्रोग्राम को देख लीजिए ।? (व्यवधान) आपने शुरू किया था, लेकिन कहीं पर भी काम नहीं हुआ । आज नमामि गंगे प्रोग्राम के माध्यम से काम शुरू हो गया है । इस बार के बजट में हमने 20 परसेंट बढ़ा कर 2,400 करोड़ रुपये किया है । दिसंबर 2024 तक इसकी 488 परियोजनाएं थीं । इसमें सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर था । 39,730 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृति दी गई । 305 परियोजनाओं को पूरा कर परिचालन किया गया है । नदी के किनारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था, उसका 52 परसेंट लक्ष्य हासिल कर लिया गया । यह रणनीतिक जल प्रबंधन का एक प्रमुख उदाहरण है । जो केन-बेतवा लिंक परियोजना है, उसमें जून 2024 तक कुल बजट के 9,105 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं । इस महत्वाकांक्षी योजना से न केवल उत्तर प्रदेश को, बल्कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके को, 10.6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी । इन नदियों को जोड़ने से, चाहे यू.पी . का बुंदेलखंड हो या मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, जो सूखा रहता है, उसमें 10.6 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता मिल जाएगी ।

महोदय, इन्होंने नदियों को जोड़ने के लिए कोई काम शुरू नहीं किया । आज केन-बेतवा परियोजना पर काम हो रहा है । आप महत्वपूर्ण नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं । आप देखिए कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जल प्रबंधन का काम चल रहा है । हरियाणा में ?मेरा पानी मेरी विरासत? योजना चल रही है । किसानों को पानी के मामले में गहन फसलों से बदलाव के लिए प्रेरित किया जा रहा है । ये सब जल प्रबंधन का एक बेहतर उदाहरण हैं ।

महोदय, अब मैं फ्लड मैनेजमेंट की बात करना चाहता हूं । राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और नदी बेसिन योजना के माध्यम से हमने और ज्यादा काम किया है । ऐसा नहीं कि केवल हम ही कर रहे हैं, बल्कि हमने नीदरलैंड के साथ सहयोग किया है । राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कैसे वाटर मैनेजमेंट हो, फ्लड कंट्रोल का काम कैसे हो और रिवर बेसिन का काम कैसे हो, इन सभी चीजों पर भी हमने ध्यान दिया है । इसी तरह से भारत और आस्ट्रेलिया ने जल संसाधन प्रबंधन, जिसमें भूमिगत जल प्रबंधन और नदी बेसिन योजना

शामिल है, इसके लिए हमने न केवल बातचीत की है, बल्कि भारत का आस्ट्रेलिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हो चुका है । आने वाले दिनों में जो चिंता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ से हमेशा प्रभावित हो जाता है, यह उसकी नियत है । बिहार कोसी नदी की बाढ़ से प्रभावित होता है । साउथ इंडिया सहित सभी जगह इसकी समस्या है । आज पहली बार इस सरकार ने फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए न केवल अपने प्रयास से, बल्कि भारत नेपाल के साथ, भारत नीदरलैंड के साथ, भारत आस्ट्रेलिया के साथ समझौता करके आने वाले दिनों में फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट का काम करेगा ।

महोदय, इसी तरीके से मैं वाटर कंजर्वेशन की बात करना चाहता हूं । मैं बेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करना चाहता हूं । अभी तक आपको मालूम है कि बेस्ट वाटर मैनेजमेंट केवल 30 परसेंट रिसाइकल हो रहा है । हमारे लिए यह चिंता का विषय है । आपको यह महसूस नहीं हो रहा है कि जल का कितना महत्व है । कितना बड़ा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कितना बड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितने शहरों का ऑर्गनाइजेशन हो रहा है । गांवों का शहरीकरण हो रहा है । किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, यह हम सब के लिए चिंता का विषय है । अवधेश प्रसाद जी, यह राजनीति का विषय नहीं है । इस चिंता में सदन के सभी लोगों को शामिल होना चाहिए । आज जिस तरीके से सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय की इन योजनाओं को लिया है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, हर घर नल से जल योजना हो, आज हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जहां भी जल की कमी थी, आज मोदी जी के प्रयास से एक क्रांति आ रही है । आज हम जल को घर-घर तक पहुंचा रहे हैं । इसे हम जन-जन तक पहुंचा रहे हैं । आज हर खेत को पानी मिल रहा है । हम हर घर को नल से जल दिला रहे हैं । नहरों से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए और नदियों को जोड़ने के लिए योजना बना रहे हैं, जो दशकों तक नामुनकिन था, आज मोदी सरकार ने उसे मुमकिन करके दिखाया है । निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्रों में पानी की सुविधा मिलने वाली है ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य जी, माननीय जल शक्ति मंत्री गुजरात से हैं । गुजरात का एक अच्छा मॉडल है । जल संसाधन विभाग का बहुत अच्छा मॉडल गुजरात में है, आप थोड़ी सी इनकी भी तारीफ कर दीजिएगा ।

श्री जगदम्बिका पाल : मोदी जी प्रधान मंत्री है और सी. आर. पाटिल जी को इन्होंने मंत्री बनाया है । जिस राज्य में उन्होंने सूखा देखा, उनके मार्गदर्शन में सी. आर. पाटिल जी ने देश में हर घर को नल से जल पहुंचाया, लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिया, फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट करने का काम इन्होंने किया है । आने वाले दिनों में किसी भी राज्य में पानी की कोई कमी नहीं होगी । मैं मानता हूं कि सी. आर. पाटिल जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर यह होगा । अपने उत्तर

भाषण में जब वे बोलेंगे तो इस बारे में कहेंगे ।? (व्यवधान) मैं कनार्टक पर भी आना चाहता हूं, मऊ पर भी आना चाहता हूं ।? (व्यवधान) हम सिंगापुर मॉडल की बात करते हैं, उस सिंगापुर के साथ हम शहरी जल प्रबंधन कर रहे हैं । हमें जितनी चिंता गांवों की है, उतनी ही शहरों की भी है । दिल्ली में भी जल का संकट था । अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव में यह चुनौती थी । पानी के टैंकर माफिया हो गए थे । एमपी यहां सवाल उठाते थे कि दिल्ली में आम आदमी के लोग टैंकर माफिया हो गए हैं । लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था और कानून व्यवस्था का सवाल हो गया था । अरविंद केजरीवाल जी इसीलिए हार गए । अब दिल्ली में हर घर पानी मोदी जी की सरकार देगी, डबल इंजन की सरकार देगी, रेखा गुप्ता जी की सरकार देगी । हमने सिंगापुर के साथ शहरी जल प्रबंधन, जल विजयन, प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट जल, मतलब वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग पर हम तकनीकी सहयोग लेने जा रहे हैं ।

भारत, नेपाल में अभी एग्रीमेंट है । उसमें जो पूर्वानुमान है या हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, उसको आप नियमित रूप से एक्सचेंज करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे सीमा पार नदी प्रणालियों का प्रबंधन हो सके । उत्तराखंड से लेकर टनकपुर तक और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, महाराजगंज, बिहार के कोसी तक नेपाल का 1,575 किलोमीटर का बार्डर है, जिसमें नेपाल से पानी आता है ।? (व्यवधान) उससे फुटहिल्स में फसलों का बहुत बड़ा नुकसान होता है । नेपाल में हमारा एक ऑफिस भी है । हम क्या नेपाल के साथ मिलकर रिजर्वायर बना सकते हैं? रिजर्वायर बनायेंगे तो हाइड्रो पॉवर हाउस भी बन जाएगा । अगर चाइना भूटान के बार्डर पर बन सकता है तो हम क्यों न इसे बनाएं? जो हर साल बिहार, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या है, वह भी इससे दूर होगी और हम हजारों मेगावॉट बिजली पैदा कर सकेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि स्थायी हल यही हो सकता है ।

आपने बाढ़ प्रबंधन के लिए बिहार को करीब साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये दिए हैं, जो फ्लड प्रोग्राम के लिए, 22 जिलों के लिए है । यह हर साल की नियत है, इसमें उत्तर बिहार है, मिथिलांचल है, आपके असम में भी है ।? (व्यवधान) नार्थ-ईस्ट वाटर रिसोर्स एंड अथॉरिटी आपने वहां बना रखी है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड बना रखा है । इन सब राज्यों में आर्सेनिक और फ्लोराइड की बड़ी प्रॉब्लम है । उत्तर प्रदेश के फुटहिल्स में पानी में फ्लोराइड और आर्सेनिक है, चाहे बिहार हो या असम हो, सभी जगह यही स्थिति है । जो इरोज़न हो रहा है, आप उस फ्लड कंट्रोल और इरोज़न पर भी ध्यान देंगे ।

संयुक्त राष्ट्र के साथ वैश्विक जल सुरक्षा और सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए आपने करार किया है, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं ।

बांग्लादेश के साथ जो द्विपक्षीय सहयोग है, जो जेआरसी है, जॉइंट रिवर कमीशन है, उसमें नदी बेसिन के प्रबंधन को बढ़ावा दिया है, जल साझा प्रबंधन किया है । वर्ल्ड वॉटर फोरम में भी हमने भागीदारी शुरू की है । आज हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं । डोनाल्ड ट्रम्प जी ग्लासगो समिट से अलग हो गए । उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के लिए अमेरिका पैसे खर्च नहीं करेगा तो पूरी दुनिया से कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने का संकल्प किसी ने लिया तो नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया है । आज यूनाइटेड नेशन्स में अमेरिका और दूसरे देश फिर से जुड़ रहे हैं । इस तरह से भारत वर्ल्ड वाटर फोरम में भी भागीदारी निभाता है, अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है और जल संरक्षण पर वैश्विक विशेषताओं को सीखता है । पार्टनरशिप विद दी वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक भी महत्वपूर्ण है । सभापति जी, यह आपके राज्य से भी जुड़ा हुआ है ।

वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप है, साझेदारी है । इससे भारत में बड़े पैमाने पर जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण हो रहा है । आज हमारे पास फ्लड्स कंट्रोल सिस्टम है । भारत और भूटान के बीच बाढ़ प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों की एक संयुक्त समूह ज्वाइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्टीज है । उसी तरह से भारत और नेपाल में भी एक ज्वाइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्टीज बनना चाहिए जिससे यूपी, बिहार और उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति ठीक हो सके । मेरी मांग है, उत्तर प्रदेश में बागपत जिला है, यहां 150 गांव हैं । कृष्णा, काली इत्यादि तमाम गांवों में जिस तरह का पानी है, वहां पानी अम्लीय और आर्सेनिक युक्त है, जिससे लोगों को कैंसर हो रहा है । इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में खुलासा हुआ है कि नदी के पास जो नाले हैं, उससे कैंसर की क्षमता बढ़ती है ।

प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया, चाहे इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, अटल भूगर्भ जल योजना हो, पानी का वॉटर लेवल नीचे जा रहा है, हर राज्य में कुछ डार्क जोन हो रहे हैं । मैं महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं, पश्चिम बंगाल में भी, कल्याण बनर्जी साहब, डार्क जोन हो रहा होगा । पानी का लेवल नीचे जा रहा है । हम कैसे पानी को रिचार्ज करें, कैसे रिसाइकल करें, यह कोई व्यवस्था नहीं है । यह विकास की धारा है, इस विकास को, जल को, जीवन नहीं जल ही विकास है । अगर भारत में इसे कोई करेगा तो नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा । इसी के साथ में आज सी.आर.पाटील जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

CUT MOTIONS

TOKEN

कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरोद्धार विभाग के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 215) में 100 रुपये कम किए जाएं ।

62

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत राज्यवार नदियों को जोड़ने का काम शुरू किए जाने की आवश्यकता । (1)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): I beg to move:

Need to allocate adequate funds for flood control and improving the drainage system. (3)

SHRI SUDHAKAR SINGH (BUXAR): I beg to move:

Need to expedite implementation of flood control projects in Bihar, particularly for Kosi, Gandak and Bagmati river basins which cause severe annual devastation. (4)

Need for comprehensive anti-erosion measures for flood-prone districts like Buxar, Saran and Bhagalpur which face severe land loss due to erosion by river Ganga every year. (5)

Need to revive the stalled Kadwan Jalashay Pariyojna and expand the Sone river irrigation channels to ensure adequate water supply for agriculture in Buxar and surrounding regions. (6)

Need to expedite completion of the Uttar Koel Irrigation Project, which has been delayed for decades, to ensure irrigation benefits reach farmers in Bihar and Jharkhand. (7)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Need to provide funds for protection of rivers from pollution. (8)

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): I beg to move:

Need to improve irrigation facilities to ensure year-round water availability for farmers. (9)

Need to address delays in interlinking of rivers, including the Godavari-Cauvery linkage for water security in Tamil Nadu. (10)

Need to improve groundwater management and rainwater harvesting initiatives to counter over-extraction. (11)

Need to ensure full compliance with the Namami Gange programme and extend similar rejuvenation initiatives to other river basins. (12)

Need to strengthen flood management programmes and early warning systems for vulnerable areas. (13)

Need to promote the use of treated wastewater for irrigation and industrial purposes. (14)

Need to ensure equitable water distribution among states to prevent inter-state water conflicts. (15)

PROF. VARSHA EKNATH GAIKWAD (MUMBAI NORTH-CENTRAL): I beg to move:

Need to control alarming levels of pollution in India's rivers by initiating effective measures for pollution control, river cleaning and the restoration of river ecosystems. (16)

Need to control groundwater depletion in many parts of the country by promoting sustainable water management practices including rainwater harvesting, aquifer recharge and efficient irrigation techniques. (17)

Need for regular inspection, maintenance and strengthening of dams to ensure their structural safety and prevent potential disasters that could endanger lives and livelihoods. (18)

***m10 SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI):** I beg to move:

Need to allocate funds for special package for Maharashtra to address critical water infrastructure gaps, drought mitigation, and rural water security challenges. (19)

Need to allocate more funds to strengthen the Central Water Commission (CWC) to address staff shortages, enhance research activities and improve flood management strategies particularly in Maharashtra including Sangli, where inadequate implementation of CWC guidelines has contributed to recurrent flooding. (20)

Need to allocate more funds to strengthen the National Hydrology Project to improve real-time water monitoring, hydrological data collection, and flood forecasting. (21)

Need to allocate more funds to enhance the National Dam Safety Authority (NDSA) to ensure rigorous safety inspections, maintenance and modernization of aging dams. (22)

Need to allocate more funds to promote large-scale rainwater harvesting initiatives in Maharashtra, particularly in drought prone regions, to enhance groundwater recharge and water conservation. (23)

Need to allocate more funds to expand the Command Area Development and Water Management Programme (CADWM) to improve irrigation efficiency and reduce water wastage, particularly in command areas in Maharashtra. (24)

Need to allocate more funds to strengthen Atal Bhujal Yojana for better groundwater management and conservation particularly in over-exploited and critical blocks in Maharashtra including areas in Sangli, where groundwater depletion is a concern. (25)

Need to allocate more funds to improve flood management under the Flood Management and Border Areas Programme (FMBAP) to mitigate the impact of recurrent floods in vulnerable areas of Maharashtra particularly Sangli, which experiences frequent flooding from the Krishna river. (26)

Need to allocate funds to establish the Namami Krishna Mission to ensure the conservation and rejuvenation of the Krishna river which is crucial for drinking water, irrigation and ecosystem balance in Sangli and neighbouring regions. (27)

Need to allocate more funds to enhance water management in forest areas to improve water retention, prevent soil erosion and support biodiversity conservation in Maharashtra. (28)

***m11 श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) :** मैं प्रस्ताव करता हूँ:

जयपुर जिले में स्थित रामगढ़ बांध को अतिक्रमण से मुक्त और संरक्षित कराए जाने की आवश्यकता । (36)

समझौते के अनुसार पंजाब द्वारा राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति कराए जाने की आवश्यकता । (37)

नागौर, डीडवाना और कुचामन जिले में नहरों के माध्यम से सिंचित क्षेत्र विकसित करने की योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता । (38)

बीकानेर, गंगानगर एवं जैसलमेर जिले में किसानों को सिंचाई हेतु इन्दिरा गांधी नहर से पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता । (39)

राजस्थान की रामजल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पीकेसी ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता । (40)

राजस्थान में लूनी, जोजरी, बांदी, बनास और अन्य नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाकर नदियों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता । (41)

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

गुजरात एवं राजस्थान के बीच वर्ष 1966 में बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के डूंगरपुर जिले में माही एवं कडाणा बांध निर्मित होने के समझौते की शर्तों को पूर्ण कर बांसवाडा-डूंगरपुर में सिंचाई योजना की परियोजना की स्वीकृति की आवश्यकता । (45)

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 और 2023-24 में अमरपुरा बांध, भाई का नाका, घोरिया बांध और अन्य बांधों और नहरों के नवीनीकरण, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, में कथित भ्रष्टाचार की जांच की आवश्यकता ।(46)

बाबरा का नाका, झोंत्री-डूंगरपुर, मोदरा महुड़ी, सिमालवाड़ा और पूरे बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नए बांधों और नहरों के निर्माण और पुराने बांधों और नहरों के नवीनीकरण की आवश्यकता । (47)

बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के डूंगरपुर जिले में मौरन, भादर वटट्रैक, मैसवो, अनस और अन्य सभी छोटी नदियों की सफाई और एनीकट के निर्माण की आवश्यकता । (48)

बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के डूंगरपुर जिले में बहने वाली माही नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ सभी बांधों और तालाबों को जोड़ने के लिए एक परियोजना को मंजूरी देने की आवश्यकता । (49)

माही नदी और सोम-कमला-अम्बा बांध की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये के अवैध रेत खनन को तत्काल रोकने की आवश्यकता । (50)

(TOKEN)

कि पेयजल और स्वच्छता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 222) में 100 रुपए कम किए जाएं । 63

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

देश भर में विशेषकर उत्तर बिहार में नदियों में जमा गाद को साफ करने की आवश्यकता । (51)

बिहार के पूर्णिया शहर के पास मलजल शोधन संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता । (52)

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): I beg to move:

Need for ensuring safe drinking water for all. (53)

Need for implementation of water supply schemes in a time bound manner. (54)

Need for preventing pollution of drinking water sources in water supply schemes. (55)

***m15 SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** I beg to move:

Need to provide funds to formulate scheme for ensuring safe drinking water and sanitation facility in rural area. (56)

Need to provide funds for conservation and protection of Ashtamudi lake and Sasthamcotta lake in Kollam. (57)

Need to provide funds for conservation of ponds and construction of new ponds. (58)

Need to provide funds for protection of drinking water sources. (59)

Need to provide funds for formulating special scheme for providing water through pipes laid under Jal Jeevan Mission by improving drinking water sources and pumping mains. (60)

Need to provide funds for strengthening the rain water harvesting. (61)

Need to provide funds for formulating scheme for promoting ground water recharging. (62)

Need to provide funds for establishing an effective scheme for ensuring the transparency in implementation of drinking water projects. (63)

Need to provide funds for completion of new projects for drinking water resources and irrigation. (64)

Need to provide funds for special project for conservation and protection of water bodies in Kerala. (65)

***m16 DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH):** I beg to move:

Need to increase budget allocation for Jal Jeevan Mission to ensure timely completion of rural drinking water projects. (66)

Need for better coordination with states to address urban water pollution and sanitation challenges. (67)

Need to implement stringent measures to curb industrial pollution in rivers and water bodies. (68)

Need to ensure sustainable urban water supply and sewage treatment plants in rapidly growing cities. (69)

***m17 PROF. VARSHA EKNATH GAIKWAD (MUMBAI NORTH-CENTRAL):** I beg to move:

Need to speed up the progress in achieving universal tap water connections and accelerate efforts to ensure access to clean and safe drinking water for all households particularly in rural areas. (70)

Need to control widespread contamination of drinking water sources by pollutants, including industrial waste and agricultural runoff through stricter enforcement of regulations and increased investment in water purification technologies. (71)

***m18 SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI):** I beg to move:

Need to allocate more funds to enhance water quality testing laboratories under Jal Jeevan Mission (JJM) particularly in Sangli region to ensure access to safe drinking water and early detection of contamination. (72)

Need to allocate more funds to strengthen the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) for improving

the credibility and reliability of rural water quality testing facilities. (73)

Need to allocate more funds to implement Village Action Plans (VAPs) under Jal Jeevan Mission (JJM) with a focus on villages in Sangli to ensure community participation and sustainable rural water management. (74)

Need to allocate more funds to repair roads damaged due to pipeline laying under JJM particularly in Sangli. (75)

Need to allocate more funds to sustain Open Defecation Free (ODF) status in rural areas like Sangli by promoting behavioral change and community-led sanitation initiatives. (76)

Need to allocate more funds to improve ODF Plus initiatives in villages declared ODF Plus to ensure sustainable sanitation infrastructure and hygiene practices. (77)

Need to allocate more funds to strengthen solid and liquid waste management systems in rural areas with a specific focus on Sangli region in Maharashtra. (78)

Need to allocate more funds to construct and maintain Community Sanitary Complexes (CSCs) in rural areas particularly in Sangli to improve sanitation facilities, especially for women and vulnerable groups. (79)

Need to allocate more funds to accelerate the implementation of the GOBARdhan scheme to promote bio-energy generation and organic waste management in rural areas. (80)

Need to allocate more funds to promote twin-pit toilets in rural households particularly in Sangli to ensure long-term sustainability and safe sanitation practices. (81)

SHRI RAJEEV RAI (GHOSI): I beg to move:

Need to provide tap water connection under Har Ghar Jal Scheme for more than 900 villages in Mau district of Uttar Pradesh. (82)

Need to expedite provision of tap water connection under Har Ghar Jal Scheme to every household which has missed the original completion

target of December 2024. (83)

Need for repair and restoration of roads, sewers, drains etc. after laying of piped water connections in Mau district. (84)

***m20 SHRI SUDHAKAR SINGH (BUXAR):** I beg to move:

Need to ensure full implementation of the Jal Jeevan Mission (JJM) in Buxar by providing 100 per cent. tap water connections to every household without delay. (85)

Need for urgent measures to prevent groundwater contamination in Buxar and Kaimur for ensuring safe drinking water by regulating industrial discharge and conducting regular water quality assessments. (86)

***m21 श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) :** मैं प्रस्ताव करता हूँ:

नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान के अन्य जिलों में सिंचाई और पेयजल के लिए राष्ट्रीय परियोजना विकसित किए जाने की आवश्यकता। (90)

राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कथित भ्रष्टाचार की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता। (91)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर देना चाहते हैं, वह दे सकते हैं।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I would like to discuss the Demands for Grants under the Ministry of Jal Shakti for 2025-26. ....*(Interruptions)*

The Ministry of Jal Sakti has got two Departments ? the Department of Drinking Water and Sanitation, and the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.

The Jal Jeevan Mission (JJM) intends to provide 55 litres of potable water per person per day to every rural household through functional household tap connections. This scheme had to be completed by 2024. But today we are in 2025.

As of now, only 80 per cent of the scheme has been completed as far as Jal Jeevan Mission is concerned. As only 15 crore of households have been given tap connections, the balance 20 per cent households are yet to be provided the connection. By which year the remaining connections will be completed has not been quoted anywhere by the Ministry. So, nearly 20 per cent household connections have yet to be done. This is very important and the Government should come forward to see that this is done on time.

I have only one question in this regard. In 2023-24, an amount of Rs.69,992 crore have been spent. Last year, the earmarked amount to be provided was Rs.70,000 crore whereas the Government spent only Rs.22,000 crore. So, nearly an amount of Rs.50,000 crore have not been spent. That means, the Government is not really interested to see that the project is completed in 2024-25 itself. They have not spent Rs.50,000 crore earmarked last year for the project. I want to know why this amount sanctioned has not been spent so far.

Sir, initially in 2019, when the programme was launched, the total outlay was Rs. 7 lakh crore. Now, they have spent only Rs. 3 lakh crore, and another Rs. 4 lakh crore need to be spent to complete the project. This is the status of the Jal Jeevan Mission. The Jal Jeevan Mission is intended to cover the entire rural India, from the source to the habitation. However, so far, things have not developed as such. In the 2014 election, our friend Modiji promised during the election campaign that he would ensure the inter-State river linking would be established. He mentioned about Himalayan rivers as well as Peninsular rivers. But so far, they have not brought out any scheme and no DPR has been created for the Himalayan and Peninsular rivers. There is no scheme at all. As far as the Peninsular rivers are concerned, this is a water-starving area, a water-deficit area, whereas the Himalayan rivers are water-surplus areas. Water surplus areas must be connected to water-starving, water-deficit areas.

Just now, my friend, Mr. Jagdambika mentioned that Arthur Cotton, the British engineer, initiated the project. He created many forums and discussed the matter with various technical groups, but nothing could be accomplished by himself. Now,

afterwards, in independent India, many forums and groups of engineers have discussed this, and even Shri K. L. Rao came forward in Parliament, stating that he would ensure that the rivers of Peninsular India would be connected as early as possible. However, nothing has been done so far. The Indian rivers in Peninsular India, especially the Mahanadi, Godavari, Krishna, Pennar, and Kaveri, need to be connected so that maximum benefit can be derived for Peninsular India. But so far, things are not moving in the correct direction. It is moving at a snail?s speed. Prime Minister Modi came forward to connect Ken and Betwa, a distance of 221 kilometres between UP and Madhya Pradesh. I am not against it; I support it. However, more initiatives need to be taken. The Ken and Betwa project between UP and Madhya Pradesh is being implemented, with more than Rs. 9,000 crore invested so far. But we do not know when that particular project will be completed. That is one thing.

Another issue in Peninsular India is that things must be taken in the correct perspective. So far, nothing has been developed, and even the project report has not been created. When Shri K. L. Rao was a Minister, he categorically stated that this could be done shortly. However, we do not know how far ?shortly? is. He has passed away, but things are not moving in the correct direction. After Ken and Betwa, we thought the Government would connect the Peninsular rivers of India, but so far, there has been no progress. There has been no discussion during the Question Hour or in discussions like this. The Minister concerned, the new Minister, should clarify when they will take up the Peninsular India inter-connection. What are the additional benefits of connecting north-south rivers? I believe the maximum transport system can be established in river waters, allowing river waters to transport cargo from north to south and south to north. This matter must be considered positively because the cash flow and the benefits from this project will be enormous.

15.00 hrs

Not only that, the power utilized for this purpose can be recovered by developing power stations here and there according to the levels of water flow. So,

power generation can be done; pollution control could be done; and fisheries can be developed. These are all the benefits out of it, but the Government is hesitant to do it.

The Government has taken up the Mumbai-Ahmedabad Bullet Train project and it is being implemented without understanding the cash benefit. They have ventured into this project, but at the same time, they are hesitating to ensure peninsular interconnection and it is being delayed. I do not know why it is getting delayed. Why are they not having the river action plan between North and South? This should be done quickly.

I would request the hon. Prime Minister and the Minister concerned to see that this is taken up. Even without understanding the questionable viability of the Bullet Train project, they have started it and they are going ahead, but at the same time, the South Indian rivers should be connected, which is more profitable, and it should be developed as quickly as possible. Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Thank you, hon. Member, Shri Baalu ji**.**

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): I wish to raise certain critical issues in respect of the demand for grants for the Ministry of Jal Shakti.

The Ministry of Jal Shakti is responsible for management of water across India and for making sure that water is available for diverse needs such as domestic use, sanitation, irrigation etc. However, the Government has been severely underperforming when it comes to carrying out tasks relating to water management and utilization of funds for development of water resources and projects in India.

I wish to point out in this regard that the Standing Committee on Water Resources in its Report tabled a few days ago has highlighted that nearly 40% of the allocated funds have remained unspent and that there were massive delays in fund disbursal and project execution. In fact, while assessing the budgetary planning of the Jal Shakti Department of the Central Government, the committee noted as follows:

The Committee observe that frequent drastic reduction of budgetary provisions of the Department at RE stage and subsequently enhancing the BE for next Financial Year indicates lack of proper planning for budgetary requirements by the Department. The Committee, therefore, recommend that the Department undertake their pre-budget exercise with much more care and prudence for making more pragmatic and conservative budgetary estimates. [2.1-recommendations In this regard, I must point out that the Jal Jeevan Mission, which is one of the flagship programs of the Central Government, had seen huge dip in the revised budgetary estimates stage which has resulted in the scheme not being able to be as effective as it was aimed to be. The Parliamentary Standing Committee has also taken a sharp note on this situation:

The Committee would like to be apprised of the specific reasons for such a huge reduction at RE stage for FY 2024-25 and its impact on execution of this ambitious Programme. In view of the fact that JJM has been extended till 2028, the Committee urge upon the Department to make concerted efforts to utilize the budgetary allocations optimally in order to obviate the possibility of huge reduction at RE stage which has been witnessed in current Financial Year (2024-25).

I must point out that the Central Government has failed to cover large number of households in Kerala with functional tap water connections which is one of the key aspects included in the Jal Jeevan Mission. The Central Government had a target of covering all households by 2024, however, this target is far from being achieved till date. The Standing Committee on Water Resources, in its report tabled in Parliament in February 2025 had noted that the progress of the Jal Jeevan Mission in many states was quite low. In fact, the panel report categorically stated that it was 'concerned and dismayed' and since the launch of the mission in 2019, only 11 states had been able to achieve the 'Har Ghar Jal' Status.

If we take States such as Kerala, Jharkhand, Rajasthan and West Bengal, then less than 60% of the households have functional taps in these states. It is important to note that most of these States are opposition ruled states and therefore a clear bias of the government in implementing central schemes comes out when one sees these

figures. I believe that no government should discriminate when it comes to resources such as water, however, this government has not even spared this domain. The Parliamentary Standing Committee on Water Resources has taken a strong note of this situation in its Report:

"However, the Committee note that still a major part of the work remains to be completed in West Bengal, Rajasthan, Madhya Pradesh, Kerala and Jharkhand which have so far achieved coverage of only 54.51%, 55.39%, 67.29%, 54.25% and 54.66% respectively.

Being of the view that active participation of the States is essential to make the Programme a success, the Committee urge upon the Department to look into the particular problems of each of the lagging States hampering timely completion of the Projects and take remedial measures for faster implementation of the Projects in these States."

Additionally, many project clearance proposal of states such as Kerala (in relation to Jal Jeevan Mission) have been pending with the Central Government and have not been cleared till date which further adds to the problem of effective implementation of the Jal Jeevan Mission across India. This aspect has yet again been noted in the Parliamentary Committee Report:

"Similarly, in case of Kerala, out of 67 proposals submitted with National Highways Authority of India (NHAI), 29 are pending. The Committee in view of the objective of the Jal Jeevan Mission (JJM) of providing assured potable tap water in adequate quantity on a regular and long-term basis to every rural household urge the Department to make necessary endeavours to expedite the clearance of the pending projects of rural water supply within a reasonable timeframe"

I wish to also highlight that in view of the budgetary discrepancies and unclear policies by both the Central and the State Government, the works in relation to many Jal Jeevan projects have been abandoned by contractors in Kerala due to huge pending dues and therefore there is a complete stalemate in such projects.

Another major issue is the provision of good quality drinking water to people all over the country. Till date, the Government has not been able to implement a mechanism through which quality drinking water is reaching each and every household in India. If we take the State of Kerala, almost 40% households would not meet quality drinking water standards (as per an Assessment Report of 2022). Accordingly, the government surely needs to work on this to improve this situation.

I wish to highlight that there are about 11000 affected habitations / affected areas where the water is completely contaminated due to iron, salinity, nitrate and heavy metals where short term measures need to be immediately provided to help the affected population. In Kerala, the districts of Allappuzha, Idukki, Kannur, Kasaragod, Kozhikode, Malapurram, Palakkad, Thiruvanthampuram, Thissur and Wayanad are such affected areas and therefore the government needs to take immediate action to improve the contaminated water situation in such places.

We live in a world where resources are scarce and therefore conservation and effective utilization of water becomes very important in today's day and age. Rainwater harvesting should therefore be promoted by the Central Government and I would urge the Central Government to increase the funding and direct incentives to states and local bodies so that they can make provisions and create adequate infrastructure for rainwater harvesting.

This Government has time and again made tall claims that it wants to clean and sanitize Ganga, however, the reality is quite different and the facts show that the government is not interested in rejuvenating Ganga at all.

i. Funds allocated towards Namami Gange have been underutilised every year since 2014-15, except two years (2020-21 and 2021-22).

ii. ii. 69% of the budgeted amount has been spent up to 2024-25. In 2015, the Clean Ganga Fund was established, to enable the public, non-resident Indians, corporates, and trusts to contribute towards Ganga conservation efforts.

iii. iii. The PAC (2024) had observed that this fund was lying largely unutilised. As of March 31, 2024, the Fund had Rs 876 crore. Of this, Rs

383 crores have been sanctioned for various projects.

Therefore, the government needs to put concerted efforts to reduce pollution in water bodies like the Ganga and make cohesive plans along with adequate budgetary allocations to implement such plans.

The allocations for Jal Shakti should also take into account certain disaster management requirements.

i. Mechanisms and plans need to be devised to prevent landslides and floods all over India.

ii. ii. Climate change is increasing the melting rate of Himalayan glaciers. Floods caused by glacial outbursts release vast quantities of water in a short time. The Standing Committee on Water Resources (2023) has noted that there are many gaps in glacier monitoring and research. No studies have been taken up to examine the loss of glacial volume in the Himalayas, changes in glacial lakes over time or the impact of atmospheric pollution on glaciers Accordingly, steps need to be taken to mitigate such issues.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): In the grand narrative of governance, numbers can often mask the realities they are meant to represent. Nowhere is this more apparent than in the Union Government's repeated proclamations around the Jal Jeevan Mission (JJM) and rural irrigation schemes. Every year, the Ministry of Jal Shakti's budget is presented with celebratory figures, citing near-universal tap water coverage, capital expenditure hikes, and infrastructure creation. But for states like Maharashtra, particularly in its drought-prone belts, these numbers conceal a far more unsettling story-one of underutilization, non-functionality, and quiet abandonment.

The 2025-26 budget, when examined closely, reveals serious cracks beneath the surface. Two critical decisions stand out: the first is the persistent underperformance and qualitative failings of the Jal Jeevan Mission in Maharashtra; the second, more alarming, is the complete discontinuation of the Special Package for Irrigation Projects meant to address agrarian distress in the state's chronically drought-affected

districts. Together, these reflect a policy approach that prioritizes headline achievements over sustainable, long-term water security for the most vulnerable.

The Jal Jeevan Mission: Prioritising Quantity Over Quality

The Jal Jeevan has been hailed as a revolutionary step towards providing every rural household with tap water connections, but its implementation in Maharashtra as well as across the country raises uncomfortable questions.

In Maharashtra, the funds actually withdrawn under the Jal Jeevan Mission have consistently remained well below even 50% of the budgetary allocation. In most financial years, utilization has stagnated around 20-30%, indicating serious bottlenecks in fund absorption and implementation capacity. This underutilization raises fundamental questions about not just administrative efficiency but also the feasibility of targets being showcased.

Moreover, the quality and functionality of these tap water connections is far from satisfactory. A 2022 evaluation by the Ministry itself revealed that although most rural households in Maharashtra had functional tap connections, only 62% received adequate, regular, and safe water. In reality, many villages receive tap water barely once a week, forcing residents to continue purchasing water from private sources. This not only places a financial burden on rural families but also undermines the core objective of universal, reliable water access.

Equally worrying is the issue of water quality and safety. The Ministry's own National Report on Functionality Assessment 2022 highlights critical gaps in water quality surveillance. Testing infrastructure remains inadequate, with several districts lacking access to NABL-accredited laboratories. There is also no robust, decentralized system to regularly test water at the community level. As a result, contamination-whether from fluoride, arsenic, iron, or microbial sources-often goes undetected for long periods.

In FY 2023-24, Maharashtra reported 9.73% chemical contamination and, even more concerningly, biological contamination, nearly 1/3 of water samples, and over 17% of submitted samples were not tested at all. Rural households are, therefore, exposed to the risk of serious health hazards, ranging from gastrointestinal diseases to long-term developmental impacts.

Additionally, there is little effort to address water safety at the household level. The Mission stops at the tap, ignoring the need for household-level filtration solutions, storage hygiene, or public awareness campaigns. Across many villages, dissatisfaction is palpable-residents report foul taste, odour, and discolouration of water, and several communities have linked these lapses to recurring illnesses, forcing them to revert to unsafe traditional water sources despite having tap connections on paper.

The systemic flaw runs deeper. 74% of Jal Jeevan Mission connections rely on groundwater sources, yet the budget lacks proportionate investment in groundwater recharge, catchment protection, or community-led maintenance efforts. Without ensuring sustainability, these schemes risk becoming yet another case of infrastructure slippage-where connections exist on paper but cease to function in reality.

These deficiencies are best illustrated by the case of a Jammu and Kashmir- based IAS officer who, in July 2024, flagged irregularities of about Rs 690 crores in the procurement of substandard pipes that were unsuitable for the hilly conditions of the state. This was not merely a case of alleged financial misconduct-it illustrates how compromised quality and lack of contextual planning can sabotage the long-term viability of such essential infrastructure. If pipes cannot withstand the climate of J&K, or the droughts of Maharashtra, then no amount of headline coverage can compensate for non-functional systems on the ground.

If the Jal Jeevan Mission is to achieve its objectives in spirit, rather than merely on paper, the government must strengthen water quality surveillance, ensuring all districts have adequate accredited laboratories and decentralized testing. In the long

term, it must invest in sustainability-groundwater recharge, catchment protection, and maintenance budgets-so that Jal Jeevan Mission does not become yet another short-lived scheme.

Discontinuation of Special Package for Irrigation Projects in Drought-Prone Areas of Maharashtra

This pattern of withdrawal and neglect extends beyond the Jal Jeevan Mission. Another deeply concerning decision reflected in this year's Budget is the complete discontinuation of the Special Package for Irrigation Projects for drought-prone districts of Maharashtra. This package, introduced in 2016 to address chronic agrarian distress in various parts of Maharashtra, had last year received ₹600 crore, of which only 2/3 was utilised. This year, its allocation stands at zero.

This is a matter of serious concern. Most of Maharashtra has not even come close to overcoming water stress. Less than 20% of cultivable land in these regions is under assured irrigation. Rain-fed agriculture continues to dominate, leaving farmers highly vulnerable to monsoon variability and crop failures. Less than one week ago, an award-winning farmer from one of the areas covered under this scheme died of suicide after he was unable to support himself and his family due to a lack of sustainable water supply to his farmland and his repeated appeals to the government were ignored.

The decision to withdraw funding, without providing status updates or indicating alternative financing mechanisms, puts the fate of thousands of ongoing irrigation works in jeopardy. These projects were lifelines designed to give farmers some respite from recurring drought and debt cycles and I urge the government to restore this scheme to avoid worsening the crisis faced by the farmers of Maharashtra.

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): I am expressing my views on Demands for Grants 2025-26 pertaining to Ministry of Jal Shakti and its working. In 2025-26, the Ministry of Jal Shakti has been allocated Rs 99,503 crore, marginally higher than the budget allocation in 2024-25 (Rs 98,714 crore). But, I want to point out that the

revised estimate for expenditure in 2024-25 is 48% lower than the budget allocation. There is drastic allocation to the Jal Jeevan Mission at the revised stage.

2. The Union Budget 2025-26, is comprehensively biased as the budget grossly ignores the needs of Tamil Nadu and betrayed the expectations of the people, therefore, the union budget is completely anti-poor, anti-women, anti- youth and anti-farmer. The Union Budget is prejudiced as it completely ignored the demands of Tamil Nadu, despite the fact the economic survey, ranking of higher Education Institutions and the NITI Aayog Reports praised the State's activities. Needless to say, reduction in central funding increase the financial burden on the State Government.

3. The State of Tamil Nadu could not be provided clean drinking water to every household by 2024 under *Nal Se Jal* Scheme which is an important component of *Jal Jeevan Mission* could not achive the target. The Standing Committee on Water Resources (2024) noted that there were challenges in providing good quality drinking water. Needless to say, people of my Parliamentary constituency have been experiencing perennial water scarcity; Sathanur Dam which is the main source of drinking water for people of Tiruvannmalai Parliamentary Constituency, has not been desilted since its construction. The water level of Sathanur dam as well as water table in the region has gone down considerably. The water woes of that area has assumed the drought like situation.

4. I, therefore, honestly request the hon. Minister to implement the following for Tiruvannmalai Parliamentary Constituency on pilot basis to avoid drought like situation and solve water crisis permanently:

(i) Piped drinking water supply to all households in the Tiruvannmalai Parliamentary Constituency;

(ii) Disilting of Sathannaur Dam on River Pennaiyar; and

(iii) Linking of Krishnagiri Dam Canal and Chettary Dam Canal by digging stretch of one Kilometer.

5. I humbly appeal to the Finance Minister to earmark sufficient budgetary allocation to Ministry of Jal Shakti to build physical infrastructure along the coastline of the Country in general and in the State of Tamil Nadu in particular for commercial utilization of coastline in order to exploring employment generation and for enhancing the contribution of State in the GDP of the Country.

Thank You

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आणंद): श्री सीआर पाटील जी, मान. मंत्री श्री जल शक्ति मंत्रालय के प्रेरणादायक सूत्र ??जल है तो कल है" को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय जेएल शक्ति मंत्री जी से मेरे लोकसभा मतक्षेत्र आनंद में जल संरक्षण के लिए एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ । हमारे क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं, आरोग्य विभाग के PHC/CHC/UHC/AAM-HWC केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा पंचायत घरों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने हेतु आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अटल भूजल योजना के अधिकारियों को आनंद लोकसभा क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु आवश्यक अनुदान देने की अनुशंसा करें ।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में, "जल संरक्षण सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन होना चाहिए । हमें प्रकृति के इस अनमोल उपहार को संरक्षित करने की जिम्मेदारी सबकी है ।" उनके जल शक्ति अभियान' और 'नमामि गंगे जैसे दूरदर्शी कार्यक्रमों ने देश में जल संरक्षण के प्रति एक नई चेतना जगाई है । आज हमारा दृष्टिकोण 'हर घर जल' से आगे बढ़कर 'हर घर जल संचय की ओर होना चाहिए, जिससे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रख सके ।

सादर,

***m27 श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी (सिवान) :** मैं इस पावन सदन में अपने सिवान लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण माँगों को रखती हूँ ।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष धन्यवाद करते हुए, सबसे पहले, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने जल संसाधनों की महत्ता को समझते हुए जल शक्ति मंत्रालय के लिए अभूतपूर्व ₹99,503 करोड़ का बजट आवंटित किया । जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,

अटल भूजल योजना जैसी योजनाओं ने देशभर में जल संकट के समाधान हेतु क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं ।

वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिला है, लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र सिवान में अभी भी कुछ गाँव इससे वंचित हैं ।

मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि जल जीवन मिशन के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि शत-प्रतिशत घरों तक नल से स्वच्छ जल पहुँचे ।

मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहतीं हूँ कि हर वर्ष घाघरा नदी में आई बाढ़ से सिवान के दर्जनों गाँव जलमग्न हो जाते हैं ।

बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) के तहत ₹450 करोड़ का आवंटन किया गया है, मैं माँग करती हूँ कि इसमें से उचित राशि सिवान क्षेत्र की बाढ़ रोकथाम हेतु दी जाए ।

हमारे किसानों को सिंचाई के लिए भूमिगत जल पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है ।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ₹8,260 करोड़ का आवंटन किया गया है, मैं माँग करती हूँ कि सिवान के किसानों को भी माइक्रो-इरीगेशन, ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाए ।

मेरे लोकसभा क्षेत्र सिवान में कई क्षेत्रों में भूजल स्तर गिरता जा रहा है, जिससे पीने और सिंचाई दोनों में समस्या उत्पन्न हो रही है । मैं माँग करती हूँ कि अटल भूजल योजना (ABY) को सिवान लोकसभा क्षेत्र में भी लागू किया जाए ।

मेरे लोक सभा क्षेत्र सिवान में दाहा नदी जो अत्यंत प्रदुषित हो गई है जिससे सिचाई एवं धार्मिक कार्यों तथा पशुपालको के उपयोग में समस्या हो रही है । मै माँग करती हूँ कि दाहा नदी को साफ-सफाई किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय मेरे लोक सभा क्षेत्र सिवान में स्थित दाहा नदी सिवान मुख्यालय होते पूरे शहर के बीच से होकर गुज़रती है । पूरे शहर का गंदा एवं नाले का पानी इस नदी में आता है । पूरा नदी प्रदूषित है, जगह जगह पर कचड़ा डंप किया जा रहा है, जिससे पानी और ज़्यदा दूषित हो रहा है । मै माँग करती हूँ कि दाहा नदी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य करके गंदा पानी को साफ-सफाई किया जाय ।

गंगा सफाई के लिए ₹2,400 करोड़ का आवंटन हुआ है, लेकिन बिहार की अन्य नदियाँ भी प्रदूषित हो रही हैं ।

मैं माँग करती हूँ कि नमामि गंगे योजना का विस्तार करके सरयू और गंडक नदी को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाए ।

मैं इस सदन के माध्यम से आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि सिवान लोकसभा क्षेत्र के जल-संकट और सिंचाई समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए ।

जैसा कि वेदों में कहा गया है: "जल ही जीवनदायी है, जल से ही शक्ति प्राप्त होती है ।"

आपके माध्यम से मैं इस सदन से अपील करना चाहती हूँ कि, हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के "हर घर जल" संकल्प को पूरा करें और अपने क्षेत्र के नागरिकों को जल सुरक्षा प्रदान करें ।

धन्यवाद! जय हिंद! जय भारत ।

***m28 श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर) :** आज मै वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किये गए 2025-26 के आम बजट में जल शक्ति मंत्रालय डिमांड और ग्रांट्स के समर्थन अपने विचार व्यक्त करता हूँ ।

मैं स्वयं को सम्मानित महसूस करता हूँ कि मुझे इस सदन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय ? जल सुरक्षा को उजागर करने का अवसर मिल रहा है । यह सतत विकास और मानव गरिमा का एक मूल स्तंभ है । जल केवल एक संसाधन नहीं है, बल्कि यह जीवनरेखा है, और इसका प्रबंधन केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है । राष्ट्रीय स्तर पर, जल शक्ति मंत्रालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो पूरे देश में जल के समानुपातिक और सतत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

2025-26 के बजट में जल शक्ति मंत्रालय के लिए 99,503 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो मंत्रालय के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक बजट है । यह एक सराहनीय वृद्धि है और यह दर्शाता है कि सरकार जल संरक्षण, उसकी सुगम उपलब्धता और सतत उपयोग को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

जल शक्ति मंत्रालय की सबसे प्रभावशाली पहलों में से एक जल जीवन मिशन (JJM) है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को शुरू किया था । जब यह मिशन

प्रारंभ हुआ था, तब केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों (17%) को नल से जल की सुविधा प्राप्त थी । लेकिन आज, मुझे गर्व के साथ यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि 1 फरवरी 2025 तक इस मिशन के तहत 12.20 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है । अब तक कुल 15.44 करोड़ ग्रामीण परिवारों को इस सुविधा से जोड़ा जा चुका है, जिससे 79.74% ग्रामीण घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा चुका है ।

इसके अतिरिक्त, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि जल जीवन मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति से हर दिन 5.5 करोड़ घंटे बचेंगे, जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा जल लाने में व्यर्थ किए जाते थे । यह मिशन न केवल जल उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम है ।

बिहार ने जल जीवन मिशन के तहत एक अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी नेतृत्व में 1.57 करोड़ परिवारों को स्वच्छ नल जल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि बिहार के 98.26% विद्यालयों में अब कार्यशील नल जल कनेक्शन उपलब्ध हैं, जिससे हमारे बच्चों के लिए बेहतर स्वच्छता, स्वास्थ्य और हाइजीन सुनिश्चित हो रही है । यह एक क्रांतिकारी उपलब्धि है, जो राज्य के सतत विकास और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार का प्रमाण है ।

मैं जल शक्ति मंत्रालय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने अटल भूजल योजना का विस्तार करते हुए इसे 8,200 करोड़ रुपये के बजट के साथ बिहार सहित पांच नए राज्यों में लागू किया है । यह पहल जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों के लिए गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि यह माइक्रो-इरिगेशन, फसल विविधीकरण और पाइपलाइन आधारित जल आपूर्ति जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों के माध्यम से भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करेगी । इसके अतिरिक्त, चेक डैम, तालाब, परकोलेशन टैंक और रिचार्ज शाफ्ट जैसी भूजल पुनर्भरण की पहलों से बिहार में जल स्तर में महत्वपूर्ण सुधार होगा । यह योजना राज्य के किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने मे अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगी ।

(WRD) के अनुसार, बिहार देश का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, जो भारत के कुल बाढ़ संभावित क्षेत्र का 17.2% हिस्सा रखता है । चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर बिहार का 76% और दक्षिण बिहार का 73% क्षेत्र, यानी कुल 6.88 मिलियन हेक्टेयर भूमि हर साल बाढ़

की चपेट में आती है । वर्तमान में, बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ संभावित हैं, जिससे लाखों लोग विस्थापित होते हैं, किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं, और कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है ।

भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील बना हुआ है, जहां कोसी, गंडक और बागमती जैसी प्रमुख नदियों के तटबंध टूटने से हर साल तबाही मचती है । वर्ष 2024 में स्थिति और भी गंभीर हो गई, जब नेपाल में कोसी नदी के बीरपुर बैराज से 6.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो लगभग छह दशकों में सबसे अधिक था । यह गंभीर स्थिति दर्शाती है कि अब स्थायी बाढ़ नियंत्रण उपायों की तत्काल आवश्यकता है । बिहार इस संकट को बार-बार झेलता नहीं रह सकता, और हम आपसे ठोस कार्रवाई की मांग करते हैं ।

मैं बिहार के वाल्मीकिनगर लोक सभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ हर वर्ष यह क्षेत्र बाढ़ के चपेट में आ जाता है अभी कुछ दिन पहले मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मसान नदी से भारी तबाही प्रतिवर्ष बरसात में होती थी, उसके स्थायी निदान हेतु गाईड बांध स्वीकृत हो गया, कार्य प्रगति पर है । इसके अलावे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अभी भी उपरोक्त के अतिरिक्त सैकड़ों गाँव हैं जो नदियों के द्वारा कटाव के कारण निवासियों के विस्थापित होने की स्थिति बनी हुई हैं । यदि यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो हो सकता है वर्षात के बाद कुछ गाँव का अस्तित्व ही नहीं रहे जैसे की लौरिया प्रखंड अंतर्गत सिकरहना नदी से प्रभावित गाँव, सिसवनिया पंचायत अंतर्गत ग्राम बरवा कला, लौरिया नगर पंचायत अंतर्गत ग्राम नोनिया टोला, बेलवा लखनपुर पंचायत के ग्राम जीरिया एवं जवाहिरपुर, पंचायत दनियाल प्रसौना के ग्राग - राम प्रसौना एवं दनियाल प्रसौना, धमौरा पंचायत में ग्राम वृंदावन तथा पंचायत का ग्राम ? बेलवाटोला

नरकटियागंज प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत हरदीटेढ़ा का ग्राम- हरदीटेढा; जो पंडई नदी से कटाव की स्थिति में है ।

गौनाहा प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत-लक्षनौता के ग्राग पोहरा महादलित बस्ती तथा ग्राम- जड़िया जो हरबोड़ा नदी से हो रहे कटाव के कारण विस्थापित होने के कगार पर है ।

आपके मध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है की कटाव को रोकने हेतु तत्काल प्रभाव से उचित निर्णय लेने की जरुरत है

अंत में मैं जल शक्ति मंत्रालय डिमांड और ग्रांट्स के समर्थन करते हुए सरकार को धन्यवाद देता हूँ

कि यह सरकार आम लोग के लिए बचनबद्ध हैंI धन्यवाद ।

SHRI RAO RAJENDRA SINGH (JAIPUR RURAL): I would firstly like to express our sincere commendation to the Ministry of Jal Shakti for the outstanding achievements it has made under the able stewardship of Hon. PM Shri Narendra Modi Ji. As my contribution to this deliberation, I seek to address to you a few matters of immense public importance that pertain with the long-term policy goals of the Ministry.

Kev Achievements in the Last 6 Years

First and foremost, let us acknowledge the remarkable strides that the Ministry of Jal Shakti has made in its mission to secure water for all. In the last 11 years in the domain of water resources, and the last 6 years of the existence of the Ministry, under the visionary stewardship of Hon. PM Narendra Modi Ji, several landmark initiatives have been launched to address the water crisis across the nation, such as:

1. Jal Jeevan Mission (JJM): The Jal Jeevan Mission, which aims to provide functional household tap connections to all rural households by 2024, has brought clean drinking water to millions. As of now, millions of rural households, including those in Rajasthan, have gained access to reliable tap water, which is a significant milestone in improving the quality of life for our people.

2. Swachh Bharat Mission (SBM): Another revolutionary initiative, the Swachh Bharat Mission, has focused on rural sanitation and the construction of household toilets. This has not only contributed to cleaner villages but has also had a direct impact on health, particularly in regions like Rajasthan where sanitation facilities were once scarce.

3. National River Conservation Plan (NRCP): Efforts to clean and rejuvenate our rivers have been a key achievement. The Ganga and Yamuna have received significant attention, but the larger goal is to ensure all rivers, especially in the desert regions like Rajasthan, are treated with care and conservation programs.

4. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT): This initiative, targeting urban areas, has helped in rejuvenating water supply systems,

sewerage networks, and green spaces, which are crucial for Rajasthan's growing urban centers such as Jaipur and Udaipur.

5. Rural Water Supply Projects: The government has worked tirelessly to ensure water availability in remote and rural regions, including Rajasthan, which is prone to both droughts and water scarcity. Through schemes like the National Rural Drinking Water Programme (NRDWP), the Ministry has supported states in improving rural water supply infrastructure.

Jal Jeevan Mission: Policy in Mission Mode

Over the last ten years, 76% of the budget allocation to the Ministry has gone to the Department of Drinking Water & Sanitation (DDWS), largely driven by allocations to the Jal Jeevan Mission. At the start of Jal Jeevan Mission in August 2019, only 3.23 Crore (16.7%) rural households were reported to have tap water connections. So far, as reported by States/ UTs as on 03.02.2025, under Jal Jeevan Mission (JJM) - Har Ghar Jal, around 12.21 Crore additional rural households have been provided with tap water connections. Thus, as on 03.02.2025, out of 19.36 Crore rural households in the country, more than 15.44 Crore (79.69%) households are reported to have tap water supply in their homes.

As reported by the state government of Rajasthan on JJM IMIS (Integrated Management Information System), on 15th August 2019, only 11.68 lakh (11%) rural households had access to tap water connections. Under JJM, 46.68 lakhs additional rural households have been provided with tap water connections and thus, as on 20.11.2024, the provision of tap water supply is available to more than 58.37 lakhs (54.40%) rural households in Rajasthan. Jal Jeevan Mission is a Prime Example of the "Art of Implementation" that the Hon. PM has taught the world, by implementing the fine print of legislative business, effectively, on ground. The Government has recently extended the Jal Jeevan Mission until 2028 and that too with an enhanced outlay of Rs. 67,000 Cr., I, along with the entire state of Rajasthan would extend its gratitude to Hon. PM Shri Narendra Modi Ji for the same. Hon. Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman stated that 15 crore households representing 80 per cent of India's rural population have benefitted by the Jal Jeevan

Mission since 2019, which should be considered a tremendous achievement and the entire state machinery must be congratulated for it.

Technological Innovations to further the Jal Jeevan Mission (JJM)

The use of technology has been critical to the success of JJM. IMIS (Integrated Management Information System) was created as the single point of contact for all data pertaining to the Jal Jeevan Mission. A JJM dashboard has also been implemented to monitor all key parameters of the grievance regime and procedure. Geolocation is used to monitor system progress at grade level. The Government has also developed the Rashtriya Jan Jeevan Kosh (RJJK) portal for individuals/organisations to make a donation for the provision of drinking water in a village of their choice. Social networks and webinars (such as the Jal Jeevan samvaad) are used for communication in connection with mass understanding.The use of modern technology within the system is a realisation of the vision of Hon. PM Narendra Modi's, Digital India.

Enhancing Community Involvement

Embodying the Gandhian spirit of the scheme, the project seeks to instill a sense of ownership in its beneficiaries. This feature was missing from the previous 2009 National Rural Drinking Water Program and became a major reason for its failure.
The scheme provides for 10% of the total fund to be contributed by the members of the village. Contributions may be payable in cash or kind (or work). This provision has been maintained in all villages, except for hilly areas and northeastern states. Not just common folk but even the respective Member of Parliaments (MPs) of these districts have actively participated in the District Level District Development Coordination & Monitoring Committee (DISHA) of the Ministry of Rural Development and their participation has truly made the Jal Jeevan Mission a Jan Andolan. The positive public perception of the mission has not only given it more impetus but has been instrumental in inculcating a feeling of Nationalism and Patriotism in the community.

<u>Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) and River- Interlinking</u>

Eastern Rajasthan Canal Project is an ambitious project of Rajasthan, which envisages the transfer of surplus water of Kunnu, Kul, Parwati, Kalisindh, Mej river sub-basin to Banas, Morel, Banganga, Kalisindh, Gambhir and Parbati river sub-basin during Monsoon period. The Government of India formulated a National Perspective Plan (NPP) of interlinking of rivers for transferring water from surplus basins to deficit basin/areas in the year 1980.

The National Water Development Agency (NWDA) has identified 30 Inter- Linking of Rivers (ILR) projects across the country, including 3 in the state of Rajasthan. The Yamuna-Rajasthan link project, the Rajasthan-Sabarmati (RS) link project and the Modified Parbati-Kalisindh Chambal (PKC) link project. Hon. Prime Minister Narendra Modi in his address to the nation on 2nd October 2021 called the Jal Jeevan Mission "A movement for decentralization". This is evident from the mission's focus on empowering the village community for water resource management in the village and water supply infrastructure. Very recently, in the year 2024, a Memorandum of Understanding (MoU) has been signed amongst the States of Rajasthan, Madhya Pradesh and the Ministry of Jal Shakti, Government of India on 28.01.2024, for broad planning of the link project and preparation of its Detailed Project Report. The Modified-PKC project is a prime example of how various state governments can come together in order to further the interest of their constituent population. This link project proposes to provide drinking and industrial water in 13 districts of eastern Rajasthan, Malwa and Chambal regions of Madhya Pradesh apart from providing irrigation in 2.8 lakh ha. area (or more) each in both the states (total of 5.6 lakh ha or more) including supplementation of enroute tanks in the states. The Modified PKC link project will help in utilizing the available water resources of Chambal basin optimally and economically.

The implementation of the river-interlinking projects is touted to increase our irrigation potential by 35 million hectares, and generate 34,000 megawatts of hydropower. This house shall be delighted to note that according to the Economic Survey 2024-25, the coverage of area under irrigation has increased between FY16 and FY21 FROM 49.3% to 55.3% of the Gross Cropped Area (GCA), while

irrigation intensity has risen from 144.2% to 154.5%. The Economic Survey also states that since the FY16 fiscal year, the government has been implementing the Per Drop More Crop (PDMC) initiative, a component of the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), to promote water efficiency. From FY16 to FY25 (end of Dec. 2024), ₹21968.75 crore was released to states for implementation of PDMC Scheme and an area of 95.58 lakh ha has been covered under which is about 104.67 per cent higher as compared to the Pre-PDMC period.

Important issues concerning Rajasthan

While these achievements are commendable, we must not ignore the unique water challenges that Rajasthan faces. As the driest state in India, Rajasthan is grappling with an acute water scarcity issue. The situation is exacerbated by several factors, including:

1. **Droughts and Water Scarcity:**

   The Central Water Commission (CWC) estimates show that in 2021, 1,486 cubic metres of water was available per person in India. Annual per capita water availability less than 1,700 cubic meters indicates a water-stressed condition. The CWC has observed that while India is not a water-deficit country, severe neglect and lack of water resource monitoring have led some regions, like Barmer in Rajasthan, to experience persistent water stress. Rajasthan is highly susceptible to droughts, which impact agriculture, livelihoods, and drinking water availability. The per-capita water availability in Rajasthan is even lesser and considered to be about 780 cubic metres. The state's dependence on rainfall is highly unreliable, and thus, solutions for water conservation and management are critical.

2. **Over-exploitation of Groundwater**

   80% of India's rural drinking water, 50% of urban drinking water, and two- thirds of water for irrigation comes from groundwater resources. The Standing Committee on Water Resources (2023) has noted that there is a growing dependence on ground water due to its decentralised availability, changes in

rainfall patterns, and increasing water demand. This has led to a severe depletion of groundwater reserves. The total annual extractable groundwater in India has been assessed as 406 billion cubic metres (BCM). As of 2024, the annual groundwater extraction is 246 BCM. Average ground water extraction in India is 60%. In 1995, this figure was 32%.

Due to a lack of surface water, Rajasthan heavily relies on groundwater. Unfortunately, this over-exploitation has led to declining water tables, which is a cause of concern for both drinking water and agricultural needs. States like Rajasthan, Punjab and Haryana have a Groundwater Extraction Percentage of over 140% today, which should raise way more alarm bells than it currently is. Over exploitation of groundwater has become an even more grave issue in states like Punjab, which does not suffer from a traditional scarcity of groundwater resources. In states like Punjab, over extraction of groundwater resources is directly proportional to the electricity subsidies provided to farmers which removes any disincentives to conserve electricity. This leads to depletion of state finances and water resources at the same time. This strategy, adopted by a few states, deserves a hard reconsideration if we are to effectively deal with the issue of water scarcity and ensure sustainable development for our people.

Release of Rajasthan's Water Share according to agreement dated 31.12.1981

An agreement was signed amongst Hon'ble Chief Ministers of Rajasthan, Punjab and Haryana on 31.12.1981 for distribution of surplus Ravi-Beas waters. According to this agreement, Rajasthan's share was fixed as 8.60 MAF out of allocated 17.17 MAF surplus Ravi-Beas water. It was stipulated in the agreement that:

"Until such time as Rajasthan is in a position to utilize its full share, Punjab shall be free to utilize water surplus to Rajasthan's requirements. As Rajasthan will soon be able to utilize its share, Punjab shall make adequate alternative arrangements expeditiously for irrigation of its own lands by the time Rajasthan is in a position to utilize its full share. As a result, it is expected that during this transitional period when Rajasthan's requirements would not exceed 8 MAF, 4.82 MAF of water should be available to Punjab in a mean year when the availability is 17.17 MAF."

Due to extensive development of the Indira Gandhi canal system, Rajasthan has been in a position since the past many years to utilize its entire share. However, Bhakra Beas Management Board (BBMB) is giving Rajasthan an allocation of 8.00 MAF. Rajasthan has repeatedly submitted its representation to the Government of India and also to the BBMB and Government of Punjab to restore its remaining share of 0.60 MAF. Punjab has passed "Punjab Termination of Agreement Act, 2004" terminating and discharging the Government of Punjab from its obligations under the agreement dated 31.12.1981 and all other agreements relating to waters of Ravi-Beas. Even after multiple requests from the Government of Rajasthan, the state of Punjab refuses to give us our share of water, as decided in our agreement dated 31.12.1981. A state like Rajasthan, which natively lacks water resources, deserves its share of Water as agreed upon by both states at one point of time.

Modification of Central Share Provided to the State of Rajasthan underJJM:

The Government of India has kept the provision of funds to states under the Jal Jeevan Missio in a ratio of 50:50 between Centre and State, as per guidelines issued under the Mission. In this regard, I would like to draw the attention of the house towards the uniqueness of the state of Rajasthan, when compared with other States of the Country, as Rajasthan is not only the largest State in terms of area but also has consistently ranked among the states with lowest per-capita water availability.

About one third of quality affected villages/ dhanies of the country are situated in Rajasthan. The villages/ dhanies in the State, especially in desert areas, are located in scattered manner due to which the cost of drinking water supply projects is very high in comparison to other States of the country. There is also a critical problem of availability of water in 13 districts of Eastern Rajasthan for which the project of interlinking of rivers would have to be taken up for providing water at 55 liters per capita per day under Jal Jeevan Mission, the cost of which would be very high. It is also mentioned here that, Government of India was earlier providing central assistance in a ratio of 90:10 under National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) for desert areas, until the year 2013, which was subsequently reduced to 60:40 and further reduced to 50:50. Therefore, the Government of India is requested

to consider the request for funding of not only the schemes of DDP blocks but for all JJM schemes of Rajasthan in 90:10 ratio sympathetically, to enable Rajasthan to move forward for expeditious implementation and timely completion of Jal Jeevan Mission.

Quality of Water distributed under JJM in Rajasthan:

Despite significant progress in the supply of water, concerns around the quality of water remain. Contaminants such as fluoride and arsenic, especially in certain parts of Rajasthan, continue to affect public health. In 2024-25, 66 lakh samples were tested, of which 3.3 lakh (5%) lakh were found contaminated. Remedial action was taken on 59% of the contaminated samples. The Standing Committee recommended that states separate the responsibilities of water supply and water quality monitoring. This would increase trust, transparency, and accountability. This proposal by the respective Standing Committee must be surely considered, especially for the state of Rajasthan. According to the 'Annual Groundwater Quality Report 2024' released by the Central Ground Water Board (CGWB), Rajasthan had the highest percentage of samples testing positive for the concentration of Nitrate, Fluoride and Uranium, including being severely affected by high Electrical Conductivity (EC) values. Barmer and Jodhpur in Rajasthan have consistently shown a rising trend in Electrical Conductivity (EC) values. All this data presents severely ominous signs for the state of Rajasthan. As we strive towards our collective goal of 'Har Ghar Jal' we must also pay heed to the quality of water that reaches the consumer.

Conclusion

In conclusion, while we must recognize the great strides made by the Ministry of Jal Shakti in addressing water-related issues across India, it is equally important that we focus on addressing the specific challenges of states like Rajasthan. With the right blend of innovation, policy reform, and grassroots participation, Rajasthan has the

potential to overcome its water crisis and set an example for sustainable water management for the entire nation.

As I put forth these demands, I would also like to express my confidence in the visionary leadership of Hon. Prime Minister Shri. Narendra Modi Ji and your able stewardship, in your ability to address all the demands of my constituency and the people of India at large.

Thank you.

***m30 श्रीमती रूपकुमारी चौधरी (महासमुन्द) :** सर्वप्रथम, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने जल के महत्व को समझते हुए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और "जल है, कल है, जल ही जीवन है" के भाव को साकार किया । जल केवल जीवन का आधार ही नहीं, बल्कि प्राचीन काल से बड़ी सभ्यताएँ नदियों के किनारे ही फली-फूली हैं । जल के बिना कृषि, उद्योग, जलवायु, पर्यावरण, और समग्र जीवन प्रणाली की कल्पना भी संभव नहीं है । जल ही राष्ट्र की समृद्धि और विकास की कुंजी है । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और लोक कल्याणकारी योजनाओं ने भारत में जल संकट को दूर करने और जल के सही उपयोग की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किए हैं । जल शक्ति मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को स्वच्छ पानी प्रदान करने, जल प्रबंधन को बेहतर बनाने, जल की उपलब्धता में सुधार करने, और जल संसाधनों का स्थायी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जो कार्य किए हैं, वह अद्वितीय और काबिल-ए-तारीफ हैं । यह हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र सेवा की भावना और उनकी दूरदर्शी सोच का स्पष्ट उदाहरण है । मान्यवर अध्यक्ष महोदय, जल शक्ति मंत्रालय की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने भारतीय समाज में जल संरक्षण को एक नया दृष्टिकोण दिया है, जहां जल केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन की धारा का आधार बन गया है ।

जल जीवन मिशन

मैं ग्रामीण परिवेश से आती है, एक ऐसे गाँव की बेटी और बहू हूँ जिसकी आबादी 600 से 700 है । हमने घर में उपयोग के लिए तालाब से और फिर हैंडपम्प से पानी भरकर लाया है, दिन में दो-दो बार जब घर की महिलाएँ केवल पानी के लिए तीन किलोमीटर चार किलोमीटर दूर जाती थी और लेकर आती थी । बुजुर्ग महिलाएँ, गर्भवती महिलाएँ और छोटी बच्चियों, हमने पानी का बर्तन सिर पर उठाकर लाने की पीड़ा खुद सही है और देखी है । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जल जीवन मिशन की घोषणा की, तो देश ने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री ने

गाँव-गरीब की पीड़ा को समझते हुए यह तय किया कि ना केवल शहर बल्कि हर ग्रामीण घर में चल से जल पहुंचाया जाए । प्रधानमंत्री जी के इस कदम ने व केवल हमारे किसानों और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया, बल्कि पूरे भारत के जल प्रबंधन को नए रूप में ढालने का एक प्रयास था । महोदय, जल जीवन मिशन के अंतर्गत लक्ष्य लिया गया था कि 2024 तक हर ग्रामीण घर को पाइप जल आपूर्ति से जोड़ दिया जाएगा और महोदय, आज मुझे यह बताते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि, आज हमने देश के 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति की सुविधा पहुंचा दी है, जिससे करोड़ों परिवारों को स्वच्छ और सुरक्षित जल मिल पा रहा है ।

नमामि गंगे परियोजना

देश में माँ गंगा का महत्व और अस्तित्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर में रक्त का । देश की जीवन रेखा माँ गंगा, जिसे हम मोक्षदायिनी मानते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों के दिशाहीन निर्णयों ने ना केवल इस पुण्यसलिला को दूषित किया, बल्कि इसके अस्तित्व को भी संकट में डालने का काम किया । तत्कालीन परिस्थितियाँ ना केवल हमारी प्रकृति के लिए, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक गंभीर संकट थीं । माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने माँ गंगा के संरक्षण और कृतज्ञता के भाव से जो दूरदृष्टि बाला निर्णय लिया और नमामि गंगे परियोजना के रूप में इस दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास के रूप में फलीभूत हो रहा है । आज नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश कर 240 से अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) स्थापित किए गए हैं, जिससे गंगा नदी की सफाई और पानी की गुणवत्ता में 30-40% सुधार हुआ है । गंगा नदी के किनारे 15 प्रमुख शहरों में जल शोधन की प्रक्रिया में भी वृद्धि हुई है । और हाल ही में प्रयागराज में हुए भव्य कुंभ ने जो इतिहास रचा उसे विश्व ने देखा है, विरोधियों ने जल की गुणवक्ता सफाई को लेकर भ्रम तो बहुत फैलाने का प्रयास किया लेकिन वैज्ञानिक शोध और परिणामों ने पूरा भ्रम साफ़ कर दिया ।

कृषि जल प्रबंधन

हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किसानों के हित को प्राथमिकता दी है । कृषि जल प्रबंधन के क्षेत्र में उन्होंने न केवल जल की अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित की, बल्कि किसानों को जल संचयन, सिंचाई और कृषि के लिए पानी का सही प्रबंधन सिखाया । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा दी गई है । साथ

ही, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में 6 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया है, जिससे पानी की बचत और कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है ।

वर्षा जल संचयन

वर्षा जल संचयन योजना के अंतर्गत देशभर में 10,000 से अधिक वर्षा जल संचयन कार्यक्रमों को लागू किया गया है । इसने न केवल जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया, बल्कि जल स्तर में भी सुधार हुआ है ।

प्रधानमंत्री जी ने हमेशा समाज के हर वर्ग के लाभ को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं । उनका मानना है कि यदि हम जल संकट को हल कर पाते हैं, तो हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो पूरी दुनिया में समृद्ध और स्थिर हो । जल जीवन मिशन, नमामि गंगे परियोजना, कृषि जल प्रबंधन, और वर्षा जल संचयन जैसे कार्यों में प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण पूरी तरह से स्पष्ट हैं । आज हमारे देश के प्रयास जल प्रबंधन की दिशा पूरी दुनिया में एक मॉडल बन चुके हैं । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधनों के प्रबंधन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है । हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि यह केवल एक जल योजना नहीं, बल्कि यह भारत के भविष्य के लिए एक दीर्घकालिक निवेश है ।

आज, हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, वह भविष्य में हर भारतीय नागरिक को सुरक्षित, स्वच्छ, और पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में सफल होगा । हम सभी को गर्व का अनुभव करना चाहिए कि हम इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा हैं और इस प्रयास को सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं । इस दिशा में हम सभी को मिलकर काम करना होगा, ताकि जल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने और हर एक भारतीय को जल का समुचित और न्यायपूर्ण वितरण हो ।

अंत में, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषकों और जन सामान्य के हित के लिए महासमुंद जिले अंतर्गत लोअर जोंक परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्रालय का मार्गदर्शन आवश्यक मानती हूँ । इस परियोजना से महासमुंद जिले के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा, साथ ही भूमिगत जल के गिरते स्तर को भी रोका जा सकेगा ।

सिकासेर जलाशय का पानी जो पानी भराव के बाद व्यर्थ में बहकर नष्ट हो जाता है, यदि नहरों का निर्माण कर दिया जाए तो गरियाबंद और महासमुंद जिले के हजारों किसानों और ग्रामीणों के लिए यह जीवनदायिनी हो सकता है ।

महासमुंद जिले के सरायपाली नगर में गिरते जल स्तर से हाहाकार की स्थिति है, आस-पास के कई ग्रामों में भी कमोबेश यही स्थिति है । लाट नाला में बांध बनाकर यदि समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत जल प्रदाय का प्रयास किया जाए तो लाखों लोगों को पेयजल प्राप्त हो सकेगा ।

साथ ही इस मेरे प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी की जल जीवन मिशन जैसी जन कल्याणकारी योजना में किए गए भीषण भ्रष्टाचार करते हुए लाखों ग्रामीणों उनके हितों से वंचित कर दिया है, मैं माननीय मंत्री महोदय से माँग करती हूँ कि केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच करवा कर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए ।

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : आज मुझे "जल शक्ति" जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं आभारी हूं । जल केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है... यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर... कृषि की जान और विकास की रीढ़ है ।हमारी सभ्यता नदियों के किनारे पली-बढ़ी है, और भारतीय संस्कृति में जल को देवतुल्य माना गया है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी कहीं पढ़ा था मैंने कि...

पानी की कीमत वो क्या जानें,

जिनके घर में कुएं और तालाब हैं,

पूछो उनसे जो बूंद-बूंद को तरसते हैं,

जिनके होंठों पर सूखे ख्वाब हैं ।
जल केवल प्यास बुझाने का माध्यम नहीं, बल्कि यह हमारी पूरी जीवनशैली से जुड़ा हुआ है । कृषि, उद्योग, बिजली उत्पादन ? सब कुछ जल पर निर्भर है ।

हमारे वेदों में जल को अमृत कहा गया है । हम नदियों को मां कहते हैं - जीवनदायिनी मां, मां गंगा, मां यमुना, मां नर्मदा, मां कावेरी ? ये केवल नदियां नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था के प्रतीक हैं । लेकिन दुर्भाग्यवश, आज ये जीवनदायिनी धारा संकट के दौर से गुजर रही है । बढ़ती जनसंख्या, अति दोहन, जलवायु परिवर्तन और जल स्रोतों का प्रदूषण हमारी नदियों, तालाबों और भूजल को सूखने की कगार पर ले आया है ।

अगर यही हाल रहा तो एक दिन...

दरिया भी प्यासा हो जाएगा,

अगर हम यूं ही बहाते रहेंगे,

कुदरत के इन अनमोल खजानों को,

ना संभाल पाए तो पछताते रहेंगे ।

आज देश के कई हिस्से जल संकट से जूझ रहे हैं । अगर यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले समय में जल को लेकर संघर्ष बढ़ जाएंगे ।

जल संकट के कारण

3. सूक्ष्म सिंचाई: Drip irrigation and sprinklers जैसी तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे पानी की बचत हो और फसलों को पर्याप्त नमी मिल सके ।

4. सामूहिक जागरूकताः जल संरक्षण के प्रति समाज में जागरूकता लाने के लिए गांव-गांव में "जल चौपाल" और "जल प्रहरी" जैसे अभियानों को बढ़ावा दिया जाए । हम लोगों को जागृत करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का भी सहारा ले सकते हैं ।

5. कानूनी प्रावधानः भूजल दोहन को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था हो । एक शायर लिखते हैं कि

"जो बूंद-बूंद को बचाएगा,

कल वही सुकून पाएगा,

धरती की प्यास बुझा दी जिसने,

असली इंसान वही कहलाएगा ।"

सरकार की पहलः

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में "जल जीवन मिशन" और "अमृत योजना" जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका

उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना है । हमें इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे ।

निष्कर्षः

अंत में, मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि जल संरक्षण को राष्ट्रीय आंदोलन बनाएं । हम सभी को मिलकर जल की हर बूंद बचाने का संकल्प लेना होगा । याद रखिए:

"यदि जल है, तो कल है ।
जल नहीं, तो जीवन नहीं ।"

और एक अंतिम शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा

"संदेश यही है जमाने को, जल को बचाओ,

कल आने वाली पीढ़ियों को, अंधेरे में मत छोड़ जाओ ।"
जय हिंद! जय भारत ! ??

***m32 श्री राहुल कस्वां (चुरू) :** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर हो रही चर्चा में बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । सरकार द्वारा पेय जल और सिंचाई के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों पर हम सभी का ध्यान केन्द्रित है, लेकिन इन योजनाओं की जमीनी सच्चाई और प्रभावशीलता पर सवाल उठाना भी आवश्यक है । पिछले कई वर्षों में सरकार ने कई बड़ी योजनाएं प्रारंभ की हैं । जैसे ?जल जीवन मिशन?, ?स्वच्छ भारत मिशन?, लेकिन क्या सही मायनों में इनका लाभ जनता तक पहुंच पाया है?

?जल जीवन मिशन? के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है । आंकड़े दर्शाते हैं कि लाखों गांवों में ?हर घर नल से जल योजना? लागू की गई है, लेकिन अभी भी जमीनी स्तर पर कई स्थानों पर पानी कि भयंकर किल्लत बनी हुई है । पानी की गुणवत्ता और उसकी अनियमितता को लेकर शिकायतें सामने आती रहती हैं । ?स्वच्छ भारत मिशन? से संबंधित भी अनेकों मुद्दे हैं । जब यह नया मंत्रालय बना था, तब देश के अंदर इस बात को लेकर एक उम्मीद जगी थी कि जल शक्ति मंत्रालय ?जल जीवन मिशन? जैसी योजनाओं के साथ-साथ इरिगेशन के पानी के ऊपर भी फोकस करेगा और इरिगेशन पर दिमाग लगाया जाएगा कि नदियों को उससे कैसे जोड़ा जाए । इससे बहुत बड़ी उम्मीदें थीं ।

महोदय, अगर आज देश के अंदर पानी की व्यवस्था को देखें, तो पूरे देश में जो वार्षिक रेनफॉल है, वह करीब-करीब 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर है । इस देश के अंदर करीब-करीब 1,30,000 क्यूसेक पानी बरसात के माध्यम से आता है । उसमें लगभग 1,200 बीसीएम ऐसा पानी है, जिसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं । उस पानी के स्टोरेज की व्यवस्था न होने के कारण नदियों के मार्फत समंदर में बह जाता है । आज की तारीख में हमारी देश की स्टोरेज कैपेसिटी 253 बीसीएम है । अपर्याप्त स्टोरेज होने के कारण जो 1,200 बीसीएम

पानी है, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हो सकती है, हम जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस सरकार का उसके ऊपर कोई फोकस ही नहीं है ।

भारत में मानसून के समय भारी मात्रा में पानी तो बहता ही है, लेकिन कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति के कारण लाखों-करोड़ों रुपयों का भी नुकसान होता है । यह हर साल की कहानी है । किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं । इसके साथ ही साथ जान-माल का भी भारी नुकसान होता है । वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से 500 से अधिक लोग मरे थे । वर्ष 2022 में नॉर्थ-ईस्ट में जो बाढ़ आई थी, नॉर्थ-ईस्ट और बांग्लादेश के लोगों को मिलाकर उसमें 2,000 से अधिक व्यक्तियों की जान चली गई थी ।

वर्ष 2021 में बाढ़ से 20 हजार करोड रुपये का नुकसान हुआ, वर्ष 2024 में अकेले हिमाचल प्रदेश के अंदर 10 हजार करोड रुपये का नुकसान हुआ । इस विपदा से निपटने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत सरकार और राज्य सरकारें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ फंड से लाखों-लाखों रुपये खर्च करती हैं । वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 55 हजार करोड रुपये का प्रावधान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में सिर्फ इसी बजट के लिए किया गया है ।

सर, अगर हम देश के अंदर सरफेस वाटर और ग्राउंडवाटर की यूटिलाइजेशन को देखें तो आज कंट्री के अंदर प्रति व्यक्ति कितना पानी हमारे पास में है । वर्ष 1951 के अंदर 5,177 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति हिंदुस्तान में था, जो वर्ष 2011 में घटकर 1,545 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति रह गया है । अगर इसी हिसाब से चलता रहा और आज की तारीख में वर्ष 2025 के आंकड़े निकालें, क्योंकि हमारे पास 2011 तक की जनगणना ही है तो यह घटकर 1,340 बीसीएम पानी रह गया है । मैं राजस्थान जैसे प्रदेश से आता हूं । वहां प्रति व्यक्ति जो पानी बचा है, वह 740 क्यूबिक मीटर बचा है, जो पूरे देश में सबसे लोएस्ट है । हरियाणा में 1,165 क्यूबिक मीटर है, पंजाब में 1413 क्यूबिक मीटर पानी बचा है । ? (व्यवधान) मैं आपसे उम्मीद करुंगा कि वह पूरा 45 मिनट बोल चुके हैं तो हमें भी मौका दिया जाए । उत्तर प्रदेश के अंदर 1,977 बीसीएम पानी रह गया है । यह आज की जनसंख्या पर है । अगर हम वर्ष 2040 में चले जाएं तो यह घटते-घटते 1,140 के एवरेज में रह जाएगा । आज की तारीख में ग्राउंडवाटर से 60 परसेंट की सिंचाई हो रही है ।

15.07 hrs (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

सर, 85 परसेंट ड्रिंकिंग वाटर इस कंट्री में ग्राउंडवाटर से मिलता है । हम पानी की ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते जा रहे हैं । हमें इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा । मैं राजस्थान क्षेत्र से आता हूं । राजस्थान का क्षेत्र 3 लाख 43 हजार स्क्वायर किलोमीटर है । हिंदुस्तान

की 10 परसेंट जमीन राजस्थान अकेले की है, लेकिन पानी की बात करेंगे तो मात्र एक परसेंट पानी हमारे पास है । 180 लाख हेक्टेयर जमीन कल्टीवेबल लैंड है, लेकिन मात्र 50 परसेंट लैंड के ऊपर भी इरीगेशन के वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है । हमारा पूरा क्षेत्र मरुस्थलीय है और वहां हमेशा पानी की कमी रही है । राजस्थान में पुराने समय में वर्षा जल संचयन के ऊपर निर्भरता रही है । पुराने समय में जोहड़, कुंड और बावड़ियों के माध्यम से हम पीने के पानी की व्यवस्था करते आए हैं । मैं चूरू, राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट पार्ट से आता हूं । पूरे चूरू में 80 परसेंट पानी सेलाइन है, पानी खारा है । बीकानेर की हालत यह है कि वहां पर टीडीएस लेवल बहुत हाई है । नागौर के अंदर हमेशा अकाल की परिस्थिति बनी रहती है । सीकर-झुंझुनू हमारी शेखावाटी बेल्ट का हिस्सा है, जहां पर हमने ग्राउंड वाटर को पूरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दिया है । श्रीगंगानगर में वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वाटर सीवेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है । अनेक जिलों की अलग-अलग परेशानी है, लेकिन वहां फोकस नहीं है । योजनाएं जरूर बनीं, लेकिन इन योजनाओं का काम जमीन पर देखने में नहीं आता है । आज मैं इस 1200 बीसीएम पानी की बात कर रहा हूं, जो बरसात का पानी नदियों के मार्फत समुद्र में चला जाता है । अगर हम इसका 5 बीसीएम पानी इस्तेमाल करके टैप करने की क्षमता रखें और गवर्नमेंट का फोकस इसके ऊपर जाए तो यह अकेला 5 बीसीएम पानी इस राजस्थान के अंदर एक करोड़ हेक्टेयर लैंड पर सिंचाई का काम कर सकता है । इतनी ताकत इस पानी के अंदर है ।

मैं राजस्थान के चूरू से आता हूं । मैं चूरू की बात इसलिए करना चाहूंगा कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई और नहरों का जाल बिछा तो हरियाणा और पंजाब के बाद राजस्थान के अंदर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में उसकी एंट्री हुई । उसके बाद एडज्वाइनिंग प्लेस चूरू है । इंदिरा गांधी कैनाल का पानी हमारे क्षेत्र में भी आता है । हम आज तक उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं । मेरे क्षेत्र के अंदर 17 लाख हेक्टेयर लैंड है और 9 लाख हेक्टेयर लैंड के ऊपर हम कृषि का कार्य कर सकते हैं, लेकिन मात्र डेढ़ से दो लाख हेक्टेयर पर सिंचाई का पानी नहर या ट्यूबल के माध्यम से हमें मिलता है । अगर इस दो या ढाई बीसीएम पानी को इस्तेमाल कर लें और मैं सरसों की पैदावार की बात करूं तो हमें प्रति व्यक्ति हेक्टेयर 3000 क्यूबिक मीटर पानी चाहिए । अगर 5 बीसीएम पानी को स्टोर करके उसे यूज करना शुरू कर दें तो अकेले चूरू के अंदर 8 से 10 लाख हेक्टेयर टन जमीन की सिंचाई कर सकते हैं, जिससे हम 18 से 20 लाख टन की पैदावार अकेले सरसों की कर सकते हैं ।

मैं आपको पिछले तीन साल के आंकड़े बताना चाहता हूं कि कितना एडिबल ऑयल इस कंट्री में इम्पोर्ट हुआ है । वर्ष 2021-22 में 135 लाख टन, 2022-23 में 142 लाख टन, वर्ष

2023-24 में 165 लाख टन एडिबल ऑयल इम्पोर्ट किया है । दालों के बारे में बताता हूं कि वर्ष 2021-22 में 27 लाख टन, वर्ष 2022-23 में 25 लाख टन और वर्ष 2023-24 में 48 लाख टन दालें हमने देश में इम्पोर्ट की हैं ।

महोदय, अकेले चुरू में इतनी पॉवर है, अगर नागौर, बीकानेर, चुरू में पानी की व्यवस्था कर दें तो हम दालें इम्पोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा । मेरे से पहले वाले वक्ता ने बताया कि कितना इनवेस्टमेंट किया गया है । इस देश में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं । दामोदर वैली कार्पोरेशन वर्ष 1948 में बना । नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्ष 1979 में शुरू हुआ । कृष्णा रिवर वैली प्रोजेक्ट वर्ष 1956, गोदावरी वैली वर्ष 1960, महानदी रिवर वैली वर्ष 1957, सतलुज रीवर वैली प्रोजेक्ट जो पूरे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की लाइफ लाइन है, वर्ष 1950 में 270 करोड़ रुपये की लागत से 9 हजार एमसीए वॉटर केपेसिटी क्रिएट की गई, जिससे हम 13 मिलियन हेक्टेयर जमीन की सिंचाई कर रहे हैं । गंगा बेसिन का डेवलपमेंट वर्ष 1986 में शुरू हुआ । चम्बल वैली प्रोजेक्ट वर्ष 1954 में शुरू हुआ । ये देश के आठ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर करोड़ों रुपये की इनवेस्टमेंट उस समय की गयी, क्योंकि वह विजनरी सोच थी । जब तक किसान और किसानी को मजबूत नहीं किया जाएगा, इस देश की पचास प्रतिशत आबादी किसानी पर टिकी हुई है, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है । दस साल के अंदर एक भी बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देश के अंदर सिंचाई का बना हो, तो आप बता दीजिए । ये कांग्रेस के समय की देन है, जिसके कारण आज देश के अंदर हम इरिगेशन कर पा रहे हैं । हम हरित क्रांति लेकर आए और करोड़ों रुपयों का पीने का पानी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में लोग पी रहे हैं ।

महोदय, मैं आपके मार्फत यह बताना चाहता हूं कि पानी के अंदर इरिगेशन की केपेसिटी को इंक्रीज करना ही एक इश्यू नहीं है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा इश्यू है । आज भी फ्लड इरिगेशन रैम्पेंट हैं और हम फ्लड इरिगेशन से काम करते हैं । दुनिया में आप देखोगे कि अलग-अलग टेक्नोलॉजीज आयी हैं । स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन थोड़ा पुराना हो गया है । दुनिया में अलग-अलग टेक्नोलॉजीस आयी हैं, जिसमें पीवोट बेस्ड इरिगेशन सिस्टम है । हमारी एफिशिएंसी देखिए, फ्लड इरिगेशन में 30 से 40 परसेंट एफिशिएंसी पानी की है । केनाल में 40 से 50 परसेंट, ड्रिप स्प्रिंकलर्स यूज़ करें तो 90 परसेंट की एफिशिएंसी आती है । यदि आज भी सरकार पूरा पैसा किसान के साथ लगकर खर्च करती तो जहां फ्लड इरिगेशन होती है, उससे डबल दि हेक्टेयर ऑफ लैंड को सिंचित करने की ताकत रखते । पिवोट बेस्ड इरिगेशन एक समय पर 400 फीट की खेती में आप पानी

डाल सकते हैं । सीड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का सूरतगढ़ में फार्म है । भारत सरकार ने एक पिवोट इरिगेशन का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए मंगवाया है, ढाई से तीन करोड़ रुपये की लागत आती है । सीड कार्पोरेशन के उस फार्म से बाहर वह पिवोट आज तक निकल नहीं पाया है और पब्लिक एट लार्ज में वह देखने को नहीं मिला है । हमारी कोई एनोवेशन नहीं है । मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अलग-अलग कंट्रीज की बात की जाती है । इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन से 85 परसेंट अपने एग्रीकल्चर को कवर कर लिया । हमारे साथी ने उदाहरण वेस्ट वाटर रिसाइक्लिंग का दिया था । 90 परसेंट ऑफ वेस्ट वॉटर रिसाइकल का हमारा सिनेरियो क्या है? अमृत सिटीज बनाई गईं, स्मार्ट सिटीज बनाई गईं । वेस्ट वाटर का कोई प्लान ही नहीं है । आप किसी शहर में चले जाओ, वेस्ट वाटर खुले में पड़ा रहता है और वह बीमारियों का अड्डा बना हुआ है । सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आज तक नहीं बने हैं । हम अपने सीवरेज और ड्रेनेज के पानी को न कभी बायफरकेट कर पाए, दोनों पानी गांवों में और शहरों में मिलकर खुले में पड़े रहते हैं और गंदगी और बीमारी फैलाते हैं । हमारे पास कोई प्लान नहीं है । न मिनिस्ट्री के पास प्लान है, न अमृत सिटीज के तहत कोई प्लान है और न स्मार्ट सिटीज के तहत प्लान है कि वेस्ट पानी को कैसे यूज किया जाएगा ।

महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सैंट्रली स्पोंर्स्ड स्कीम्स की बात कही गई है । पीएमकेएसवाई हर खेत को पानी देने का प्रावधान है । जब यह एनाउंस हुआ था, तब यह वर्ल्ड सुनने में बहुत अच्छा लगा था कि अब हमारे राजस्थान के खेतों में भी पानी आ जाएगा । मैं पूछता हूं कि जब सोर्स ही क्रिएट नहीं किया जा रहा है तो पानी कहां से और कैसे आएगा? सीएडी एक स्कीम थी, जिसके तहत हम नहरों की लाइनिंग करते थे, अपलिफ्ट करते थे । वर्ष 2024-25 में 1400 करोड़ रुपये का एस्टीमेट था । यह बहुत अचम्भे की बात है कि रिवाइज्ड एस्टीमेट मात्र 100 करोड़ रुपये छोड़ दिया गया । कैसे केनाल का कमांड एरिया बढ़ेगा, जब पैसा ही नहीं दे पा रहे हो? एआईबीपी स्कीम 2500 करोड़ रुपये की एक्सक्लेटेड इंटीग्रेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम था । वर्ष 2024-25 के अंदर 2500 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाए । पीएमकेएसवाई का टोटल बजट घटा दिया गया । जो बजट आबंटन 8200 करोड़ रुपये का था, उसे 6600 करोड़ रुपये रिवाइज्ड एस्टीमेट कर दिया ।

सर, आपकी कहती है कि हमने हर खेत को पानी योजना के तहत इस देश में 24 से 25 लाख हेक्टेयर सिंचाई का पानी उपलब्ध करवा दिया । ये आंकड़े तो समझ में नहीं आते हैं, कौन-से क्षेत्र में हुआ, यह समझ में नहीं आता कि कहां से ये आंकड़े आए हैं ।

सर, हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात करते हैं । हर चीज में बजट घटा । वर्ष 2024-25 में 4 हजार करोड़ रुपये का बजट था, रिवाइज्ड एस्टीमेट में यह 2 हजार करोड़

रुपये हो गया । मेजर इरीगेशन सिस्टम में 14 हजार 967 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया, लेकिन 10 हजार करोड़ रुपये भी खर्च नहीं हो पाए । ?नमामि गंगे? का जो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 33 सौ करोड़ रुपये की सैंक्शनिंग थी, 3 हजार करोड़ रुपये रिवाइज्ड एस्टिमेट में आ गए । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021 के मध्य ?नमामि गंगे? कार्यक्रम के तहत केवल 4 हजार 16 करोड़ रुपये खर्च किए गए । जो बजट आपने आवंटित किया था, यह उसका मात्र 20 प्रतिशत हिस्सा है । बातें बड़ी हैं, दिखावा बहुत अच्छा है, लेकिन एक्जीक्यूशन करने में बहुत प्रॉब्लम है ।

माननीय सभापति : कृपया समाप्त कीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके 15 मिनट्स हो गए ।

श्री राहुल कस्वां : सर, भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कई अन्य स्पीकर्स भी हैं । वह अच्छे सांसद हैं, मैं जानता हूं ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल कस्वां : सर, नैशनल वाटर मिशन के अंतर्गत जल शक्ति अभियान, कैच द रेन का प्रोग्राम चला, इसके तहत ?जेएसए-सीटीआर? का कैंपेन वर्ष 2024 में लागू हुआ । 617 जिलों में डिस्ट्रिक्ट वाटर कन्जर्वेशन प्लान बनाया गया । हम सभी सांसद देश के अलग-अलग कोनों से आते हैं । कोई एक माननीय सदस्य यहां खड़ा होकर बता दे कि उसने डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान देखा है । हम एक सांसद के रूप में प्रतिदिन पब्लिक को डील करते हैं । अगर आज गांव में फोन उठाऊं, तो पहला फोन यही आता है कि पीने के लिए पानी नहीं मिलता है । डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान चल गया । यह अभियान आपने वर्ष 2024 में चलाया और सांसदों को इसका पार्ट ही नहीं बनाया गया । ? (व्यवधान) यह तो हालत है ।

सर, बजट एस्टिमेट में बजट एलोकेशन आपने देश में बहुत अच्छे किए हैं । पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आप प्रतिदिन 17 रुपये देते हैं । हमें अच्छा लगता है कि उनको 6 हजार रुपये एक साल में मिलते हैं । 4 लाख 35 हजार करोड़ रुपये खर्च हो गए । बुलेट ट्रेन पर 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपये खर्च हो गए । एनपीए लोन्स की 11 लाख 35 हजार करोड़ रुपये की वेविंग कर दी गई । हाईवे बहुत बड़े-बड़े और अच्छे बन रहे हैं । इस वर्ष इसमें 2 लाख 62 हजार रुपये दिए हैं । रेलवे को भी 2 लाख 52 हजार करोड़ रुपये दिए हैं । पिछले

साल भी दिए थे । लाखों-लाख रुपये डेवलपमेंट पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इरीगेशन के लिए पैसा नजर नहीं आता? कोई एक लाख, दो लाख, 5 लाख करोड़ रुपये की योजना ही दिखे । हम दाल बाहर से मंगा रहे हैं, एडिबल ऑयल्स बाहर से मंगा रहे हैं, हमारे बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है । आज भी हम ?मिड डे मील? के तहत बच्चों को केवल दाल-चावल ही खिला रहे हैं । हमारे बच्चों को, हर बच्चे को आज भी हेल्थ न्यूट्रीशन की एडीशनल टेबलेट्स देनी पड़ती हैं ।

माननीय सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री राहुल कस्वां : सर, केवल दो मिनट और लूंगा । आप हैं, इसलिए भाषण हो जाएगा, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, आप कृपया आज्ञा दीजिए, मैं जल्दी ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ।

माननीय सभापति : आपके 15 मिनट्स हो गए हैं, और भी मेंबर्स हैं ।

श्री राहुल कस्वां : सर, ?जल जीवन मिशन? की हालत देखिए । चुरू में 4 लाख 10 हजार घरों को पीने का पानी देना था । ऑलरेडी 42 हजार घरों को दिया जा चुका था । मैं चुरू का एक क्लासिक उदाहरण दूंगा कि क्या हालत है सिस्टम की । Tap connection given in JJM, 2 लाख 25 हजार यानी करीब 70 परसेंट डैशबोर्ड पर एंट्री हो चुकी है कि टैप का पानी घर तक पहुंचा दिया गया है । हालत यह है कि चुरु के राजगढ़ ब्लॉक में 19 SLR, Second level Reservoirs, जिनको ओएचआर बोलते हैं, उन्हें बनाना था, लेकिन आज तक यानी 5 सालों में केवल दो पूरी हुई हैं और आपने 70 परसेंट घरों में पानी दे दिया । आज के पेपर की रिपोर्ट में लिखा है कि जोधपुर में 239 घरों में और 118 घरों के अंदर पीने के पानी का विभाग ने पोर्टल पर शो तो कर दिया, लेकिन आज तक वहां पानी नहीं पहुंचा । पोर्टल की एंट्री का इतना दुरुपयोग किया गया है कि आपने पाइपलाइन कनेक्शन कर दिया, तो पोर्टल पर एंट्री कर दो । विभाग को लगता है कि काम पूरा हो गया है । सरकार सोचती है कि राज्यों के गांवों में काम हो रहा है । काम हो ही नहीं पा रहा है । क्वालिटी ऑफ वर्क की बात करूं, तो मेरे संसदीय क्षेत्र में 12-13 सौ करोड़ रुपये के जेजेएम के कार्य चल रहे हैं । यह बताते हुए दुख होता है कि 12 सौ करोड़ रुपये के इस काम के चक्कर में 4 सौ करोड़ रुपये की रोड तोड़ दी । रोड को ठीक करने वाला कोई नहीं है । यहां पर बैठे सभी सांसद मेरी बात से सहमत होंगे । ? (व्यवधान)

सर, रोड्स तोड़ दी गईं । खराब क्वालिटी है । आज के जमाने में एसएलआर से हम पानी दे रहे हैं । राजस्थान के अंदर हमारा रेगिस्तानी इलाका है, वहां लास्ट एंड पर बैठा हुआ जो

व्यक्ति है, उस तक पानी नहीं पहुंच पाता । पंपिंग के थ्रू लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए ।

सर, मेरी बस दो महत्वपूर्ण बातें रह गई हैं । एक भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है । राजस्थान में हाईएस्ट वाटर सप्लाई होती है । राजस्थान के लिए 8.67 एमएएफ पानी का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन 0.6 एमएएफ पानी हमें आज तक नहीं मिला । ऐसे ही हमारा सिद्धमुख कैनाल के लिए 0.47 एमएएफ पानी था, लेकिन हमें 0.17 एमएएफ पानी आज तक नहीं मिला । सिद्धमुख के नाम पर कैनाल बनी, लेकिन वहां से पानी आज तक नहीं आया । हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का यह केस 33 साल से ट्रिब्यूनल में अटका हुआ है । वहां पर आपकी डबल इंजन की सरकार है । आपकी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है । राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है । ट्रिपल इंजन की सरकार भी फैसला नहीं कर पा रही है कि किसानों को पानी कब मिलेगा?

सर, मैं यमुना लिंक नहर की बात करूंगा । ? (व्यवधान) सर, मैं मेरी पार्टी का फर्स्ट स्पीकर हूँ इसलिए आप मुझे बोलने का समय दीजिए । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप एक मिनट रुक जाइए । गौरव गोगोई जी, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हैं । इस बिल के लिए चार घंटे का समय दिया गया है । उन चार घंटों में आपकी पार्टी के लिए 44 मिनट्स हैं । आपकी पार्टी से 11 स्पीकर्स के नाम हैं । ये ऑलरेडी 20 मिनट बोल चुके हैं । आप बीएसी में इस बिल पर या तो चार से आठ घंटे चर्चा बढ़वा दीजिए । अगर आप अपने 10 स्पीकर्स को नहीं बुलवाना चाहते हैं तो मैं इनको पूरे 44 मिनट्स दे दूंगा ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : हमारी पार्टी का समय भी 1 घंटे 46 मिनट का है ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल कस्वां : सर, यमुना लिंक नहर से हम राजस्थान में रेन वाटर को टैप करके ताजेवाल हेड से पानी लेकर आ रहे थे । राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने चुनाव के समय उसे भागीरथ का नाम दिया और उन्होंने कहा कि हम यमुना लिंक के पानी का डीपीआर बनाएंगे । डीपीआर आप ही की सरकार में वर्ष 2018 में बनकर तैयार हुई थी । वह 22 हजार करोड़ रुपये की डीपीआर है । 220 किलोमीटर दूर पानी पाइप लाइन के माध्यम से जमीन के नीचे

से आएगा । इससे हिन्दुस्तान में इरिगेशन की नई टेक्नोलॉजी की शुरूआत होती, लेकिन वह पानी आज भी अटका पड़ा हुआ है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बारे में जानना चाहता हूँ । ? (व्यवधान) सर, मेरा यह कहना है कि ईआरसीपी में बजट आवंटन कर दिया तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाने की बात की जाएगी?

मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि न पानी पीने के लिए है, न पानी सिंचाई के लिए है । राजस्थान का पानी लोगों की आँखों में आ गया है । आपके द्वारा ?सबका साथ, सबका विकास? की बात की गई थी । आपका साथ दो बार दिया गया है । इसलिए आप एक बार हमारा भी साथ दीजिए और यमुना लिंक नहर परियोजना को धरती पर लाने का काम कीजिए ।

श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद (संत कबीर नगर) : आज मैं उन लार्खा नागरिकों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जिन्हें इस सरकार के खोखले वादों से धोखा दिया गया है, एक ऐसी बुनियादी आवश्यकता पर जो अभी भी हमारी आबादी के विशाल हिस्सों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, से दूर है । जल शक्ति मंत्रालय के लिए 2025-26 के बजट अनुमान न केवल अक्षमता बल्कि हमारे राष्ट्र की जल सुरक्षा के प्रति एक निर्दयी उपेक्षा को दर्शाते हैं । कुल सकल बजट आवंटन वास्तव में BE 2024-25 में 2107,624.51 करोड़ से घटकर BE 2025-26 में ₹107.391.92 करोड़ हो गया है, जो 0.22% की कमी है । यह कमी, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करने पर, वास्तविक रूप से एक महत्वपूर्ण कटौती का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसे समय में जब हमारी जल चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं । मेरा निर्वाचन क्षेत्र, संत कबीर नगर, जो राप्ती, सरयू और घाघरा नदियों से बार-बार बाढ़ से तबाह होता है, बजट में कटौती और कार्यान्वयन की विफलताओं से कहीं बेहतर का हकदार है ।

सरकार का बाढ़ प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण को आपराधिक रूप से लापरवाह के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता । ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा रहा है, बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम को BE 2024-25 में 2449.57 करोड़ से BE 2025-26 में ₹450 करोड़ तक मामूली 0.10% की वृद्धि मिली है । मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करने पर यह वास्तव में एक कमी है । इससे भी अधिक प्रकट करने वाला यह है कि वे इस तुच्छ राशि को भी खर्च नहीं कर सके, RE 2024-25 ₹400 करोड़ पर खड़ा है, जो आवंटित से 11.03% कम है । हर मानसून में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के लोग विनाशकारी बाढ़ का सामना करते हैं, फिर भी इस सरकार को बाढ़

सुरक्षा के लिए उचित धन आवंटित करने की परवाह नहीं है । संत कबीर नगर में, 38 गांव घाघरा नदी के बाढ़ के पानी से घिरे हुए थे, नदी खतरे के निशान को पार कर घरों को नष्ट कर रही थी । गयाघाट दक्षिण के ग्राम प्रधान ने बताया था कि आठ घर बह गए हैं । क्या यह सरकार कार्रवाई करने से पहले और अधिक घरों के बह जाने का इंतजार कर रही है?

हमारी आपदा तैयारियों का सबसे चौंकाने वाला विश्वासघात हमारी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का लगभग पूर्ण विघटन है । जल संसाधन सूचना प्रणाली, जो बाद पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण है, को BE 2024-25 में ₹115 करोड़ से 44.88% की कटौती के साथ BE 2025-26 में केवल ₹63.39 करोड़ कर दिया गया है । इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना को वस्तुतः समाप्त कर दिया गया है जिसमें BE 2024-25 में 661.20 करोड़ से 98.03% की कभी के साथ BE 2025-26 में मात्र ₹13 करोड़ रह गए हैं । हरे राष्ट्रबादी अविश्यवाणी और तैयारी करने की केसीको से कम नहीं है । अब अमली बाव आपदा आएगी और हजारो लोग अनजान रहेंगे, तो यह सरकार उन प्रणालियों को नष्ट करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी जो पारंभिक पेवतियां प्रदान कर सकती थी । उत्तर प्रदेश के बाद पंवर क्षेत्रों में लोम- जहां हमारी पाटी आम लोगों की सेवा करती है इस सरकार के विनाशकारी विकल्पों का खामियाजा भुगतेगे । शोध से पता चलता है कि संत कबीर नगर में तीन कौली मेहदावल और बेलहरकला बाढ़ के सबसे अधिक ओखिम में हैं, जिनके 11-18% क्षेत्र कमऔर हैं और 52,478 लोग सीधे ओखिम में हैं । फिर भी इस सरकार के पास इन कमजोर समुदायों के लिए कोई व्यापक योजना नहीं है ।

बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम को BE 2024-25 में 46.98 करोड़ से BE 2025-26 में ₹50.30 करोड़ तक मात्र 7.07% की वृद्धि मिली है, जो कि पूरी तरह से अपर्याप्त है क्योंकि हमारे पास 50 वर्ष से अधिक पुराने 1,115 से अधिक बड़े बांध हैं । यह मध्य वृधि हमारे बुढ़ापे वाले बांध बुनियादी ढांचे की गंभीर सुरक्षा चिंताओं को दूर नहीं कर सकती । 2024-25 के संशोधित अनुमान ₹42.28 करोड़ पर खड़े हैं, जो इस महत्वपूर्ण सुरक्षा क्षेत्र में भी 10% कम खर्च दिखा रहे हैं । क्या हम बांध सुरक्षा को गंभीरता से लेने से पहले बांध विफलता की आपदा का इंतजार कर रहे हैं? ऐस लगता है कि इस सरकार ने पिषले बांध विफलताओं और उनके विनाशकारी परिणामों के सबक को भुला दिया है । संत कबीर नगर के राप्ती नदी बेसिन में, हमारे पास कुल 22.38 किलोमीटर की लंबाई वाले केवल चार तटबंध हैं जो केवल 8,938 हेक्टेयर भूमि की रक्षा करते हैं । फिर भी शोध से पता चलता है कि 2017 में 10,254.12 हेक्टेयर जलमग्न हो गए थे । सुरक्षा में कुल अंतर स्पष्ट है. फिर भी यह सरकार बाद प्रबंधन के लिए धन कम करती है ।

बाढ प्रबंधन धन में क्षेत्रीय असमानताएं इस सरकार के आपदा प्रबंधन के प्रति चयनात्मक दृष्टिकोण को उजागर करती हैं । उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत की कुछ सबसे गंभीर और बार-बार आने वाली बाढ़ का सामना करता है, फिर भी अपर्याप्त आवंटन प्राप्त करता है । बिहार, ओ सालाना कोसी और गंडक की बाढ़ से तबाह होता है, के पास सामान्य FMBAP के अलावा कोई लक्षित कार्यक्रम नहीं है । ब्रह्मपुत्र बोर्ड, जो हमारे सबसे अधिक बाढ़ प्रवण नदी बेसिन में से एक के लिए जिम्मेदार है, BE 2025-26 में मात्र 62 करोड़ रूपये प्राप्त करता है, जो वास्तव में RE 2024-25 में ₹63 करोड़ से घट रहा है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे किसान और नागरिक समान उपेक्षा का सामना करते हैं क्योंकि हर मानसून में बाढ़ उनके घरों और खेतों को तबाह कर देती है । उपरा पूर्वी और तुकौलिया जैसे गांवों में, नदी की धारा सीधे तटबंधों की मारती है. फिर भी यह सरकार मुश्किल से इतना पैसा आवंटित करती है कि एक मुट्ठी भर नावे तैनात की जा सकें गंभीर बाढ़ के दौरान संत कबीर नगर के 25 गांवों के लिए केवल 39 । इस सरकार की कुछ क्षेत्रों के प्रति उदासीनता विशेष रूप से वे जो उनकी पार्टी द्वारा शासित नहीं हैं- इन भेदभावपूर्ण आवंटनों में स्पष्ट है ।

बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम BE 2025-26 में जल संसाधन विभाग के बजट का मात्र 1.36% है, जो BE 2024-25 में 1.49% से कम है । यहां तक कि अगर हम सभी बाढ़-संबंधित घटकों (FMBAP + बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी) को जोड़े, तो वे मंत्रालय के बजट का 1.45% हिस्सा बनते हैं । यह वह मूल्य है जो यह सरकार बाढ़ आपदाओं से लाखौ नागरिकों की रक्षा पर रखती है । आवंटन का इतिहास एक निंदनीय कहानी बताता है: वास्तविक 2023-24 में ₹198.39 करोड़ से BE 2024-25 में ₹449.57 करोड, RE 2024-25 में ₹400 करोड, BE 2025-26 में ₹450 करोड़ - अनिवार्य रूप से स्थिर धन जबकि बाढ़ के जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं । मेरे जिले के मदरा, छपरा मगरवी, रामपुर बाराह कोनी और भोथा जैसे गांवों में, बाढ़ का पानी लोगों को हर मानसून में अपने घरों को छोड़ने और अपनी फसलों को खोने के लिए मजबूर करता है, फिर भी यह सरकार इस अस्तित्वगत खतरे को संबोधित करने के लिए जेब खर्च आवंटित करती है । जब अगापुर गुलरिहा के 2,000 निवासियों के घरों में बाढ़ का पानी घुसा, बच्चे कई दिनों तक भोजन के बिना रहे, परिवार पानी से घिरे खाटों पर बैठे रहे, और गुलरिहा, उपरा पूर्वी और धरमचिया में स्कूलों जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बंद करने के लिए मजबूर किया गया । यह केवल वित्तीय उपेक्षा नहीं है, यह दृष्टि और रणनीति की पूर्ण अनुपस्थिति है । जबकि भाजपा सरकार आपदा लचीलापन के बारे में बड़े-बड़े घोषणा करती है, उनका बजट उनके दावों के पीछे खोखली सच्चाई को उजागर करता है ।

मैं माननीय मंत्री को महत्वपूर्ण जल सुरक्षा कार्यक्रमों में इन विनाशकारी कटौतियों को स्पष्ट करने की चुनौती देता हूं । आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के लिए बाढ़ प्रबंधन की आपराधिक उपेक्षा को कैसे उचित ठहराएंगे? आप उन लाखों लोगों का सामना कैसे करेंगे जो अभी भी नल के पानी के कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं जबकि आपका प्रमुख कार्यक्रम अपने आधे बजट का भी उपयोग करने में विफल रहता है? आप करमैनी, बेलौहा, भरथुवा और नौगो जैसे गांवों के लोगों को कैसे समझाएंगे, जहां राप्ती नदी खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर बहती है, आपने उन्हें बचाने के लिए बनाई गई प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को वस्तुतः समाप्त क्यों कर दिया है? यह बजट न केवल अपर्याप्त है, यह भारतीय लोगों के विश्वास और उनके जल सुरक्षा के मौलिक अधिकार के मौलिक विश्वासघात का प्रतिनिधित्व करता है । हमारी पार्टी किसानों, बाढ़ पीडितों और सभी नागरिकों के साथ खड़ी है जिन्हें पानी के अधिकार से वंचित किया गया है । हम भारत के लोगों के साथ, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से, जवाबदेही की मांग करते हैं, जो खोखले वादों और खोखले बजट से बेहतर के हकदार हैं ।

जय हिन्द । जय समाजवाद ,

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : मैं Ministry of Jal Shakti Demands for Grants 2025-26 पर अपने विचार व्यक्त करता हूं । हमारे समाज में जल संसाधन को बहुत मूल्यवान माना जाता था ऋगवेद में कहा गया है कि जल में अमृत है, जल में औषधयी है । Water Resource Management के विभिन्न प्रकार के अनेक प्राचीन उदाहरण पूरे देश में उपलब्ध हैं जो आज भी प्रासंगिक है । हमारी प्राचीन जल-प्रबंधन प्रणालियों पर शोध होना चाहिए और आधुनिक संदर्भ में उनका व्यावहारिक उपयोग होना चाहिए । सरोवर, कुआं, तालाब, जल-कुंड और पोखरी, ऐसे सभी जल - निकाय, सदियों से हमारे समाज के लिए Water-bank रहे हैं ।

जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में शुरू की गई थी । मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे । मार्च 2025 तक 15.52 करोड़ से अधिक परिवारों को उनके हारों में नल जल पानी सप्लाई हो रहा है । शेष पड़े 3-84 करोड परिवारों के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है । यह सराहनी पहल है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है ।

आज जब पर्यावरण और जल-संरक्षण की बात आती है, तो कई सच्चाइयों का हमेशा ध्यान रखना है । भारत में दुनिया के कुल fresh water का सिर्फ 4 प्रतिशत ही है । कितनी ही

विशाल नदियां भारत में हैं, लेकिन हमारे एक बड़े भूभाग को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है । कई जगहों पर पानी का स्तर लगातार गिर रहा है । क्लाइमेट चेंच इस संकट को और गहरा रहा है । इस सबके बावजूद, ये अपना देश ही है जो अपने साथ-साथ पूरे विश्व के लिए इन चुनौतियों के समाधान खोज सकता है । हम उस संस्कृति के लोग हैं, जहां जल को ईश्वर का रूप । कहा गया है, नदियों को देवी माना गया है । सरोवरों को कुंडों को देवालय का दर्जा मिला है । इसलिए दूसरों के लिए पानी बचाना सबसे बड़ा दान माना गया है ।

आज से लगभग 24 सौ वर्ष पहले के ग्रन्थ 'अर्थ-शास्त्र' में कौटिल्य ने लिखा है कि 10 परिवारों के लिए एक सार्वजनिक कुआं उपलब्ध होना चाहिए । उस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है कि पानी के बहाव की व्यवस्था कराना नगर के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, यदि कोई व्यक्ति, पानी के बहाव को रोकता है तो उस पर जुर्माना लगेगा ।

पहले देश के केवल 3 करोड़ हारों में पाइप से पानी पहुंचता था । आज देश के 15 करोड़ से अधिक ग्राणीण घरों को पाइप से पानी मिलने लगा है । जल-जीवन मिशन के जरिए देश के 75 प्रतिशत से ज्यादा घरों तक नल से साफ पानी पहुँच चुका है ।

World Health Organization (WHO) का आकलन है कि हर घर पाइप से जल पहुंचने से देश के लोगों के करीन साढ़े 5 करोड़ घंटे बचेंगे । World Health Organization अपनी रिपोर्ट्स में कहती है कि जल जीवन मिशन से सवा लाख से ज्यादा बच्चों की असमय मौत भी रोकी जा सकेगी । हम हर साल 4 लाख से ज्यादा लोगों को डायरिया जैसी बीमारियों से भी बचा पाएंगे यानि बीमारियों पर लोगों का जो खर्च होता था, वो भी कम हुआ है ।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पानी की जरूरतों का 80 प्रतिशत हिस्सा, खेती के कामों में आता है । Sustainable agriculture की दिशा में हमारी सरकार drip irrzation जैसी तकनीकों को लगातार बढ़ा रही है । Per drop more crop जैसे अभियान इनसे पानी की बचत भी हो रही है, कम पानी वाले इलाकों में किसानों की आय भी बढ़ रही है । है । सरकार दलहन, तिलहन और मिलेट्स जैसी कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती को भी बढ़ावा दे रही है ।

विश्व समुदाय ने, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाए गए Sustainable Development Goals के तहत, वर्ष 2030 तक, सभी के लिए जल की उपलब्धता तथा स्वच्छता को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है । इन लक्ष्यों में, महिलाओं और लडकियों की जल तथा स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं का विशेष उल्लेख किया गया है । जल के अभाव से पीड़ित लोगों की संख्या कम करने का लक्ष्य, पूरी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । Sustainable Development

Goals के तहत, जल और स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन देने और मजबूत बनाना जरूरी है इसमें सब की भागीदारी ज़रूरी है ।

पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का 2.5 प्रतिशत A fresh water या मीठा पानी होता है । उसमें भी एक प्रतिशत ही मानव समाज के उपयोग के लिए उपलब्ध हो पाता है । जल-संसाधन सीमित हैं । उनके सक्षम उपयोग से ही सबके लिए जल की आपूर्ति संभव है । विश्व के जल-संसाधन में भारत का हिस्सा चार प्रतिशत है । हमारे देश में उपलब्ध जल का लगभग 80 प्रतिशत कृषि-क्षेत्र के उपयोग में आता है । कृषि के अलावा विद्युत उत्पादन, उद्योग तथा घरेलू जरूरतों के लिए पानी की उपलब्धता अनिवार्य है । पानी के सक्षम उपयोग द्वारा ही संतुलित तरीके से विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है ।

भारत में विश्व की करीब 18 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है । अनियोजित शहरीकरण ने तालाबों और झीलों जैसे जल-संचय के परंपरागत तरीकों को लुप्त कर दिया है जिसका परिणाम आज पानी की समस्य के साथ-साथ global सामने है । global warming के रूप में भी हमारे सामने है ।

केन-बेतवा लिंक परियोजना 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई और 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी, जबकि संशोधित पार्वती-कालीसिंध चंबल ईआरसीपी 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई और 50 लाख लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराएगी ।

2025-26 में जल शक्ति मंत्रालय को 99,503 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, जो 2024-25 के बजट आबंटन (98,714 करोड़ रुपये) से थोड़ा ज्यादा है । 2024-25 में व्यय का संशोधित अनुमान बजट आबंटन से 48% कम है । यह संशोधित चरण में जल जीवन मिशन के लिए कम आबंटन के कारण है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में हुई बाढ़ की विभीषिका एवं उससे हुए जान-माल के नुकसान की ओर इस सदन के माध्यम से मैं माननीय जलशक्ति मंत्री जी का ध्यान इस और दिलाना चाहता हूँ ।

मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में बाढ़ का मुख्य कारण नेपाल में लगातार बारिश होने से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ जाना है और वाल्मीकि नगर बराज से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ देने से जिला जलमग्न हो से रातों-रात पूरा जिला घटते-बढ़ते जलस्तर की है । गंडक नदी के लगातार घटते-बढ़ते. जाता है । वजह से बाँध में कटाव होता है और बाँध दूर जाना है । इससे करीब एक सौ पच्चास (150) गाँव के लोग प्रभावित होते हैं तथा हजारों की तादाद में

लोग विस्थापित हो जाते हैं । पिछले कई सालों में लाखों लोगों के घर नदी के कटाव के कारण समाप्त हो गए । कल तक जहाँ गाँव हुआ करता थ आज वहाँ कई किलोमीटर तक नदी की धारा बह रही है वर्ष 2017 में 300 परिवार वाला टिहरी टोला गंडक की उग्र धारा में बह गया था । कई स्कूल एवं सरकारी भवन भी बह गए । हमारे गोपालगंज में 72 किलोमीटर की दूरी में गंडक नदी बहती है, जिसमें 8 जगहों पर डेंजर प्वाइंट है मेरे संसदीय क्षेत्र के 6 प्रखण्ड जिसमें बरौली, सिधौलिया, बैकुण्ठपुर, कुचायपोट एवं गोपालगंज ब्लाक सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं ।

इसका समाधान यह है कि अगर जलशक्ति मंत्रालय बाँध में बोल्डर लगा दें एवं किनारों को सीमेन्टेड कर दें तो कटाव को रोका जा सकता है तथा इससे बाढ़ से होने वाली बर्बादी को भी रोका जा सकता है । जैसाकि उत्तर प्रदेश में गंडक नदी पर सरकार ने किया है । इससे सरकार को हर साल खर्च होने वाले करोड़ों रूपये को बचाया जा सकता है साथ-साथ बाढ़ का स्थाई समाधान भी है ।

अतः मैं माननीय जलशक्ति मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं ताकि केन्द्रीय टीम के भेजकर सर्वे कराया जाए एवं स्थायी समाधान निकाला जाए । बाढ़ के स्थायी समाधान से देश का पैसा बचेगा एवं लोगों के जीवन में खुशहाली आयेगी ।

धन्यवाद

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : सभापति, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में प्रस्तुत जल शक्ति मंत्रालय की 2025-26 की अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूं । यह बजट हमारे देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है । यह देशवासियों के लिए प्रसन्नता की बात है कि वित्तीय बजट में जल जीवन मिशन का बजटीय परिव्यय बढ़कर 67,000 करोड़ रुपए किया गया है और साथ ही इस मिशन का विस्तार 2028 तक किया गया है । यह मिशन अगले 3 वर्षों की अवधि में शत प्रतिशत कवरेज हासिल करेगा । सरकार के महात्वाकांक्षी जल जीवन मिशन की डेडलाइन 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है । उन्होंने दावा किया कि 2019 से लेकर अब तक 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेय जल की सुविधा प्रदान की जा चुकी है । जो कुल ग्रामीण आबादी का 80 फीसदी है । अगले चार सालों में बची हुई 20 फीसदी ग्रामीण आबादी तक नल से पेयजल की सुविधा प्रदान की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव भी किया जाएगा । हालांकि, इस बार के केंद्रीय बजट आंकड़ों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 67000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । बीते वित्त वर्ष 2024-25 के मुकाबले इस बार जल जीवन मिशन के लिए किया गया प्रावधान

काफी अधिक है । जल जीवन मिशन का मुख्य ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता और "जन भागीदारी" के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में पाइप से जल आपूर्ति योजना के ऑपरेशन एंड मेंटनेंस पर होगा । इसके लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पृथक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जायेंगे, ताकि इसकी निरंतरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा को तय किया जा सके । वहीं केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 74226.02 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । इसमें करीब 90 फीसदी बजट का हिस्सा जल जीवन मिशन के लिए ही है । यानी ग्रामीण पेयजल को छोड़कर महज 10 फीसदी बजट अन्य ड्रिंकिंग सैनिटेशन कार्यों के लिए है । डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिग वाटर सैनिटेशन के हिस्से में दूसरा बड़ा मद ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के लिए है । सरकार ने बजट के प्रावधानों में स्पष्ट किया है कि इस मद का इस्तेमाल गांवों को स्वच्छ रखने और खुले में शौच से मुक्त रखने के लिए किया जाएगा ।

भारत की ग्रामीण आबादी के 80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 करोड़ लोगों को 2019 से जल जीवन मिशन से फायदा हुआ है । इस मिशन के तहत नल का पेयजल उपलब्ध कराया जाता है और अगले 3 वर्षों में मिशन का लक्ष्य शत प्रतिशत लोगों को नल का पेयजल उपलब्ध कराना है । यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ परिवारों, जो भारत की ग्रामीण आबादी का 80 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं, को पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराया गया है । इस मिशन का मुख्य ध्यान अवसंरचना की गुणवत्ता और 'जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से जल आपूर्ति योजना के प्रचालन और रख-रखाव (ओएण्डएम) पर होगा । राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पृथक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाएगा ताकि, इसकी संधारणीयता और नागरिक? केंद्रित जल सेवा वितरण को सुनिश्चित किया जा सके ।

भारत में जल संसाधनों के प्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है । केंद्र स्तर पर, जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है । यह सुनिश्चित करता है कि घरेलू उपयोग, स्वच्छता, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग जैसी विविध जल आवश्यकताओं के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए । यह नदियों और अन्य जल निकायों के संरक्षण को भी सुनिश्चित करता है । 2025-26 में जल शक्ति मंत्रालय को 99,503 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2024-25 के बजट आवंटन से अधिक है । केन्द्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में पेयजल और स्वच्छता विभाग के लिए 74,226 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिनमें से अधिकांश जल

जीवन मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं जिसका उद्देश्य ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है । यह आवंटन विभाग के लिए 2024-25 के लिए 29,916 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से काफी अधिक है ।

यह प्रसन्नता की बात है कि ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन 150 मिलियन के आंकड़े को पार कर गया है । जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को 25,276.83 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो संशोधित अनुमान से 21,640.88 करोड़ रुपये अधिक है । नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत नदी की सफाई और पुनरुद्धार के लिए 3,400 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष 3,000 करोड़ रुपए थे । जल जीवन मिशन (जेजेएम) को 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों और सार्वजनिक संस्थानों को सुनिश्चित नल जल आपूर्ति प्रदान करना है । जेजेएम का उद्देश्य ग्रे वाटर प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करके पानी की गुणवत्ता को भी संबोधित करना है । हमारी सरकार ने जल संचयन और प्रबंधन के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं । इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएँ हैं । जल संचयन योजना जल संचयन के लिए विभिन्न तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है । जल प्रबंधन योजना जल प्रबंधन के लिए विभिन्न तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है । जल शिक्षा योजना जल शिक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है । हमारी सरकार की जल शक्ति मंत्रालय के बजट से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे । जल शक्ति मंत्रालय के बजट से लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे । यह रोजगार के अवसर देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे ।

देश में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में हुआ है, जिसका पूरा ग्रामीणों को मिल रहा है । मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर (उ०प्र०) में जल जीवन मिशन योजना "हर घर जल" के अन्तर्गत करवाए जा रहे कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है । मुझे क्षेत्र में दौरे के दौरान निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जो निर्माण कार्य कार्यदायी एजेंसी के माध्यम से करवाए जा रहे हैं, वे गुणवत्ताविहीन और मानक के अनुरूप नहीं है । निर्माण कार्य में अत्यधिक घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है तथा कार्यदायी एजेंसी द्वारा कार्य को जिन छोटे-छोटे ठेकेदारों में बांटा गया है, उनको उक्त कार्य का अनुभव ही नहीं है । कार्यदायी एजेंसीं द्वारा जो पाइपलाइन डाली जा रही है, उसकी गुणवत्ता भी अत्यधिक घटिया है । पाइपलाइन बहुत हल्की है एवं साइट पर डालते समय टूट-फूट हो रही है । इसके अलावा पाइप लाइन डालने के उपरांत रोड को कहीं भी ठीक /

रिस्टोर नहीं किया गया है । मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर की सभी ग्राम पंचायतों में यह स्थिति है । जनपद के विकास खंड सिंधौली के ग्राम मुर्छा में जल जीवन मिशन के तहत घटिया निर्माण सामग्री से बन रही पानी की टंकी की सीढ़ी गिरने से मजदूर भी घायल हुए हैं ।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय मंत्रालय स्तर पर एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति गठित करके उपरोक्त पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करवाने तथा कार्यदायी एजेंसी को तत्काल प्रभाव से ब्लैक लिस्ट करते हुए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करने और कार्यों को कुशल कार्यदायी एजेंसी को आवंटित किए जाने हेतु समुचित कार्यवाही की जाए । अंत में, मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी और उनके सहयोगी राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी और श्री सी०आर० पाटिल जी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों का पूरजोर समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): The Ministry of Jal Shakti, has been allocated Rs 99,503 crore in budget 2025-26. While this figure appears substantial, a closer examination reveals a landscape riddled with inefficiencies, underachievement, and systemic issues that demand immediate attention and reform.

The Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS), is entrusted with enormous financial responsibility.

The revised estimate for expenditure of DDWS is a staggering 48% lower than the budget allocation, primarily due to reduced allocation to the Jal Jeevan Mission. This glaring underutilization of funds raises serious questions about the government's capacity to effectively implement its much hyped Jal Jeevan Mission.

In the much hyped Jal Jeevan Mission, there are two schemes

1. Ground Water Based Schemes,

2. Surface Water Based Schemes

Both of them are categorised into three types; 1. PWS, 2.H.P/ Borewell/Tube Well & Other spot sources and others.

As far as Tamil Nadu under the Ground water Based Schemes, through PWS 94,408 habitants are covered. Through H.P/Borewell/Tubewell & other spot sources. This is awfully inadequate. Fortunately for Tamil Nadu inspite of hardships to supply water, the Dravidian model rule has achieved many years ago what the union government is targetting to achieve by 2030.

The Jal Jeevan Mission (JJM), launched in 2019 with the ambitious goal of providing assured tap water supply to all 19 crore rural households by 2024, has failed to meet its target and the scheme has now been extended to 2028. This shortfall is not merely a statistical lapse; it is a failure of governance that directly impacts the lives of millions.

Even more concerning is the functionality assessment report, which reveals that only 62% of households have fully functional tap connections. Full functionality implies not just the presence of a tap, but also a regular supply of water in adequate quantities and of acceptable quality.

Shockingly, in many states more than 40% of households receive water that does not meet quality standards. In 2024-25, 5% of the 66 lakh samples tested were found to be contaminated, and remedial action was taken on only 59% of these. Also, in 2024-25, only 31% of the central share allocated has been released.

Budget allocations for JJM have oscillated wildly. For the fiscal year 2025-26, Rs 67,000 crore has been earmarked-a figure that, on paper, projects confidence and ambition. Yet, when contrasted with the revised expenditure estimates of the previous year, which hovered around a dismal Rs 22,694 crore, the discrepancy is glaring. Such a vast difference between budgetary intent and actual spending speaks volumes about the inefficiencies that plague project implementation. The government's inability to translate funds into tangible results has created an environment where financial pledges are rendered impotent by procedural delays, administrative apathy, and a lack of genuine commitment to reform.

While the budget estimate for 2025-26 is nearly double that of 2024-25's revised estimate, the actual expenditure in previous years has been shockingly low. Such inconsistencies suggest that the allocation of funds is less a reflection of on-the-ground needs and more a symbolic gesture-an attempt to present a façade of progress while the underlying issues remain unresolved.

The most important natural wealth of our country is the large number of rivers flowing across different states. Most of the Rivers, particularly the peninsular rivers are flooded during the heavy wet monsoons and dry during the other seasons due to scarce rainfall in the catchment areas of these rivers. Hence the Farmers are in the clutches of either a severe flood or drought. This is a very bad situation for farmers of this country. It not only affects their crops but also make them suffer most to repay their loans resulting in the suicides of farmers in the country.

The Nationalization of rivers and inter-linking of the rivers are very important as they not only solve the inter-state water sharing disputes among the Indian States but is also the only way through which adequate water for irrigation in various states could be ensured and the problems faced by the farmers due to lack of water and drought could be solved permanently. Also the government should consider creating a comprehensive National Policy on Indian rivers and National river water Grid to enhance the process of inter-linking of rivers flowing in various states. In this way the government can harness the excess water in the rivers cleverly and judiciously to benefit drought hit parts of the country.

Water is indispensable for Agriculture. Irrigation is the blood circulation of Agriculture. Without water nothing could be done, without adequate water even if we spend crores of rupees, without water, farmers have no chance of flourish. The River Cauvery is the lifeline of Tamil Nadu, particularly the millions of farmers in the delta regions in Tamil Nadu. But unfortunately year after year Tamil Nadu farmers are betrayed due to the non release of adequate water from river Cauvery. The unconcerned attitude of the higher riparian State of Karnataka has killed hundreds of farmers in Tamil Nadu and has driven several thousand out of the

agriculture. The total loss due to the non release of Cauvery water for crop seasons in Tamil Nadu has taken heavy toll on Agriculture and farmers of Tamil Nadu.

The Union Government should urge the Cauvery Management Board to direct the Karnataka state to release rightful share of water from Cauvery river in accordance with the award of the Cauvery Water Disputes Tribunal (CWDT) in monthly deliveries to ensure adequate release of Cauvery water from Karnataka for irrigation in Tamil Nadu.

The Union Government has to allocate more funds for the proper maintenance and use of existing dams and water reservoirs in the country. The deepening and de-silting of local water bodies and the lakes is crucial for growth of agriculture. The Union Government has to allocate more funds for the river restoration projects in the country and also to increase and enhance the water catchment capacity in the country. The development of social forestry and increase of green cover in the country is also part of the agro development activity only.

Tamil Nadu always perform better when it comes to people and reserved the best for adverse conditions. The Hogenakkal Integrated Drinking Water project and the Athikadavu Avinashi project are standing testimonial to the commitment of the DMK government headed by Hon'ble Chief Minister Thalapathi M.K. Stalin in providing water to underprivileged people living in dry regions. The Veeranam Water Supply scheme, The Palar water Supply scheme cater the water needs of the people of Greater Chennai region and adjoining districts of Thiruvallur, Chengalpattu and Kanchipuram are also the brain child of Muthamilarignar Dr Kalaignar. The southern Districts of Ramanathapuram, Thoothukudi, Virudhunagar too benefitted through the far sighted water management of the Government of Tamil Nadu.

Water Resources is the most indispensable thing in the development of civilizations. History teach us about the River valley Civilisations that thrived on the banks of the perennial rivers.

North Indian States are blessed with perennial rivers from the Himalayas and South Indian States depend on rain fed rivers. In this situation to provide equitable distribution of water for both drinking and irrigation purposes requires a meticulous planning, bold decisions and impeccable execution.

Unfortunately the Modi BJP government in the last 10 years prioritize ambition over accountability, spectacle over sustainable progress and political gains over productivity. This government neither addresses the perils due to spate of Himalayan rivers and penury due peninsular rivers.

Water is one of the basic gifts of nature to mankind. There is no life without water. The origin of life began in Water. Around 1 in 4 people lacked safely managed drinking water in their homes and nearly half the world's population lacked safely managed sanitation. COVID-19 has highlighted the urgent need to ensure everyone can access good hand hygiene. We need to learn our lessons from such dreaded pandemic and be prepared for the future pandemic and calamities.

Billions of people will lack access to safe water, sanitation and hygiene in 2030 unless progress quadruples.

By 2030, only 70 per cent of the country's population will have access to safe drinking water at home, leaving millions without; Only 60 per cent will have safe sanitation services.

As per the latest reports, vast inequalities with vulnerable children and families suffering the most due to lack of access to safe water and sanitation. To achieve universal access to safely managed drinking water by 2030, the current rate of progress in the Least Developed States in India would need to increase ten-fold. In fragile contexts, where people were twice as likely to lack safe drinking water, it would need to accelerate twenty times more.

Ancient Tamil literature provides fascinating insights into water. management practices and the cultural significance of water in Tamil Nadu.

Thousands of years ago, Tamils possessed remarkable knowledge of water management. Kings built tanks and lakes to store water, some of which still exist today.

Water was considered sacred, and its judicious use was emphasized. Ancient Tamil literature mentions 47 water bodies, reflecting the prescient wisdom of Tamils in harvesting water.

Different terms were used to describe various types of water: Munneer: Refers to the sea, formed by water from rains, rivers, and springs. It symbolized antiquity and purity.

Nanneer: Denoted good water from rivers.

Inneer: Referred to sweet water suitable for drinking.

The Sangam era celebrated water through the festival of "Munneer Vizhavu," recognizing its role in soil creation, nourishment, and erosion.

Sangam literature believed that a person's character was shaped by water and soil. Life revolved around water, and villages were built around water bodies. Ancient Rituals from birth to death are centred on water. Houses were constructed around wells, emphasizing water's importance.

Tamil literature highlights the deep connection between water, culture, and sustainable practices. While challenges persist today, learning from ancient wisdom can guide better water management in the future.

Thank you.

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : मोदी सरकार ने जल प्रबंधन और ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में जल शक्ति मंत्रालय के लिए अभूतपूर्व 99 हजार 503 करोड़ रूपए आवंटित किए हैं, जो 2013-14 में यूपीए शासन के अंतर्गत मात्र 17 हजार 342 करोड़ रूपए की तुलना में लगभग छह गुना वृद्धि को दर्शाता है ।

यूपीए शासन के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में जल संसाधन और पेयजल के लिए कुल 17 हजार 342 करोड़ रूपए के संयुक्त आवंटन की तुलना में, वर्ष 2025-26 में केवल पेयजल

और स्वच्छता विभाग को ही 74 हजार 226 करोड़ रूपए का अभूतपूर्व आवंटन प्राप्त हुआ है ।

यूपीए सरकार की जल संसाधनों के प्रति वित्तीय प्रतिबद्धता बेहद अपर्याप्त थी, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश 2002-03 में मात्र लगभग 2,000 करोड़ रूपए से बढ़कर 2013-14 में 11,000 करोड़ तक ही पहुंचा पाया था । वित्त वर्ष 2025-26 में जल शक्ति मंत्रालय के लिए वर्तमान मोदी सरकार द्वारा आवंटित 99 हजार 503 करोड़ रूपए की तुलना में नगण्य प्रतीत होता है ।

देश के प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में मोदी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (JJM) की शुरुआत की गई, जोकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ग्रामीण सशक्तिकरण और जनकल्याण की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है ।

आज, 15 करोड़ से अधिक परिवारों, यानी भारत की 80% ग्रामीण आबादी को नल के माध्यम से स्वच्छ जल की सुविधा प्राप्त हो चुकी है, जो 2018 में मात्र 3 करोड़ परिवारों की तुलना में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है ।

इस परिवर्तनकारी प्रभाव और शेष चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 195% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है ।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 2014 से नमामि गंगे कार्यक्रम केवल एक नारे तक सीमित न रहकर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनर्जीवन के लिए ठोस प्रयासों में परिवर्तित हो गया है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी घाटी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और गंगेटिक डॉल्फिन तथा कछुओं जैसी जैव विविधताओं की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है ।

केंद्रीय बजट 2025-26 में नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए 2400 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 20% अधिक है । यह सीवेज उपचार क्षमता निर्माण और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को तेज करने के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।

मोदी सरकार की प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), जिसे 2015-16 में शुरू किया गया, भारत के कृषि भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण

कदम है, जो आश्वस्त सिंचाई के माध्यम से कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करता है ।

इस योजना के शुभारंभ के बाद से लगभग 60,000 करोड़ रूपए का निवेश प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किया गया है, जिसके उत्कृष्ट परिणाम मिले हैं-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के तहत 63% प्रमुख परियोजनाएं 2016-17 में पी.एम.के.एस.वाई (PMKSY) में शामिल होने के बाद पूरी हो चुकी हैं ।

भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर वर्ष आने वाली विनाशकारी बाढ़ के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, मोदी सरकार ने बाढ़ प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है । इसके अंतर्गत, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) के माध्यम से संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक दोनों प्रकार के उपाय अपनाए गए हैं और 400 से ज्यादा परियोजनाओं को पूर्ण किया गया ।

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) के अंतर्गत 450 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जिससे महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण उपायों की निरंतरता सुनिश्चित होगी ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान पानी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सराहनीय कार्य किया है । समग्र सरकार के दृष्टिकोण की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया । जल जीवन मिशन के जरिए हर घर में नल से पानी की आपूर्ति की गई, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों के खेतों तक जल आपूर्ति को सरल बनाया गया, आज देश भर में 60 हजार से अधिक अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं ।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों को जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध करवाकर इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया, जिसके फलस्वरूप आज देश में भूजल के स्तर में सुधार हुआ और देश में साफ़-सफाई का माहौल बना ।

मैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल जी का आभार व्यक्त करते हुए इस बजट का समर्थन करता हूँ ।

संसदीय क्षेत्र हेतु मांग :-

1. असम घाटी में हर साल बाद आती है, जो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के कारण होती है और कुछ क्षेत्रों, खासकर ऊंचे इलाकों में, सूखे की गंभीर समस्या रहती है, अतः

उत्तर-पूर्वी भारत को बाढ़ से बचाने और देश में जल के समान वितरण को ध्यान में रखते हुए नदियों से नदियों को जोड़ने वाली परियोजना के पुनः क्रियान्वन की दिशा में ठोस कदम उठाये जाएं ।

2. ब्रह्मपुत्र / बराक नदी और उसकी सहायक नदियाँ, जैसे लोहित, दिबांग और सुबनसिरी, नदी तट कटाव (Bank Erosion) के लिए जानी जाती हैं, जो एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक समस्या है । इन कटावों से उपजाऊ भूमि को नुकसान होता है, जिससे कृषि और स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित होती है । इसके समाधान हेतु उचित कदम उठाए जाएं ।

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): At the very outset, I would like to commend Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Jal Shakti Minister Shri C.R. Patil ji for their unwavering commitment to India's water security. The historic allocation of Rs. 99,503 crore for the Jal Shakti Ministry in this year's budget is a testament to their vision and dedication. This is not just a budgetary provision-it is an investment in the future of our country, in ensuring that no village, no town, and no citizen is left behind when it comes to access to clean and sustainable water resources.

Over the past ten years, under PM Modi ji's leadership, we have seen a paradigm shift in water management. When we speak of transformative governance, Jal Jeevan Mission stands out as a shining example. From just a handful of homes having tap connections in 2019, today, 14 crore households across India have access to functional tap water connections. This is not just an achievement in numbers but a revolution in improving public health, women's empowerment, and rural development. Atal Bhujal Yojana has been another landmark initiative, empowering local communities to manage groundwater resources and ensuring sustainable water use. The Namami Gange Mission has rejuvenated our sacred river Ganga, making it one of the most successful river rejuvenation programs in the world. And beyond these, the government's focus on interlinking rivers, increasing irrigation efficiency, and holistic watershed management has brought a new era of water security in India.

Sir, while these national initiatives have transformed lives across the country, Andhra Pradesh is at a critical juncture in its water management journey. Our state is home to Polavaram, a national project that is crucial for irrigation, drinking water, and flood control. However, it is also a project that was neglected and stalled under the previous state government. Today, I am proud to say that under our new Chief Minister's decisive leadership, we have put Polavaram back on track. A crucial sanction of Rs. 12,127 crore has been secured from the Central Government for Phase 1, ensuring that this project-the lifeline of Andhra Pradesh-finally moves forward with full momentum.

But Polavaram alone is not enough. Andhra Pradesh has the potential to become a model state for sustainable water use, provided we receive the right support. Unfortunately, the previous government failed to utilize even 13% of the ₹16,855 crore allocated to the state under the Jal Jeevan Mission. This was not just inefficiency-it was a betrayal of the people's trust. Now, with new Detailed Project Reports (DPRs) prepared, we are committed to fixing these past mistakes. We seek an enhanced allocation of ₹70,000 crore under Jal Jeevan Mission, and I urge the Hon'ble Minister to approve this at the earliest, so that Andhra Pradesh can achieve 100% tap water coverage and ensure clean drinking water for every household.

I come from Rayalaseema, a region that has long struggled with droughts and water scarcity. Despite its severe groundwater depletion, Andhra Pradesh has not been included in the Atal Bhujal Yojana. I urge the Hon'ble Minister to rectify this and include Andhra Pradesh in the scheme, so that Rayalaseema and other water-stressed districts can receive critical funding and technical support to replenish groundwater and secure their future.

While the Jal Jeevan Mission is ensuring tap water, and Atal Bhujal Yojana is working on groundwater sustainability, our Chief Minister has a bold vision for intra-state river interlinking. The Polavaram-Banakacherla river interlinking project is a game-changer for Andhra Pradesh. It aims to transfer surplus Godavari water to the Penna River via Krishna, ensuring equitable distribution of water across the state. By constructing key reservoirs at Bollapalli in Guntur and Banakacherla in

Nandyal, this project will provide drinking water to 80 lakh people and irrigate 7.5 lakh acres of farmland. Every year, nearly 2,000 TMC of monsoon water from the Godavari flows into the Bay of Bengal, unused. Instead of letting it go to waste, we must channel it to the regions that need it the most. But such an ambitious project requires a massive investment of ₹80,112 crore, and I urge the Central Government to provide financial support to make this vision a reality.

I conclude by once again expressing my gratitude to Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Jal Shakti Minister Shri C.R. Patil ji for their visionary leadership and unwavering commitment to water security. Under their guidance, India is moving towards a future where no citizen is deprived of clean drinking water. It is now our responsibility to ensure that hese ambitious initiatives reach the last mile and truly transform lives. I look forward to the continued support of the Central Government in strengthening water security in Andhra Pradesh, particularly for Rayalaseema and other drought-prone regions, ensuring that every drop counts, every resource is utilized, and every citizen benefits.

Thank you!

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : सभापति महोदय, मैं जल शक्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने सुझाव रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

सभापति महोदय, जल शक्ति मंत्रालय आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ, किसानों के जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जो जनहित में काम करता है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं, जो नदियों का देश है और जहां बरसात के दिनों में लगातार बरसाती पानी आता है, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट न होने के कारण हम उसको संरक्षित नहीं कर पाते हैं, जिससे आए दिन यह समाचार मिलता है कि पानी की कमी के कारण हमारे देश के कई जगहों पर किसानों को न तो सिंचाई के लिए पानी मिल पाता है और न ही पीने के लिए पानी उपलब्ध हो पाता है ।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान बाणसागर परियोजना की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना थी और जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पायी है । हम चाहते हैं कि वह परियोजना आगे बढ़े । उसे आगे बढ़ाकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तक, मिर्जापुर के लोगों तक और चन्दौली के क्षेत्र के लोगों के लिए सिंचाई के काम

को पूरा करने के लिए बाणसागर परियोजना को धंधरौल बांध, नौगढ़ बांध और साथ ही साथ आगे चन्द्रप्रभा बांध तक जोड़ दिया जाए ।

चकिया, चंदौली जहां से मैं चुनकर के आया हूं, वहां के किसानों को पानी मिल सके । वह अहरौरा बांध से भोक कट तक जाता है । अगर वह जोड़ दिया जाए तो किसानों को बहुत फायदा होगा । हरित क्रांति के दौरान वर्ष 1967-68 में वाराणसी जिले और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने नहरों का जाल बिछा करके हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की थी, लेकिन इतने वर्षों के बीत जाने के बाद नहरों की हालत बड़ी जर्जर है । वहां की जितनी भी बंधियां हैं, वे सब जर्जर हालत में हैं । उनको गहरा करने तथा उनकी मरम्मत करने की बहुत आवश्यकता है । अगर उनकी ठीक तरीके से मरम्मत हो जाए, तो किसान पानी से आबाद रहेंगे और जब किसान पानी से आबाद रहेंगे तो निश्चित रूप से उनके चेहरे पर मुस्कान लौटकर आएगी ।

यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है । भारत सरकार ?हर घर नल से जल योजना? के तहत पानी पहुंचने की एक महत्वाकांक्षी स्कीम लाई है लेकिन अफसोस की बात है कि जहां तक मेरी नजर है, जहां तक मेरी पहुंच है, मैं विशेष रूप से अपने क्षेत्र में जाता हूं, वहां कागजों पर 50 प्रतिशत से ऊपर पूर्णता की बात कही जाती है, लेकिन वह पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि जितनी पतली पाइप से नल से पानी पहुंचाने का काम हो रहा है, उस पाइप से अगर किसान एक बाल्टी पानी अपने लिए इकट्ठा करना चाहे तो आधे घंटे से पौने घंटा लग जाता है । यह पूरी तरीके से फेल है । साथ ही साथ गांवों में बनी सड़कों और गलियों को खोद करके पाइप्स डाली गई हैं, उन सड़कों की स्थिति यह है कि बरसात के दिनों को छोड़ दीजिए, गर्मी में भी उनकी मरम्मत न होने के कारण उन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है ।

मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को एडवाइजरी जारी किया जाए, क्योंकि जब मैं यहां के मंत्रालय में माननीय मंत्री जी से इस बात की चर्चा करता हूं तो वे कह देते हैं कि यह प्रदेश के अधीन है । जब मैं प्रदेश के मंत्री जी से मिलता हूं तो वे कहते हैं कि यह केंद्र सरकार की योजना है । इसलिए मैं यहां पीठ से कहना चाहता हूं कि आप एक एडवाइजरी जारी करें ताकि लोगों का कल्याण हो सके ।

जल शक्ति मंत्रालय का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भूगर्भ जल स्तर से संबंधित है । आज आप सभी जानते होंगे कि हमारी जमीन का जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है । तमाम ऐसे ब्लॉक्स डार्क जोन में आ गए हैं । हमारे यहां जल स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होने के कारण भूमि

का जल स्तर नहीं बढ़ रहा है । हमें याद है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में किन्हीं दो नदियों को जोड़ने की बात या उनकी कार्रवाई पर अमल दिखाई नहीं देता है ।

मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मैं बनारस से आता हूं । हमारे यहां से प्रधान मंत्री जी चुने गए हैं । प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में छोटी-छोटी नदियां हैं ।

वरुणा और गरई नदी है, इसके अलावा तीन-चार और नदियां हैं, यदि इनको गहरा कर दिया जाए तो भूजल में बढ़ोतरी हो सकती है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त करें । सात मिनट हो गए हैं ।

? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : महोदय, मैं दो बातें कहना चाहता हूं ।

दिघवट के पास बादशाही ताल की 100 एकड़ जमीन है, यह जमीन छिछली है । यहां पानी इकट्ठा हो सकता है, यदि इसे गहरा कर दिया जाए । इससे भूगर्भ जल में बढ़ोतरी भी हो सकती है ।

मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के उन नहरों की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां पम्प केनाल के जरिए पानी जाता है । पम्प इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि गंगा नदी से पानी नहीं मिलता है । मेरी मांग है कि इसे गहरा किया जाए । बाढ़ के दिनों में गंगा नदी से जो कटान होते हैं, इससे हजारों फसल खराब हो जाती हैं ।

माननीय सभापति: श्री बापी हलदर I

***m42 श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद) :** सर्वप्रथम, मैं भारत सरकार के पक्ष में अपनी बात रखने का अवसर पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ । आज हम जलशक्ति मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2025 के बजट पर अनुदान की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह बजट हमारे देश के जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है ।

माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व और आर्थिक कुशलता से इस बजट को तैयार किया है । उनके मार्गदर्शन में यह बजट न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि हमारे देश के हर कोने में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस रोडमैप प्रस्तुत करता है । मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि

उन्होंने जल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन को प्राथमिकता दी और इसे जन-जन तक पहुँचाने के लिए प्रभावी योजनाएँ प्रस्तुत की । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' इस बजट में साफ झलकता है । उनके नेतृत्व में जलशक्ति मंत्रालय ने जल संकट से निपटने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं । 'जल जीवन मिशन' इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने ग्रामीण भारत में हर घर तक नल से जल पहुँचाने का संकल्प लिया है । यह मंत्रालय नदियों के संरक्षण, भूजल स्तर को बढ़ाने और जल संचय के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है, और इसके लिए मैं जलशक्ति मंत्रालय की पूरी टीम को बधाई देता हूँ ।

अब बात करें गुजरात की, जो मेरे लिए गर्व का विषय है । इस बजट में गुजरात के लिए जलशक्ति मंत्रालय को विशेष प्रावधान दिए गए हैं । गुजरात, जो कभी जल संकट से जूझता था, आज जल प्रबंधन का मॉडल बन चुका है, और यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि का परिणाम है । बजट में गुजरात के लिए नदियों को जोड़ने, बांधों के रखरखाव और सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है, जो राज्य के किसानों और ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होगा ।

जल शक्ति मंत्रालय के बजट 2025 की प्रमुख विशेषताएँ, हर घर जल योजना, जल जीवन मिशन हैं । आपने उल्लेख किया है कि अब तक 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन मिल चुका है और इस वर्ष इस योजना के लिए 70,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है । हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 12 मार्च 2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.52 करोड़ (80.15%) से अधिक परिवारों को उनके घरों में नल जल आपूर्ति हो चुकी है । इसके अलावा, वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है । बजट आवंटन के संदर्भ में, जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो आपके द्वारा उल्लिखित 70,000 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है ।

नमामि गंगे परियोजना हेतु आपने उल्लेख किया है कि इस बजट में नदियों के पुनरुद्धार एवं जल संरक्षण के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, विशेष रूप से गंगा, नर्मदा, साबरमती जैसी प्रमुख नदियों के संरक्षण के लिए । हालांकि, उपलब्ध स्रोतों में नमामि गंगे परियोजना के लिए विशेष बजट आवंटन के बारे में सटीक आंकड़े नहीं मिले हैं । इसलिए, इस जानकारी की पुष्टि के लिए आधिकारिक बजट दस्तावेजों की समीक्षा आवश्यक होगी । बाढ़ और सूखा नियंत्रण के बारे में आपने बताया है कि बाढ़ प्रभावित और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए 12,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है । हालांकि, उपलब्ध

स्रोतों में इस विशेष आवंटन के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिली है । इसलिए, इस दावे की पुष्टि के लिए भी आधिकारिक बजट दस्तावेजों की जांच आवश्यक होगी ।

जल शक्ति मंत्रालय के इस बजट से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार "हर घर जल", "हर खेत को पानी", और "जल संरक्षण" को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है । इस बजट से न केवल दाहोद जैसे आदिवासी बहुल जिलों का समग्र विकास होगा, बल्कि यह किसानों, ग्रामीण परिवारों और जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा, इसलिए, मैं इस सदन से अनुरोध करता हूँ कि जल शक्ति मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदानों को पूर्ण समर्थन दें, जिससे देश में जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन हो सके और भारत जल समृद्ध राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़े ।

विशेष रूप से दाहोद की योजनाओं की बात करें, तो यह क्षेत्र मेरे दिल के बहुत करीब है । दाहोद, जो गुजरात के पूर्वी हिस्से में बसा एक आदिवासी बहुल जिला है, अब विकास की नई ऊँचाइयों को छू रहा है । इस बजट में दाहोद के लिए जलशक्ति मंत्रालय के तहत कई महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बनाई गई है । यहाँ भूजल स्तर को सुधारने के लिए चेक डैम और तालाबों के निर्माण पर जोर दिया गया है । साथ ही, 'जल जीवन मिशन? के तहत दाहोद के हर गांव में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए विशेष धनराशि आवंटित की गई है । इसके अलावा, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से यहां के किसानों की आय में वृद्धि होगी, जो आत्मनिर्भर भारत के सपने के साकार करने में योगदान देगा ।

गुजरात के लिए इस बजट में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत विशेष योजनाएं शामिल की गई हैं, खासकर दाहोद जिले के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:-

- दाहोद जिले के 1200 से अधिक गांवों में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है ।
- वर्ष 2025 के अंत तक 100 परसेंट ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ।
- बजट में इस योजना के लिए 950 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ।
- दाहोद जिले में कृषि सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।
- पंचमहल-दाहोद लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 350 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है ।
- माही नदी परियोजना के तहत दाहोद में 50,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा जाएगा ।

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए जल पुनर्भरण परियोजनओं में गुजरात के आदिवासी बहुल इलाकों में जल स्तर सुधारने के लिए विशेष योजना लागू की जा रही है ।
- दाहोद में 250 से अधिक जलाशयों का पुनरुद्धार करने के लिए इस बजट में 275 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।
- बोरी बंध परियोजना के तहत वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है ।
- नर्मदा सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत दाहोद जिले में 3 नई पंपिंग स्टेशनों की स्थापना होगी ।
- जल विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए 120 मेगावाट क्षमता की नई परियोजना का बजट में प्रावधान किया गया है ।

यह बजट जलशक्ति मंत्रालय के माध्यम से देश के हर नागरिक तक जल सुरक्षा पहुँचाने का संकल्प लेता है । यह न केवल गुजरात और दाहोद के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए एक समृद्ध और सतत भविष्य की नींव रखता है । मैं भारत सरकार, माननीय वित्त मंत्री जी और हमारे प्रेरणास्रोत प्रधानमंत्री जी को इस शानदार बजट के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR): I am expressing my views on THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 2025-26 FOR THE MINISTRY OF JAL SHAKTI. On this occasion, I also want to thank our beloved Leader Smt. Sonia Gandhi Ji and our Leader of Opposition, Shri Rahul Gandhi Ji for giving me this opportunity to raise various issues.

With regard to Telangana State, I would like to raise some pending issues. Several representations in this regard have been submitted from time to time by our Hon'ble Chief Minister, Shri Anumula Revanth Reddy Garu to take necessary action in the matter which I am going to mention hereunder:-

First and foremost issue is - A letter has been represented to the Hon'ble Prime Minister of India by the Hon'ble Chief Minister of Telangana Vide Letter Ref. No.57/PSCM/2023 dt. 26.12.2023 - Requesting to declare Palamuru- Rangareddy Lift Irrigation Scheme as a National Project. The scheme is an important Irrigation Project for Telangana as it envisages supplying water to drought prone areas of the

State and more than 12 lakh acres besides providing water for drinking and industrial areas.

In this regard, Hydrology, ISM, I.P., Cost Clearance are yet to be cleared from CWC.

Second issue is - Providing drinking water facilities to rural households through Functional Household Tap Connections (FHTCs) under Jal Jeevan Mission for Financial Year- 2024-25 in the State of Telangana.

Third issue is - There is need to Link River Godavari from Mallanna Sagar reservoir with Musi river to provide 5 TMC water to clean river Musi and supply of 15 TMC drinking water to Hyderabad Urban Agglomeration (HUA). In this regard, a proposal was submitted to Jal Shakti Ministry to facilitate the linking of Godavari with Musi to clean river Musi in Telangana State.

Fourth issue is - A proposal was sent to the Ministry of Jal Shakti by our Telangana Government to kindly consider Drinking water project of Godavari Phase-2 either under AMRUT 2.0 or a special project and also requested to sanction Rs.7,400 Crores as financial assistance to take up these projects.

With these few words, I would like to conclude my speech.

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): I thank you for giving me the opportunity to express my views on the Demand for Grants for the Ministry of Jal Shakti for 2025-26. On behalf of my leader and the Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, I would like to appreciate and applaud the vision of our Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, Finance Minister, Smt. Nirmala Sitharaman ji, and Jal Shakti Minister, Sri Gajendra Singh Shekhawat ji, for their unwavering commitment to ensuring water security and sustainable water management across the nation. Under the leadership of the NDA government, India's water sector has seen unprecedented progress, with transformational initiatives such as Jal Jeevan Mission (JJM), which has significantly improved rural water supply by providing tap connections to millions of households; Atal Bhujal Yojana, which has

strengthened groundwater management in critical and over-exploited regions; Namami Gange, which has revitalized and rejuvenated India's sacred rivers; and Mission Amrit Sarovar, which has focused on water conservation and the revival of traditional water bodies. However, despite these commendable efforts, several critical challenges remain in Andhra Pradesh, particularly in the Konaseema district and the broader Godavari basin, requiring urgent attention and adequate budgetary allocations.

I am highlighting the critical gaps in funding and implementation of water resource management in Andhra Pradesh, with a special focus on the Konaseema region. Despite the ambitious targets set under Jal Jeevan Mission (JJM) and other water-related schemes, the state continues to struggle with safe drinking water accessibility, groundwater sustainability, and flood management.

While Jal Jeevan Mission aims to provide functional household tap connections to all rural households, Andhra Pradesh has lagged behind the national average in its implementation. The recent budget allocations reveal a concerning reduction in expenditure under JJM, raising doubts about the timely completion of projects in the state. The Committee on Water Resources has already noted that Andhra Pradesh, along with a few other states, may not achieve full coverage before 2027, extending well beyond the initial 2024 deadline. Moreover, the state's groundwater quality is severely compromised. The Annual Groundwater Quality Report highlights that 23.5% of samples exceed permissible nitrate levels, 27.68% of groundwater is unsuitable for irrigation due to high residual sodium carbonate, and 23 districts report salinity beyond permissible limits. Yet, the state currently lacks mobile water testing laboratories to effectively monitor and address these concerns. This gap leaves communities vulnerable to unsafe drinking water and further delays necessary interventions.

In the Konaseema region, the Godavari delta faces unique and urgent water-related issues. The district is highly prone to flooding, which disrupts access to clean drinking water and damages existing infrastructure. Furthermore, rapid groundwater depletion due to unscrupulous extraction and illegal tapping of supply pipelines has

exacerbated the water crisis. Several peripheral mandals in the constituency still lack functional tap water connections, despite budgetary allocations under JJM.

A key concern in Konaseema is the increasing water pollution from aquaculture farms and untreated waste discharge. Over the past two decades, the region has grappled with the discharge of untreated waste into irrigation canals. This malpractice has led to contaminated water sources, adversely affecting both agriculture and public health. Furthermore, brackish water discharge from aquaculture farms into agricultural canals has exacerbated the situation, contaminating freshwater supplies and threatening paddy cultivation and soil health, thereby jeopardizing the livelihoods of local farmers. This issue needs immediate intervention through stricter regulations and improved wastewater treatment mechanisms.

Additionally, the recurring floods in the Godavari basin pose a severe risk to Konaseema, leading to displacement, infrastructure damage, and water contamination. The government must prioritize flood management programs through measures such as strengthening embankments and modernizing drainage systems to prevent overflow and waterlogging, implementing early warning systems to enhance disaster preparedness, and increasing investments in flood prevention infrastructure, particularly in Konaseema, to mitigate the adverse impact of seasonal floods on water quality and availability.

To address these pressing concerns, I urge the Ministry of Jal Shakti to take the following immediate steps: establish mobile water testing laboratories for real-time monitoring of drinking water quality and groundwater contamination; set up an Electric Defluoridation Plant to combat fluoride contamination in 17 affected districts; strengthen JJM implementation by ensuring full tap water coverage in all mandals, with a special focus on flood-prone and remote areas of Konaseema; regulate industrial and aquaculture waste by preventing direct discharge of pollutants into irrigation canals and implementing sustainable waste treatment solutions; enhance flood management infrastructure by improving embankments, drainage systems, and early warning mechanisms to mitigate flood damage and

water supply disruptions; and develop a comprehensive Godavari Basin Water Management Plan to ensure flood control, sustainable water utilization, and long-term water security for vulnerable districts like Konaseema.

Furthermore, coordination between the Atal Bhujal Yojana and Jal Jeevan Mission in Konaseema is essential for tackling water stress and ensuring long-term sustainability in groundwater management. A well-integrated approach between these flagship schemes will enhance groundwater recharge, prevent depletion, and secure drinking water sources for future generations.

Honourable Speaker, while India is moving towards achieving Har Ghar Jal, it is imperative that the Ministry of Jal Shakti ensures targeted interventions in vulnerable districts like Konaseema. I urge the Honourable Minister to allocate adequate resources, expedite project implementation, and adopt a more integrated approach to ensure a resilient and sustainable water future for Andhra Pradesh.

Thank You.

***m45 श्री दुलू महतो (धनबाद) :** आज हम यहां वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं । जल शक्ति मंत्रालय का उद्देश्य देशभर में जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन और संरक्षण करना है, ताकि सभी नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके । जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और जल संकट की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक योजनाओं की शुरुआत की है । वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित अनुदान का मुख्य उद्देश्य इन योजनाओं को साकार करना और जल संकट से निपटने के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करना है ।

अब मैं अपने संसदीय क्षेत्र धनबाद से संबंधित कुछ मांगों को आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहूँगा ।

1. तोपचांची डेम की सफाई और पुनर्वासः

आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि तोपचांची झरिया वाटर बोर्ड डेम, जिसे तोपचांची डेम के नाम से जाना जाता है, का निर्माण वर्ष 1915 से 1924 के बीच 559 हेक्टेयर और छह किलोमीटर की परिधि में किया गया था । इस झील की गहराई निर्माण के समय 72 फीट थी । दुर्भाग्यवश, इस डेम में दिन प्रतिदिन गाद भरते जाने के कारण जल स्तर कम हो रहा है, और

इसमें लगभग 30 फीट तक गाद जमा हो चुकी है । यह गाद निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे डेम का जल स्तर घट रहा है । इस डेम का जल दूर-दूर तक सप्लाई किया जाता है, और यह जल पीने योग्य है । धनबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस डेम से जल सप्लाई की जाती है. वो भी बिना किसी मोटर व वाटर पंप के । हालांकि, डेम में पानी कम होने के कारण लाखो लोग प्रभावित हो रहे हैं ।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि तोपचांची डेम की सफाई और उसका पुनर्वास किया जाए, ताकि जल स्तर बढ़ सके और गर्मी के दिनों में जल संकट से बचा जा सके ।

इसके अतिरिक्त, गर्मी के मौसम में हर साल पूरे धनबाद जिले में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है । इस समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि जिला के नागरिकों को जल संकट से निजात मिल सके ।

2. मैथन और पंचेत जलाशय से जल आपूर्ति का सुधारः

धनबाद के कुछ क्षेत्रों जैसे निरसा, सिंदरी और आसपास के इलाके पानी की कमी से जूझ रहे हैं । खासकर गर्मी के महीनों में इन क्षेत्रों में जल संकट चरम पर पहुँच जाता है । अगर मैथन जलाशय का पानी पूरी तरह से धनबाद, निरसा, और सिंदरी क्षेत्र में मिलाया जा सके, तो इस समस्या का स्थायी समाधान संभव हो सकता है ।

मैथन जलाशय से पानी की आपूर्ति मैथन जलाशय, जो धनबाद जिले के समीप स्थित है, का पानी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में आपूर्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

हालांकि, वर्तमान स्थिति में मैथन जलाशय का पानी कुछ क्षेत्रों तक पहुँचता तो है. लेकिन पानी का दबाव (प्रेशर) पर्याप्त नहीं होता है, जिससे पानी घरों तक नहीं पहुँच पाता है । इसलिए, इस समस्या को दूर करने के लिए जलापूर्ति प्रणाली में सुधार और जल आपूर्ति के दबाव को बढ़ाने की आवश्यकता है. ताकि हर घर तक पानी आसानी से पहुँच सके ।

3. पंचेत जलाशय का महत्वः

पंचेत जलाशय का निर्माण मुख्य रूप से सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए किया गया था । यह जलाशय धनबाद और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, खासकर जब अन्य जल स्रोत सूख जाते हैं । पंचेत जलाशय का पानी आसपास के क्षेत्रों में पीने के पानी

के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे जल संकट को काफी हद तक दूर किया जा सकता है ।

जल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति वर्तमान में, पंचेत जलाशय से पानी की आपूर्ति कुछ क्षेत्रों तक पहुँचती है, लेकिन यह पूरी तरह से प्रभावी नहीं है । पानी का दबाव (प्रेशर) और वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, ताकि जल आपूर्ति सही तरीके से घरों तक पहुँच सके । कई बार देखा गया है कि जलाशय से पानी पहुंचता तो है, लेकिन प्रेशर की कमी के कारण वह उचित तरीके से उपयोग में नहीं आ पाता है ।

सुधार की आवश्यकताः पंचेत जलाशय से पानी की आपूर्ति को सटीक और प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है । इनमें शामिल हैं ।

1. जल आपूर्ति नेटवर्क का विस्तार और सुधारः जल आपूर्ति नेटवर्क को और विस्तृत किया जाए, ताकि पंचेत जलाशय का पानी अधिक से अधिक क्षेत्रों में पहुँचा सके । इसके लिए नए पाइपलाइनों और टंकी की व्यवस्था की जा सकती है ।

2. प्रेशर बढ़ाने के उपाय: जल आपूर्ति के दबाव (प्रेशर) को बढ़ाने के लिए पानी की आपूर्ति प्रणाली में सुधार किया जाए । पानी की पाइपलाइन में पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया जा सकता है, जिससे पानी का प्रेशर सही स्तर पर बने रहे और वह घरों तक आसानी से पहुँच सके ।

3. स्टोर टैंक और जलाशयों का निर्माणः जगह-जगह छोटे स्टोर टैंक और जलाशय बनाए जाएं. जहां पानी एकत्रित किया जा सके, ताकि जरूरत के समय इसका उपयोग किया जा सके ।

4. जल प्रबंधन योजनाः पंचेत जलाशय से पानी की आपूर्ति के लिए एक ठोस जल प्रबंधन योजना बनाई जाए, जिसमें जल के वितरण की प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाएं । खासकर गर्मी के महीनों में जब जलाशय का स्तर कम हो जाता है, तब जल आपूर्ति का उचित प्रबंधन आवश्यक है ।

4. जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन में सुधारः

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान जल जीवन मिशन के तहत धनबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हर घर नल कनेक्शन की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करना

चाहता हूँ । वर्तमान में, इस योजना के तहत कई घरों को नल कनेक्शन प्रदान किया गया है, लेकिन जल आपूर्ति की गुणवत्ता और दबाव में निरंतर कमी देखी जा रही है ।

कई स्थानों पर या तो जल आपूर्ति अत्यधिक कम दबाव में हो रही है, या फिर बिल्कुल भी आपूर्ति नहीं हो रही है । इस स्थिति के कारण स्थानीय निवासियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. और उन्हें पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है । जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर को गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र एक विस्तृत निरीक्षण किया जाए ताकि जल आपूर्ति में सुधार किया जा सके और स्थानीय जनता को पर्याप्त जल मिल सके ।

5. पर्यटन स्थल के रूप में मैथन, पंचेत और तोपचांची का विकासः

इसके साथ-साथ मेरा आग्रह है कि पर्यटन स्थल के रूप में मैथन, पंचेत और तोपचांची का विकास किया जाए । इन स्थानों की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्त्व को देखते हुए यहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है । इससे न केवल पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे ।

धनबाद जिले के इन इलाकों में पर्यटन के विकास से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं में भी वृद्धि होगी । इससे गांवों में रहने वाले लोगों को आय के नए स्रोत मिलेंगे और उनकी जीवन-स्तर में सुधार होगा ।

महोदय, जल संकट एक वैश्विक समस्या है और इससे निपटने के लिए हमें सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है । वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय का प्रस्तावित अनुदान इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है । मुझे विश्वास है कि इस अनुदान मांगों से हमारे देश में जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और संरक्षण संभव होगा ।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जल शक्ति मंत्रालय से सम्बंधित हमारी मांगों पर अवश्य विचार करके हमारे संसदीय क्षेत्र के निवासियों को कृतज्ञ किया जाए ।

धन्यवाद ।

***m46 श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर (बनासकांठा) :** केन्द्रीय बजट 2025-2026 के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ । महोदय जल का महत्व हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण है कहा जाता है की जल ही जीवन है लेकिन आज

कुछ लोगों द्वारा जल आम लोगों तक पहुंचाने के बजाय इसमे भ्रष्टाचार किया जा रहा है । उदाहरण के लिए गुजरात राज्य समेत सम्पूर्ण देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल योजना मे पानी सप्लाई करने के लिए यहाँ पर प्राइवेट ऑपरेटर रखा गया है जिससे इस कार्य में काफी मात्रा में भ्रष्टाचार की सूचना आ रही है मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि पानी सप्लाई के लिए सरकारी ऑपरेटर रखा जाय जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है । मेरे क्षेत्र बनासकांठा के दाँता तालुका एवं वाव तालुका जो की अन्तराष्ट्रिय सीमा क्षेत्र है मे पानी की कमी है यहाँ पर पानी पहुंचाने की उचित व्यवस्था किया जाय तथा सरकार द्वारा बारिश के पानी को संचय करने की ब्यवस्था किया जाय कई जगहों पर देखा जाता है कि लोग बारिश का संचय करने के लिए ग्राउंड टंकी बनाते है अगर ऐसे सरकार द्वारा बनाया जाता है तो पानी के कमी को दूर किया जा सकता है ।

धन्यवाद,

SUSHRI PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE (SOLAPUR): The underutilization of funds and inefficiencies in the implementation of the schemes of the Ministry of Jal Shakti have been constant issues. The revised estimate for 2024-25 was 48% lower than the budgeted allocation. This was mainly due to reduced allocation to the Jal Jeevan Mission (JM).

Regarding JJM, the scheme's targets have not been met, leading to an extension of the deadline to 2028. As of January 2025, 15 crore households have been covered under JJM, with many households still remaining. The Standing Committee on Water Resources (2024) observed that under the JJM, certain surveys were carried out without physically visiting households. This resulted in inaccurate data reporting and the exclusion of numerous households.

According to a 2022 functionality assessment of JJM, only 62% rural households had fully functional tap connections (ie. working taps with adequate and regular water supply). Also, the quality of water remains a pressing issue. The Pey Jal Survekshan, last year, highlighted that only 46 cities out of the 485 AMRUT cities had good water quality.

Some of the issues affecting Solapur-

Solapur has been facing severe water scarcity, affecting both rural and urban populations. A semi-arid climate, irregular rainfall, and over extraction of groundwater have worsened the crisis. The Standing Committee on Water Resources also raised concern about groundwater depletion.

There is a need for timely maintenance and repair of water bodies in the constituency, including at Huljanti, Mangalwedha. Regular desilting, cleaning, and reinforcement of embankments can help maintain water quality and storage capacity of these bodies. Additionally, the government must implement robust monitoring mechanisms to identify potential risks early and allocate sufficient resources for repairs when needed.

The government should consider removing the Rs.20 lakh cap on public works under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) to enhance the scope and effectiveness of developmental activities, particularly in the area of water conservation and maintenance of water bodies.

A significant portion of the public works carried out under MGNREGA focuses on improving water infrastructure, such as desilting ponds, constructing check dams,strengthening embankments, and restoring traditional water sources. These activities are crucial for ensuring water security, improving agricultural productivity, and supporting livelihoods in rural areas. However, the current financial cap of Rs.20 lakh severely limits the scale and impact of such projects.

The Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) facility in Solapur constituency has been associated with the release of untreated industrial effluents, leading to significant environmental and public health concerns.
The effects linked with the discharge of such untreated effluents are highly detrimental to the local water bodies, ultimately posing a significant threat to the local environment and people. The underground water has been polluted because of this. In agriculture, contaminated water used for irrigation has led to the potential uptake of toxins into the food chain. Furthermore, soil quality degradation due to the accumulation of pollutants reduces agricultural productivity.

The persistent issue of untreated effluent discharge by MIDC highlights an urgent need for the government to enforce stricter environmental regulations and mandate the implementation of effective effluent treatment solutions. It is imperative for authorities to act decisively to ensure that industrial activities do not jeopardize the health and well-being of local communities or harm the environment.

Given the various challenges faced in water conservation, and maintenance of water bodies, it is concerning that there has been persistent underspending in the Ministry's schemes. In the financial year 2024-25, only 31% of the allocated central share under JJM had been released as of February 2025. This underutilization of funds hampers the effective implementation of crucial projects, delaying essential maintenance work and limiting efforts to address water scarcity and rural development.

श्री कुलदीप इंदौरा (गंगानगर) : सभापति जी , हरिके बैराज से निकलने वाली इंदिरा गांधी फीडर की कुल लम्बाई 204 कि.मी है जिसमें से 151 कि.मी पंजाब में व शेष 53 कि.मी हरियाणा व राजस्थान में स्थित है । इंदिरा गाँधी फीडर की आर डी से आर की 179 तक की जर्जर नहर के रिलाईनिंग कार्य को अभी तक स्वीकृती भी नहीं मिली है जबकि इंदिरा गाँधी फीडर की (आर डी 179 से 670) कुल 150 कि.मी लम्बाई में रिलाईनिंग का कार्य स्वीकृत हुआ था जिसमें से आर डी 179 से 496 तक रिलाईनिंग का कार्य पंजाब द्वारा व आर डी 496 से 671 तक राजस्थान द्वारा करवाया जाना था । राजस्थान द्वारा आर डी 496 से 671 तक की रिलाईनिंग का कार्य करवा दिया गया है परन्तु पंजाब के हित्ते में लगभग 11 कि.मी रिलाईनिंग का कार्य शेष है । इंदिरा गाँधी फीडर जर्जर होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से इसमें निर्धारित क्षमता 18500 क्यूसेक के स्थान पर 12000 क्यूसेक चाल प्रवाहित किया जाता है । इससे राजस्थान राज्य को नुकसान उठाना पड़ता है । वर्षा के समय आने वाले अतिरिक्त पानी को इंदिरा गाँधी फीडर जर्जर होने के कारण पाकिस्तान की ओर छोड़ना पड़ता है । यदि इंदिरा गांधी फीडर की पंजाब में पूर्ण रिलाईनिंग हो जाती है तो पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी राजस्थान के किसानों के उपयोग में आ सकता है । इसलिए केन्द्र सरकार ध्यान देते हुए शीघ्रातिशीघ्र इस वर्ष में ही पंजाब में इंदिरा गाँधी फीडर की शेष 11 कि.मी में रिलाईनिंग का कार्य पूर्ण करवाए तथा इंदिरा गाँधी फीडर की आर डी 0 से आर डी 179 तक रिलाईनिंग का प्रारम्भ कार्य करवाए जिससे फीडर में निर्धारित क्षमता के अनुसार जल प्रवाहित हो सके ।

पौंग बाँध की कुल क्षमता 1400 फीट है तथा इसको 1390 फीट तक भरा जाता है । इसका कारण यह है कि बाँध के दूब क्षेत्र में कुछ विस्थापित मुआवजा प्राप्त करने के पश्चात् भी यहाँ पर कृषि कर रहे हैं । उनकी सुरक्षा को देखते हुए पौंग बाँध को 10 फीट कम भरा जाता है जिससे राजस्थान के किसानों को नुकसान होता है । अतः केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप कर पौंग बाँध को पूर्ण क्षमता तक भरने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए ।

काफी वर्ष पूर्व इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के पूर्ण निर्माण से पहले राजस्थान द्वारा अपने आवंटित जल 8.60 MAF में से 0.60 MAF पंजाब को इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के पूर्ण निर्माण तक अस्थाई तौर पर उपयोग करने हेतु सहमति दी गई थी । आज दिनांक चूक इस 060 MAF पानी को पंजाब द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है । राजरथान को यह 0.60 MAF पानी की मात्रा नहीं मिल रही है । केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप कर राजस्थान को हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध करवाने हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ।

BBMB बोर्ड में राजस्थान को सचिव पद दिया गया था लेकिन अब तक कोई स्थाई नियुक्ति नहीं हुई है । इससे राजस्थान को अपने जल अधिकारों की उचित पैरवी करने का मंच नहीं मिल पा रहा है । केन्द्र सरकार को राजस्थान के अधिकारी की नियुक्ति कर प्रतिनिधित्व का भौका देना चाहिए ।

फिरोजपुर फीवर व इससे निकलने वाली बीकानेर कैनाल की जर्जर स्थिति के कारण राजस्थान को पूर्ण जल आपूर्ति नहीं हो पा रही । है । पानी का रिसाव बढ़ने से जल हानि हो रही है और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल नहीं पहुँच पा रहा । इनकी रिलाईनिंग के लिए DPR तकनीकी कमेटी में प्रस्तुत की जा चुकी है परन्तु अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है । केन्द्र सरकार को शीघ्रातिशीघ्र DPRस्वीकृत करवाकर रिलाईनिंग का कार्य पूर्ण करवाना चाहिए ।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) जिसका नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है, राजस्थान के 13 जिलों को पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित है, लेकिन यह परियोजना धीमी गति से चल रही है । परियोजना की धीमी प्रगति से इन जिलों में औद्योगिक और पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है । जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को त्वरित गति से पुर्ण करने हेतु प्रयास करने

चाहिए।

यमुना जल समझौता (1994) के तहत राजस्थान को ताजेवाला हैड से यमुना नदी से 1950 क्युसेक पानी मिलना प्रस्तावित हुआ था जिसकी दो बार DPR बन चुकी है परन्तु धरातल पर

कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । अब जबकि दोनों राज्यों व केन्द्र में समान दल की सरकार है इसलिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस मामले का संज्ञान लेकर निर्माण कार्य प्रारम्भकरवाने हेतु प्रयास करने चाहिए ।

जल जीवन मिशन में इंदिरा गाँधी मुख्य नहर की आर डी 507, आर डी 750, आर डी 1120 व आर डी 1350 पर जलाशयों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित था । इन कार्यों की गति बहुत धीमी है । वर्षा के समय इंदिरा गाँधी मुख्य नहर में प्रवाहित अतिरिक्त जल को इन जलाशयों में संचय करना संभव नहीं हो सका । इन कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण करवाकर जल संचय की व्यवस्था करना अति आवश्यक है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हो सके ।

सभापति, बुढा दरिया का इतिहास और वर्तमान - पहली पातशाही श्रीगुरुनानक देव जी सन 1515 सतलुज नदी से बुढा दरिया अलग हुआ यह बुढा दरियाका ऐतिहासिक धार्मिक महत्व है ।

बुढा दरिया जिसे अब बुढा नाला कहा जाता है. लुधियान ताजपुर रोड (इण्डस्ट्रीयल एरिया) में लगी काई फैक्ट्रियों का अपशिष्ट कैमिकल युक्त दूषित पानी एवं कई शहरों के सीवरेज का पानी आज लुधियाना शहर के 60 किमी एरिया से गुजरता हुआ भूडरी-वलिपुर गांव से सतलुज नदी में मिलता है ।

सतलुज व्यास नदियों का संगम हरिके पतन बैराज पर होता है । हरिके बैराज से ही राजस्थान को तीन नहरों से पानी मिलता है । क्रमश: इन्दिरागांधी नहर परियोजना, भांखड़ा नहर परियोजना और गंग नहर । गंग नहर से सिंचाई पानी पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर जैसलमेर और बाडमेर तक पहुंचता है ।

बुढा दरिया के माध्यम से आ रहे अपशिष्ट दूषित पानी को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब प्रदूषण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदुषण बोर्ड की रिपोट पर सख्त एक्शन लेते हुये बूढ़ा दरिया की सफाई के लिये एक्शन प्लान तैयार करने के आदेश दिये गये जिस पर लुधियाना नगर निगम एवं पंजाब सिंचाई विभाग ने 30 जून 2020 तक सभी सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट अपग्रेड करने का एक्शन प्लान बनाया, जिस पर काम आधा भी नहीं हुआ है. जो हुआ उसकी देखरेख नहीं होने से स्थिती और खराब हो गयी ।

सीमान्त पश्चिमी राजस्थान हर शहर में कैंसर, किडनी खराब, पीलिया की गम्भीर बिमारियों के मरीज बढ़ रहे है । गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे जन्म लेते ही मर रहे है

।

भारतीय परम्परा अनुसार नदियों को मां का दर्जा प्राप्त है । सतलुज दरिया -सतयुग का प्राय है राम तेरी गंगा मेली हो गयी वही हाल आज सतलुज नदी का हो गया है । जल है तो जीवन है । परन्तु आज यही अपशिष्ट दूषित पानी जानलेवा बन गया है ।

स्वच्छ जल मानव ही नहीं अपितु पशु पक्षियों और जानवरों का भी अधिकार है । स्वच्छ जल एवं सुरक्षित पेय अधिनियम 1972 के तहत बिना परमिट के किसी बिन्दु स्त्रोत से प्रदूषण को छोडना अवैध कृत्य है ।औधोगिक अपशिष्ट जल नदियों, झीलो, धाराओं के लिये विशाक्त पदार्थ और बेक्टिीरिया को हटाने के लिये उपचारित किया जावें । यह कानून अमेरिका में जल प्रदूषण को नियत्रित करने का प्राथमिक कानून है ।

सतलुज नदी में आ रहे अपशिष्ट दूषित पानी से सीमान्त पश्चिमी राजस्थान में 2 करोड और दक्षिणी पंजाब के करोड़ लोग भयकर बिमारियों से ग्रस्त है । हर घर की चौखट पर मौत दस्तक दे रही है और सरकारें नाकाम होकर रह गयी है । प्रदुषित पानी को रोकने के लिये श्रीगंगानगर जिले की मण्डियां 9 नवम्बर 2024 को पूर्णतया बन्द रही और 3 दिसम्बर को लुधियाना में जबरदस्त प्रर्दशन हुआ ।

***m49 श्री भजन लाल जाटव (करौली-धौलपुर) :** मैं जल जीवन मिशन (JJM) और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ । सबसे पहले, जल जीवन मिशन (JJM) की बात करते हैं । सरकार ने 2024-25 में राजस्थान में 25 लाख नल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन मात्र 10 लाख कनेक्शन ही लगाए गए । जब यह तथ्य हमने सामने रखा, तो मंत्री जी ने स्वीकार किया कि कुछ क्षेत्रों में एक कनेक्शन की लागत 4-5 लाख रुपये तक आती है । जब हमने पहले यह बात कही थी, तब आप अनर्गल आरोप लगाते थे । लेकिन अब आप खुद मान रहे हैं कि स्थिति कठिन है । मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर राजस्थान के लिए JJM में स्पेशल ग्रांट देने और समय बढ़ाने की मांग की थी, जिसका आपकी पार्टी ने विरोध किया । लेकिन अब आप समय बढ़ाने के लिए मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं ।

आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि 2022-23 में हमारी सरकार ने 13.88 लाख कनेक्शन किए, जबकि 2024-25 में आपकी सरकार मात्र 9.09 लाख कनेक्शन कर पाई । देशभर में JJM धीमी गति से चल रहा है क्योंकि इसे राज्यों पर बिना सोचे-समझे थोपा गया है ।

अब ERCP एवं यमुना जल समझौते की बात करें । यमुना जल समझौता, जिसे सत्ता पक्ष ने बड़ी उपलब्धि बताया, वास्तव में 1994 में ही तय हो चुका था, जिसमें राजस्थान को 1190 MCM पानी मिलना था । लेकिन आपके हालिया समझौते में ये घटकर 577 MCM रह गया । ERCP को लेकर आपकी सरकार ने MoU के बारे में जानकारी देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है । इसके बावजूद, MoU को चुपके से National Water Development Agency की वेबसाइट पर डाल दिया गया ।

असली समस्या यह है कि मध्य प्रदेश अपस्ट्रीम में है और उसकी प्राथमिकता पहले पूरी होगी । अगर कुछ पानी बचेगा तभी राजस्थान को मिलेगा । यह भी स्पष्ट है कि आपकी सरकार के MoU के तहत मध्य प्रदेश को 3120 MCM पानी मिलेगा और वहाँ 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी, जबकि राजस्थान का क्षेत्र बड़ा होने के बावजूद उसे कम पानी मिलेगा ।

आपकी सरकार ने यह भी दावा किया कि ERCP के लिए 90% फंडिंग भारत सरकार देगी । लेकिन जब हमने पूरा बजट देख लिया, तो कहीं भी ERCP के लिए कोई धन का प्रावधान नहीं था ।

यह जनहित का मुद्दा है और यह स्पष्ट है कि इस MoU में राजस्थान के हितों की अनदेखी की गई है । मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि वह स्पष्ट करें कि क्या यह समझौता वास्तव में राजस्थान के हित में है या नहीं । यदि नहीं, तो सरकार को राज्य के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए ।

1. अपूर्ण कार्य और धीमी प्रगतिः कई गांवों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य अधूरा पड़ा है । जहां नल लगाए भी गए हैं, वहां भी जल की नियमित और निरंतर आपूर्ति नहीं हो रही है । कई स्थानों पर पानी के कनेक्शन सिर्फ दिखावे के लिए हैं ।

2. खराब गुणवत्ता का पानीः

अनेक क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता की जांच नहीं की जा रही है । लोगों को गंदा और अशुद्ध पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है ।

3. भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमीः

इस योजना में ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच मिलीभगत की घटनाएं सामने आ रही हैं । बिना काम किए भुगतान कर दिए जा रहे हैं और योजनाओं का ठेकेदारों द्वारा दुरुपयोग किया

जा रहा है ।

4. अपर्याप्त बजट और संसाधनः

सरकार द्वारा इस योजना के लिए आवंटित बजट आवश्यकता के मुकाबले बहुत कम है । बजट का सही उपयोग न होने के कारण कई जगहों पर काम ठप पड़ा है ।

5. लोगों की समस्याओं की अनदेखीः

सरकार ने योजना की शुरुआत तो कर दी, लेकिन आम जनता की समस्याओं को सुनने और समाधान करने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है ।

6. अनियोजित क्रियान्वयनः

योजना के क्रियान्वयन में समन्वय और प्रबंधन की गंभीर कमी है । कई गांवों में पाइपलाइनें तो बिछा दी गईं, लेकिन जल स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई ।

7. वित्तीय अनियमितताएं:

विभिन्न जिलों से वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट आ रही हैं । ठेकेदारों को दिए गए पैसे का उपयोग गलत ढंग से किया जा रहा है, और कई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं ।

8. जनता में जागरूकता की कमीः

सरकार ने योजना को लागू तो कर दिया, लेकिन लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कोई प्रभावी अभियान नहीं चलाया । इससे लोग योजना के लाभों से वंचित रह रहे हैं ।

9. समीक्षा और मॉनिटरिंग की कमीः

योजना की प्रगति का आकलन करने और आवश्यक सुधार लाने के लिए कोई ठोस और पारदर्शी प्रणाली नहीं बनाई गई है । सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी में उलझी हुई है ।

SHRI ANUP SANJAY DHOTRE (AKOLA): I express my views on Demand for Grants for the Jal Shakti Ministry.

As we gather here today, our nation faces significant challenges in ensuring access to clean water and sanitation for all citizens. The Jal Shakti Ministry plays a vital

role in addressing these challenges, and it is our responsibility to provide the necessary resources to support its efforts.

The Demand for Grants for the Jal Shakti Ministry for the year 2024-25 focuses on several key areas, including:

Jal Jeevan Mission: Providing clean drinking water to every household in rural areas.

Swachh Bharat Mission: Ensuring sanitation and hygiene in rural and urban areas.
Water Conservation: Promoting efficient use of water resources and reducing waste.
These initiatives require significant investment, and I urge the government to allocate sufficient funds to support the ministry's efforts. I request that the Demand for Grants be approved, enabling the Jal Shakti Ministry to continue its vital work.

As we consider this Demand for Grants, I would like to emphasize the importance of transparency and accountability in the allocation and utilization of funds. As members of Parliament, it is our duty to ensure that the funds allocated are used efficiently and effectively to achieve the intended objectives.

For Akola, Maharashtra, I propose the following key initiatives:

We must ensure effective implementation of the Jal Jeevan Mission, providing functional household tap connections to every rural household in Akola. This will significantly improve access to clean drinking water for our citizens.

To address water scarcity issues in Akola, we must implement water conservation measures, such as rainwater harvesting and watershed development. This will help reduce our reliance on groundwater and promote sustainable water management practices.

Restoring and renovating traditional water bodies, such as ponds and lakes, is crucial to increase water storage capacity and recharge groundwater levels. This will not only improve water availability but also support biodiversity and ecosystem services.

Improving drinking water quality in Akola is essential, and we must establish water testing laboratories and implement measures to reduce contamination. This will ensure that our citizens have access to safe and clean drinking water.

Developing sanitation and hygiene infrastructure, including individual household toilets and community toilets, is critical to achieving Open Defecation Free status in Akola. We must prioritize this initiative to improve public health and hygiene.

Flood control and management measures, such as river embankments and flood protection walls, are necessary to protect Akola from frequent floods. We must invest in these measures to safeguard our citizens and their properties.

To address declining groundwater levels, we must implement groundwater recharge and management measures, such as artificial recharge structures and groundwater monitoring systems.

Implementing watershed development and soil conservation measures, such as contour bunding and terracing, will reduce soil erosion and improve water retention.

Providing capacity building and training programs for stakeholders, including government officials, gram panchayats, and community members, is essential to ensure effective implementation of Jal Shakti schemes.

Finally, we must establish a robust monitoring and evaluation mechanism to track progress, identify gaps, and make necessary adjustments to ensure successful implementation of Jal Shakti schemes in Akola.

I urge the government to allocate sufficient funds to support these initiatives and ensure that the Jal Shakti Ministry has the necessary resources to address the water and sanitation challenges facing Akola.

I conclude by urging my fellow members to support the Demand for Grants for the Jal Shakti Ministry, and I request the government to provide the necessary resources to support the ministry's efforts to ensure access to clean water and sanitation for all citizens.

SHRI YADUVEER WADIYAR (MYSORE): Thank you very much for allowing me to express my views on a very important matter regarding the Demand for Grants for the Ministry of Jal Shakti. The Ministry of Jal Shakti and its demand for grants is amongst the most important matters when allocating of Budget, as it deals directly with the fundamental need of every human of access to clean and pure Wafer, furthermore, the Ministry also deals with the important matter of ensuring that our rivers and other sources of water, are also kept clean and conserved in a manner befitting the aspirations of modern India.

Under the Modi led governments, Jal Shakti has received a tremendous boost, especially, with innovative policy framework such as the Jal Jeevan Mission. Additionally, the impetus given to cleaning of our rivers and ensuring that clean drinking water is available to all is a particularly laudable initiative of the Modi led governments.

Given the need to conserve time, I would like to focus on the needs and priorities of our state, Karnataka. As we all know, water is not just a basic necessity, it is the lifeblood of our agricultural, industrial, and social ecosystems. Karnataka, with its vast agricultural landscape, rapidly urbanizing cities, and diverse climatic conditions, faces unique challenges and opportunities in water management. It is imperative that we address these challenges through strategic planning and targeted investments.

Addressing the Water Crisis in Karnataka has been facing recurring droughts, fluctuating rainfall patterns, and depleting groundwater levels. The districts of northern Karnataka, in particular, are grappling with severe water scarcity. These regions, which are primarily dependent on rain-fed agriculture, suffer from unpredictable monsoons and erratic rainfall, affecting the livelihood of millions. The demand for grants for 2025-26 seeks to prioritize the revival of irrigation systems, the construction of new reservoirs, and the recharging of groundwater tables in these vulnerable areas. We must urgently focus on augmenting the capacity of water bodies through integrated watershed management practices, ensuring that our farmers, who are the backbone of our state, have access to reliable irrigation and

water for drinking. The Atal Bhujal Yojana in particular requires urgent reviewing as the state has not fully utilized the opportunities available in this scheme to revive and conserve our groundwater.

Support for the Jal Jeevan Mission (JJM) Karnataka has made significant progress in the implementation of the Jal Jeevan Mission (JJM), aiming to provide tap water to every rural household. However, there remains a gap in certain regions where accessibility and infrastructure are still lacking. The demand for grants in 2025-26 includes critical support to bridge these gaps by expanding water distribution networks and providing adequate drinking water infrastructure in underserved areas, especially in tribal and backward regions of Karnataka. This will especially benefit my constituency, as Kodagu being a very hilly terrain has faced issues in the past of incomplete connections and delays in infrastructure related to the Jal Jeevan Mission.

I would also like to add that strengthening community participation in the management of water resources, empowering local bodies to take ownership of water supply systems, and ensuring that water quality is regularly monitored will ensure that the community is an active stakeholder. This will not only enhance secess to water but also ensure its sustainability in the long term.

Water Quality and Pollution Control Water quality is an issue that requires our urgent attention. In Karnataka, rivers such as the Krishna, Cauvery, and Tungabhadra are crucial for both drinking water and agriculture. However, industrial and domestic waste, as well as the over-extraction of water, have led to severe degradation in water quality. Over 17 rivers have overly polluted stretches, including the 1 akshman Tirtha, which flows in my constituency. The demand for grants includes substantial support for the Namami Cauvery Programme and other river rejuvenation projects, aimed at cleaning and restoring these vital water sources, which will be a big boost. It is a matter of pride that the Cauvery originates in my constituency and this policy will ensure that the river continues to be the life-force for our people. A dedicated effort is required to improve wastewater treatment

infrastructure will ensure that our rivers, lakes, and groundwater remain clean and safe for consumption.

Harnessing Water from Rainfall: Rainwater Harvesting and Storage
Given Karnataka's reliance on the monsoon and the challenges posed by fluctuating rainfall, rainwater harvesting remains a vital component of our strategy for water conservation. The 2025-26 demand for grants will focus on enhancing state-wide efforts for rainwater harvesting infrastructure, particularly in urban areas like Bengaluru, which faces increasing pressure on its water resources due to rapid population growth.

Promoting Sustainable Water Use in Agriculture, Agriculture in Karnataka, especially in the drought-prone regions, is highly dependent on water availability. To ensure the long-term sustainability of farming practices, the demand for grants emphasizes investment in micro-irrigation systems like drip and sprinkler irrigation, which can drastically improve water use efficiency. Karnataka has already seen positive results from schemes like the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), and continued funding for such programs is essential for extending irrigation to small and marginal farmers.

Urban Water Supply and Distribution Karnataka's urban centers, particularly Bengaluru, and sometimes even my hometown of Mysore, face water supply challenges due to a rapidly growing population, industrialization, and urbanization. The demand for grants will include enhanced funding for urban water supply systems, ensuring that cities across Karnataka have the necessary infrastructure to meet their water needs. This includes improving wastewater treatment facilities, recycling of water, and better management of urban water distribution networks.

Incentivizing Water-Efficient Technologies and Public Awareness The future of water security in Karnataka lies not just in infrastructure but also in the adoption of innovative technologies and the promotion of public awareness about water conservation. The demand for grants for 2025-26 seeks to support the promotion of water-efficient technologies and encourage the private sector, farmers, and local

communities to adopt sustainable water use practices. Awareness campaigns will be essential in educating citizens on the importance of water conservation, especially in urban areas where water consumption per capita is higher. Honorable Speaker and esteemed colleagues in conclusion, Karnataka is at a critical juncture in its water management journey. The demand for grants in the Ministry of Jal Shakti for 2025-26 is not just about addressing the immediate water needs of our state but also about ensuring that future generations inherit a sustainable and resilient water supply. The investments we make today will determine whether Karnataka remains a thriving agricultural powerhouse and an economically vibrant state.

Thank you.

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Thank you for the opportunity. Ever since the ministry of Jal Sakthi was created in 2019, the problem of the supply of sufficient quantities water for both Drinking and Irrigation has been going high. The government has done nothing to address the issues of inter state water sharing problems.

The government which says One Nation one Election or one Nation one Ration Card...But not speak any thing like One Nation One River...le. The Nationalisation of Rivers and the linking of Himalayan rivers with Peninsular rivers was not initiated.

Coming to this budget, The Ministry of Jal Shakti, has been allocated Rs 99,503 crore in budget 2025-26. While this figure appears substantial, a closer examination reveals a landscape riddled with inefficiencies, underachievement, and systemic issues that demand immediate attention and reform.
Sir, Water can create peace or spark conflict. History will teach us many lessons and many important factors that are very essential for peaceful, progressive and productive Nation. When water is scarce or polluted, or when people have unequal, or no access, tensions can rise between communities and countries.

More than 3 billion people worldwide depend on water that crosses national borders. Yet, only 24 countries have cooperation agreements for all their shared

water. The plight of lower riparian States in the inter-state water sharing is precarious and often end with protest and pandemonium.

As climate change impacts increase and populations grow, there is an urgent need, within and between countries, states to unite around protecting and conserving our most precious resource, Water.

Public health and prosperity, food and energy systems, economic productivity and environmental integrity all rely on a well-functioning and equitably managed water cycle.

When we cooperate on water, we create a positive ripple effect fostering harmony. generating prosperity and building resilience to shared challenges.
We must act upon the realization that water is not only a resource to be used and competed over - it is a human right, intrinsic to every aspect of life.Today we all need to unite around water and use water for peace, laying the foundations of a more stable and prosperous tomorrow.

Trans-boundary waters account for 60 per cent of the world's freshwater flows, and 153 countries have territory within at least 1 of the 310 trans-boundary river and lake basins and inventoried 468 trans-boundary aquifer systems.

Water-related disasters have dominated the list of disasters over the past 50 years and account for 70% of all deaths related to natural disasters.
Prosperity and peace rely on water. As nations manage climate change, mass migration and political unrest, they must put water cooperation at the heart of their plans.

The issue of water tenure affects social cohesion and peace among different water users. Water can lead us out of crisis. We can foster harmony between communities and countries by uniting around the fair and sustainable use of water from United Nations conventions at the international level, to actions at the local level.

Safe drinking water and sanitation are human rights. Without access to these services, a life of dignity, stability and good health is virtually impossible. Water,

when managed sustainably and equitably can be a source of peace and prosperity. It is also the literal lifeblood of agriculture, the major socio-economic driver for billions of people.

It can promote community stability and peace building especially in fragile situations and contribute to migration management and disaster risk reduction.

In an unstable world where security threats are growing, we must all recognize that ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all -the aim of Sustainable Development Goal 6 is essential for global prosperity and peace.

The most important natural wealth of our country is the large number of rivers flowing across different states. Most of the Rivers, particularly the peninsular rivers are flooded during the heavy wet monsoons and dry during the other seasons due to scarce rainfall in the catchment areas of these rivers. Hence the Farmers are in the clutches of either a severe flood or drought. This is a very bad situation for farmers of this country. It not only affects their crops but also make them suffer most to repay their loans resulting in the suicides of farmers in the country.

The Nationalization of rivers and inter-linking of the rivers are very important as they not only solve the inter-state water sharing disputes among the Indian States but is also the only way through which adequate water for irrigation in various states could be ensured and the problems faced by the farmers due to lack of water and drought could be solved permanently. Also the government should consider creating a comprehensive National Policy on Indian rivers and National river water Grid to enhance the process of inter-linking of rivers flowing in various states. In this way the government can harness the excess water in the rivers cleverly and judiciously to benefit drought hit parts of the country. Sir, Water is indispensable for Agriculture. Irrigation is the blood circulation of Agriculture. Without water nothing could be done without adequate water even if we spend crores of rupees, without water, farmers have no chance of flourish. The River Cauvery is the lifeline of Tamil Nadu, particularly the millions of farmers in the delta regions in Tamil Nadu.

But unfortunately year after year Tamil Nadu farmers are betrayed due to the non release of adequate water from river Cauvery. The unconcerned attitude of the higher riparian State of Karnataka has killed hundreds of farmers in Tamil Nadu and has driven several thousand out of the agriculture. The taken heavy toll on Agriculture and farmers of Tamil Nadu.

The Union Government should urge the Cauvery Management Board to direct the Karnataka state to release rightful share of water from Cauvery river in accordance with the award of the Cauvery Water Disputes Tribunal (CWDT) in

monthly deliveries to ensure adequate release of Cauvery water from Karnataka for irrigation in Tamil Nadu.

The Union Government has to allocate more funds for the proper maintenance and use of existing dams and water reservoirs in the country. The deepening and de-silting of local water bodies and the lakes is crucial for growth of agriculture. The Union Government has to allocate more funds for the river restoration projects in the country and also to increase and enhance the water catchment capacity in the country. The development of social forestry and increase of green cover in the country is also part of the agro development activity only.

Tamil Nadu always perform better when it comes to people and reserved the best for adverse conditions. The Hogenakkal Integrated Drinking Water project and the Athikadavu Avinashi project are standing testimonial to the commitment of the DMK government headed by Hon'ble Chief Minister Thalapathi M.K. Stalin in providing water to underprivileged people living in dry regions. The Veeranam Water Supply scheme, The Palar water Supply scheme cater the water needs of the people of Greater Chennai region and adjoining districts of Thiruvallur, Chengalpattu and Kanchipuram are also the brain child of Muthamilarignar Dr Kalaignar. The southern Districts of Ramanathapuram, Thoothukudi, Virudhunagar too benefitted through the far sighted water management of the Government of Tamil Nadu.

Ancient Tamil literature provides fascinating insights into water management practices and the cultural significance of water in Tamil Nadu.

Thousands of years ago, Tamils possessed remarkable knowledge of water management. Kings built tanks and lakes to store water, some of which still exist today.

Water was considered sacred, and its judicious use was emphasized. Ancient Tamil literature mentions 47 water bodies, reflecting the prescient wisdom of Tamils in harvesting water.

Different terms were used to describe various types of water: Munneer: Refers to the sen, formed by water from rains, rivers, and springs. It symbolized antiquity and purity. Nanneer: Denoted good water from rivers.

Inneer: Referred to sweet water suitable for drinking.

The Sangam era celebrated water through the festival of "Munneer Vizhavu," recognizing its role in soil creation, nourishment, and erosion.

Sangam literature believed that a person's character was shaped by water and soil. Life revolved around water, and villages were built around water bodies. Ancient Rituals from birth to death are centred on water. Houses were constructed around wells, emphasizing water's importance.

Tamil literature highlights the deep connection between water, culture, and sustainable practices. While challenges persist today, learning from ancient wisdom can guide better water management in the future

The water resources management policies of union government is ill planned with misguided priorities and excessive spending on promotion and publicity.

One of the most damning observations comes from the Public Accounts Committee, which noted excessive expenditure on advertising and promotion has little to offer in terms of tangible environmental benefits.

Instead of channelling funds towards measures that directly improve water quality or enhance wastewater treatment capacity, the programme has, in many instances, prioritize superficial activities that generate political mileage but fail to address the underlying environmental degradation.

The amount underutilised and unspent in the Namami Gange Programme can be used to clean up a number of rivers such as the Kaveri and Thamirabarani, on which millions of farmers in Tamil Nadu depend upon.

The ambitious project of river inter-linking, envisioned to link water-deficit river basins with water-surplus basins, remains largely a distant dream.
India is facing a looming water crisis, with per capita water availability declining steadily. In 2021, the per capita water availability was 1,486 cubic meters, below the water-stressed threshold of 1,700 cubic meters..

In rural villages across India, the repercussions of inadequate water management are felt daily. Families still struggle to secure clean water for drinking, cooking, and sanitation. Farmers, who form the backbone of our society, face the twin challenges of unreliable irrigation and dwindling groundwater reserves. Communities that once thrived along the banks of sacred rivers now confront the dual burdens of pollution and neglect.

Imagine the despair of a village where, despite being declared "Har Ghar Jal" or "ODF," residents continue to face erratic water supply and deteriorating sanitation conditions. This government is only a slogan mongering government not bothered about the good execution of the projects.

Consider the plight of a farmer, forced to depend on depleting groundwater resources, whose yields are diminishing with every passing season.

These are not abstract statistics-they are real lives, hopes, and dreams that are slipping away in the wake of systemic mismanagement of resources by the union government.

This structural ambiguity is further compounded by the reliance on self-certification by local bodies. For instance, even after achieving 100% FHTC coverage, villages are allowed to self-certify their "Har Ghar Jal" status without any independent verification. Out of the 2.5 lakh villages that reported full connectivity, a staggering 61% have self-certified, raising serious concerns about the integrity of the data and the actual quality of service provided. When local governance is entrusted with such critical responsibilities without rigorous oversight, it opens the door for complacency, misreporting, and, ultimately, a disconnect between reported progress and the lived reality of citizens.

The Swachh Bharat Mission - Grameen (SBM-G), launched in 2014, aimed to end open defecation by providing all rural households access to toilets. While the government declared that Phase-I met its target in October 2019, the National Family Health Survey 5 reveals that 19% of households (26% rural and 6% urban) still practiced open defecation between 2019 and 2021.

Phase II of the scheme, which aims to make all villages ODF Plus Model villages by 2024-25, also faces significant challenges. As of January 30, 2025, only 44% of SBM-G villages have had their ODF Plus Model certification verified. Furthermore, the majority of toilets in 14 states and Union Territories continue to be single-pit, hindering effective faecal sludge management.

Plastic waste management, a key objective under SBM-G Phase II, is also lagging. As of December 2024, there were only 978 operational Plastic Waste Management Units (PWMUs) in the country, with 13 states and Union Territories having none.

Financial mismanagement continues to plague SBM-G, with less than 50% of funds allocated by the Centre to states/UTs being released between 2020-21 and 2022-23. Delays in states releasing their share of funds, procedural delays, and insufficient resources are cited as reasons for this dismal performance.

While sanitation remains a critical pillar of public health, the nation's agricultural backbone is equally imperiled by mismanagement in irrigation. The Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) was envisioned as a transformative scheme to

increase cultivable land under assured irrigation, improve water use efficiency, and support the livelihoods of millions of farmers. Yet, the promise of a water-abundant future for our agrarian economy remains unfulfilled.

Ambitious Targets versus Harsh Realities: PMKSY's goal was to significantly expand the irrigation potential of India. Despite the allocation of substantial resources-budget estimates have nearly doubled in recent fiscal cycles-the scheme's actual impact falls far short of its promise. For instance, under the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP), while the target was to create irrigation potential for millions of hectares, only a fraction of this potential has been achieved. Cost overruns, delays in land acquisition and protracted clearance procedure have hampered progress, leaving farmers in water-scarce regions stranded.

Delays and Cost Overruns: A detailed review reveals that many projects under PMKSY have suffered significant delays. Cited delays ranging from one to 18 years not only inflate the cost of projects but also render the original designs and estimates obsolete. The lack of effective project management has resulted in a situation where planned improvements remain merely aspirational while the real needs of farmers go unmet.

The plight of PMKSY is a sobering reminder that the government's ambitious projects, despite their grand scale on paper, often falter at the implementation stage. The continuing gap between policy pronouncements and tangible outcomes has left our agrarian communities grappling with water scarcity, reduced crop yields, and mounting economic distress.

Our nation's dependence on groundwater is both a blessing and a curse. While groundwater has long served as a critical buffer against the uncertainties of rainfall, its over-extraction and mismanagement have now emerged as a crisis of monumental proportions. The Atal Bhujal Yojana (ABY) was conceived as a corrective measure-a strategy to manage and rejuvenate groundwater resources in water-stressed regions.

Insufficient Fund Release and Utilization: The ABY, with a total outlay of Rs 6,000 crore, was launched with the promise of community-led groundwater management and a sustainable approach to water use. Yet, the report indicates that only about 57% of the allocated funds have been released to states, and even of these, only 48% have been effectively utilized. This underutilization signals not just bureaucratic lethargy but a profound disconnect between policy intent and ground-level execution.

Slow Progress on Critical Targets: While equipment installation and the construction of piezometers have, in some instances, surpassed targets, the overall improvement in groundwater decline rates remains abysmally low.

The slow pace of training and capacity building at block and district levels leaves communities ill-equipped to manage their own water resources. Without the necessary expertise and local empowerment, even the most well-funded initiatives will flounder.

Systemic Issues in Groundwater Governance: Beyond the technical aspects, there lies a deeper issue-the fragmentation of responsibility between central and state agencies. Groundwater, which accounts for 80% of rural drinking water and the bulk of agricultural irrigation, remains largely unmonitored due to overlapping jurisdictions and a lack of integrated policy frameworks. The failure to enact and enforce robust groundwater management laws has allowed unsustainable practices to continue unchecked, further depleting this vital resource.

The case of ABY illustrates a recurring theme in our water governance framework: the absence of a coherent, long-term strategy that brings together technological innovation, community participation, and stringent regulatory oversight. Without such integration, efforts to manage groundwater remain piecemeal and ineffective, imperiling the very lifeline of our agricultural communities.

There are several pertinent questions in the minds of the people expecting the answer from the union minister of Jal Sakthi.

Whether the union government has sanctioned any funds for the protection and preservation of River Palar and if so the details thereof? if not the reasons there for?

b) Whether the union government has contributed any funds for the construction of first bed dam at the confluence of Goddar and Palar rivers at Erayangadu village in Vellore for the benefit of farmers in Anaicut and K.V. Kuppam regions in my Vellore Parliamentary constituency. If so the details thereof

c) Whether the union government has any plans to support for the Construction of more bed dams to restore lost river sand and discharge excess rainwater to dry portions of a river. If so the details thereof

what action was taken by the union government in this regard.The Hon'ble Minister has to answer this.

We have another question Whether it is true that the Union Government has sanctioned the States like Uttar Pradesh, Rajasthan 5 times higher than Tamil Nadu in the Jal Jeevan Mission program and if so the details thereof the funds allocated in the last 3 years, State-wise

b) Whether the union government has sanctioned Rs.731.67 crores only to Tamil Nadu till 31 December 2024 for implementation of Jal Jeevan Mission program, If so the details thereof and the reason for the very less allocation and release of funds to Tamil Nadu

c) the status of funds central allocation and release to various States till 31 January 2025 for the JJM program

d) Whether it is a fact that the Water Resources Department and Central water commission has chalked out any new schemes for the safe potable drinking water in rural and arid regions and if so the details thereof, if not the reasons there for. We need a categorical answer from the union government.

Sir, there are many harmful effects of drinking of contaminated ground water.

Whether the government is aware of the harmful effects on human and animals through high levels of contamination of Arsenic, Mercury and Fluoride in ground water

b) If so the details thereof

c) Whether the government has any new proposal or project for control of contamination of Arsenic, Mercury and Fluoride and if so the details thereof and the total amount sanctioned in this regard

d) Whether it is a fact that the Water Resources Department and Central water commission has chalked out any new schemes for the safe potable drinking water in rural and arid regions and if so the details thereof, if not the reasons there for There are many such questions lingering in the minds of the people.

Before I conclude, I would like to end with few couplets from Tirukkural equating the importance of Water in the life of the people and country.

Vinninru Poippin Virineer Viyanulakaththu

Ulninru Udatrum Pasi

If the clouds do not provide us with rain there would be famine all around in this world

Keduppadooum kettaarkku Saarvaay Mattraange

Eduppathooum ellam mazhai

Rain has the power to ruin us and it also has the power to bring back transformation in the ruined life.

OoruNi Neer NiRainthatre Ulakavaam

PeraRivaalan Thiru

The wealth of a wise philanthropist is similar to a pond filled with water.

MaNi Neerum MaNNum Malaiyum aNinizhaR

Kaadum udaiyathu araN

Clean water, open space, high rise mountains and dense forests remain like a fortress for a nation .

श्री रोडमल नागर (राजगढ़) : महोदय, जीवन निर्वाह और सतत विकास के लिए जल आवश्यक है बढ़ती आबादी तीव्र औदयोगिकरण बढ़ते शहरीकरण ने जल की उपलब्धता को महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया है इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार विभिन्न मुददों ने जल क्षेत्र में स्थिति को और अधिक चुनौती पूर्ण बनाया है इसलिए जल सुरक्षा पर्यावरणीय निर्वाह और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधनों का कुशत्र प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कल 25276.83 करोड रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है । केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 13431.48 करोड रुपए के बजट एस्टिमेट आवंटन के मुकाबले 2025-26 में 17643.94 करोड रुपए की निधि प्रस्तावित है जो वर्ष 2024-25 के बजट एस्टिमेट आवंटन की तुलना में लगभग 4212.46 करोड रुपए अधिक है

भारत में जल उपलब्धता व उपयोग के कुछ तथ्यों पर विचार करें तो भारत में वैश्विक ताज़े जल स्रोत का मात्र 4 प्रतिशत मौजूद है जिससे वैश्विक जनसंख्या के 18 प्रतिशत (भारतीय आबादी) हिस्से को जल उपलब्ध कराना होता है । नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत में जल की मांग, उसकी आपूर्ति से लगभग दोगुनी हो जाएगी । " देश में वर्ष 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घनमीटर थी, जो वर्ष 2000 में 2300 घनमीटर रह गई तथा बर्ष 2031 में इसे 1367 घनमीटर प्रतिवर्ष अनुमानित किया गया है ।

भारत में बहने वाली मुख्य नदियों के अलावा हमें औसतन मिलीलिटर बारिश का पानी मिल जाता है, इसके अलावा नवीकरणीय जल संरक्षण से भी हमें सालाना 1608 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल मिल जाता है । जिस तरह का मज़बूत बैकअप हमें मिला है और दुनिया का जो नौवाँ सबसे बड़ा फ्रेश वॉटर रिज़र्व हमारे पास है, उसके बाद भारत में व्याप्त पानी की समस्या स्पष्टत: जल प्रबंधन प्रणाली मे सार्थक नवाचार की मांग को इंगित कर रही है ।

कुल जल का 90 प्रतिशत सिंचाई, शेष पीने के पानी एवं औद्योगिक इकाइयों में खर्च होता है । जिले में पीने के लिए जल जीवन मिशन ।

मोर क्रॉप पर ड्रॉप, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करना

जल दक्षता का प्रयोग मध्य प्रदेश मे मेरे अपने संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में व्रहद बांध परियोजना मोहनपुरा एवं कुंडलिया के निर्माण के माध्यम से किया गया है इस परियोजना के द्वारा खुली नहर की अपेक्षा बांध से खेतों तक प्रेशर पाइप प्रणाली के माध्यम से जल उन्नयन दक्षता में दो गुना से अधिक वृद्धि हुई है सिंचाई परियोजनाओं के कुल उपलब्ध 90 प्रतिशत जल का सिचाई का राष्ट्रीय औसत ३8% है जबकि मोहनपुरा परियोजना द्वारा जल उन्नयन दक्षता 80% तक मर हक हो गई है जहां पहले एक मिलियन घन मीटर में 170 हेक्टेयर क्षेत्र में खुली नहर से सिंचाई की जाती थी वहीं अब एक मिलियन घन मीटर जल से 490 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है यह जल दक्षता केवल राजगढ़ क्षेत्र में कम जल से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करने की है कहानी नहीं है अपित संपर्ण विश्व में कषि उपयोग में जल उपयोग दक्षता उन्नयन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है माननीय प्रधानमंत्री जी दवारा मोर क्रॉप पर ड्रॉप एवं हर खेत को पानी की दृष्टि को साकार करते हुए राष्ट्रव्यापी अनुकरणीय एवं नीति निर्धारण हेतु उल्लेखनीय पहल है ।

माननीय प्रधानमंत्री जी दवारा परम श्रद्धेय अटल जी के नदियों के जोडने की परिकल्पना को साकार कर देश की पहली नदी जोड़ों योजना केन बेतवा लिंक परियोजना को लगभग 45 हजार करोड़ रुपये आवंटित कर परियोजना को गति प्रदान की है । इसी प्रकार लगभग 72 हजार करोड़ की पार्वती कालीसिंध चंबत्र के समझौतों को मर्त रुप देकर क्रियान्वयन की दिशा में अग्रसर हये है । इस परियोजना से मेरे अपने राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र मे अतिरिक्त 1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होने जा रही है ।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जितने बड़े बांध बने हैं, ओपन कैनाल हैं, वहां अतिरिक्त बजट का प्रावधान प्रेशर पाइप प्रणाली से खेत तक पानी पहुंचाया जाए । सूक्ष्म सिंचाई की दिशा को प्रोत्साहित किया जाए ।

नदी खंडों का संदूषण और घरेलू सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के अपर्याप्त प्रबंधन के कारण भूजल की गुणवत्ता में गिरावट है तथा रसायनों, उर्व्रकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग भी एक प्रमुख चिंता का विषय है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रत्येक नगरीय निकाय के जल अपशिष्ट औद्योगिक जल अपशिष्ट के लिए विशेष योजना बनाके के लिए बजट की आवश्यकता है ।

हम नदियों को केवल दूषित करना छोड़ दे तो वे स्वयं ही अपने सतत प्रवाह से स्वयं को स्वच्छ कर लेती है ।

देश के जिन नदियों के उद्गम क्षेत्रों में ग्लेशियर नहीं है वहां नदियां सजीव एवं सतत प्रवाहित होती रहे इस हेतु जल निकायों के किनारो पर वृक्षारोपण का प्रावधान करने कि आवश्यकता है जिससे वर्षाकाल के समय वृक्ष अपनी जड़ो मे जलत्र संग्रहण करे एवं आवश्यकता पड़ने पर अपनी जड़ो से जल छोड़कर जलस्रोतो को को निर्जीव होने से बचाकर गतिमान रखें, इसके लिए भी अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है ।

ग्रामीण एवं नगरीय निकायों मे अनिवार्य रूप से अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली, भूमिगत प्रेशर पाईप सिंचाई प्रणाली , ड्रिप इरिगैशन , वर्षा जल संग्रहण ,जल निकायों के किनारों पर वृक्षारोपण, प्राकृतिक जल निकायों की देखभाल एवं जल संरक्षण बिन्दुओ को मद्देनजर रखते हुए अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूँ ।

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : आज मैं सदन में जल शक्ति मंत्रालय के 2025-26 के बजट आवंटन और देश में जल प्रबंधन की वर्तमान स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं । जल हमारे जीवन का आधार है और इसके संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक होनी चाहिए । लेकिन, जल शक्ति मंत्रालय के हालिया बजट आवंटन और इसके क्रियान्वयन पर गौर करने से स्पष्ट होता है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है ।

बजट आवंटन में असंगतियाँ ? वर्ष 2025-26 के बजट में जल शक्ति मंत्रालय को 99,503 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (51,558 करोड़ रुपये) से 93% अधिक है । यह आंकड़ा भ्रामक है, क्योंकि वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान में जल जीवन मिशन (JJM) के लिए आवंटन में भारी कटौती की गई थी । वर्ष 2023-24 में JJM के लिए 69,992 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान में घटकर मात्र 22,694 करोड़ रुपये रह गए । यह कटौती सरकार की योजनाओं के प्रति गंभीरता की कमी को दर्शाती है ।

जल जीवन मिशन, लक्ष्य और वास्तविकता - जल जीवन मिशन (JJM) को अगस्त 2019 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराना था । लेकिन, इस मिशन के लिए आवंटन में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है । वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान में JJM के लिए आवंटन 22,694 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2025-26 में अचानक 67,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है । यह असंगति सरकार की योजनाओं में अराजकता और अव्यवस्था को दर्शाती है । क्या सरकार यह मान रही है कि अंतिम वर्ष में अचानक धन बढ़ाने से लक्ष्य हासिल हो जाएगा?

इसके अलावा, JJM के तहत ग्रे वाटर प्रबंधन और जल गुणवत्ता पर ध्यान दिए जाने की बात कही गई है, लेकिन इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने में सरकार विफल रही है । ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता एक गंभीर समस्या बनी हुई है, और इसके समाधान के लिए पर्याप्त धन और योजनाएं नहीं हैं ।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) की उपेक्षा - स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के लिए आवंटन पिछले वर्ष के समान ही रखा गया है, जो 7,192 करोड़ रुपये है । यह दिखाता है कि सरकार ग्रामीण स्वच्छता के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है । ग्रामीण भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध है, और इस मद में आवंटन न बढ़ाना सरकार की उदासीनता को दर्शाता है ।

जल संसाधन विभाग की चुनौतियां - जल संसाधन विभाग को वर्ष 2025-26 में 25,277 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (21,641 करोड़ रुपये) से केवल 17% अधिक है । यह वृद्धि नदियों के पुनरुद्धार, जल संरक्षण और बाढ़ प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए पर्याप्त नहीं है ।

नमामि गंगे - नमामि गंगे योजना के लिए 2025-26 में 2,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (2,000 करोड़ रुपये) से केवल 20% अधिक है । गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए यह आवंटन नाकाफी है ।

नदी जोड़ो परियोजना - नदी जोड़ो परियोजना के लिए 2025-26 में 3,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (3,000 करोड़ रुपये) से केवल 13% अधिक है । यह परियोजना देश के जल संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त धन और योजनाएं नहीं हैं ।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) - PMKSY के लिए वर्ष 2025-26 में 8,260 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (6,621 करोड़ रुपये) से 25% अधिक है । हालांकि, यह वृद्धि कृषि सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं है, खासकर तब जब देश के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति गंभीर है ।

जल प्रबंधन में गंभीरता की कमी - माननीय सदस्यगण, जल प्रबंधन केवल धन आवंटन का मामला नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है । लेकिन, सरकार की नीतियों और क्रियान्वयन में गंभीरता की कमी दिख रही है । जल संकट देश के कई हिस्सों में गहराता जा रहा है, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, और भूजल स्तर लगातार गिर रहा है । ऐसे में, सरकार को

जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक समग्र और दीर्घकालिक रणनीति बनाने की आवश्यकता है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि वह जल संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण को गंभीरता से ले । जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए । नदियों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जाए । यदि हमने अभी इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए, तो आने वाले समय में जल संकट और गहराएगा, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा । धन्यवाद ।

***m55 प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) :** सभापति जी , सम्मानित सहयोगियों और मेरे प्यारे देशवासियों, कल मैं सदन में खड़ी थी और मैंने भारतीय रेलवे की नाकामियों को उजागर किया था । एक जीवनरेखा जो लापरवाही, कुप्रबंधन और खोखले वादों के बोझ तले दम तोड़ रही है । आज मैं फिर यहाँ हूँ, न प्रशंसा के लिए, बल्कि एक और कमज़ोर आधार जल शक्ति मंत्रालय की सच्चाई सामने लाने के लिए ।

पानी भारत की धड़कन है, उसकी आत्मा, उसका जीवन, लेकिन यह धड़कन कमज़ोर पड़ रही है, प्रदूषित और खत्म होती जा रही है । यह मंत्रालय कोई समाधान नहीं दे रहा, यह तो वादों का कब्रिस्तान बन गया है, जो 140 करोड़ भारतीयों को खासकर मेरे महाराष्ट्र को प्यासा, ठगा हुआ और परेशान छोड़ रहा है । सरकार बड़ी-बड़ी योजनाओं और दिखावे की बातें करती है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमारे किसान पानी के अभाव में संकट झेल रहे हैं, नदियाँ नालों में बदल गई हैं, बच्चे प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं और यह सरकार अपनी प्रशंसा में व्यस्त है ।

पहले बजट की बात करें । इस साल जल शक्ति मंत्रालय को 99,503 करोड़ रुपये मिले हैं, जो 2024-25 के 98,714 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है । सुनने में बड़ा आँकड़ा लगता है, पर यह खोखला है । पीने के पानी और स्वच्छता विभाग को 74,226 करोड़ रुपये मिले । कुल का 75 प्रतिशत ज्यादातर जल जीवन मिशन के लिए । सरकार ने वादा किया था कि 2024 तक हर गाँव के हर घर में नल होगा । मार्च 2025 आ गया हम कहाँ है? सिर्फ 80 प्रतिशत घरों तक पहुँच 19.3 करोड़ में से 15.5 करोड़ । अब समय 2028 तक बढ़ा दिया गया, क्योंकि यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका । महाराष्ट्र में हम मुश्किलों से जूझ रहे हैं । कई इलाकों में दो दिन में एक बार पानी आता है, वह भी गंदा और बदबूदार ।

मराठवाड़ा और विदर्भ में नल सूखे हैं या प्रदूषित पानी देते हैं । कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि देशभर में सिर्फ 62 प्रतिशत नल सही हालत में हैं । महाराष्ट्र में तो यह भी नहीं । नासिक और सोलापुर में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और केंद्र अपनी उपलब्धियाँ गिनाने में लगा है ।

जल जीवन मिशन को इस साल 69,926 करोड़ रुपये मिले, जो पिछले साल के संशोधित बजट से 2 प्रतिशत अधिक है । लेकिन पिछले साल 69,622 करोड़ में से सिर्फ 63,232 करोड़ 91 प्रतिशत खर्च हुआ । क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र जैसे राज्य प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पाते, केंद्र समय पर फंड नहीं देता । 2024-25 में हमने 2,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त माँगे, पर बहुत कम मिला । इस साल भी यही हाल है । स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 2024-25 में 66 लाख पानी के सैंपलों में 5 प्रतिशत यानी 3.3 लाख सैंपल प्रदूषित थे, जिनमें बैक्टीरिया और लोहा पाया गया । सिर्फ 59 प्रतिशत सैंपल ठीक किए गए । महाराष्ट्र में टेस्टिंग लैब कम हैं, जाँच एक सपना है, बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और मंत्रालय इसे ?प्रगति? कहता है? प्रगति कहाँ है, जब मेरे लोग संकट में हैं?

अब भूजल की बात, अटल भूजल योजना । पानी की कमी वाले इलाकों को बचाने का दावा है । देशभर में 8,152 ब्लॉक हैं । महाराष्ट्र के सात जिले पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, जलगाँव, सांगली, सोलापुर, इसमें शामिल हैं । पाँच साल के लिए 6,000 करोड़ रुपये, लेकिन 2025-26 तक सिर्फ 3,418 करोड़ का बजट आधा खर्च, आधा रुका हुआ । महाराष्ट्र ने 55 प्रतिशत फंड से 99 प्रतिशत मेहनत की, कुओं को बचाने की कोशिश की । मराठवाड़ा के खेत बंजर हो रहे हैं, विदर्भ के गाँव पानी को तरस रहे हैं और केंद्र कहता है, ?60 प्रतिशत लक्ष्य पूरे? । 60 प्रतिशत? यह हर उस किसान और माँ के लिए अपमान है जो अपनी फसल और पानी की बूँदें गिन रही है ।

सिंचाई का हाल भी बुरा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना । इस साल 8,226 करोड़ रुपये, पिछले साल के 7,036 करोड़ से 17 प्रतिशत अधिक । दस साल बाद भी सिर्फ 55 प्रतिशत काम, 76 लाख हेक्टेयर में से 41 लाख को पानी । महाराष्ट्र के खेत ज्यादातर बारिश पर निर्भर हैं । मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश न हो तो सब खत्म और केंद्र का जवाब? देरी । रिपोर्ट्स कहती हैं कि पिछले साल 1,190 करोड़ रुपये इस्तेमाल नहीं हुए । क्यों? क्योंकि यह मंत्रालय योजना नहीं बना पाता और हम जैसे राज्य कितना और इंतज़ार करें? किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, खेत सूख रहे हैं, इसे कहते हैं ?हर खेत को पानी?? यह ?हर खेत को परेशानी? है ।

फिर स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, शौचालय का दावा । 2019 में कहा गया, ?खुले में शौच से मुक्त? । यह सच नहीं है । नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि 26 प्रतिशत ग्रामीण घरों में शौचालय नहीं हैं । महाराष्ट्र के गाँवों में भी टूटे शौचालय हैं । फेज़ ॥ का लक्ष्य 2024-25 तक स्वच्छ गाँव ODF प्लस और कचरा प्रबंधन । सिर्फ 44 प्रतिशत गाँव बने, 6.6 लाख में से 2.9 लाख । महाराष्ट्र में कचरा फैला है, मुंबई की सड़कें प्लास्टिक से भरी हैं, गाँव कूड़े के ढेर हैं । रिपोर्ट्स कहती हैं कि 13 राज्यों में एक भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट नहीं । फंड? इस साल 2,900 करोड़, लेकिन पिछले साल सिर्फ 2,130 करोड़ 73 प्रतिशत खर्च हुआ । राज्य हिस्सा नहीं दे पाते, तो केंद्र फंड रोकता है और 7 प्रतिशत ब्याज लगाता है । यह मदद नहीं, परेशानी है । जल संसाधन विभाग 25,277 करोड़, पिछले साल के 21,595 करोड़ से 17 प्रतिशत अधिक ।

सबसे ज्यादा नमामि गंगे को 2014 से 16,200 करोड़, लेकिन 10 साल में सिर्फ 69 प्रतिशत 11,172 करोड़ खर्च हुआ । सीवेज प्लांट धीमे हैं 2,923 MLD में से 1,620 MLD इस्तेमाल । औद्योगिक कचरा गंगा की 50 प्रतिशत गंदगी 2,700 कारखानों से बेरोकटोक बह रहा है । महाराष्ट्र की नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, भीमा भी प्रदूषित हैं । मुंबई की मीठी नदी नाले में बदल रही है । रिपोर्ट्स कहती हैं कि क्लीन गंगा फंड में 876 करोड़ हैं, लेकिन सिर्फ 383 करोड़ इस्तेमाल हुआ । पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है, देरी, खराब रिकॉर्ड, नतीजा शून्य । मुंबई में हर मॉनसून संकट 2024 में 2,468 लोग ट्रेनों और बाढ़ से मरे और बाढ़ का समाधान? सिर्फ कागज़ों पर ।

यह सरकार वंदे भारत और जल जीवन जैसे दिखावों में उलझी है । महाराष्ट्र में झुग्गियाँ पानी के लिए तरस रही हैं, किसान आसमान देख रहे हैं, बच्चे धूल में बाल्टियाँ ढो रहे हैं । यह शासन नहीं, हमारे लिए संकट है ।

मैं महाराष्ट्र के लिए बोलती हूँ, मुंबई के गरीब, मराठवाड़ा के किसान, विदर्भ के बच्चे । हम मुश्किलों में हैं । मुंबई में बाढ़ परेशान करती है, गाँवों में सूखा भूखा रखता है, नदियाँ प्रदूषित हैं और केंद्र निष्क्रिय है । जल जीवन का नल अधूरा, स्वच्छ भारत का गाँव अस्वच्छ, नमामि गंगे का दावा खोखला। महाराष्ट्र सीमित संसाधनों से लड़ता है, 55 प्रतिशत फंड, 99 प्रतिशत मेहनत, लेकिन केंद्र पूरा साथ नहीं देता । दिखावा बंद करें, विज्ञापन बंद करें, हमें पानी दें, स्वच्छता दें, जीवन दें । इस मंत्रालय को सुधारें, वरना इतिहास आपको वह सरकार कहेगा जिसने भारत और महाराष्ट्र को संकट में छोड़ दिया।

अंत में एक कच्ची, जलती चीख -

नदियाँ गंदी, वादे झूठे, सरकार के ढोल हैं फूटे ।

किसान प्यासा, खेती मरे, पानी नहीं, सपने जरे ।

स्वच्छता का गीत सुहाना, हकीकत में बस बहाना ।

SHRIMATI ANITA SUBHADARSHINI (ASKA): I express my views on the demand for grants of the Ministry of Jal Shakti for the year 2025-26.

The Budget allocation for the Ministry of Jal Shakti is about Rs. 99503 crores for the year 2025-26. During the last 10 years 76% of the budget of the Ministry of Jal Shakti has allocated to the Department of Drinking water and Sanitation (DDWS) with the commitment of hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji to provide safe drinking water and sanitation facility in the rural villages of the country. The aim of Jal Jeevan Mission (JJM) is to provide 19 crore rural households in the country with functional household tap water connections (FHTCs) by 2024. An estimate of 15 crore households have been given functional household tap water connection as on 21st January, 2025. This scheme is further extended until 2028 to reach the target of 100%. My State Odisha has achieved 76% of FHTCs target till date.

The Department of Water Resources (DoWR) has been allocated Rs. 25277 crore in the Budget 2025-26, which is 17% higher than the revised estimate of 2024-25. The Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) was launched in 2015-16 with the aim to increase cultivable area under assured irrigation, improve water availability on farms and increase water use efficiency. The Ministry of Jal Shakti implements Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) and Har Khet Ko Pani (HKKP). The Major & Medium irrigation projects are taken up under AIBP while the minor irrigation projects are under HKKP.

As a Member of Parliament from ASKA, District Ganjam of the State of Odisha, my constituency's demand is the inter linking of rivers. This project is expected to increase the irrigation of 35 million hectares of land and will generate 34,000 megawatts of hydro power. The other benefits from inter linking of rivers are

irrigation, navigation, flood control and fisheries. The Nagarul Bansadhara Rusikulya river link will be pathbreaking and ensure three crop cultivation in Ganjam district in the state of Odisha. I request hon'ble Minister Jal Shakti to start the above said river link project as well as allocation of fund for renovation of Surada reservoir of my constituency.

The people of my constituency ASKA are very hopeful for the fulfillment of the basic need of drinking water as there is a double engine Sarkar. The renovation of Surada water reservoir is an essential project, many problems of my constituency will be solved and people of my Parliamentary Constituency will be highly obliged. Thanking you.

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): First, I would like to thank our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for his vision which has changed the country in the last ten years. All the Ministries are developing the country like never before. And now, even Odisha which was not developing since last 25 years is now developing with our double engine *Sarkar*.

I would like to thank our hon. Jal Shakti Minster, Shri Patil ji. Your efforts to allocate additional funds for various schemes and programs aimed at ensuring water security, sanitation and hygiene are truly commendable. I must appreciate the increased allocation towards the Jal Jeevan Mission. The focus of our Minister to provide clean drinking water, water conservation and sustainable ground water conservation is commendable. Our Ministry's emphasis on improving sanitation facilities and promoting cleanliness through Swachh Bharat Mission Gramin is laudable.

The budget allocation for Jal Shakti in 2025-26 is Rs. 99,503 crore, which is higher than the previous year's allocation. This allocation is divided between the following departments: Department of Drinking Water and Sanitation, and Department of Water Resources, River Development, and Ganga Rejuvenation. Department of Drinking Water and Sanitation: Rs. 74,226 crore, with a significant portion allocated to the Jal Jeevan Mission (JJM) at Rs. 67,000 crore. Department of

Water Resources, River Development, and Ganga Rejuvenation: Rs. 25,277 crore, with allocations for schemes like Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojana (PMKSY) at Rs. 8,260 crore, River Interlinking at Rs. 3,400 crore, and Namami Gange at Rs. 2,400 crore.

I would like to make a request to our hon. Minister for my constituency of Kalahandi with two districts of Kalahandi and Nuapada. Sir, Kalahandi constituency is the second highest paddy producing constituency In Odisha and we are hoping to become the number one constituency in Odisha with your help. The way work is happening all over India is now happening in Odisha also after we have hot out own double engine *Sarkar*, the hopes of the people are very high.

Kamal irrigation project or Motor irrigation project over the river motor at Kuntia village in Koksara block. Its irrigation potential is 7500 hectare. It will irrigate 50 villages of 11 gps of both Koksara and Dharamgarh.

Uttar-roul irrigation project over the river Uttei Raul and Buda river. Its irrigation potentiality is 60000 hectare. It will benefit the people of Kesinga, M Rampur, Narla and Karla Munda.

Lower Uddanri irrigation project over the river Uddanri in Bordi at Golamunda block. Its irrigation potential is 12000 hectare. It is a major project 40 villages of Bhawanipatna, six villages of Golamunda block in Kalahandi constituency and 17 villages of Titlagarh in Bolangir district. This project is also held up die to Mahanadi water dispute tribunal. Please look into that as well.

Upper Udanti Barrage Project over river Udanti at Patialapara village in Sinapali block of Nuapada district. Its irrigation potentiality is 10000 hectare. It is a major project. It will benefit 39 villages of Sinapali block and 14 villages of Borden block a total of 53 villages.

Upper Jonk Irrigation Project located at Patora in Nuapada district needs environmental clearance. Please look into this and pass it as it will irrigate 9200 hectares of land.

To conclude my speech, I must again thank our hon. Minister for the great work being done in the Jal Shakti Ministry and also request our hon. Minister to please look into the demands of people of my Kalahandi constituency. Thank you.

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): I expressing my views on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Jal Shakti.

I am happy that I am participating in a subject which is most essential for a human being i.e. Jal, in Malayalam is *Jalam* or *Vellam*.

It is good that the scheme Jal Jeevan Mission (JJM) rural household tap connectivity scheme has been extended till the year 2028.The State of Kerala will be benefitted out of the extension provided in the Union Budget for 2025-2026 as the State has been lagging behind in its implementation of the said scheme. To implement the scheme Kerala needs to pump in about Rs.17,500 crore more as its share over the next two years. Where is the money? The State is unable to provide its share Kerala and whatever the work done in the State on account of the Central share. The State has urged the Centre to allow the financing requirements for Centrally-Sponsored Schemes over and above the limit of the State borrowings and this aspect has not been addressed. Therefore, the State would not be able to complete the works on time. Therefore, the Jal Shakti Ministry should come forward to help the State of Kerala to implement the above scheme within the time extended time period by taking up the part of financial requirement.

All over Kerala, the roads have been dug for laying of pipes and pipes have been laid, but the main task of constructing water storage tanks for supply through the laid pipelines have not been done in most of the places. The general public questions what is the source of water for all these pipelines laid all over the State and when will water flow through these laid pipelines.

The steady depletion of groundwater is a cause of concern. In many places extraction of groundwater has become impossible as the groundwater level has gone deep or dried up. Therefore, the Government needs to focus more on rainwater harvesting, which will help to prevent the depletion level of groundwater. The

Government should come forward with a scheme to encourage rainwater harvesting like we provide incentives in the case of solar energy.

There is another issue which is very vital as far as storage of water in our dams is concerned. The storage capacity of water in most of our dams has been reduced due to accumulation of soil that came with the water. These dams were constructed many decades ago. Therefore, the Government should take immediate steps to remove the accumulated soil from all our dams as well as components such as nitrates, fluoride, uranium, etc. that contaminate the water. The Central Government should formulate policy towards and aid the concerned State Governments. There are eight dams in Palakkad district alone and the storage capacity of these dams have got reduced due to the above factor. It is a well-known fact that when the dams are full to its capacity, we can control inflation, so dams play a pivotal role in our economy too.

Another issue which I would like to highlight here is about the dried-up water resources. We need to rejuvenate the rivers and ponds, etc. on a time bound basis, to make availability of water for drinking and irrigation purposes.

Sir, the water sharing pacts between the States were done many decades ago in most of the cases. Like-wise, water sharing from Parambikulam - Aliyar Project also done between Kerala and Tamil Nadu many decades ago. As per the agreement, Kerala was to get 7.25 TMC of water, but Kerala has been getting only half of the agreed share of water. The agreement was done when we were not doing much agricultural activities in those water-flowing area of the project. But now, it has increased by double or triple hectares in thousands. Water from the project flows through Chittoorpuzha and finally merge into Bharathapuzha. Since the area is not getting the agreed share of water, several places are facing a drought like situation and the wells have been dried up.

The water resource for two taluks in Palakkad namely Attappadi and Mannarkkad is from river Bhavani. But due to construction of check dams across river Bhavani by Tamil Nadu, these taluks under Palakkad district are facing acute

shortage of water for drinking and irrigation purposes. Therefore, the Centre should take steps to ensure that parties to water sharing agreements honour their commitments and flow of water should not be stopped by creating check dams across rivers as is the case of river Bhavani.

Another issue, which I would like to state is about excess nitrates, fluoride and uranium. According to a Report by the Central Groundwater Board, 440 districts in the country have excess nitrates in groundwater which is a health hazard, particularly for young children. The groundwater extraction is at peak in many States. So, this contamination of ground water with these hazardous materials will pose a threat to our population. Therefore, the Government should create awareness among the people about this health hazard arising out of contaminated groundwater with nitrates, fluoride and uranium.

It is also a demand that where there is a scarcity of water, no company or institution should be allowed to function as they happen to extract more groundwater for running of their units. For example, the people of Elappully Panchayat in Palakkad district have been agitating against the decision of the Government of Kerala to allow to set up of a brewery over an area of 26 acres in Elappully Panchayat in Palakkad district as it will seriously affect the farming activities as well as the availability of water in the Panchayat. The people of this area solely depend upon the groundwater for all their needs as it is a water scarce area. The proposed brewery has to extract groundwater to run their units which will result in the depletion of groundwater in the area, forcing the people to move out of the Panchayat on this account alone.

The people of Elappully Panchayat had resisted the attempt to set up a brewery in Elappully in the year 2020 on these accounts and the proposal had to be withdrawn because of strict resistance of the people. Moreover, the proposal to set up a brewery was cleared by the State Government without undertaking any environmental impact study. On three issues, namely water deficit, loss of farming, and impact on the environment, this proposal should not be allowed.

Therefore, it is urged that the Ministry of Jal Shakti should take a note of the above and advise the State Government not to go ahead with the said proposal.

With this I conclude.

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : सभापति जी , मैं आज जल संकट, जल शक्ति और जल संसाधनों के संरक्षण पर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ । जल हम सभी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है । हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन और जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जल संकट को एक गंभीर चुनौती बना चुके हैं । यह सत्य है कि जल संकट का सामना सिर्फ हमारी कृषि, बल्कि पूरे देश के विकास और समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है । हमें जल के महत्व को समझते हुए इसे संरक्षित करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका सही तरीके से उपयोग कर सकें ।

आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जल शक्ति, जल संरक्षण और जल पुनर्चक्रण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं । प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जल संसाधनों के प्रबंधन में एक नई दिशा दी गई है । जल जीवन मिशन, नमामि गंगे योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और जल शक्ति मंत्रालय जैसे कदम भारत को जल संकट से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं ।

जल जीवन मिशन: मान्यवर अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर में पाइप से जल आपूर्ति करना है । यह योजना पूरी दुनिया में जल के महत्व को समझते हुए, भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है । माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्त्व में अब तक 11 करोड़ से अधिक घरों को नल जल से जोड़ा जा चुका है । इसका फायदा न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को हो रहा है, बल्कि यह कदम हमारे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार ला रहा है । स्वच्छ पानी की उपलब्धता से जलजनित बीमारियों में भी कमी आई है ।

नमामि गंगे योजना: इसके अलावा, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है जो गंगा नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने और उसकी सफाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है । इस योजना के तहत गंगा के किनारे स्थित 157 नगरों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिससे जल की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । यह योजना गंगा नदी को पुनः जीवन देने का एक सशक्त प्रयास है जो न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि देश की सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्था से भी जुड़ी हुई है ।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की शुरुआत की, जिसके तहत 50,000 करोड़ रुपये अधिक का बजट आवंटित किया गया । इस योजना के तहत किसानों को सस्ती और सुरक्षित सिंचाई सुविधाएं मिल रही हैं । इससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है, बल्कि जल संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं । सिंचाई के लिए पानी की बचत करने वाली नई तकनीकों को बढ़ावा दिया गया है, जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई, जो किसानों की मदद कर रही हैं ।

जल शक्ति मंत्रालयः प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की है, जिससे जल के संरक्षण, वितरण और पुनर्चक्रण में तेजी आई है । जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और जल संकट से निपटने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं । इसके साथ ही देशभर में वर्षा जल संचयन की पहल भी की गई है जो जल संकट से निपटने में सहायक साबित हो रही है ।

जल शक्ति अभियान (Jal Shakti Abhiyan) के तहत जल संचयन की प्रणालियों को स्थापित किया गया है । इसके परिणामस्वरूप कई जिलों में जल स्तर में वृद्धि देखी गई है । कृषि क्षेत्र में जल प्रबंधन पर भी ध्यान दिया गया है । कृषि के लिए जल की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नदी जोड़ने की परियोजना पर भी कार्य जारी है ।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र बालाघाट-सिवनी की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा करना चाहूंगी । मैं इस सदन के माध्यम से बालाघाट और सिवनी क्षेत्र के लाखों नागरिकों की समस्याओं को उठाना चाहती हूं । सबसे पहले मैं ढुटी घाट वैनगंगा नदी पर एक उच्चस्तरीय पुल निर्माण की मांग करती हूँ । इस पुल के निर्माण से इन क्षेत्रों के नागरिकों का यात्रा समय कम होगा और सड़कें सीधी होंगी । यह पुल पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा नेशनल पार्क जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा जिससे पर्यटन में अपार वृद्धि होगी ।

इसके अलावा बरघाट, वारासिवनी, कटंगी, लांजी और परसवाड़ा जैसे क्षेत्रों में स्थित नहरों के सुधार और उन्नयन की आवश्यकता है । इन नहरों के सुधार से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल सकेगा जिससे उनकी कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी ।

वैनगंगा नदी के किनारे स्थित बजरंग घाट, शंकर घाट और मृत्युंजय घाट (जागपुर) जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है । बाढ़ के कारण इन घाटों की मिट्टी का कटाव हो रहा है जिससे न केवल वन संपदा को नुकसान हो रहा है, बल्कि धार्मिक आस्था

भी संकट में है । इन घाटों के संरक्षण के लिए पक्के घाटों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे इन धार्मिक स्थलों की स्थिरता वनी रहेगी और वन संपदा को भी बचाया जा सकेगा ।

अंत में, मैं बालाघाट-सिवनी क्षेत्र में स्थित पुराने गढ़ों और बंधों के सीमेंटकरण की आवश्यकता पर जोर देना चाहूंगी । यदि इन गढ़ों और बांधों का सीमेंटकरण किया जाता है तो जल संचयन और जल संरक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार होगा ।

अब मैं एक महत्वपूर्ण तुलना करना चाहूंगी । कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार के कार्यों के बीच की स्पष्ट अंतर को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है । जहां पहले कांग्रेस सरकार ने जल संकट पर अधिक ध्यान नहीं दिया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल के महत्व को समझते हुए इसे अपनी प्राथमिकताओं में शुमार किया ।

कांग्रेस के शासन में जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्रालय जैसी योजनाओं का अभाव था । जल संकट से निपटने के लिए स्पष्ट नीति और कार्यवाही की कमी थी । वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल संरक्षण, जल प्रबंधन और जल शक्ति के क्षेत्र में कई ठोस कदम उठाए हैं । नमामि गंगे योजना, जल जीवन मिशन, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं से यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार ने जल संकट को गंभीरता से लिया है और जल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए कारगर कदम उठाए हैं ।

कांग्रेस सरकार की नीतियों में दीर्घकालिक दृष्टिकोण की कमी थी जबकि मोदी सरकार ने ठोस और स्थायी समाधान प्रदान किए हैं । जहां पहले जल संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था, अब मोदी सरकार ने जल संचयन, पुनर्चक्रण और वितरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है ।

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य किए गए हैं, वे हमारे देश के जल संसाधन प्रबंधन में एक नया अध्याय जोड़ते हैं । जल संकट से निपटने के लिए सरकार की योजनाओं और प्रयासों के परिणामस्वरूप हम जल संकट की दिशा में सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं । बालाघाट और सिवनी क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना मेरी प्राथमिकता है । मैं इस सरकार से निवेदन करती हूं कि इन योजनाओं पर शीघ्र कार्यवाही की जाए और हमारे क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता दी जाए ।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): In 2025, we stand here debating the failure of the Ministry of Jal Shakti to deliver this basic necessity to millions across the country. Instead of ensuring access to clean drinking water, efficient river

management, and sustainable groundwater use, this Ministry has become a symbol of inefficiency and misplaced priorities. The biggest failure indicators are the massive budget cuts and underutilization of funds. In 2024-25, the Ministry allocated Rs. 70,163 crore to JJM but spent only Rs. 22,694 crore ? the lowest expenditure since 2020-21. Now, in 2025-26, Rs. 67,000 crore has been allocated, but can we trust that these funds will be effectively used, or will they once again remain unspent while millions suffer?

Even when funds are released, the Centre makes it nearly impossible for States to utilize them. In 2024-25, only 31 per cent of the Centre?s allocation for JJM was released. Why? Because the States had to first contribute their share ? a condition that is impossible for many financially struggling States to meet. Odisha, for instance, was allocated Rs. 2,456 crore but has been able to use only Rs. 1,056 crore because of bureaucratic roadblocks. This is not cooperative federalism; this is fiscal strangulation.

India is facing a massive groundwater depletion crisis. Over 80 per cent of rural drinking water and 50 per cent of urban water comes from groundwater, but our aquifers are running dry. In Odisha, groundwater extraction has reached dangerous levels of 48 per cent, and yet there is no serious policy response from the Ministry of Jal Shakti. Both districts of my constituency Koraput and Rayagada, where agriculture and daily life depend on groundwater, are on the verge of a water catastrophe. The Government?s Atal Bhujal Yojana (ABY) was supposed to tackle groundwater depletion, but as of 2025, only 60 per cent of its targets have been met. The Centre claims to be focusing on conservation, but what it is really doing is letting the crisis spiral out of control while making big claims on paper.

In Odisha, the failure of Jal Jeevan Mission is particularly glaring. In Koraput and Rayagada, many villages still rely on contaminated groundwater because the JJM pipeline projects have either not been completed or are lying defunct. The Government has focused on installing pipelines, but has ignored water sources ? leading to drying reservoirs and dysfunctional supply networks. Fluoride and iron contamination in drinking water remains a severe issue, affecting thousands of

families in these districts. The biggest flaw in this scheme is its sustainability. Even in areas where pipes have been laid, the lack of water recharge plans means that sources will run dry in just a few years. The Jal Jeevan Mission is a classic example of this Government?s obsession with short-term numbers instead of long-term impact.

Irrigation projects across the country have become synonymous with delays, mismanagement, and unfulfilled promises, failing to deliver the intended benefits to farmers and rural communities. One of the most recent failures is the Telengiri Multi-Purpose Irrigation Project in Koraput. This project was meant to provide water security to thousands of farmers, but farmers faced problems due to its leakage, draining away the very water that was meant to sustain agricultural livelihoods. For the last few months, water has been continuously flowing out of the reservoir due to an unresolved leakage. The water level is falling drastically, and farmers now fear they will not get water. The consequences are devastating ? 24,000 farmers in Koraput are on the verge of losing their crops. And what is the Government?s response? Denial, inaction, and empty promises. Instead of immediately fixing the problem, officials dismiss it as a minor issue, while the farmers are left to bear the brunt of their incompetence. The additional chief engineer of the Telengiri project has already admitted that plugging will be done only after the water level reaches 596 metres, which means farmers will not receive water soon.

Another glaring example of the Government?s apathy toward farmers is the Parbati Giri Mega Lift Irrigation Project in Jajpur district. Designed to irrigate 12,800 hectares of farmland, it has been 15 years since its launch, yet 40 per cent of the targeted area still does not receive water. Farmers have repeatedly reported irregularities in the project, alleging that officials have manipulated data to claim success, even when thousands of hectares remain dry. A local farmers? organization, had to complain with the State Water Resources Department, exposing the misrepresentation of irrigation coverage and the misallocation of funds.

How is it possible that after 15 years, this Government still cannot provide irrigation to farmers who depend on it? How is it possible that even after crores of rupees have been allocated, irrigation systems are still non-functional? Farmers from villages like Bhagirathpur, Sarangapur, and Tikarapada are still waiting for water to reach their fields. Pipelines were laid on their land a decade ago, yet not a single drop of water has flowed through them. These farmers were promised prosperity and financial stability; instead, they have been left with debt, despair, and loss.

This pattern of failure is not limited to a few projects. It is widespread. Take the case of the Tulasipur Pump House project, which was supposed to lift water from the Kharasrota River and irrigate 2,000 hectares of farmland. Farmers in Barchana, Bari, Dharmasala, and Korei were supposed to benefit from this initiative. But to this day, the water supply remains non-functional, leaving thousands of farmers at the mercy of erratic monsoons. These failures are not accidents. They are consequences of deliberate mismanagement, unchecked corruption, and a lack of accountability. This Government?s irrigation policies are nothing but a web of broken promises that serve bureaucrats and contractors while destroying the lives of farmers.

The failures in irrigation management are not confined to a few States but are a nationwide concern, affecting both farmers and the agricultural sector at large. In Goa, over a period of 12 years, there has been a 20.9 per cent decline in minor irrigation schemes, reducing the number to 6,133. This decline includes 739 groundwater schemes (15 per cent) and 883 surface water schemes (30 per cent) that are no longer operational. Consequently, the irrigation potential utilized in Goa has decreased by 3.7 per cent compared to the previous evaluation in 2013-14. The financial burden of these irrigation schemes predominantly falls on the farmers themselves. Farmers have to get their own pump sets and they take huge loans for that which further exacerbates their plight.

One of the most hyped projects of this Government has been Namami Gange, which was supposed to clean and rejuvenate the Ganga River. Yet, after thousands

of crores spent, the reality remains grim. The pollution levels in the Ganga are still alarmingly high, sewage treatment plants remain non-functional, and waste disposal continues unchecked. The Namami Gange programme has turned into a financial black hole. Since 2014, only 69 per cent of the funds allocated have actually been spent. The Government has shut down factories along the river in the name of pollution control, but most sewage treatment plants remain non-functional or poorly maintained. In 2024, only 52 per cent of the targeted sewage treatment capacity had been achieved, while untreated sewage continues to be dumped into the river. Even worse, of the Rs. 876 crore collected under the Clean Ganga Fund, only Rs. 383 crore has been sanctioned for actual projects. What about the rest? It is lying unused while the river continues to suffer. But the failure is not limited to the Ganga. Other rivers ? Yamuna, Krishna, Godavari, and Mahanadi ? are also dying due to pollution, encroachment, and mismanagement. The Vamsadhara River, which is critical to Rayagada district, faces severe contamination and water-sharing disputes, yet the Ministry of Jal Shakti has failed to resolve these issues or initiate a proper rejuvenation plan.

Similarly, the Mahanadi River dispute remains unresolved, as Chhattisgarh continues to divert water meant for Odisha, affecting thousands of farmers and villages. The Ministry has refused to intervene effectively, failing to protect Odisha?s water rights. While the Government boasts about cleaning one river, dozens of other rivers across the country remain polluted, over-exploited, and neglected. If this Government does not act now, India is heading toward a catastrophic water crisis. And when that happens, history will remember this Ministry as the one that drowned the country in its own incompetence.

India?s per capita water availability has now dropped to 1,486 cubic metres per year, well below the 1,700 cubic metre threshold for water stress. By 2050, it is projected to fall to 1,228 cubic metres. This means that in just 25 years, India could be facing an all-out water emergency. Yet, what is the Centre doing? Instead of tackling the root causes, this Government is busy making tall claims and deflecting responsibility onto the States. While the Government boasts about urban

infrastructure projects, rural and tribal communities are still struggling for drinking water. In Koraput and Rayagada, entire villages lack access to clean drinking water, forcing people, especially women, to walk for miles just to fetch water from unsafe sources.

Where is Swachh Bharat, Modiji? You go to real India, and you will find piles of garbage on roads, clogged drains overflowing with filth, and waste mismanagement at its peak. The Government claims India is open defecation free (ODF), yet in rural areas, people still have to defecate in open fields due to lack of functional toilets. You promised a clean India, but what has happened to Swachh Bharat Cess, which was collected from the hard-earned money of citizens? Where has that money gone?

Gandhi ji envisioned a clean and self-reliant India, but he would have been heartbroken to see how his image has been misused by this Government to promote a scheme riddled with corruption and mismanagement. Instead of true cleanliness, Swachh Bharat Mission has become a propaganda tool, an excuse for officials and contractors to pocket funds, and an obstacle for States in utilizing other developmental grants. What is even more shocking is the cost of toilet construction. The Government sets a minimal allocation per toilet, but every MP in this House can tell you that the money is never fully disbursed. Corruption is rampant, from local contractors to officials at the highest level. There are thousands of incomplete and non-functional toilets across the country built on paper but not in reality.

While the Government talks about clean India, the reality is stinking landfills in every major city, choked drainage systems, and incomplete waste management projects. The Government claims that toilets have been built across India, but how many of them are actually usable? In many rural areas, toilets have been built but remain locked because there is no water supply. Sewage systems remain unfinished, leading to overflowing drains that spread diseases. Waste collection is irregular and inefficient, with garbage accumulating in urban and semi-urban areas. Sanitation workers continue to work in inhumane conditions, with manual scavenging still prevalent, despite being banned. Even under the Swachh Bharat Mission, many

toilets in rural areas lack running water, making sanitation unusable and ineffective. How can we claim to have achieved Swachh Bharat when people do not even have water to use these facilities?

This is the high time that we come together, not just as representatives of our constituencies but as custodians of the future. For too long, we have witnessed misuse of funds, unfinished irrigation projects, non-functional toilets, and worsening groundwater depletion. The crisis is here, and we must act now with a sustainable, transparent, and corruption-free approach. We must have an independent audit of Swachh Bharat and Jal Jeevan Mission to expose corruption, mismanagement, and non-functional projects. Ensure proper water supply to every constructed toilet and invest in faecal sludge and sewage treatment instead of just building infrastructure. Stop misuse of Swachh Bharat Cess and provide full transparency on funds collected and spent. Fix failing irrigation projects like Telengiri Dam, Parbati Giri Mega Lift, and Tulasipur Pump House to ensure farmers get water. Resolve water-sharing disputes like the Polavaram and Mahanadi conflicts and protect Odisha?s water rights. Strengthen groundwater conservation by enforcing rainwater harvesting, curbing industrial over-extraction, and improving Atal Bhujal Yojana. End water privatization to ensure drinking water and irrigation remain affordable and accessible to all, especially rural and tribal communities. We demand accountability; we demand action; and we demand justice for every citizen still struggling for water.

***m61 श्री नवीन जिंदल (कुरुक्षेत्र) :** मैं जल शक्ति मंत्रालय के नेतृत्व में भारत सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों और उन चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ । जो हमारे जल संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के मार्ग में अभी भी बाकी हैं । यह एक ऐसा मंत्रालय है जो न केवल जल की शक्ति को संरक्षित करता है, बल्कि जीवन की नींव को मजबूत करने का संकल्प भी रखता है ।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह मंत्रालय जल संरक्षण, स्वच्छता, और समृद्धि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति का प्रतीक बन गया है ।

नमामि गंगे मिशन हमारी सबसे महत्वाकांक्षी पहलों में से एक है । वर्ष 2024 में इस मिशन ने 25 परियोजनाओं को पूरा किया, जिसके साथ अब तक कुल 303 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं । इसके साथ ही 2,056 करोड़ रुपये की लागत से 30 नई परियोजनाओं को मजूरी दी गई, जिससे कुल स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 488 हो गई है, जिनकी लागत 39.730 करोड़ रुपये है ।

सीवरेज आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच 305 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उपचार क्षमता के सृजन और पुनर्वास के लिए 12 परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं, जबकि 750 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाली 16 परियोजनाएँ पूर्ण हुईं ।

आज तक, गंगा बेसिन में 203 सीवरेज परियोजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं, जिनसे 6,255 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज उपचार क्षमता और 5,249 किलोमीटर सीवर नेटवर्क का निर्माण हुआ है । यह न केवल गंगा की स्वच्छता का प्रमाण है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के पति हमारी प्रतिबद्धता का भी परिचायक है ।

विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से चल रही बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना 19 राज्यों और तीन केंद्रीय एजेंसियों में 736 बाँधों के पुनर्वास को लक्षित करती है । यह योजना जल संसाधनों की सुरक्षा और संस्थागत गजबूती को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही है । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2021-26) के तहत 93,068 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है, जिससे लगभग 22 लाख किसानों को लाभ होगा । 2016-17 से 2023-24 तक 34.63 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के लक्ष्य के मुकाबले 25.80 लाख हेक्टेयर (लगभग 74.5%) क्षमता सृजित की गई है । यह हमारे अन्नदाताओं के लिए जीवन रेखा बन रही है ।

बाढ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2024 तक बाढ़ प्रबंधन के लिए 7,136 करोड़ रुपये और सीमा क्षेत्र पुनर्वास के लिए 1,258.73 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है । जलाशयों के मरम्मत, नवीकरण और पुनर्जनन योजना के तहत 12वीं योजना से अब तक 3,075 योजनाएं चल रही हैं, जिनकी लागत 2,834.692 करोड रुपये है । मार्च 2024 तक 554.279 करोड़ रुपये की सहायता जारी की गई और 2,192 जलाशय पूर्ण हुए, जिससे 2.41 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में से 2 लाख हेक्टेयर बहाल हुई । यह जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण में हमारी सफलता को दर्शाता है । जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को हुई, जब देश के केवल 3.23 करोड ग्रामीण परिवारों (17%) के पास नल से जल था । तब से अब तक 12.19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए गए हैं ।

आज 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.45 करोड़ (79.81%) के पासं स्वच्छ नल जल उपलब्ध है । यह जीवन की गुणवता और सुगमता को बढ़ाने का एक ऐतिहासिक कदम है ।

देश भर में 2,180 जल गुणवता परीक्षण प्रयोगशालाओं में से 1,580 को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला मान्यता बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है । स्कूलों में 98.26% तक नल जल पहुँच चुका है और 86.44% गाँव खुले में शौच से मुक्त प्लरा मॉडल बन गए हैं । स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 अक्टूबर 2014 को 38.7% स्वच्छता कवरेज थी जो अब 11.80 करोड व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण से 100% हो गई है । यह स्वच्छता क्राति का प्रमाण है । इन उपलब्धियों के बावजूद, जल शक्ति मंत्रालय के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं । पहली परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन । नमामि गंगे जैसी योजनाओं में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या बढ़ रही है, परंतु पूर्णता दर को और तेज करना होगा ।

दूसरी, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव । अनियमित मानसून और सूखे से जल संकट गहरा रहा है, जिसके लिए दीर्घकालिक रणनीति जरूरी है ।

तीसरी, आधारभूत संरचना का रखरखाव । सीवेज उपचार सयंत्रों और जलाशयों की निरंतर कार्यक्षमता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उपकरणों का पुराना होना और धन की कमी इसे प्रभावित करती है ।

चौथी चुनौती है जल गुणवता । यद्यपि प्रयोगशालाएँ बढ़ी हैं, परंतु प्रदूषण के बढ़ते स्तर और औद्योगिक अपशिष्ट से जल स्रोतों की शुद्धता खतरे में है । पॉचवीं, सामुदायिक सहभागिता । जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की सफलता जन जागरुकता और उपयोग पर निर्भर है. जिसे और मजबूत करना होगा ।

अंत में. वितीय स्थिरता । इन योजनाओं के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है. और विश्व बैंक जैसे बाहरी सहायता पर निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशी ससाधन जुटाने की जरूरत है । जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण, स्वच्छता. और जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में अद्वितीय योगदान दिया है । यह प्रगति भारत को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है । परंतु, चुनौतियों हमें याद दिलाती हैं कि यह यात्रा अभी अधूरी है । हमें तकनीकी नवाचार, सामुदायिक भागीदारी, और नीतिगत दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना होगा । आइए, हम सब मिलकर इस संकल्प को साकार करें कि जल हर जीवन तक पहुँचे, और स्वच्छता हर घर की शान बने ।

धन्यवाद, जय हिंद ।

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : मैं वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांग पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ । आज में इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश भर में किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों पर प्रकाश डालना याहता हूँ । हमारी सरकार ने जल संरक्षण, सिंचाई, और स्वच्छता के क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं ।

मैं कुछ प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर प्रकाश डालना चाहूंगा । राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 में 25 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, जिससे अब तक कुल 303 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं । इसके अतिरिक्त 2,056 करोड़ की 39 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 488 और कुल लागत 39,730 करोड़ रुपये हो गई है ।

सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है । जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच 305 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता के निर्माण/पुनर्वास के लिए 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है । इसी अवधि में, 750 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता के निर्माण/ पुनर्वास के लिए 16 परियोजनाएं पूरी की गई हैं ।

आज तक गंगा बेसिन में 6,255 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता के निर्माण और 5,249 किलोमीटर सीवर नेटवर्क बिछाने के लिए कुल 203 सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है । यह प्रगति हमारी पवित्र नदी गंगा को स्वच्छ बनाने की सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है ।

केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) नदियों को आपस में जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसके कार्यान्वयन की शुरुआत हो चुकी है । यह परियोजना जल संकटग्रस्त बुदेलखंड क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी । इस परियोजना को दिसंबर 2021 में 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ मंजूरी दी गई है । जिसमें केंद्र सरकार का 19,317 करोड़ रुपये का सहयोग शामिल है ।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP) के तहत देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 736 चयनित बांधों के पुनर्वास का कार्य प्रगति पर है । यह विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली परियोजना हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है ।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत 2021-26 के लिए 93,068 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है, जिससे लगभग 22 लाख किसानों को लाभ होगा । वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के माध्यम से 25.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है, जो लक्षित क्षमता का लगभग 74.5 प्रतिशत है । यह योजना हमारे किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है ।

बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) के तहत भी सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है । दिसंबर 2024 तक, इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8394.73 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है । इसके अतिरिक्त, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (RRR) योजना के तहत, 12वी पंचवर्षीय योजना के बाद से 2192 जल निकायों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है, जिससे सिंचाई क्षमता में सुधार हुआ है । जल जीवन मिशन (JJM) हमारी सरकार की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है । 15 अगस्त 2019 को इस मिशन की घोषणा के समय, देश के केवल 17 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन थे । आज इस मिशन के तहत लगभग 12.19 करोड नए नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे अब देश के लगभग 79.81 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है । यह ?ईज ऑफ लिविंग? को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । कोविड-19 महामारी के बाद और शहरीकरण में वृद्धि के कारण, भारत में कई शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) और विशेष रूप से ठाणे जैसे शहर जल प्रबंधन के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं । इन ULBs को अपने क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छोटे चेक डैम जैसे जल संरक्षण ढांचे बनाने में सक्षम बनाने हेतु सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए ।

जल शक्ति मंत्रालय देश के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को सफलतापूर्वक जारी रखे और शहरी स्थानीय निकायों की जल संबंधी आवश्यकताओं पर भी ध्यान दे ।

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The vision of Antodaya-reaching benefit to the most marginalised person is the governing philosophy championed by Hon'ble Prime

Minister Sh. Narendra Modi ji

For this, our government has worked tirelessly to ensure "Sabka Saath, Sabka Vikas across our nation

Among the various rights, I believe right to food and right to safe drinking water are the most fundamental and most important rights

Since COVID, our government has provided "free ration" to over 80 crore citizens to ensure food safety for all

Poverty Reduction

I commend the dynamic leadership of PM Modi ji

A recent study by Economists has found that Extreme Poverty, which is measured at Rs 150 per day Income

Has been reduced to below 1% of the population in India

When compared to World Bank's US3.65 Purchasing Power Parity - or Rs 350

India's poverty rate has fallen from 52% in 2011-12 to 15% in 2023-24.

This unprecedented growth in income has been made possible due to the dynamic leadership of PM Modi ji

Har Ghar Jal

Like I said before, right to food and right to safe drinking water are the most fundamental and most important rights

Along with food security, our government is working to secure clean and safe drinking water for all

Towards this, our Govt has allocated Rs 99503 cr to Jal Shakti Minister

Through the "Jal Jeevan Mission - Har Ghar Jal Yojana" the Ministry is working to provide drinking water for all - FY 2025-26 allocation Rs 67000 cr

In 2019 only 16% of the households had tap water connection

Today, over 80% of the households in the country have tap water

I thank and applaud PM Modi Ji, and Jal Shakti Minister CR Patil ji for their dynamic leadership, which is making this possible.

Swachh Bharat Gramin

In addition to providing water, Jal Shakti Ministry is also working to provide modern sewerage facilities for our villages

Towards this, our Govt has allocated Rs 7192 crore in FY 2025-26

Today, 96% of the villages have become Open Defection Free

73% of the villages have Solid Waste Management arrangements

Our nation is moving towards swachhta at a rapid pace.

Jal Jeevan Mission in West Bengal

Sir, despite adequate support from the Central Government, the WB Govt has failed to implement "Har Ghar Jal" scheme properly

I am sad to report that today West Bengal is among the worst performing states in India

Only 54% completed till date - that too only on paper

Along with this, there has been massive Ghotala

In my Darjeeling constituency alone 714 projects worth Rs. 2451 cr 'Har Ghar Jal? schemes have been granted by the Central Government

But, if you come on the ground you will not even see 30% work completed

Money arrives in Kolkata and disappears

Ghotala in Darjeeling and Kalimpong Region

In Darjeeling and Kalimpong hill region The 'Jal Jeevan Mission' projects in the region are being developed, managed and implemented by a separate division of PHE created by the West Bengal Government - Neorakhola W/S & MTC Division in collaboration with the Gorkhaland Territorial Administration.

The said agencies have created the DPRs for Har Ghar Jal projects in our region without making any provisions for identifying the source of the water.

Almost all the DPRs are only concerned with laying of the pipes, constructing storage tanks, however it has now come to fore that no provisions for identifying the water source and how water will flow from the source to the tanks have been undertaken.

The WB Govt has failed to develop any monitoring mechanism for the project development and implementation

This has resulted in massive ghotala in almost all the 'Jal Jeevan Misison' projects implemented in the region.

I have myself visited various parts of constituency extensively and witnessed the shoddy work being undertaken first hand.

In addition, I have received over 100 complaints on phone, and around 20 written complaints from across the constituency accompanied with pictures and videos highlighting the shoddy work being undertaken.

Please note that the Darjeeling and Kalimpong districts are situated in the mountains, with fragile ecology and environment and geological conditions. We get very high degree of rainfall, and landslides are a regular occurrence.

Hence it is important for the pipes laid, the route they follow, the tanks being built are constructed maintaining to the highest standards of engineering. However, that is not happening.

Nature of Ghotalas

Instead of Gl or steel pipes, majority of the contractors are using cheap plastic pipes, which won't even last for a year.

In almost all places, pipes are being laid down randomly without conducting any sort of engineering survey.

Majority of the times, these pipes are being left hanging precariously, or supported by thin pieces of wood instead of a proper platform being created.

It is but given that none of these pipes will survive the oncoming monsoon season, and I fear they will be the cause of landslides in many places, as the pipes have been laid blocking the natural drains through which rainwater flows.

In most of the cases, the contractors are using existing tanks, some built during the British times, and merely painting over them or putting a thin layer of plaster and passing them off as tanks built under the 'Har Ghar Jal' scheme.

In places where new tanks have been built, the quality of the material used has been very low standard, and the tanks themselves will come undone after a year or two.

Request on Har Ghar Jal

Since this is perhaps a one-time investment by the Govt of India to provide drinking water to each and every household across the country, I am most worried that the entire project will fail to make any actual change in Darjeeling Lok Sabha Constituency due to the massive ghotala that is going on, and the shoddy nature of the work that is being undertaken.

Given these, I am therefore requesting you to kindly have the allegations of corruption duly inspected by Central Investigative Agencies and take due action against the culprits as per the law.

Stop release of all payments to all 'Jal Jeevan Mission' projects until and unless projects are given 'satisfied all criteria and was implemented properly? certificate by the DISHA Committee.

Teesta Floods

Further the absolute discrimination against Darjeeling hills, Teral, Dooars region by the WB Govt is shameful.

In October 2023, massive floods on Teesta River severely impacted nearly 500 families, causing loss of homes, agricultural land, livelihoods, and claiming 12 lives in Darjeeling and Kalimpong.

Despite this, the WB Government has refused to recognize it as a "disaster". Because of which, people have been deprived of PMNRF and SDRF support.

Now Teesta is flooding again, the river-bed has risen by over 50-feet, WB Govt has not given any support to the people.

We are also part of India; our people also pay taxes.

In fact, our region contributes the highest amount of revenue per capita to the WB Govt. Revenue from Teesta's hydro-dams alone exceeds Rs 750 crores annually. totalling over Rs 7500 crores in the past decade.

However, whenever we are in need, we are treated as second class citizens.

This is why, people have been demanding a Separate State Gorkhaland. Because, people feel WB Govt will always discriminate against our region.

Request on Teesta

I request Central Govt to declare Teesta Floods as National Disaster, and provide Central Support to the people, not only in Sikkim but also in Darjeeling and Kalimpong.

Further, I have received a response from MoS Jal Shakti Sh. Raj Bhushan Choudhary ji, informing me that "Brahmaputra Board has taken up the preparation of master plan for Teesta river sub-basin for sustainable development and utilization of Water Resources in the region including flood and erosion management, catchment area treatment using State of the Art Technology."

In this regard, I am inviting the Board Members to visit Teesta river basin in Darjeeling and Kalimpong Districts, to meet with the victims of 2023 Teesta Floods and develop plans that will contribute towards preventing and/or minimizing the impacts of floods on river Teesta.

I will be most grateful, if the Brahmaputra Board members visit Darjeeling and Kalimpong to take stock of the situation, and physically verify the need for embankments and developing of critical infrastructure along Teesta River.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The Ministry of Jal Shakti has been allocated Rs.99,503 crore in 2025-26, which is marginally higher than the budget allocation in 2024-25 which was Rs.98,714 crore. The revised estimate for expenditure in 2024-25 is lower than the budget allocation. It may be because of the reduced allocation to the Jal Jeevan Mission at the revised stage. Over the last ten years, 76 per cent of the budget allocation has gone to the Department of Drinking Water and Sanitation. Until 2021-22 the gap between allocations to the two departments remained less than Rs.50 crore. In 2021-22 allocation for Drinking Water and Sanitation almost tripled over the previous year, largely driven by increased allocation to the Jal Jeevan Mission.

Jal Jeevan Mission is a centrally sponsored scheme which was launched in 2019 to provide assured tap water supply to all 19 crore rural household and public institutions by 2024. As on January 21, 2025, 15 crore households i.e. 80 percent of all households have been provided with functional household tap water connections. The scheme has been extended until 2028. Though all rural households in eight states and three Union Territories have tap water connections, less than 60 percent households in four states namely, Jharkhand, Kerala, Rajasthan and West Bengal been covered as on January 2025. Around 2.5 lakh villages have reported 100 percent tap connectivity, but 1.5 lakh villages have self-certified their ?Har Ghar Jal' status. For certification the Gram Panchayats need to pass a resolution self-certifying the Har Ghar Jal' status.

Jal Jeevan Mission guidelines require that at least 55 litres of water per person per day be supplied. Water supply be considered regular if it is available daily, for all 12 months. The functionality Assessment Repor on 2022 states that in Kerala, Sikkim and Tripura water supply to more than 40 percent of households did not meet quality standards. As Jal Jeevan Mission is a Centrally sponsored scheme funding is divided between Centre and States on 50:50 basis and for Himalayan and North-Eastern states on 90:10 basis. But it is pertinent to note that in 2024-25 only 31 percent of the Central share allocated has been released as of February 25. The Standing Committee on Water Resources has noted in 2024 that cost overruns have also created additional financial burden on States, which delayed the release of the States' share.

Another flagship programme is Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY). As large part of India agricultural land is rain-fed and only less than half of net sown area is under irrigation, PMKSY was launched in 2015-16 to Increase cultivable area under assured irrigation. Accelerated Benefit Programme (AIBP) AND Har Khet Ko Pani (HKKP) are two components of this Scheme. Since 2016-17 a total Rs.59,34 crore has been allocated toward PMKSY and 87% has been the actual expenditure. AIBP's Irrigation potential target was 15 million hectares. Up to March 2023, 48 percent of the target i.e. 7.2 million hectares has been met. Since AIBP's inclusion under PMKSY in 2016-17, 63 per cent of projects i.e. 62 out of 99 have been completed. Odisha's Brahmani Left Canal is one of such project which is yet to be completed. There has been cost over-run and needs attention of the Union Government for speedy completion of this project and would irrigate large areas of Dhenkanal and Cuttack districts of Odisha. In 2018, a CAG audit of AIBP found delays in project completion ranging from one of 18 years. This has led to a cost overrun almost thrice the original cost of 84 crores while targeted benefits were not realised.

River Inter-linking have been a cherished dream of may visionaries of this country. Thirty river-linking projects have been identified under the National Perspective Plan of 1980. The aim of these projects is to link water deficit river basins with

water-surplus basins. As of now only one, namely, Ken-Betwa link project have been completed. Odisha, in that aspect has number of river valleys which are rain-fed rivers. At times, some rivers go dry. They are not perennial rivers. Yet during non-monsoon times these valleys need water. Therefore, Dams been constructed on river Mahanadi, Brahmani, Indravati. Accordingly, Barrages been constructed too. There is a proposal to link these Barrages through canals. The Anandpur Barrage over Baltarani need to be connected with Bidydharpur Barrage over Salandi river and further be linked with Buddha Balanga river is a long-cherished dream of Bhadrak and Baleswar district of Odisha. Similarly, connecting Samal Barrage over river Brahmani with Anandapur Barrage over Baitarani in the North and with Mahanadi in the South will increase the irrigation potential of Jajpur and Cuttack district of Odisha. For project like these, Union Government's active support is required. I would say, primarily inter-linking of rivers within the State should be taken up first instead of drawing ambitious projects of inter-State in nature.

Central Water Commission's estimate show that in 2021, 1486 cubic metres of water was available per person in India. Annual per capita water availability less than 1700 cubic metres indicates a water-stressed condition. Our country receives water from river, groundwater and rain. A calculation says 61 percent of utilizable water is from surface water sources, and 39 percent from ground water. In India 90 percent of water is used for agriculture, 7 percent for domestic use, and 2 percent for industrial purposes. For the last four decades ground water has been the main source of water for irrigation. Though India is not a water deficit country, severe neglect and lack of water resources monitoring have led some regions to experience persistent water stress. 80 percent of India's rural drinking water, 50 percent of urban drinking water and two-thirds of water for irrigation comes from groundwater resources. Since almost 90 percent of extracted groundwater is used for irrigation, it becomes important to examine water-use efficiency in agriculture. Free electricity supply for agricultural use has led to indiscriminate water extraction and subsequent wastage.

Water in all its forms is a single entity, with groundwater and surface water continuously interacting with each other. Therefore, management and governance of water resources needs an integrated, holistic and multidisciplinary approach. Central agencies and State departments should work together to conserve and manage groundwater. Water management is an inter-disciplinary field, connecting geosciences, environmental sciences and socio-economic sciences. The Central Water Commission, established since 1945 and Central Ground Water Board established since 1971 have continued unreformed for decades are working in an isolated manner. It is high time a National Water Commission be established as the apex body dealing with water policy, data and governance in India.

Pollution of water is another issue which needs attention of the Government. We have Central Pollution Control Board which monitors and assesses the quality of river stretches across the country. Release of effluents into the rivers is the main reasons that pollute the river waters. As most of the factories release pollutant waste into the river and sewage of cities and towns are left into the rivers untreated, some rivers have become pollutant to such an extent that its waters are not used for bathing, what to talk of human consumption.

Groundwater assessment in India have identified the presence of contaminants like fluoride, arsenic nitrate, iron and heavy metals beyond permissible limit. In Odisha, river like Brahmai have become pollutant because of large discharge of effluent into the river. There are areas in Khandapada and Bhapur Block of Nayagarh district where groundwater is arsenic and it is causing health problems. Large number of people facing kidney problem in Narasinghpur, Baramba, Tigiria of Cuttack district of Odisha because of contaminant water, both ground and surface water. I draw the attention of the Government to take steps to provide adequate, safe potable water in this region.

Though management of floods and erosion falls under State jurisdiction, the Union Government provides technical guidance and financial assistance. Hirakud Dam construction was completed in 1957 which has tamed floods of Mahanadi to a great extent. But number of big barrages been constructed in the catchment area of

Mahanadi in Chhattisgarh which has curtailed steady water flow and during the non-Monsoon period, the reiver has become totally dry.

The new Jobra Barrage was constructed in 1979 and it also needs upkeepment. Two things need to be considered on urgent basis. Firstly, Hirakud Dam needs proper care and water flow into its reservoir be uninterrupted so that on the downstream there would be no difficulty in getting water. Support be provided to construct at least seven more barrages on the downstream of Hirakud on Mahanadi where water reservoirs be constructed in the riverbed. Before I conclude I must say, let us ensure that water is made available for diverse water needs, such as domestic use, sanitation, irrigation and industrial use. Let us ensure conservation of rivers and other water bodies.

Thank you.

***m65 श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) :** माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2024 के दौरान जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने कई नई पहल की हैं और महत्वपूर्ण परिणाम/मील के पत्थर हासिल किए हैं । वर्ष 2024 में विभाग की कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने वर्ष 2024 में 25 परियोजनाएं पूरी कीं, जिसके परिणामस्वरूप अब तक कुल 303 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और ₹ 2,056 करोड़ की लागत से 39 नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिससे कुल ₹ 39,730 करोड़ की लागत से 488 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं ।

वर्ष 2024 के दौरान अन्य प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

01 मार्च 2023 को माननीय प्रधानमंत्री ने हुगली, पश्चिम बंगाल से ₹ 575 करोड़ की तीन परियोजनाओं का उद्घाटन किया ।

02 मार्च 2024 को माननीय प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद, बिहार से ₹ 2,189 करोड़ की लागत वाली बारह परियोजनाओं का उद्घाटन किया ।

02 अक्टूबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री ने 1,555 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली दस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया । इनमें से उत्तर प्रदेश और बिहार में 534.25 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया । माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास (निर्मल गंगा के अंतर्गत) किया गया ।

4 जनवरी 2024 को माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने उत्तर प्रदेश के बागपत में ₹ 77.36 करोड़ की लागत से 2.4 किमी इंटरसेप्शन और डायवर्जन (आई एंड डी) नेटवर्क के साथ 14 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का उद्घाटन किया ।

18 जनवरी 2024 को माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में 370 करोड़ रुपये की लागत वाली 220 एमएलडी मेरठ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) इंटरसेप्शन और डायवर्जन (आई एंड डी) परियोजना की आधारशिला रखी ।

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम)

?जल शक्ति अभियान- कैच द रेन (जेएसएः सीटीआर) 2024? अभियानः पानी को सभी का व्यवसाय बनाने और पिछले वर्षों में जल शक्ति अभियानों की सफलता से उत्साहित होकर, माननीय जल शक्ति मंत्री ने 09.03.2024 को अपनी श्रृंखला में 5वां ?नारी शक्ति से जल शक्ति? थीम पर ?जल शक्ति अभियान: कैच द रेन-2024? का शुभारंभ किया ।

?जल संचय जन भागीदारी? पहल

जेएसएः सीटीआर अभियान को और गति देने के लिए 06.09.2024 को सूरत, गुजरात में ?जल संचय जन भागीदारी? पहल शुरू की गई है । माननीय प्रधान मंत्री ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्त्व पर जोर देते हुए एक आभासी संबोधन दिया । इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य औद्योगिक घरानों, नागरिक निकायों और जल क्षेत्र के उत्साही लोगों से सीएसआर फंड द्वारा समर्थित वर्षा जल संचयन, जलभृत पुनर्भरण और बोरवेल पुनर्भरण के माध्यम से जल पुनर्भरण को बढ़ाना है ।

केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी): नदियों को आपस में जोड़ने वाली पहली परियोजना है, जिसके लिए कार्यान्वयन शुरू हो चुका है । यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले पानी की कमी से जूझ रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी होगी, जिसमें क्रमशः पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुर और रायसेन तथा बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले शामिल हैं ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 25.12.2024 को खजुराहो (मध्य प्रदेश) में केबीएलपी की आधारशिला रखी ।

इस परियोजना को आठ वर्षों में मार्च, 2030 तक पूरा करने की योजना है ।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

2021-26 के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) में 93,068 करोड़ रुपये का प्रावधान अटल भूजल योजना (अटल जल) किया गया है, जिससे लगभग 22 लाख किसानों को लाभ मिलेगा ।

अटल भूजल योजना (अटल जल)

अटल भूजल योजना (अटल जल) भारत सरकार की 6000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य देश के सात राज्यों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में 229 प्रशासनिक ब्लॉकों/तालुकाओं की 8203 जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में चिन्हित जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और मांग पक्ष हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करना है । विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित यह योजना 1.04.2020 से 6 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित की जा रही है ।

लगभग 6.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ड्रिप, स्प्रिंकलर, मल्चिंग, फसल विविधीकरण आदि सहित कुशल जल उपयोग प्रथाओं के अंतर्गत लाया गया है ।

ग्राम पंचायत स्तर पर 70,000 से अधिक कुओं के जल स्तर की निगरानी की जा रही है तथा इसकी जानकारी समुदाय के साथ साझा की जा रही है ।

भारत जल सप्ताह 2024 के दौरान नई दिल्ली में डेनमार्क, गुयाना, तंजानिया एवं जिम्बाब्वे जैसे विदेशी राष्ट्रों के मंत्रियों के साथ माननीय जल शक्ति मंत्री की द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं ।

आपने मुझे सदन में जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चल रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ । जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है तथा यह सुनिश्चित करता है कि घरेलू उपयोग, स्वच्छता सिंचाई और औद्योगिक जैसी विविध जल आवश्यकताओं के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए । यह मंत्रालय देश में नदियों और अन्य

जल निकायों के संरक्षण को भी सुनिश्चित करता है । भारत सरकार देश के 140 करोड़ नागरिकों की जल की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है । इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने 67,000 करोड़ रूपये के प्रावधान के साथ वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया है । इस विस्तार का उद्देश्य देशभर के हर ग्रामीण घर को स्वच्छ पेयजल प्रदान करना, पानी की पहुंच में महत्वपूर्ण सुधार करना है और समुदायों के लिए दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है । जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस संबंध में तमाम सराहनीय कदम उठाए गए हैं ।

मेरे क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई की सुविधा नहीं है । वालिया, झगडिया, नेतरंग, डेडियापाडा, सागबारा में सिंचाई की सुविधा नहीं है । डेडियापाडा, सागबारा में सिंचाई हेतु जो बांध बने हैं, उनमें कर्जण डैम और नर्मदा डैम के विस्थापित लोग शामिल हैं जिन्होंने सिंचाई की सुविधा हेतु अपनी कीमती जमीन दी है उन्हें ही सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है ।

गुजरात में जो नर्मदा डैम बना है । उससे पूरे गुजरात, सौराष्ट्र तथा कच्छ और भुज में सिंचाई हेतु पानी मिलता है । कर्जण डैम और उकाई डैम दक्षिण गुजरात का पूरा क्षेत्र कवर करता है । देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों के कारण पूरे गुजरात में पानी की समस्या हल हो गई है ।

परन्तु कुछ डैम वाले इलाकों में पानी उपलब्ध नहीं है । उन इलाकों में लिफ्ट करके पानी की आपूर्ति की जा सकती है । इस संबंध में मैंने डेडियापाडा में गंगापुर डैम की भी मांग की है । इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त स्थानों में तत्काल सिंचाई तथा पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप जल सुरक्षित देश बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए मैं माननीय जल शक्ति मंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

SHRI RAMESH AWASTHI (KANPUR): I express my views on the DFG for Jal Shakti Ministry. At a time when the world is burdened by climate change, failing to provide drinking water and struggling to manage its natural resources, India, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, has taken bold and transformative steps to ensure water security, conservation, and equitable distribution. Access to clean and safe drinking water is not just a basic necessity; it is a fundamental right and a cornerstone of development. While many nations are still grappling with the challenges of water scarcity, India has demonstrated an

unwavering commitment to tackling this crisis head- on through initiatives like the Jal Jeevan Mission, Atal Bhujal Yojana, and the ambitious Namami Gange Programme.

National Ganga Plan & the Kumbh Mela:

- At Mahakumbh 2025 in Prayagraj, the Namami Gange Pavilion has emerged as a symbol of India's unwavering commitment to protecting and rejuvenating the sacred Ganga River. Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, this grand event has witnessed unparalleled success, bringing millions together in a spiritual and cultural confluence. The Ministry of Jal Shakti's Namami Gange Pavilion has captivated visitors with its cutting-edge technology, breathtaking displays, and deep cultural significance. The Interactive Biodiversity Tunnel immersed people in the sounds and sights of Ganga's rich ecosystem, reminding everyone of their duty to protect its purity. The Prayag Manch platform provided real-time insights into the river's health, while models of sewage treatment plants and riverfront developments, showcase the government's relentless efforts in conservation. The presence of a reading corner by the National Book Trust and contributions from IIT Delhi, the Wildlife Institute of India, and the Ganga Task Force made this pavilion an educational powerhouse for future generations.
- A significant testament to the Modi government's dedication to Ganga rejuvenation is the substantial budgetary increase for the National Ganga Plan. The Budget Estimate (BE) for 2025-26 has been set at ₹3,400 crore, marking an increase from the BE 2024-25 of ₹3,345.70 crore and a sharp rise from the Revised Estimate (RE) 2024-25 of ₹3,000 crore. This represents a 13.33% increase from the RE 2024-25, underscoring the government's unwavering resolve to ensure cleaner, healthier rivers. This financial commitment is further strengthened by nationwide public awareness campaigns, ensuring that the mission is not just about policy but a people's movement for safeguarding India's most sacred river.

- This spectacular initiative has not only raised awareness but has also forged a deep emotional and cultural bond between the people and the river that has nourished India for centuries. The Ganga is not just a river, it is the lifeline of India, a sacred entity, and an economic backbone.

Jal Jeevan Mission:

Since the launch of Jal Jeevan Mission (JJM) - Har Ghar Jal in 2019 under the visionary leadership of the BJP-led NDA government, India has witnessed a historic transformation in rural water supply. Today it delivers tap water to an astounding 12.20 crore additional rural households, a monumental leap that now covers 79.74% of rural India. Today, 15.44 crore families no longer have to struggle for clean drinking water, their children no longer trek miles for a basic necessity. This mission is not just about numbers, it's about dignity, health, and a promise fulfilled.

A watershed moment has been reached, with 188 districts, 1,838 blocks, 1,09,996 Gram Panchayats, and 2,33,209 villages proudly reporting 'Har Ghar Jal' status, ensuring every home has access to safe, clean water. In a testament to efficiency and determination, 11 States and Union Territories, including Goa, Gujarat, Punjab, and Arunachal Pradesh, have achieved 100% tap water coverage, proving that with strong leadership and unwavering commitment, even the most ambitious dreams can become reality.

This is more than just a policy, it's a revolution that is quenching the thirst of the nation, empowering women, securing children's health, and bringing hope to every doorstep.

Despite challenges like water scarcity, difficult terrains, and compliance issues in some states, the Modi government has taken proactive steps such as interest-free capital assistance to states, capacity-building programs like the Nal Jal Mitra Programme, and convergence with schemes like MGNREGS to ensure sustainability. The government has also launched the Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain campaign, with the 2024 theme "Nari Shakti se Jal Shakti", recognizing the crucial role of women in water conservation. With the extension of JJM until 2028

and enhanced budgetary support, the BJP-led government remains dedicated to ensuring universal tap water access, transforming rural lives, and fulfilling its vision of a Viksit Bharat.

Swachh Bharat Mission - Grameen (SBM-G)7:

The mission achieved its first milestone in 2019 when 100% of villages across all 36 States and UTs were declared Open Defecation Free (ODF), building on this success, Phase II of SBM-G, launched in 2020, has made extraordinary strides in ensuring ODF sustainability, solid and liquid waste management, and holistic village cleanliness.

As of today, a remarkable 460% increment in ODF Plus villages from 1 lakh in 2022 to over 5.61 lakh in 2024, with over 69% of these having achieved ODF Plus Model status. More than 11.77 crore Individual Household Latrines (IHHLs) and 2.49 lakh Community Sanitary Complexes (CSCs) have been constructed, ensuring universal sanitation access in rural India. The Swachhata Hi Seva campaign (2024) witnessed record- breaking participation of over 30 crore people, demonstrating how deeply this movement has engaged the public. Moreover, a groundbreaking study published in Nature (2024) confirms that SBM-G has directly contributed to reducing infant and under-five mortality rates, saving 60,000-70,000 infant lives annually, a monumental achievement in public health.

To further accelerate this mission, the Budget Estimate (BE) for 2025-26 stands at 7,192 crore, reinforcing the government's unwavering commitment to rural sanitation and hygiene. With a strong data-driven approach, real-time monitoring through the SBM- G dashboard, and impactful public engagement campaigns, the BJP and NDA government have ensured that Swachh Bharat is not just a mission but a people's movement, bringing cleanliness, dignity, and better health to every corner of rural India.

Ken-Betwa Interlinking Project (KBLP):

India's unpredictable climate has caused immense loss of lives, livelihoods, and hardships for farmers, especially in drought-prone regions. Recognizing this crisis, Prime Minister Narendra Modi took a historic step in 2024 by inaugurating the Ken-Betwa River Linking Project (KBLP), India's first under the National Perspective Plan. This transformative project is set to irrigate 10.62 lakh hectares of land, bringing relief to farmers across the Bundelkhand region of Madhya Pradesh (MP) and Uttar Pradesh (UP), where recurring droughts have long plagued agriculture.

KBLP will directly benefit districts[10] like Chhattarpur, Tikamgarh, Panna, Sagar, Damoh, and Datia in MP, as well as Banda, Mahoba, Jhansi, and Lalitpur in UP, ensuring reliable water supply for farming communities. Additionally, 62 lakh people (41 lakh in MP and 21 lakh in UP) will gain access to 194 Million Cubic Metres (MCM) of drinking water, drastically improving living conditions. The project is also set to generate 130 MW of renewable energy (103 MW hydropower, 27 MW solar), marking a major step towards sustainability and energy self-sufficiency.

Beyond irrigation and drinking water, KBLP is a game-changer for rural India, creating jobs, revitalizing local economies, and empowering countless farming families. This visionary initiative is not just about managing water, it's about securing India's future, and ensuring that no farmer is left behind in the fight against climate adversity.

Conclusion:

I would like to conclude by saying that the journey of Viksit Bharat is not a distant dream but a reality unfolding before our own eyes. Under the decisive leadership of the BJP-led-NDA government, India is witnessing an era of unprecedented transformation where every drop of water, every strengthened household, and every empowered village stands as proof of a nation- rising unstoppable and resolute towards its destiny of greatness.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : मैं जल शक्ति मंत्रालय की वित्त वर्ष 2025-26 की अनुदान माँग पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ ।

सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और निर्देशन में माननीय जल शक्ति मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ वित्त वर्ष 2025-26 में जल शक्ति मंत्रालय के लिए कुल 99,503 करोड़ रूपए के बजट का भारी आवंटन किया गया है ।

इस बजट आवंटन से पूरे देश भर में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, जे.जे.एम विभाग, एस.बी.एम-जी विभाग, पी.एम.के.एस.वाई विभाग, नदी जोड़ो विभाग, नमामि गंगे विभाग एवं एबीवाई जैसे अति महत्वपूर्ण विभागों के जनहित की बड़ी- बड़ी परियोजनाओं को संचालित किया जायेगा ।

सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पूज्य श्रदेय भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करने के लिए नदी जोड़ो विभाग को बड़े पैमाने पर 3,400 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है, जिससे भारत की कई नदियों को आपस में जोड़कर जल की कमी वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति होगी, जिसका सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा ।

जल शक्ति मंत्रालय के लिए वर्तमान बजटीय व्यवस्था की एक और विशेषता यह है कि जल जीवन मिशन के लिए ग्रामीण परिवारों एवं सार्वजनिक संस्थानों को सुनिश्चित नल-जल आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रे वाटर प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित कर पानी के गुणवत्ता में सुधार की भी बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई है ।

वर्तमान बजट में जल शक्ति मंत्रालय के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के तहत वर्षा की कमी वाले कृषि भूभाग को सिंचित करने के लिए भी बड़े स्तर पर कदम उठाया गया है, जिससे देश के अन्दर वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों के किसानों को अपना कृषि उत्पादन करने में बड़े स्तर पर लाभ मिलेगा । इसी तरह अटल भूजल योजना के तहत भी देश के कई राज्यों के लिए विशेष धन का आवंटन किया गया है, जिससे भूजल के स्तर को ऊँचा उठाते हुए सिचाई एवं पीने के पानी की सुलभ उपलब्धता का प्रयास किया गया है ।

माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रारंभ में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा मैया के प्रति जिस श्रद्धा भाव के आवाहन के साथ गंगा माता की सफाई के लिए जो संकल्प लिया गया था, वह आज मूर्त रूप लेता दिख रहा है । इस कार्य में सबसे बड़ी भूमिका जल शक्ति मंत्रालय के नमामि गंगे योजना की है । इस योजना के माध्यम से आज भारत के अन्दर माई स्वरूप कई नदियों की सफाई के अभियान कई स्तर पर चलाये जा रहे हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं ।

अंत में, माननीय महोदय को मैं पुनः हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया । इसी के साथ अब मैं अपने संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र, बिहार में जल शक्ति मंत्रालय से सम्बन्धित कुछ कार्यों कों कराने के लिए महोदय के माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ:-

1. माँझी नगर पंचायत में वाटर ट्रीमेंट प्लांट का निर्माण ।

2. बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत, बिहार राज्य अंतर्गत सारण जिला के पानापुर से तरैया होते हुए अमनौर एवं मकेर से जाने वाले सारण तटबंध को विशेष पैकेज देकर मजबूतीकरण का कार्य ।

3. सारण जिला अंतर्गत माँझी नगर पंचायत माँझी में सरयू नदी के तट पर विधुत शवदाह गृह का निर्माण ।

4. सारण जिला अंतर्गत माँझी प्रखंड के डुमाईगढ़ में विधुत शवदाह गृह का निर्माण ।

5. सारण जिला अंतर्गत पानापुर प्रखंड के ग्राम पंचायत भोरहा के सारंगपुर में गंडक नदी के तट पर विधुत शवदाह गृह का निर्माण ।

6. सारण जिला अंतर्गत लहलादपुर प्रखंड के ग्राम दंदासपुर में गंडक नदी के तट पर विधुत शवदाह गृह का निर्माण ।

7. बाढ़ प्रबधन योजना के तहत, बिहार राज्य अंतर्गत सारण जिला के तरैया के हसनपुर बनिया सगुनी तक नये तटबंध का निर्माण कराया जाये ।

***m68 श्रीमती संजना जाटव (भरतपुर) :** आज देश में पानी की बहुत बड़ी समस्या है । मैं खासकर अपने संसदीय क्षेत्र भरतपुर में पानी की समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी । मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा खारा पानी है, जिसमें नाईट्रेट फलोराइड होता है । इसके कारण हजारों लोग बीमार हो रहे हैं । इस समस्या को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है । पानी की समस्याओं से शहर और आसपास के इलाकों, गांवों में विशेषकर कठूमर विधान सभा पानी की कमी से जूझ रही है । जल स्रोत, जैसे नदियां, जलाश्य, कुएं सूखते या घटते जा रहे हैं । इस कारण जल संकट बढ़ रहा है । सूखे जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं । मानसून में कम बारिश होने से जल संकट और भी गंभीर हो जाता है । नदियों और तालाबों का सही संरक्षण न होने के कारण पानी की समस्या बढ़ रही है ।

जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य किये जा रहे हैं, वे भी धरातल पर नहीं हैं । शहर और गांवों में नलकूप तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन बोरवेल में पानी न होने के कारण नलों में पानी नहीं आता है । यदि कहीं आता भी है, तो खारा पानी आता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है । इस पानी को पीने से कैंसर आदि जैसी घातक बीमारियां होती हैं । खारे पानी से खेती की सिंचाई करने पर खेती खराब हो जाती है ।

कठूमर विधान सभा क्षेत्र, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, अर्ध-शुष्क जलवायु और जल संकट की समस्याओं से जूझ रहा है । यहां पीने और कृषि योग्य पानी की पूर्ति के लिए एक समग्र और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है ।

ये उपाय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक हो सकते हैं । वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) ? घरों, स्कूलों, पंचायत भवनों और अन्य सार्वजनिक भवनों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जाए । छतों पर गिरने वाले वर्षा जल को भंडारण टैंकों में संग्रहित किया जाए । खेत तालाब (Farm Ponds) बनाए जाएं, जहां बारिश का पानी एकत्र किया जा सके । नहरों, जोहड़ों, और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर वर्षा जल को संरक्षित किया जाए । सूखे और क्षतिग्रस्त बोरवेल्स का उपयोग जल पुनर्भरण के लिए किया जाए । मिट्टी संरक्षण और वनस्पति क्षेत्र बढ़ाकर वर्षा जल का रिसाव सुनिश्चित किया जाए ।

पुराने तालाबों और जोहड़ों की मरम्मत और गहरीकरण किया जाए ? इन जलाशयों का उपयोग पेयजल और सिंचाई के लिए किया जा सकता है । छोटे चेक डैम और एनिकट (जलरोधक संरचनाएं) बनाकर पानी को रोकने और भंडारण करने की व्यवस्था की जाए ।

यमुना नदी से पानी लाना ? यमुना नदी के पानी को कठूमर क्षेत्र तक लाने के लिए गुड़गांव कैनाल प्रोजेक्ट या अन्य नहर परियोजनाओं का विस्तार किया जाए । अंतरराज्यीय जल वितरण समझौतों के माध्यम से हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी साझा करने की व्यवस्था की जाए । सरकार द्वारा सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए ।

सूखा-सहिष्णु फसलों को बढ़ावा ? बाजरा, मूंग, चना, ज्वार जैसी फसलें उगाने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए ।

जल गुणवत्ता में सुधार ? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (Community Water Purification Plants) लगाए जाएं । फ्लोराइड और खारे पानी की समस्या से निपटने के लिए आरओ सिस्टम और अन्य शोधन तकनीकों का उपयोग किया जाए ।

धन्यवाद ।

***m69 श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) :** इस बार वर्ष 2025-2026 के केन्द्रीय बजट में जल शक्ति मंत्रालय को 99,503 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।

वर्ष 2025-2026 के बजट में जल शक्ति मंत्रालय को आवंटित बजट में किस योजना और किस विभाग के लिए कितना बजट रखा गया है, वह मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ । पेयजल एवं स्वच्छता के विभाग के लिए कुल 74,226 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिनमें से जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपये, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 7,192 करोड़ रुपये, जल संसाधन विभाग के लिए कुल 25,277 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है । जिनमें से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8,260 करोड़ रुपये, नदी अंतर्योजन के लिए 3,400 करोड़ रुपये, नमामि गंगे के लिए 2,400 करोड़ रुपये, अटल भूजल योजना के लिए 1,780 करोड़ रुपये इस बात आवंटित किए गए हैं ।

अब मैं जल जीवन मिशन योजना के बारे में बताना चाहूँगा । इस योजना को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था, जिसके तहत अब तक 80 प्रतिशत ग्रामीण घरों में पीने के पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है, जो वर्ष 2019 में 15 प्रतिशत था । इसके लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2019 से रुपये 3.6 लाख करोड़ खर्च किए हैं । वर्ष 2028 तक हमारा लक्ष्य 100 फीसदी घरों में पानी पहुँचाने का है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के इस सपने को यथाशीघ्र पूरा करेगी । इसके लिए जल जीवन मिशन का बजट बढ़ाकर 67 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

अब मैं हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियाँ गिनाना चाहता हूँ, जो काम कभी सबसे ज्यादा 70 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वह काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कर दिखाए हैं । इनमें से कुछ विशेष उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं ।

वर्ष 2020-21 से केंद्र सरकार पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है । वर्ष 2022-23 में इस योजना के लिए एक लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं । इसमें से 4 हजार करोड़ रुपये जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए रखे गए हैं । वर्ष 2025-26 में पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

वर्ष 2014 में सभी ग्रामीण परिवारों के खुले में शौच को खत्म करने के लिए यह मिशन शुरू किया गया था । हमारी सरकार ने हर घर में शौचालय बनवाकर दिए । यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2019 में हमने इस योजना के पहले चरण को प्राप्त कर लिया है । योजना के दूसरे चरण का उद्देश्य सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल गाँव बनाना है । स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण योजना के तहत आने वाले 5.86 लाख गांवों में से हमने 30 जनवरी 2025 तक 5.63 लाख यानी 96 प्रतिशत गाँवों को प्लस मॉडल गांव बनाने में सफलता पाई है ।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत में जल संसाधन प्रबंधन, बाढ़ और सिंचाई प्रबंधन, भूजल विकास और नदियों के पुनरुद्धार के लिए कार्य करता है और इसके लिए वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों से 17 प्रतिशत अधिक है ।

हर खेत को पानी:-

वर्ष 2016 और वर्ष 2023 के बीच कुल 6.9 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और 55 प्रतिशत परियोजनाएँ (10,642 में से 5,893) पूरी हो चुकी हैं ।

महोदय, हमारी सरकार ने वह कर दिखाया है, जो सबसे लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस नहीं कर पाई । इस बात पर मुझे गर्व होता है ।

आवश्यकता:-

1. वर्ष 2015-16 के दौरान बने भैरवी जलाशय जिसका कुल जल संग्रह 120 वर्ग मीटर है, जिससे दो प्रखंडों गोला और दुलमी के गांवों को पानी पहुँचना था, जिससे वहाँ के लाखों किसानों को लाभ मिलता, जिसका निर्माण कार्य आज तक पूर्ण नहीं हो पाया । कृपया, इसे पूर्ण कराया जाए ।
2. कोनार डैम से निर्गत कोनार नहर सिंचाई परियोजना को पूर्ण करवाया जाए ।
3. तिलैया डैम से सिंचाई हेतु लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था की जाए ।

धन्यवाद ।

***m70 श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) :** मैं जल शक्ति मंत्रालय के लिए 2025-26 के बजट में प्रस्तावित ₹99,502 करोड़ की मांग का पूर्ण समर्थन करता हूँ, जिसमें जल संसाधन विभाग के लिए ₹25,276 करोड़ और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए ₹74,226 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

यह बजट जल संरक्षण, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे देशभर में जल संकट के समाधान को गति मिलेगी ।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के तहत 2024 में 25 परियोजनाएँ पूरी हुईं, जिससे अब तक 303 परियोजनाएँ सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं । इसके अतिरिक्त 39 नई परियोजनाएँ ₹2,056 करोड़ की लागत से स्वीकृत की गई हैं, जिससे कुल स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 488 हो गई है ।

गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने और उसकी अविरल धारा बनाए रखने के लिए 6,255 MLD सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता विकसित की गई है और 5,249 किमी लंबी सीवेज नेटवर्क बिछाई गई है ।

कृषि सिंचाई क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के लिए 2021-26 के दौरान ₹93,068 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है । अब तक 34.63 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 74.5% यानी 25.80 लाख हेक्टेयर पहले ही पूरा किया जा चुका है ।

बाढ़ प्रबंधन और जल निकाय पुनर्जीवन (FMBAP & RRR Scheme) के तहत अब तक ₹7,136 करोड़ की केंद्रीय सहायता राज्यों को दी गई है और 2192 जल निकायों का पुनरुद्धार पूरा किया जा चुका है, जिससे 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बहाल हुई है ।

पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र में, जल जीवन मिशन (JJM) के तहत 2019 में ग्रामीण इलाकों में मात्र 17% घरों में नल जल कनेक्शन था, जो अब बढ़कर 79.81% हो चुका है । बिहार में 95.71% ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति मिल रही है और 98.26% स्कूलों में नल जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है ।

इसी तरह, 86.44% गाँव ODF Plus घोषित किए गए हैं । स्वच्छ भारत मिशन (SBM-G) के तहत 2014 में केवल 38.7% स्वच्छता कवरेज थी, जो अब 100% हो चुकी है । महाराष्ट्र में 129.01 लाख शौचालय बनाए गए हैं और 87.88% गाँव ODF Plus घोषित किए जा चुके हैं ।

अब मैं विशेष रूप से मुंबई और कोंकण क्षेत्र की जल समस्या पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । मुंबई महानगर को हर दिन 4,200 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तविक आपूर्ति 3,800 मिलियन लीटर है, जिससे 400 मिलियन लीटर की कमी बनी हुई है ।

आने वाले वर्षों में यह समस्या और विकराल हो सकती है, क्योंकि 2031 तक पानी की मांग 5,320 MLD और 2041 तक 6,424 MLD तक बढ़ने की संभावना है ।

झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजनाओं और नए निर्माण कार्यों के कारण यह संकट और गंभीर होता जा रहा है । इसे ध्यान में रखते हुए, गारगाई और पिंजाल बांध परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है, जिससे 1,305 MLD अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सके । इसके अलावा, अपशिष्ट जल पुनः उपयोग परियोजनाओं को मजबूत किया जाए, जिससे 2,464 MLD पानी को पुनः उपयोग में लाया जा सके । वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) और भूजल पुनर्भरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

कोंकण क्षेत्र में नई बाँध परियोजनाएँ लाई जानी चाहिए और चिपलून में वशिष्ठी नदी का पानीसमुद्र में बह जाता है, उसे उपयोग में लाने के कदम उठाए जाने चाहिए ।

अंत में, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जल शक्ति मंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि वे देशभर में जल संसाधन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में इतिहास रच रहे हैं ।

लेकिन हमें और भी अधिक प्रयास करने होंगे, विशेष रूप से मुंबई, कोंकण, बिहार और महाराष्ट्र में जल संकट से निपटने के लिए तेजी से नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देनी होगी और उनके लिए आवश्यक बजट आवंटित करना होगा । जल ही जीवन है, और इसका संरक्षण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए ।

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I express my wholehearted support for the Demand for Grants 2025-26 presented by our esteemed Jal Shakti Minister, Shri C.R. Patil Ji. Under the visionary leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, the Jal Shakti Ministry has taken remarkable strides toward ensuring water security for our nation.

The total allocation of Rs. 99,503 crore to the Ministry of Jal Shakti, which is 93 per cent higher than the revised estimates for 2024-25, demonstrates the priority our Government places on water resource management. This substantial investment will undoubtedly accelerate our nation's progress toward comprehensive water security.

Under the visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, the Jal Jeevan Mission has transformed the rural landscape of India. From a mere

fraction of households with tap connections in 2019, today 15 crore households, constituting 80 per cent of all rural households, have functional household tap water connections. Eight States and three Union Territories have already achieved 100 per cent coverage, bringing the dream of "Har Ghar Jal" to reality. The allocation of Rs. 67,000 crore to this mission, a 195 per cent increase over the revised estimate for 2024-25, will further enhance our capabilities to reach every home.

The Swachh Bharat Mission-Grameen continues to make remarkable strides with an allocation of Rs. 7,192 crore. It is heartening to note that 96 per cent of SBM-G villages are now ODF Plus villages, and 73 per cent have self-certified as ODF Plus Model villages. The establishment of 978 Plastic Waste Management Units across the country further reinforces our commitment to comprehensive rural sanitation. These achievements are a testament to Prime Minister Modi Ji's vision of a clean and hygienic India, restoring dignity to millions of our citizens.

I commend the Department of Water Resources for its excellent work, which is reflected in its increased allocation of Rs. 25,277 crore, 17 per cent higher than the previous year. The Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana with an allocation of Rs. 8,260 crore, marking a 25 per cent increase, has already enabled the completion of 63 per cent of irrigation projects, bringing water to millions of hectares of agricultural land and directly benefiting our farmers. This initiative has significantly enhanced agricultural productivity and improved rural livelihoods across the country.

I must highlight the remarkable progress made in the Namami Gange programme, which has been allocated Rs. 2,400 crore, a 20 per cent increase over the previous year. The improvement in water quality of our sacred river Ganga, with dissolved oxygen levels and biochemical oxygen demand now within acceptable limits for almost the entire stretch, reflects the success of this initiative. The laying of 86 per cent of the targeted sewage network demonstrates our government's commitment to preserving our national river and cultural heritage.

The Atal Bhujal Yojana, with an allocation of Rs. 1,780 crore, a remarkable 197 per cent increase in this budget, has shown impressive results in groundwater management. With 57% of the total outlay already released to states and high utilization rates, this scheme exemplifies the effectiveness of community-led initiatives in natural resource management.

As we address the challenges of water stress in our country, I am confident that the integrated approach adopted by our Government will yield positive results. The formation of the National Inter-Departmental Steering Committee, with representatives from State Governments and Central Ministries is a step in the right direction for coordinated water management.

While I wholeheartedly support these national initiatives, I would like to bring to the attention of the hon. Minister some critical water management issues facing my Constituency of Pali. These challenges, if addressed within the framework of the Ministry's excellent initiatives, would significantly enhance water security in this water-stressed region of Rajasthan.

Firstly, I must highlight the critical condition of small and medium dams across Pali and parts of Jodhpur Districts that fall within my constituency. Most blocks in the region have one to three dams that serve as lifelines for irrigation and drinking water supply. However, many of these structures have deteriorated significantly due to sedimentation, structural degradation, and inadequate maintenance. The water storage capacity has reduced by approximately 30 per cent to 40 per cent in several cases, severely compromising their efficiency.

I request the Ministry for allocation of dedicated funds under the Dam Rehabilitation and Improvement Programme for comprehensive structural assessment and restoration of these vital water infrastructure assets. Modern technologies such as geomembrane lining, automated spillway gates, and advanced seepage control measures would significantly enhance their longevity and operational efficiency. Additionally, scientific desilting operations and catchment area treatment using watershed management approaches would substantially

improve the water retention capacity. These interventions would align perfectly with our government's commitment to water conservation and management.

Secondly, I propose the development of a model integrated dam system in Pali District, implementing the concept of dam interlinking at the micro level. This innovative approach would involve hydrological assessment, topographical mapping, and the construction of reinforced gravity-flow water transfer mechanisms between strategically located dams. Such a system would optimize water distribution, minimize transmission losses, and significantly reduce the distance between irrigation sources and agricultural fields, thereby enhancing water use efficiency by an estimated 25 per cent 30 per cent.

This model dam network could serve as a pioneering demonstration project for the entire Rajasthan region, incorporating water harvesting structures, solar-powered pumping systems, and real-time monitoring through IoT-based sensors. I request an allocation of approximately Rs. 75 to Rs. 100 crore for this integrated water management system, which would directly benefit thousands of farmers in the region.

My third point relates to the larger River Interlinking Project that our Government has championed. The dam interlinking initiative in Pali could serve as a valuable precursor and complementary component to the broader river interlinking vision. The hydraulic engineering knowledge, water balance methodologies, and environmental impact mitigation techniques developed through our local project would provide valuable inputs for similar initiatives across the country. I request the Ministry to consider allocating Rs. 25 crore to Rs. 30 crore specifically for technical studies and pilot implementation of dam interlinking structures in Pali District.

Perhaps the most pressing concern in my constituency is the severe pollution of the Bandi River and Nehra Dam due to untreated effluents from textile industries in Pali, Jodhpur, and Balotra.

I propose a three-pronged approach to address this critical issue. First, the establishment of advanced Common Effluent Treatment Plants (CETPs) with

tertiary treatment capabilities for the textile clusters. Second, the implementation of a closed-loop water recycling system where treated water from these industries could be channeled to the recently established refinery in Balotra, which currently draws fresh water from the Rajasthan Canal. This would create a sustainable industrial symbiosis, conserving approximately 10-15 million liters of fresh water daily.

Third, I recommend the development of a comprehensive river rejuvenation plan for the Bandi River, incorporating bioremediation techniques, constructed wetlands, and riparian zone restoration. This integrated approach would not only address the immediate pollution concerns but establish a sustainable water management model that balances industrial requirements with ecological preservation.

I urge the Ministry to consider allocating Rs. 150 crore to Rs. 200 crore under the National River Conservation Plan specifically for the Bandi River Basin, which would transform the water quality situation while preserving the economically vital textile industry that provides livelihood to thousands of families.

These proposals from my constituency represent strategic interventions that align perfectly with the Ministry's broader objectives of water conservation, equitable distribution, pollution control, and sustainable management. The implementation of these projects would directly benefit approximately lakhs of citizens while establishing replicable models for similar water-stressed regions across the country.

I express my sincere appreciation to the Hon'ble Minister Shri C. R. Patil Ji for his exemplary leadership of this vital ministry. The transformative initiatives outlined in this budget will undoubtedly propel our nation toward greater water security and prosperity. Under the visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, who has elevated water conservation to a Jan Andolan a people's movement India is witnessing an unprecedented water revolution. His foresight in creating the integrated Ministry of Jal Shakti and his personal commitment to

ensuring "Har Ghar Jal" demonstrates his deep understanding that water security is fundamental to our nation's development and the welfare of our citizens.

I am confident that the hon. Minister, guided by the Prime Minister's vision of "Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas," will give due consideration to these proposals that address both immediate challenges and long-term sustainability goals.

With these words, I wholeheartedly support the Demand for Grants for the Ministry of Jal Shakti for the year 2025-26.

Thank you.

SHRI AMAR SHARADRAO KALE (WARDHA): I am grateful to you and the party leadership for giving me an opportunity to express my views on demands for grants under the control of the Ministry of Jal Shakti.

India's population is 17 per cent of the world's total population. But, we have access to only 4 per cent of the world's fresh (drinking) water sources. Therefore, conservation and sustainable use of water resources is very important for us. The issue of water resources is very important and talking about this issue is a matter of loss for me as a farmer.

It is said - "Water is life. Where there is no water there is no life." Water is the most basic need of human life. It is a part of the Constitution of India Article 21 enshrines the right to life and inviolability of human rights. The biggest scheme of the Ministry is Jal Jeevan Mission (JJM). Prime Minister Narendra Modi launched this mission on August 15, 2019. It is promised to provide tap water to 19 crore rural households and public institutions by 2024. Even today if you go to the website of the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti India, it clearly says- "Water for every household by 2024." But, this is also a part of a long list of countless unfulfilled promises by the government as we all know. As of 16 March 2025, and this is data taken from your JJM dashboard, only 80 per cent of households have tap water connections. According to official guidelines, a water

supply is considered fully functional only when the tap connections are working regularly, there is sufficient water available, and the water quality is up to the prescribed standards. The JJM guidelines also say that at least 55 liters of water should be provided per person per day. Water supply will be considered regular only if it is done daily or on a fixed schedule. Accordingly it should be available throughout the year. But, how many houses have got the tap water connections and whether the guidelines being followed?

Most of the rural households are falsely claimed by the government to have been given water connection. If you admire its grand dashboard, if you look at it, it shows that 80% households across India have been given tap water connection. But, if you go and ask people, millions of people across the country are still struggling with water scarcity. Sir, the pipelines have been laid, but there is no water - they are just for show off and have become objects. Taps are installed, but no water comes out of them. That is contrary to your own instructions. But, all paper tap connections are shown as "active" on paper. Another problem is - if water does come, the quality is very poor. A total of 66 lakh samples were tested in 2024-25, out of which 3.3 lakh (5 per cent) samples were found to be contaminated. I have to ask - who was this plan ultimately made for? Did not this scheme meant to help the poor, weak and needy? Or NRR was only for those contractors - so they could make more money laying pipelines. Can we make our profit by contracting?

In the year 2020-21, the second phase of SBM-G was launched, which aims to convert all villages from ODF (Open Defecation Free) to ODF Plus by 2024-25. The model had to be changed in the villages. But, this too turned out to be another unfulfilled promise. under SBM-G Phase plastic waste management is a major target. According to this, plastic which cannot be recycled will be sent to Plastic Water Management Unit (PWMU) at block level. However, by December 2024, there will be only 978 MWWUs across the country. Operations are performed. Sir, there are more than 7200 blocks in the country. 13 states and union territories including Assam, Haryana and Rajasthan have no MWMU. There are only 21 blocks selected in Maharashtra which has more than 300 blocks. These are physical

route management units. How are you planning to achieve the objectives of any scheme with such a poor performance? The provision in the budget also does not show hope. In 2022-23, SBM-G rural budget was reduced by 28 per cent compared to 2021-22. From 2022-23, the Center will provide SBM-G to the States and Union Territories to release less than 50 per cent of the amount allocated for the scheme.

Sufficient funds, in 2022-23, for Maharashtra (including Haryana, Odisha and Telangana) was not given, how to work without money?

Atal Bhujal Yojna (ABY) aims to provide water resources to seven water stressed states. Groundwater resource management has to be improved through community-based techniques. Between 2020 and 2025, only 57 per cent (Rs. 3,421 crore out of Rs. 6,000 crore) of the total sanctioned amount was disbursed to states. Even Maharashtra, which has utilized 99 per cent of the funds so far, has only issued 55 per cent of the funds. North Maharashtra and Marathwada have been suffering from drought-like conditions for a long time. In 2018, NABARD rated the availability of water resources in Maharashtra as 'critical' and classified as 'critically endangered'. Most of the agricultural areas in the state depend on rain water. Poor farmers suffer the most from climate change and increased rainfall uncertainty. Even today, the net irrigated area in Maharashtra is only 31.28 lakh hectares, while the total sown area is 167.22 lakh hectares. The non-irrigated area is only 18%, much lower than the national average of 50 per cent. Relief has been repeatedly called for in drought-stricken areas, but no concrete steps have been taken yet. According to the official statistics of the National Crime Records Bureau (NCRB), Maharashtra has the highest rate of farmer suicides. Why has the government ignored this serious question so far? I demand that additional funds be allocated to improve availability and irrigation, which I hope will solve the acute water crisis in Maharashtra.

Any additional financial demand raised at state level or parliamentary constituency level can be added here. Jai Hind!. Jai Maharashtra.

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): I am grateful for this opportunity to present my views on the Demands for Grants for Jal Shakti. The Ministry had set an ambitious target of providing safe and adequate drinking water through individual household tap connections by 2024 to all households in rural areas. But it has fallen short of this target by around four crores. Despite this, the revised estimate of expenditure on the scheme in 2024-25 was Rs. 22,694 crore, the lowest-ever allocation. The budget estimate for 2025-26 is 5 per cent lower than the budget estimate of 2024-25. It is also not enough to provide tap connections; it is also necessary to ensure that these taps provide drinking water. Concerningly, only about one-sixth of India?s roughly 192 million households across 600,000 villages had a functional water tap. Further, the penetration of the scheme is concentrated in a portion of States, while some States like Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Manipur are lagging. The success of the scheme cannot be ensured without addressing issues without addressing implementation issues like depleting groundwater reserves, contamination, and terrain challenges.

Coming to Swachh Bharat Mission-Grameen (SBM-G) the budgeted estimates have decreased drastically since 2019. In 2019-20, the estimated budget allocation towards this scheme was 35 per cent less than in the previous year. It decreased again, by 28 per cent in 2022-23. The actual expenditure has been even less than the budget estimates for the last five years. SGB-M Phase II focuses on plastic waste management and calls for the setting up of plastic waste management units (PWMUs) at the block level. However, there are no operational PWMUs in 13 States and Union Territories.

The Finance Ministry?s decision to levy a 7 per cent interest rate in case States delay transferring funds to the nodal account may be well-intentioned. But it can prove counterproductive for States that are facing resource crunches.

Atal Bhujal Yojana must be expanded to cover more water-stressed areas across the country. Training for efficient water use must be amped up at all levels. And communities should be educated on simple methods of water conservation to avoid overreliance on groundwater. India extracts more groundwater than any other

country in the world; but instead of conserving it, we are depleting it at an alarming rate. The Atal Bhujal Yojana, meant to address this crisis, has been a failure due to poor implementation.

Over 60 per cent of districts in India are facing severe groundwater depletion. Unregulated industrial extraction continues unabated. Rainwater harvesting laws exist on paper but are rarely enforced. The Government needs to wake up to this crisis. Without urgent groundwater conservation measures, future generations will be left with barren lands and dry wells.

Launched with much fanfare and thousands of crores in funding, yet the Ganga remains polluted. The same is true for the Yamuna, Godavari, and Cauvery, which are choking with industrial waste and untreated sewage.

Sewage treatment plants (STPs) are underperforming or non-functional. Industries continue to dump pollutants into rivers with little to no accountability. Despite huge investments, independent reports show little improvement in water quality. Cleaning our rivers is not just about spending money ? it requires strong enforcement, transparency, and scientific planning, all of which are missing under this Government.

India is already experiencing more frequent floods and droughts due to climate change, yet the Government has no comprehensive strategy for climate-resilient water management.

Drought-prone regions lack proper water conservation measures. Flood-affected areas continue to suffer from poor infrastructure and disaster planning. There is no long-term policy for managing extreme weather impacts on water resources. The future of India?s water security depends on serious climate action and sustainable planning ? not just short-term, election-driven schemes.

Water is life. It is not just about infrastructure or budgets ? it is about the dignity, health, and survival of our people. But this Government has failed to

provide a real, long-term solution to India?s growing water crisis. I would like to make the following suggestions:

1. A complete audit of Jal Jeevan Mission to assess actual progress on the ground.
2. Strict groundwater regulations with penalties for overuse.
3. A scientific and accountable approach to river cleaning.
4. Decentralized, community-driven water conservation efforts.
5. A comprehensive, climate-resilient national water policy.

I would also like to take this opportunity to bring to the hon. Minister?s attention a critical issue affecting my constituency.

The Cauvery Integrated Drinking Water Project for Manapparai and Kulithalai Assembly constituencies is an urgent necessity for the people of this region. The Government of Tamil Nadu has already announced this project in the State Assembly and is committed to its implementation. However, for the project to move forward without delay, I request the immediate release of the Union Government?s share of Rs.590 crore.

This project will provide much-needed drinking water security to thousands of residents, and I urge the hon. Minister to take swift action to ensure its timely execution.

Thank you.

SHRI SACHITHANANTHAM R. (DINDIGUL): On behalf of CPI (M), I share my views on the Demands for Grants of the Ministry of Jal Shakti.

The population growth and improving living standards will result in an ever-increasing demand for high quality municipal and industrial water as well as an ever-increasing volume of effluents.

The quality of the drinking water is a primary determinant of human health.

Brazil has the world?s greatest renewable water resources, estimated at 8,647 BCM. It is estimated that Russia has a second-largest resources in the globe with volume of 4525 BCM. But India ranks eighth and produced 1.91 BCM of water.

According to the NITI Aayog?s survey, 70 per cent of the fresh water resources were found to be contaminated and India ranked 120th out of 122 countries in terms of water quality. Furthermore, 387 districts in India were contaminated by nitrate; 297 districts were contaminated by iron; 276 districts were contaminated by fluoride; and 36 districts were contaminated by arsenic.

The major sources of contamination were landfills, septic tanks, leaking gas tanks, and excessive fertilizer and pesticide use. A significant amount of untreated domestic effluent was also discharged into local waterways. This is attributable to the lack of adequate water treatment capacity.

A high-level multi-disciplinary technical panel within the Department of Drinking Water and Sanitation has recommended five technologies, three for safe drinking water and two for sanitation. These recommendations should be implemented.

Households use a variety of water sources to meet domestic water demand including wells, borewells, tankers, handpumps, ponds, and packaged drinking water. Packaged drinking water is commonly known as RO water jars. As this water is treated with reverse osmosis technology, packaged and refilled ROs are like plastic jars.

Providing free piped water supply to households, especially for poor people, is very essential.

***m75 श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) :** मैं जल शक्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2025-2026 पर अपने विचार व्यक्त करती हूं । पिछले एक दशक में मंत्रालय के कुल बजट का 76 प्रतिशत हिस्सा पेयजल और स्वच्छता विभाग को आवंटित किया गया है, जो दो प्रमुख योजनाओं जल जीवन मिशन (JJM) और स्वच्छ भारत

मिशन ग्रामीण (SBM-G) का संचालन करता है । इन योजनाओं ने ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की सुविधा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, जल जीवन का आधार ही नहीं, बल्कि जल जीवन का अभिन्न अंग भी है । यह हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है ।

हमारी दैनिक आवश्यकताओं के साथ-साथ जल, कृषि, उद्योग और समग्र आर्थिक विकास के लिए भी अपरिहार्य है ।

हमारी सरकार माननीय प्रधान मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और 'हर घर जल' के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है ।

देश भर में जल संसाधनों के प्रबंधन, विकास और संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 'सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास? के मंत्र के साथ हमारी सरकार जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है ।

मेरा दादरा और नगर हवेली प्रदेश अपनी विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के साथ, जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और विकास की विशेष आवश्यकता रखता है ।

अगस्त, 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में शुरू की गई ?जल जीवन मिशन? योजना की शुरुआत से ही हमारी सरकार ने हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा ।

'हर घर जल' मिशन के तहत हमारी सरकार ने अभूतपूर्व प्रगति की है । जब यह मिशन शुरू हुआ था तो केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति थी । आज मार्च, 2025 तक यह संख्या बढ़कर लगभग देश के 12.28 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति की जा रही है ।

नल से पीने योग्य जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं 'हर घर जल' मिशन को गति प्रदान करना और देश के हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुँचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार प्रतिबद्ध है ।

जल जीवन मिशन (शहरी) को सुदृढ़ करना और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी सभी घरों तक सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुँचाना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और सरकार उस पर तेजगति से काम कर रही है ।

नमामि गंगे कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है । गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता और निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है ।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) की स्थापना, नदी तटों का विकास और औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने जैसे कार्यों पर और तेज गति से काम हो रहा है ।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 60 प्रतिशत सिंचाई और 80 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति भूजल पर निर्भर है । भूजल के महत्व को समझते हुए अटल भूजल योजना का विस्तार किया जा रहा है । भूजल हमारे देश में सिंचाई और पेयजल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है । भूजल के सतत प्रबंधन और इसके अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए अटल भूजल योजना को और अधिक क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा । इसके तहत, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है और जल संरक्षण की तकनीकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ की घटनाओं को रोकने और बाढ़ प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने और सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएँ मिल सकेंगी और फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा ।

जल शक्ति अभियान जल संरक्षण के महत्व को जन-जन तक पहुंचाने और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए 'कैच द रेन' अभियान को और अधिक प्रभावी जा रहा है । इसके लिए जागरूकता कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है ।

दादरा और नगर हवेली में भी जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है, किन्तु अभी भी बहुत चुनौतियां हैं जिनका समाधान करना अति आवश्यक है, और मेरा पूर्ण विश्वास है की सरकार उस तरफ भी ध्यान देगी ।

मेरे लोकसभा क्षेत्र की जमीनी स्थिति अन्य जगहों से बिल्कुल अलग है जिसके विषय में मैं आपको विस्तार में बताना चाहती हूँ । दादरा नगर हवेली एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ

सैकड़ों गाँव पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसे हुए हैं । इन गाँवों में आज भी नल से जल योजना का लाभ महज 35-40 प्रतिशत घरों तक ही पहुँच पाया है । अब तो वहां हालत यह है कि लोग कई दिनों तक स्नान नहीं कर पाते । वहां महिलाएँ और बच्चियों को कई किलोमीटर पैदल चलकर जंगलों से पानी लाना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी असर हो रहा है । पानी की कमी के कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और खेती लगभग ठप्प है । क्षेत्र में भूजल दोहन 131.53 प्रतिशत तक पहुँच चुका है, जो बेहद गंभीर स्थिति है । भूजल स्तर का अत्यधिक दोहन और गिरता जल स्तर चिंता का विषय है। दादरा और नगर हवेली में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन रेट 131.53 प्रतिशत तक पहुँच चुका है । यह बेहद खतरनाक स्थिति है, जिससे भविष्य में जल संकट और गहराएगा ।

आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहती हूँ कि समस्याओं से ग्रसित लोगों को तत्काल राहत के लिए अधिक प्रभावित गाँवों में तुरंत पानी के टैंकरों से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जाए । स्थायी समाधान यह है कि जल जीवन मिशन के तहत दादरा नगर हवेली के इन ऊँचाई पर बसे, दूरस्थ आदिवासी गाँवों के लिए विशेष योजना बनाई जाए हर गाँव में ऊँची पानी की टंकी, पाइपलाइन और मोटर पंप की व्यवस्था की जाए । गाँवों में वाटर ATM / जल केंद्र जैसी सुविधा स्थापित की जाए ।

विशेष विकास पैकेज दी जाए । बुंदेलखंड की तर्ज पर हमारे क्षेत्र के लिए भी "आदिवासी जल संजीवनी योजना" लाई जाए, जिससे दादरा नगर हवेली और दमन दीव के ग्रामीण क्षेत्रों को राहत मिल सके ।

किसानों के लिए चेक डैम, छोटी नहरें, कुएं और जल संरक्षण परियोजनाएँ शुरू की जाएं, ताकि खेती संभव हो सके । जैसे देश के बड़े हिस्सों के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना शुरू की गई है, वैसे ही दादरा नगर हवेली और आदिवासी इलाकों के लिए भी विशेष जल परियोजना या पैकेज घोषित किया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र की दशकों पुरानी पानी की समस्याओं का स्थायी समाधान हो । मेरा माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि इन समस्याओं का तत्काल संज्ञान लें और आवश्यक कदम उठाएं । यह न सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र की जरूरत है, बल्कि हमारे आदिवासी भाई-बहनों का हक भी है ।

धन्यवाद ।

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) : मैं इस सदन में जलशक्ति मंत्रालय के 2025-26 के अनुदान मांग पर अपनी बात रखता हूँ । यह मंत्रालय देश में जल प्रबंधन, जल संरक्षण, सिंचाई और पेयजल जलापूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ा है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में

'जल जीवनं मिशन', 'अटल भूजल योजना', 'स्वच्छ गंगा मिशन' और अन्य जल संरक्षण योजनाओं को लागू किया गया है, जिससे देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है । सरकार का यह प्रयास सराहनीय है कि वर्ष 2025-26 के बजट में जलशक्ति मंत्रालय के लिए ₹97,278 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है । मोदी जी की सरकार की सोच है कि हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो और जलजनित बीमारियों से बचाया जा सके । इस योजना के अंतर्गत अब तक 12.5 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुँचाया गया है । सरकार ने 2024 तक हर घर नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें बहुत सफलता मिली है । महाराष्ट्र में अब तक 1.2 करोड़ घरों में नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है । पालघर जिले में भी 3.5 लाख से अधिक घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है, लेकिन कुछ आदिवासी क्षेत्रों में अभी और कार्य करने की आवश्यकता है । पालघर जिले के कुछ गाँवों में पाइपलाइन विस्तार की आवश्यकता है, ताकि 100% कवरेज सुनिश्चित हो सके ।

अटल भूजल योजना का उद्देश्य भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए सामुदायिक भागीदारी और जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है । सरकार चाहती है कि किसानों और ग्रामीणों को भूजल संकट से बचाने के लिए दीर्घकालिक समाधान दिया जाए । भूजल स्तर की गिरावट एक गंभीर समस्या बन चुकी है । इस योजना के तहत अब तक ₹15,000 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं । महाराष्ट्र में 1,200 से अधिक गाँवों में जल पुनर्भरण के लिए परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं । पालघर जिले में भूजल स्तर औसतन 2.5 मीटर प्रति वर्ष घट रहा है, इसे नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है । पालघर में सूखे से प्रभावित गाँवों में वर्षा जल संचयन और छोटे जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए ।

नदी पुनर्जीवन और जल स्रोतों का संरक्षण योजना का उद्देश्य देश की प्रमुख नदियों को स्वच्छ बनाना और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना है । सरकार नदियों को प्रदूषण मुक्त करना चाहती है ताकि जल संकट और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखा जा सके । गंगा, यमुना और अन्य नदियों की सफाई के लिए स्वच्छ गंगा मिशन को ₹9,225 करोड़ का बजट दिया गया है । महाराष्ट्र की गोदावरी, कृष्णा और भीमा नदियों के पुनरुद्धार के लिए विशेष पैकेज दिया गया है । पालघर जिले में प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है । पालघर के वसई-विरार क्षेत्र में जल निकायों के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष फंड की आवश्यकता है ।

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार योजना किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ प्रदान कर कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है । सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को जल उपलब्ध कराना है ताकि किसान सूखा और जल संकट से बच सकें । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत ₹20,500 करोड़ का आवंटन किया गया है । पालघर के किसानों को सिंचाई के लिए अधिक तालाबों और चेक डैम की जरूरत है । इस वर्ष महाराष्ट्र में 300 नई सिंचाई परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं । पालघर के आदिवासी क्षेत्रों में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता है ।

ग्रामीण एवं शहरी जल आपूर्ति योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए शुरू की गई है । सरकार हर नागरिक को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना चाहती है ताकि जल संकट समाप्त हो । जल संकट को दूर करने के लिए ₹50,000 करोड़ की योजनाएँ चल रही हैं । पालघर जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में टैंकर से पानी की आपूर्ति की जाती है. जिससे लोग परेशान होते हैं । यहाँ के गाँवों में दीर्घकालिक समाधान हेतु नदी जोड़ परियोजना और जल संचयन प्रणाली विकसित करने की जरूरत है । पालघर जिले में शहरी जल आपूर्ति के लिए अत्याधुनिक जल शुद्धिकरण संयंत्र की आवश्यकता है ।

आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है । जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों परिवारों को नल जल सुविधा मिली है । सिंचाई सुविधाएँ बेहतर हो रही हैं, और जल प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाया जा रहा है । भारत में पहली बार जल संकट को दूर करने के लिए इतनी व्यापक योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जो सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है ।

जल ही जीवन है और इसके कुशल प्रबंधन के बिना सतत विकास संभव नहीं है । इसलिए, मैं इस सदन से अनुरोध करता हूँ कि जलशक्ति मंत्रालय के अनुदान मांग 2025-26 को पूर्ण रूप से स्वीकृत किया जाए और इसमें आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाए, ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध हो सके ।

SHRI TANGELLA UDAY SRINIVAS (KAKINADA): I express my views on the Demand for Grants for the Ministry of Jal Shakti.

I extend my heartfelt congratulations to our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and the Minister of Jal Shakti Shri C.R. Patil Ji for their unwavering commitment to water security. This commitment is reflected in the Rs. 99,503 crore

allocated to the Ministry of Jal Shakti in the 2025-26 budget, a slight increase from the previous year?s allocation of Rs. 98,714 crore. In the past few years, we have witnessed transformative progress:

Under the Jal Jeevan Mission, 14 crore rural households now have access to tap water-a staggering leap from just 3 crore in 2019.

The Swachh Bharat Mission (Gramin) has made India 100 per cent Open Defecation Free (ODF), significantly reducing groundwater contamination risks.

The Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) has expanded irrigation facilities to lakhs of hectares, ensuring that farmers get the water they need to sustain their livelihoods.

all these achievements are commendable. But at the core of all these efforts lies one fundamental resource-groundwater. It is the backbone of our water security, fulfilling 60 per cent of irrigation needs, 85 per cent of rural drinking water demand, and roughly 45 per cent to urban water consumption. Yet, while we have focused on availability and conservation, one critical aspect remains largely overlooked the quality of our groundwater.

Millions of Indians especially in rural areas are consuming contaminated water. Their drinking water is polluted by fluoride, arsenic, heavy metals, and industrial waste. Even my home state, Andhra Pradesh, is no exception to this crisis.

All districts in Andhra Pradesh have recorded high nitrate levels in groundwater, a major cause for concern.

Across India, the number of districts with excessive nitrate levels has risen from 359 in 2017 to 440 in 2023, as per the latest Central Groundwater Board report. This is a serious health hazard, particularly for young children, and a growing source of environmental toxicity.

Additionally, 17 districts in Andhra Pradesh are struggling with excess fluoride in groundwater, which is directly linked to skeletal and dental fluorosis-a condition

that leaves entire generations suffering from bone deformities and chronic illness.

This problem is not just confined to Andhra Pradesh. Fluoride contamination is a major concern in Rajasthan, Haryana, Karnataka, Telangana, and other parts of the country.

Programs like Atal Bhujal Yojana and National Project on Aquifer Management attempt to regulate and conserve groundwater, but they fall short in addressing its deteriorating quality. We need dedicated, large-scale interventions-not just to store water, but to ensure that every drop is free from toxins.

I take this opportunity to highlight the commitment of our Deputy Chief Minister and Rural Water Supply Minister of Andhra Pradesh, Shri Pawan Kalyan Garu, who has made clean and safe drinking water a top priority for the state. Under his leadership, we are working towards comprehensive groundwater purification measures, strengthening water quality monitoring, and implementing scientific decontamination strategies to tackle fluoride and nitrate pollution. His vision is clear every household in Andhra Pradesh must not only have access to water but also be assured of its safety.

This fight cannot be left to the states alone. Groundwater contamination is a national emergency that demands urgent and decisive action. I urge the government to move beyond conservation and launch a National Mission for Groundwater Purification.

Many nations have faced severe groundwater crises and turned their situations around with strategic intervention. Australia, once grappling with high salinity and contamination, implemented large-scale groundwater treatment and recharge projects, combined with strict industrial regulations. Similarly, under this mission, we must enforce strict pollution controls, ensuring industries and agricultural sectors do not discharge toxins into groundwater. Real-time monitoring systems must be deployed nationwide, allowing us to track contamination and act swiftly.

At the regional level, we need large-scale groundwater purification plants in critically affected areas, working alongside aquifer recharge projects to restore and protect water sources. Decentralized treatment units must be set up at the community level, ensuring that even the most remote villages get access to safe drinking water. Nations like Israel have pioneered localized desalination and filtration techniques, proving that technology-driven solutions can be game-changers.

Finally, this mission must have dedicated funding and innovation support to promote advanced water purification technologies and assist states in implementing these solutions effectively.

Let us not wait for the crisis to deepen. Access to clean drinking water is not a privilege it is a fundamental right. Ensuring safe groundwater is not just about protecting health-it is about securing the future of our people, our farmers, and our economy.

Thank you.

SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY (NELLORE): I express my views on the Demands pertaining to the Ministry of Jal Shakti.

Water is the soul of the Earth. We have not inherited it from our forefathers, but on loan from our children and we have to handover to them, at least, as it was handed over to us is what Gandhiji said. This small statement has a huge meaning of what we have to do to optimally utilize, preserve and save this Mother Earth?s Nectar. So, the Constitution has given this responsibility to two Departments River Development and Ganga Rejuvenation and the Department of Drinking Water and Sanitation of the Ministry of Jal Shakti and also to Stats.

The Ministry of Jal Shakti has been given the mandate for development and management of water as a national resource and ensure that water is made available, optimally, for domestic use, sanitation, irrigation, industrial use and conserve rivers and other water bodies.

The hon. Minister?s efforts, I would say, paid off as he has got 93 per cent higher allocation for 2025-26 when compared to 2024-25 RE. Sir, the Ministry has got Rs.51,558 crore in 2024-25 RE and hon. FM allocated, for 2025-26, Rs.99,500 crore. So, I compliment the hon.Minister for getting sufficient money for next year to implement various schemes and programmes of the Ministry.

This Ministry is very, very important for my State of Andhra Pradesh, not because of Jal Jeevan Mission, Swachh Bharat Mission or PMKSY, but it is this Ministry which is supporting my State for construction of Polavaram Project which, once completed, transforms the face of Andhra Pradesh.

Before I make my submission on the Demands of the Ministry, I would like to make my submissions relating to Polavaram Project. The hon. FM has given Rs.5,936 crore for Polavaram for 2025-26. But, if one looks at the Expenditure Budget document, the revised cost of Polavaram is proposed at Rs. 30,436 crore and the balance Central grant for the project has been limited to Rs.12,157 crore. All I appeal to the hon. Minister is to provide sufficient and required money for land acquisition, rehabilitation and resettlement for displaced people and for completion of the project as our hon. CM, Shri Chandrababu Naidu, committed to complete the project by December, 2027.

The next point I wish to touch upon is Jal Jeevan Mission and Swachh Bharat Mission which are the two important Centrally-sponsored Schemes of the Department of Drinking Water and Sanitation. There is no doubt that allocation for JJM has increased three times for the next fiscal when compared to 2024-25 RE, but less than 5 per cent when compared to BE of 2024-25?s figure of Rs.70,163 crore. I am surprised that the scheme is yet to achieve 100 per cent household tap water connections and could achieve only 15 crore against the target of 19 crore connections, but how come that the Budget, when compared to BE of 2024-25, has been reduced.

When it comes to Andhra Pradesh, Sir, only about 74 per cent of households have got tap water connections and there are still 26 per cent households to get

piped drinking water. So, I appeal to the hon. Minister, since the scheme has been extended till 2028, to cover all households in my State with tap water connections by following the water quality standards, such as hardness, alkalinity, presence of chloride, ammonia, nitrate, etc.

Next, I come to Swachh Bharat Mission which has remarkably transformed our villages and the figures indicate that more than 96% of villages have been declared as Open Defecation Free. If one looks at the allocation for this scheme, Sir, Rs.7,200 crore was given for 2025-26; it is almost same as was given in BE and RE of 2024-25. But, if one looks at the objectives of the scheme, we have aimed to make all villages into ODF Plus Model Villages by March this year. But, we have been able to convert only 73 per cent (4.3 lakh) villages. So, there is work in progress and I suggest for consideration of the hon. Minister to push hard. Secondly, under SBM-Grameen, we have covered only 5.62 lakh villages. But, as per 2011 Census, we have almost 6.5 lakh villages and the present unofficial figures show that the number of villages have crossed the 7 lakhs mark. So, I suggest for consideration of the hon. Minister to cover the left out villages under this Mission, but how he would do is a big challenge since 2022-23 budget remained constant. So, I also take this opportunity to appeal to the hon.FM for more allocation to realize the dream of Mahatma Gandhi and goals set by hon. PM Modi ji.

My next point is relating to inter-linking of rivers. This project is very important, because once rivers are interlinked, we can create irrigation potential of additional 35 million hectares. I compliment the hon. Minister for taking up Ken-Betwa Link Project with an estimated cost of Rs. 44,605 crores. Sir, similarly, we have Godavari- Cauvery link project (comprising 3 link projects - Godavari (Inchampalli) Krishna (Nagarjunasagar) link, Krishna (Nagarjunasagar) Pennar (Somasila) link and Pennar (Somasila) - Cauvery link)} which has also been identified as Priority Link Project. I am given to understand that Chhattisgarh which was opposing the project earlier now agreed in the 17th meeting of the Task Force held in March, 2023, for giving up its unutilized water share. Of course, there are also other projects. So, all I would like to know from the hon. Minister the progress

made in DPR for linking above rivers and when the project will see the light of the day may kindly apprised to the House while replying to the debate.

My next point is relating to Accelerated Irrigation Benefit Programme. Sir, the Government has set a target of covering 15 million hectares under AIBP. But, progress is not so encouraging. Out of about 100 projects, we have been able to complete only 60 projects. Here, I would like to know from the hon. Minister details of projects identified from AP, status of progress of each of the identified project, target for creating additional irrigation benefit and details of irrigation benefit so created.

Atal Bhujal Yojana is another important scheme of the Ministry for which the World Bank has given Rs. 6,000 crores to implement in over-exploited and water-stressed areas of the country. Sir, my Rayalaseema region in AP is water-stressed and over-exploited region. But, I am given to understand that this region has not been included under ABY. All I appeal to the hon. Minister to include Rayalaseema region in AP under ABY. Sir, the Standing Committee in 2023 recommended that ABY be expanded to include all other water-stressed areas across the country and hence I appeal for including Rayalaseema under this.

Namami Gange is another important programme of the Ministry which aims to conserve and rejuvenate Ganga and its tributaries. I am not going into how much money has been budgeted, how much has been utilized, etc. All I wish to submit is that Godavari in South covering Maharashtra, Telangana and Andhra Pradesh travels about 1500 kms and is called 'Dakshin Ganga. Unfortunately, Godavari is polluted at many places. Sir, Godavari has historical, cultural, religious and other significance and there is a need to abate pollution, conserve and rejuvenate River Godavari. So, I suggest for consideration of the hon. Minister that Namami Godavari be taken up as a Flagship Programme on the lines of Namami Gange by setting up sewerage treatment infrastructure, river-surface cleaning, afforestation, river-front development, bio-diversity, bringing public awareness, etc., to bring back its past glory. I also request the hon. Minister to positively consider appointing consultant INTACH as was done in the case of Namami Gange for Namami

Godavari. This will go a long way, Sir, in achieving the various objectives once Namami Godavari is completed.

So, these are some of the issues which I wish to touch upon with a request to the hon. Minister to ponder over these and see that they are taken up and considered favourably. With these submissions, I support the Demands pertaining to the Ministry of Jal Shakti. Thank you.

MS. BANSURI SWARAJ (NEW DELHI): I strongly support the Demand for Grants for the Ministry of Jal Shakti. Water is the essence of life, the force that drives civilization, and the foundation upon which our Nation's progress stands. Yet, for millions of Indians, access to clean and reliable water has long been a struggle. Through the unwavering commitment of the Modi Government, we are changing this reality, ensuring that every citizen has access to safe and clean water.

Under the decisive and visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Government has revolutionized Bharat's approach to water security, sanitation, and sustainability. Every household with access to piped water, every farmer benefiting from enhanced irrigation, and every child drinking safe water in school is a testament to the government's unwavering commitment to a healthier and more secure future.

Today, I proudly stand before this House in support of the Rs. 2,99,503 crore allocation for the Ministry of Jal Shakti, a bold and ambitious step towards ensuring universal access to clean water, sanitation, and sustainable irrigation. This is not just a budget it is a promise to the people of Bharat that their future will be secure.

Imagine a mother in a remote village, walking miles every day to fetch water for her children. Imagine a farmer helpless as his crops wither due to water scarcity. This was the grim reality for millions before the Modi Government launched the Jal Jeevan Mission (JJM) in 2019. At that time, only 3.23 crore rural households (16.8%) had tap water connections. But today, the picture has changed. As of November 2024, an astounding 15.30 crore rural households, which is 80% of the target, now have access to clean drinking water! And I am proud to share that as of

January 2025, the states like Goa, Gujarat, Haryana, Sikkim, and Mizoram, along with the Union Territories of Puducherry, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, and Andaman & Nicobar Islands, have achieved 100% functional household tap connections (FHTCs). This is not just a statistic, this is the Modi Government bringing dignity, health, and progress to every doorstep.

To accelerate this mission, the JJM budget has been strengthened to 267.000 crore this year, ensuring that by 2028, every household in Bharat will have clean, piped water. Moreover, the Nal Jal Mitra Programme has been launched to train local communities in maintaining water supply infrastructure, creating thousands of jobs in the process.

Clean water and sanitation go hand in hand. When Prime Minister Modi ji launched the Swachh Bharat Mission in 2014, it was not just a scheme, it was a mass movement. Today, because of this mission, 96% of Bharat's villages are Open Defecation Free. This is a landmark achievement that has transformed public health, dignity, and hygiene for millions of Indians.

With 27,192 crore allocated for SBM-G, the focus now shifts to waste management and sustainability. Across Bharat, 978 Plastic Waste Management Units are operational, ensuring that waste is effectively recycled, and our environment is protected. This is the Modi Government's commitment not just to sanitation, but to a healthier and cleaner Bharat.

Water is the heartbeat of Indian agriculture. Without water, our farmers struggle, and our nation's food security is at risk. The Modi Government is committed to empowering our farmers through schemes like the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY), which has received a 25% budget increase this year, ensuring more irrigation facilities and efficient water use.

Additionally, 21,780 crore has been allocated to the Atal Bhujal Yojana (ABY), focusing on groundwater conservation, a 197% increase over last year's revised estimate. This will help water-stressed regions, ensuring that future generations inherit a water-secure Bharat.

Our rivers are not merely water bodies, they are the lifeblood of our civilization, deeply woven into our cultural and spiritual heritage. Maa Ganga, revered by millions, is not just a river but a symbol of purity and sustenance. Recognizing this, the Modi Government launched the Namami Gange Programme, a historic initiative dedicated to rejuvenating and restoring the pristine glory of our sacred river.

Through a multi-faceted approach that includes scientific water treatment, pollution control, and sustainable riverfront development, the Modi Government has made significant strides in reviving Maa Ganga's health. This year, the programme's budget has been increased to 22,400 crore, a substantial 20% rise, demonstrating the Government's unwavering commitment to preserving this invaluable lifeline for future generations.

Under the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the long overdue revival of Maa Yamuna has begun. A river that has been the silent witness to our history, our prayers, and our dreams. For years, Maa Yamuna suffered neglect, but now, its restoration is not just a mission, it is a promise to our future generations. With unwavering determination, advanced pollution control, and a collective resolve, we will restore its lost glory, ensuring that this sacred river flows clean and vibrant once again, as a testament to our heritage and our commitment to a cleaner, greener Bharat.

As the elected representative of the New Delhi Parliamentary Constituency, I witness firsthand the severe water crisis that the people of Delhi endure due to the mismanagement and neglect of the previous Aam Aadmi Party (AAP) government. Every summer, families in Patel Nagar, Rajinder Nagar, and Karol Bagh were left to suffer as water shortages reach critical levels. Schools struggled to provide safe drinking water for children, and entire localities were forced to rely on private tankers, paying exorbitant amounts for a resource that should be their fundamental right.

Now, with a BJP government in Delhi, we finally have the opportunity to correct these past failures and deliver real solutions. I urge the Central Government to extend its full support in upgrading Delhi's water infrastructure, eliminating tanker mafias, and ensuring a consistent, clean, and affordable water supply for all residents. With the decisive leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the commitment of the BJP-led Delhi government. we will transform Delhi's water crisis into a story of efficiency, reliability, and good governance.

Under the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Bharat is not just ensuring access to clean water, it is securing the future of every child, every family, and every farmer. Water is life, dignity, and hope. The ₹99,503 crore budget for the Ministry of Jal Shakti is not just a number; it is a promise, a promise that no child will go thirsty, no village will struggle for sanitation, and no farmer will watch his crops wither due to lack of irrigation. This is the foundation of a New Bharat, where every drop of water fuels progress, prosperity. and pride. With unwavering resolve, we are not just building infrastructure, we are restoring faith, transforming lives, and shaping a future where every Bharatiya thrives.

Jai Hind! Jai Bharat!

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): I express my views on the Demands for Grants for the Ministry of Jal Shakti.

Water is the lifeline of a nation. With a growing population and evolving consumption patterns, the demand for water is rising like never before. Managing our water resources wisely has been the need of the hour, and this Government has risen admirably to the challenge. I would like to thank the hon. Minister, Shri C.R. Patil ji for the transformative initiatives undertaken to ensure equitable access, sustainable management, and the careful conservation of this precious resource.

At the heart of this Government's governance lies the principle of 'Antyodaya', ensuring welfare reaches the last person in society. This philosophy shapes the entire approach to water security. A clear testament to this commitment is the substantial Rs. 99,503 crore budget allocated to the Ministry of Jal Shakti for 2025-

26. This significant investment demonstrates the Government's unwavering dedication to effective water management, conservation, and accessibility, fully aligning with the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of 'Sabka Saath, Sabka Vikas' There was a time when women and children in rural parts of India had to walk long distances to fetch water, spending hours on this exhausting task. However, this Government has been tirelessly working to make this struggle a thing of the past. Through the Jal Jeevan Mission, this Government has provided tap water connections to over 15.51 crore households, covering 80.07 per cent of the total rural population. When the Mission began, only 3.23 crore households had access to piped water. Today, it is a matter of great pride that eight States and three Union Territories, including the state of Gujarat, have achieved 100 per cent tap water coverage. To sustain this momentum, the Jal Jeevan Mission has been extended till 2028, with a dedicated budget of Rs. 67,000 crore for 2025-26. However, providing access to water alone is not enough, ensuring water quality is equally vital. Currently, India has 2,160 water-testing laboratories, including 1,570 NABL-accredited labs, actively monitoring and safeguarding the quality of drinking water. By ensuring water quality, communities are empowered, and health outcomes are improving nationwide.

India is one of the world's largest consumers of groundwater, and its conservation is vital for long-term water security. The Atal Bhujal Yojana is a commendable initiative undertaken by the Government to address groundwater depletion across seven water-stressed States through community-led management and scientific planning. So far, 60 per cent of the targets have been met, and over Rs. 3,421 crore has been released to States. Through these efforts, we are on our way to ensuring groundwater levels are restored and used sustainably for generations to come.

Clean water and sanitation go hand in hand. The Swachh Bharat Mission-Grameen (SBM-G), which successfully achieved Open Defecation-Free (ODF) status in its first phase, is now in phase two, focused on converting villages into ODF Plus. This means ensuring solid and liquid waste management, eliminating

stagnant water, and maintaining public cleanliness. As of 27th December 2024, over 95 per cent of villages in India have been declared ODF Plus, and more than 69 per cent of villages are designated as ODF Plus Model under SBM-G. Remarkably, there has been a 460 per cent surge in ODF Plus villages from one lakh villages in December 2022 to over 5.61 lakh villages in December 2024. This transformation significantly contributes to making rural India cleaner, healthier, and more sustainable.

This Government firmly believes in educating and mobilizing communities at the grassroot level to create a water-secure future. When people take ownership of their water resources, conservation becomes a collective movement. Annually, the "Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain" has been implemented, covering all rural blocks and urban areas in every district across the country. Campaigns such as this ensure that water conservation is not only a Government initiative but also a collective responsibility shared by every citizen.

At the same time, technology is transforming the way we manage and conserve water. Through the National Aquifer Mapping Project (NAQUIM), over 25 lakh square kilometers have been mapped, providing States with crucial data for implementing scientific water conservation and recharge strategies. The Bhu-Neer Portal, launched in September 2024, enhances transparency in groundwater management, making data accessible for better planning and accountability. Additionally, the FloodWatch India app (Version 2.0) delivers real-time flood forecasts from 592 monitoring stations, significantly improving disaster preparedness and response. These are just some examples of how this Government is successfully harnessing the power of technology to make water management more efficient, data-driven, and future-ready.

A decade ago, the water challenges faced by the nation were daunting. There was limited access to clean drinking water, depleting groundwater levels, poor water quality, and inadequate sanitation facilities. Today, these challenges are being successfully addressed through targeted interventions, dedicated community

engagement, and the deployment of cutting-edge technology. As we navigate towards the future, I am confident we are being steered toward a secure, sustainable, and water-resilient future for all citizens.

I support the Demands for Grants for the Ministry of Jal Shakti. Thank you!

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने भारत को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा परिकल्पित जल सुरक्षित देश बनाने के लक्ष्य और मिशन को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है । जल शक्ति मंत्रालय जिसे वर्ष 2019 में सभी जल संबंधित विभागों और संगठनों को एक छतरी के नीचे लाकर स्थापित किया । भारत को जल संरक्षित बनाने की दिशा में केंद्रीय रणनीति को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, साथ ही पूरे देश में मूल्यवान और सीमित जल संसाधनों के अनुकूल उपयोग सुनिश्चित कर रहा है । वर्ष 2024 के दौरान जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने कई नई पहल की है और महत्वपूर्ण परिणाम मिल के पत्थर हासिल किए हैं ।

वर्ष 2024 में विभाग की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं, जो मैं सदन को बताना चाहता हूं । राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने वर्ष 2024-25 में परियोजनाएं पूरी की है । जिसके परिणाम स्वरुप अब तक कुल 303 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं । 2,056 करोड रुपए की लागत की 39 नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है जिससे कुल 39,730 करोड़ की लागत की 488 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं । सीवरेज बुनियादी ढांचे में जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच 305 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता के निर्माण / पुनर्वास के लिए 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है । आज तक 6255 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता के निर्माण और 549 किलोमीटर सीवेज नेटवर्क बिछाने के लिए गंगा बेसिन में कुल 203 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है । माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 जनवरी, 2024 को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 790.5 करोड रुपए की संचय लागत वाली निम्नलिखित परियोजनाओं का उद्घाटन किया- मसानी मथुरा में 30 एमएलडी एसटीपी का निर्माण नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हाइब्रिड अनन्युटी आधारित पीपीपी मॉडल के तहत मौजूदा ट्रांस यमुना में 30 एमएलडी मसानी मथुरा में 6 पॉइंट एमएलडी एसटीपी का पुनर्वास कुल 36.8 एमएलडी और 20 एमएलडी टीटीआरो प्लांट मसानी मथुरा का निर्माण कराया गया । मुरादाबाद में 264 किलोमीटर लंबाई और सीवरेज नेटवर्क सहित 58 एमएलडी एम एसपी का निर्माण कराया गया ।

10 मार्च, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से 1114 करोड रुपए की लागत वाली तीन सीवेज परियोजनाओं का उद्घाटन किया । इन परियोजनाओं में नैनी हाफामऊ और झूसी प्रयागराज में 72 एमएलडी एसटीपी और इंड नेटवर्क कार्य जौनपुर में 30 एमएलडी एसटीपी और इंड नेटवर्क कार्य तथा इटावा में 45 एमएलडी एसटीपी कार्य शामिल है । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को 1555 करोड रुपए की कुल लागत वाली 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया । इनमें से उत्तर प्रदेश और बिहार में 534.25 करोड रुपए की लागत वाली पांच परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया । इसके अलावा बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश में 1021 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 और परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई । 4 जनवरी, 2024 को माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के बागपत में 77.36 करोड़ की लागत से 2.4 इंटरसेप्शन और डायवर्जेंट नेटवर्क के साथ 14 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया ।

18 जनवरी, 2024 को माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में 370 करोड रुपए की लागत वाली 220 एम मेरठ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंटरसेप्शन और डायवर्सन परियोजना की आधारशिला रखी । इसके अलावा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा ऑडिट पर प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया गया । एनएमसीजी ने कार्य स्थल सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक 9 आभासी सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा ऑडिट पर 1500 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया ।

भारत सरकार ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए वर्ष 2014-15 में 20,000 करोड रुपए के बजट के पर्याय के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था जिसकी अवधि 5 वर्षों के लिए मार्च 2021 तक थी । इस कार्यक्रम को 22,500 करोड़ रुपए के बजट के परिवहन के साथ मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है ।

राष्ट्रीय गंगा योजना को वर्ष 2025-26 के लिए 3400 करोड रुपए का वित्तीय परिवहन आवंटित किया गया है । इस निवेश का उद्देश्य सीवेज उपचार क्षमता को बढ़ाना पानी की गुणवत्ता में सुधार करना और गंगा नदी का संरक्षण करने तथा वर्ष 2025 तक निर्धारित स्नान मानकों को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक कचरे के निर्वहन को विनियमित करना है । दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से एक गंगा नदी को अत्यधिक जल दोहन और प्रदूषण के कारण गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है । भारत की सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण हिस्से और जीविका के प्रमुख संसाधन के रूप में इस नदी की स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है ।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को प्रदूषण को प्रभावित ढंग से काम करने और गंगा नदी को संरक्षित करते हुए उसे फिर से पवित्रता और शुद्धता के पुराने रूप में लाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था । गंगा नदी बेसिन भारत में सबसे बड़ा है, जो देश के 27% भूभाग में फैला हुआ है और यह लगभग 47 परसेंट आबादी का भरण पोषण करता है । यह 11 राज्यों में फैला है । इस बेसिन में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 27 परसेंट हिस्सा शामिल है । इस बेसिन के अधिकांश भाग लगभग 65.57% में कृषि कार्य किया जाता है, जबकि 3.47% क्षेत्र में जल निकाय है, वर्ष के संदर्भ में कुल बारिश का 35.5% प्राप्त करने के बावजूद गंगा नदी बेसिन भारत में साबरमती बेसिन के बाद दूसरा सबसे अधिक पानी की कमी वाला बेसिन है । जिसमें प्रमुख भारतीय नदी बेसिनों में औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक वर्षा जल का केवल 39% है ।

उत्तर प्रदेश के सात जिलों मिर्जापुर, बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं, अयोध्या, बिजनौर और प्रतापगढ़ में 7 जैव विविधता पार्क और उत्तर प्रदेश में तीन बिहार में एक और झारखंड में एक में प्राथमिकता वाले भूमि को मंजूरी दी गई है । प्रयागराज में यह उल्लेख करना उचित होगा कि वर्ष 2017 से 2024 तक उपचार क्षमता 268 एमएलडी से बढ़कर 348 एमएलडी हो गई है । इसके अलावा नदी के जल की गुणवत्ता 4 से सुधार कर पांच हो गई है । इसके अतिरिक्त 2017 में 60 untapd नालों में से कोई भी untapd नाला नहीं है । इसी तरह वाराणसी के लिए उपचार क्षमता 100 एमएलडी से बढ़कर 420 एमएलडी हो गई है । अनटैप्ड नालों की संख्या 8 से घटकर एक आंशिक रूप से अनटैप्ड नाला तक पहुंच गई है और पीआएस 4 से सुधर कर पांच हो गया है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के अंतर्गत मल्लावा बिलग्राम विधानसभा में गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित इलाका है । प्रत्येक वर्ष गंगा नदी से बाढ़ आने पर कटरी-परसोला -छिबरामऊ सहित काफी गांवों की न केवल फसल बर्बाद हो जाती है । वे आवास विहीन हो जाते हैं । उनकी जीविका का सहारा समाप्त हो जाता है । वे बेघर भी हो जाते हैं । गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित ग्रामों में बचाव हेतु एक बांध मेहंदी घाट से होते हुए राजघाट सरिया पुल तक केंद्रीय आवंटन से बनाए जाने हेतु आवश्यकता है । जब तक बांध का निर्माण नहीं होता है तब तक कटाव को रोकने के लिए छोटी-छोटी ठोकर बनवाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए । इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

SHRI G. SELVAM (KANCHIPURAM): I express my views on Demands for Grants pertaining to Ministry of Jal Shakti. Water forms the basis of sustainability of life,

livelihood and development. There is an old saying that there is no life without water in this Universe. While discussing this Budget, we should review that whether the proposed expenditure is in consonance with the urgent needs and challenges faced by our country. There is reduced allocation of funds in this Budget. This year? s budget allocation has been increased Last year it was Rs. 95,109 crore and this has been increased to Rs. 99,503 crore this year. For Drinking water and Sanitation, the allocation has been reduced to Rs. 74,226 crore this as against the last year allocation of Rs. 77,391 crore. I urge that if there is justifiable reason with the Union Government for reducing the budget for this important department, I request that information should be shared in this august House. An amount of Rs. 77,391 crore was allocated in the actual Budget and which was later reduced to Rs. 29,917 crore in the revised Budget, it means that there is a reduction of almost 61 per cent. It comes to a reduction in amount by Rs. 47,474 crore which is a shocking one. Provision of clean drinking water to the villages of India is still a distant dream. This year allocation for Jal Jeevan Mission/National Rural Drinking Water Scheme is less than the allocation for the year 2023-24. This year Rs. 67,000 crore has been allocated by the Union Government for Jal Jeevan Mission. But during the year 2024-25 the allocation was Rs. 70,000 crore. I must say the actual Budget allocation originally made for the year 2023-24 was also Rs. 70,000 crore. But during the Budget Estimates it was revised to Rs. 22,694 crore. I fail to understand why this Union Government is reducing the budget allocation made for the Schemes which provide basic facilities such as drinking water to our people. Whether crores of our people should wait for long to get drinking water? Flood management and Border Areas Programme is an important Scheme for protecting the infrastructure of the people living in such vulnerable areas. Earlier the Budget was Rs. 450 crore. Then it was reduced by Rs. 50 crore and made as Rs. 400 crore. Why have you reduced Rs. 50 crore for this Scheme? Will the people living in vulnerable areas be left in the lurch without support from the Union Government and at the disposal of nature? These are not just reduction in figures or funds. They are just making a dent on the hopes and lives of the people of this country. Budget is not just an economic document. This is a moral commitment for the people. Water is not a luxury.

Sanitation is not a thought for backwardness. Spending on flood management is not a waste of expenditure. These are spending for ensuring quality life in our country. Dravidian Model of Governance under the leadership of hon. Chief Minister of Tamil Nadu has been implementing *Kalaignar* Women?s Rights Grant Scheme providing financial assistance to women of the State. This Scheme has been followed by almost all the States of the country. In the same way, the Union Government should formulate the Budget of the country protecting the interest of the people by sufficient allocation of funds in lines with the Budget presented by the Tamil Nadu Government under the able leadership of our Chief Minister *Thalapathi* Thiru M.K. Stalin. Water pollution: crisis beyond scarcity. Even if we get water whether it is fit for drinking? Out of the 1920 places in rivers samples are collected and tested. Out of this, 817 samples failed in the Biochemical Oxygen Demand test. Industrial effluents, sewage water and agricultural waste water flow into the water bodies of India making them toxic and dangerous for consumption. Ground water remains unsafe in hundreds of districts as they are found to contain Fluoride, Arsenic, Nitrate and Uranium contents. Delay in release of funds from the Union Government. Water related schemes under the Ministry of Jal Shakti are facing problems in execution as there is inordinate delay on the part of Union Government in releasing the funds. As of February, 2025, only 31 percent of the funds from the share of the Union Government has been released under Jal Jeevan Mission for the year 2024-25. This creates further delay in providing piped drinking water connections to rural areas. Why the fund for an important Scheme of the Government is reduced time and again? I do not know whether under the Revised Estimates of the Budget, whether the fund allocation be reduced? Atal Bhujal Yojana ABY is implemented in 7 States of India where there is water scarcity. It was found by the Parliamentary Standing Committee on Water Resources in the year 2023 that only 37 per cent of the States are covered under this Scheme. States having severe water scarcity like Tamil Nadu, Punjab, Himachal Pradesh and Delhi have been excluded from this Scheme. The Standing Committee of Parliament recommended for inclusion of all the water scarcity States in the Programme. This Committee of Parliament has even noted that some States which have severe water

scarcity are not listed under this Atal Bhujal Scheme. Union Government should allocate special funds for treatment of waste water, rainwater harvesting in urban areas, urban river rejuvenation programmes. Although Jal Jeevan Mission has a set target of providing potable pipe water to all the households of our country, the successful implementation is delayed due to the delay in release of funds from the Union Government to the States concerned.

Without proper monitoring and accountability mechanisms in place, there is a risk of this Scheme being changed into a failure one. Moreover, climate change and unpredictable monsoon have increased our water woes. It has also created an impact on both drought and flood. Instead of providing temporary relief at times of disaster, Union Government should prioritize climate change resilient infrastructure. Desalination plants at places of water scarcity, exchanges between reservoirs, big scale afforestation should be given importance. Instead of being a mute spectator, the Union Government should take urgent corrective measures for water conservation, equitable distribution of water and in talking climate change for all the States of the country. Water conservation, beyond all political compulsions, should act as an important pillar of sustainable development. I urge that in the footsteps of Dravidian Model of Governance led by our Revered leader Hon Chief Minister of Tamil Nadu *Thalapathi* Thiru M.K. Stalin, we should work with an aim of providing everything for everybody. Thank you.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : मैं जल शक्ति मंत्रालय की 2025-26 की मांगों के समर्थन करता हूँ, क्योंकि यह मंत्रालय हमारे जल संसाधनों का प्रबंधन, स्वच्छता और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । इस वर्ष जल संसाधन विभाग को 25,276 करोड़ रुपये और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को 74,226 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । यह न केवल हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि जल संकट, प्रदूषण, और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है । हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, जल शक्ति मंत्रालय तेजी से जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य कर रहा है । हमने जल संसाधनों के सतत उपयोग, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और बाढ़ नियंत्रण के लिए कई योजनाएँ लागू की

हैं, जो न केवल गंगा की स्वच्छता और जल आपूर्ति में योगदान दे रही हैं, बल्कि भारत को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं ।

नमामि गंगे मिशन, इस मिशन के तहत 2024 में 25 परियोजनाएँ पूर्ण की गईं, जिनसे अब तक कुल 303 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं । इसके अलावा, 39 नई परियोजनाओं को 2,056 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी मिली, जिससे कुल स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 488 हो गई, जिनकी लागत 39,730 करोड़ रुपये है । सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, 305 MLD (मिलियन लीटर प्रति दिन) सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ाने के लिए 12 नई परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं, जबकि 750 MLD क्षमता की 16 परियोजनाएँ पूर्ण हुईं । गंगा बेसिन में अब तक 6,255 MLD सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता और 5,249 किमी सीवर नेटवर्क का निर्माण किया गया है । जल जीवन मिशन (JJM), 15 अगस्त 2019 को जब इस योजना की घोषणा हुई, तब केवल 17% ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन था । आज यह आँकड़ा 79.81% तक पहुँच चुका है । विशेष रूप से बिहार में 16 करोड़ परिवारों को नल से जल मिल रहा है, और 95.71% ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है । डिजिटल वॉटर क्वालिटी टेस्टिंग, देश में 2,180 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं, जिनमें से 1,580 को NABL मान्यता प्राप्त है । महाराष्ट्र में 129.01 लाख शौचालय बनाए गए हैं, जिससे 87.88% गाँव ओडीएफ प्लस मॉडल में आ चुके हैं । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), 2021-26 के लिए 93,068 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे 22 लाख किसानों को लाभ मिलेगा । 2016-17 से 2023-24 तक 34.63 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के लक्ष्य के मुकाबले 25.80 लाख हेक्टेयर (74.5%) क्षमता पूरी की जा चुकी है । महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, जहां बाढ़ और सूखा दोनों ही बड़ी समस्याएँ हैं । महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र हर साल सूखे से प्रभावित होता है । यहाँ के बीड़, लातूर, नांदेड़ और उस्मानाबाद जिलों में जल संकट चरम पर रहता है । हमें पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से जलापूर्ति, वर्षा जल संचयन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन, और गर्मी के मौसम में जलाशयों के जल स्तर की निगरानी को प्राथमिकता देनी होगी । मुंबई को 4200 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि आपूर्ति केवल 3800 मिलियन लीटर ही हो पाती है । भविष्य में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 2031 तक 5320 MLD और 2041 तक 6424 MLD जल की जरूरत होगी । जल प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का उपयोग अत्यंत आवश्यक है, जिससे जल संरक्षण और वितरण को प्रभावी बनाया जा सके । इसके लिए GIS (Geographic Information System) आधारित जल संरक्षण योजनाओं को अपनाना चाहिए, जिससे जल संसाधनों की निगरानी और बेहतर प्रबंधन संभव हो । इसके अलावा, स्मार्ट वाटर मीटरिंग और लीकेज डिटेक्शन तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि जल आपूर्ति की बर्बादी को कम किया जा सके

और जल की बचत सुनिश्चित हो । स्थानीय समुदाय की भागीदारी जल संरक्षण को सफल बनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है । ग्राम पंचायतों को जल संरक्षण योजनाओं में शामिल करना आवश्यक है, जिससे ग्रामीण स्तर पर जागरुकता बढ़े और जल संसाधनों का सही प्रबंधन किया जा सके । इसके साथ ही, जल उपभोक्ता समितियों का गठन कर आम नागरिकों को भी इस प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए ।

बाढ़ नियंत्रण और जल भंडारण संरचनाओं को मजबूत करना भी जल प्रबंधन का एक अहम हिस्सा है । महाराष्ट्र में नए बाँधों के निर्माण और पुराने जलाशयों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे वर्षा जल का अधिकतम संचयन किया जा सके और भविष्य में जल संकट से बचा जा सके । इसके अलावा, नदी जोड़ परियोजना को प्राथमिकता देते हुए सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी, जिससे किसान और ग्रामीण समुदायों को राहत मिले । जल प्रबंधन में वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है । इसके लिए जल प्रबंधन परियोजनाओं में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि संसाधनों की उपलब्धता बढ़े और आधुनिक तकनीकों का समुचित उपयोग किया जा सके । साथ ही, CSR (Corporate Social Responsibility) फंडिंग को जल संरक्षण और जल पुनर्भरण परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे निजी कंपनियाँ भी जल संरक्षण के इस राष्ट्रीय मिशन में योगदान दे सकें । आज जल शक्ति मंत्रालय जल संरक्षण, स्वच्छता और जीवन स्तर में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । हालाँकि, परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, आधारभूत संरचना का रखरखाव, जल गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वित्तीय संसाधन जुटाना जैसी बड़ी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं । हमें केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज, उद्योग और स्थानीय प्रशासन को मिलकर जल संकट का समाधान निकालने के लिए प्रयास करने होंगे । तकनीकी नवाचार, जल प्रबंधन में सुधार और बाढ़-सूखा नियंत्रण की प्रभावी रणनीति के माध्यम से हम न केवल महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश को जल आत्मनिर्भर बना सकते हैं ।

SHRI BHASKAR MURLIDHAR BHAGARE (DINDORI): In my Dindori Lok Sabha constituency, Dindoripeth, Surgana and Kalvan are tribal dominated tehsils. It receives about 2500-3000 mm of rainfall during Monsoon, but many villages do not get drinking water in summer. There is no water available for agriculture, citizens are migrating in large numbers. Therefore, funds should be approved and water supply project

should be set up under the Nar-Par-Tapi Scheme to meet the needs of this area, and also reserve excess water for the locals.

In addition to this, there is a severe drought condition in Chandwad, Deora, Nandgaon, Yeola and Malegaon Tehsil. Therefore, the water schemes for Girna and Godavari valley should be approved and excess water should be made available to the farmers and villagers of this area.

Under ?Jaljeevan Mission? water supply schemes were approved in many villages of my Dindori Lok Sabha constituency. But, while completing the project, it was necessary to dig a well first and then do the following work if water was available. However, by doing other work first, like installing a water tank and laying a pipeline, the contractors, in collusion with the corrupt officials, withdrew the money for the said work and pretended that the work was completed on paper. Even today, those villages do not get drinking water Therefore, investigation of the scheme should be done and strict action should be taken against the culprits.

In 2027, Mahakumbh Mela will be organized on the banks of Godavari river and billions of devotees will be coming here for ?holy dip?. But, at present, the river is completely polluted.

Due to sewage water from Nashik Municipal Corporation area and contaminated water drained from industries, Godavari river is completely polluted. The river basin in Nashik and Niphad Tehsil, it is completely covered by waterfowl. Therefore, there is a foul smell to this water and the colour of the water has also become black. The fishes and small animals are dying. Drinking water has been contaminated in the villages near the river. So, your Ministry should allot sufficient funds for cleaning of Godavari river.

Thank you.

SHRI DHAIRYASHEEL RAJSINH MOHITE-PATIL (MADHA): I express my views on demands for grants under the control of the Ministry of Jal Shakti.

India's population is 17 per cent of the world's total population. But, we have access to only 4 per cent of the world's fresh (drinking) water sources. Therefore, conservation and sustainable use of water resources is very important for us. The issue of water resources is very important and talking about this issue is a matter of loss for me as a farmer.

It is said - "Water is life. Where there is no water there is no life." Water is the most basic need of human life. It is a part of the Constitution of India Article 21 enshrines the right to life and inviolability of human rights. The biggest scheme of the Ministry is Jal Jeevan Mission (JJM). Prime Minister Narendra Modi launched this mission on August 15, 2019. It is promised to provide tap water to 19 crore rural households and public institutions by 2024. Even today if you go to the website of the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti India, it clearly says- "Water for every household by 2024." But, this is also a part of a long list of countless unfulfilled promises by the government as we all know. As of 16 March 2025, and this is data taken from your JJM dashboard, only 80 per cent of households have tap water connections. According to official guidelines, a water supply is considered fully functional only when the tap connections are working regularly, there is sufficient water available, and the water quality is up to the prescribed standards. The JJM guidelines also say that at least 55 liters of water should be provided per person per day. Water supply will be considered regular only if it is done daily or on a fixed schedule. Accordingly it should be available throughout the year. But, how many houses have got the tap water connections and whether the guidelines being followed?

Most of the rural households are falsely claimed by the government to have been given water connection. If you admire its grand dashboard, if you look at it, it shows that 80 per cent households across India have been given tap water connection. But, if you go and ask people, millions of people across the country are still struggling with water scarcity. Sir, the pipelines have been laid, but there is no water - they are just for show off and have become objects. Taps are installed, but no water comes out of them. That is contrary to your own instructions. But, all

paper tap connections are shown as "active" on paper. Another problem is - if water does come, the quality is very poor. A total of 66 lakh samples were tested in 2024-25, out of which 3.3 lakh (5 per cent) samples were found to be contaminated. I have to ask - who was this plan ultimately made for? Did not this scheme meant to help the poor, weak and needy? Or NRR was only for those contractors - so they could make more money laying pipelines. Can we make our profit by contracting?

In the year 2020-21, the second phase of SBM-G was launched, which aims to convert all villages from ODF (Open Defecation Free) to ODF Plus by 2024-25. The model had to be changed in the villages. But, this too turned out to be another unfulfilled promise. under SBM-G Phase plastic waste management is a major target. According to this, plastic which cannot be recycled will be sent to Plastic Water Management Unit (PWMU) at block level. However, by December 2024, there will be only 978 MWWUs across the country. Operations are performed. Sir, there are more than 7200 blocks in the country. 13 states and union territories including Assam, Haryana and Rajasthan have no MWMU. There are only 21 blocks selected in Maharashtra which has more than 300 blocks. These are physical route management units. How are you planning to achieve the objectives of any scheme with such a poor performance? The provision in the budget also does not show hope. In 2022-23, SBM-G rural budget was reduced by 28 per cent compared to 2021-22. From 2022-23, the Center will provide SBM-G to the States and Union Territories to release less than 50 per cent of the amount allocated for the scheme.

Sufficient funds, in 2022-23, for Maharashtra (including Haryana, Odisha and Telangana) was not given, how to work without money?

Atal Bhujal Yojna (ABY) aims to provide water resources to seven water stressed states. Groundwater resource management has to be improved through community-based techniques. Between 2020 and 2025, only 57 per cent (Rs. 3,421 crore out of Rs. 6,000 crore) of the total sanctioned amount was disbursed to states. Even Maharashtra, which has utilized 99 per cent of the funds so far, has only issued 55 per cent of the funds. North Maharashtra and Marathwada have been suffering from drought-like conditions for a long time. In 2018, NABARD rated the

availability of water resources in Maharashtra as 'critical' and classified as 'critically endangered'. Most of the agricultural areas in the state depend on rain water. Poor farmers suffer the most from climate change and increased rainfall uncertainty. Even today, the net irrigated area in Maharashtra is only 31.28 lakh hectares, while the total sown area is 167.22 lakh hectares. The non-irrigated area is only 18 per cent, much lower than the national average of 50 per cent. Relief has been repeatedly called for in drought-stricken areas, but no concrete steps have been taken yet. According to the official statistics of the National Crime Records Bureau (NCRB), Maharashtra has the highest rate of farmer suicides. Why has the government ignored this serious question so far? I demand that additional funds be allocated to improve availability and irrigation, which I hope will solve the acute water crisis in Maharashtra. Another serious issue that I would like to raise is the pollution of water sources. During 2019-21, 817 out of 1,920 river sites monitored were unable to meet the biological oxygen demand (BOD) standards set for quality (3 treatments (not more than 1 mg/litre). 311 river segments (places with frequent flowing water) were found to be polluted. Additionally, groundwater pollution is a major concern especially in water-scarce countries. There is a high dependence on it. In India: 80 per cent of rural drinking water, 50 per cent of urban drinking water and two-thirds of irrigation Water comes from ground water sources. Ground water assessment conducted in India shows that contaminants like fluoride, arsenic, nitrates are present in excess of permissible limits. Any additional money raised at state level or parliamentary constituency level can be added here. Any additional financial demand raised at state level or parliamentary constituency level can be added here.

Jai Hind! Jai Maharashtra.

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): The Karnataka Government's approach to water management on the Cauvery has long been a contentious issue between Karnataka and Tamil Nadu. While Karnataka has been constructing dams across the river, it is also attempting to impound water under the guise of hydropower projects. Tamil Nadu has consistently opposed these efforts, recognising the potential for

Karnataka to claim a lack of water reserves after impounding water for power generation.

Tamil Nadu's opposition dates back to the 1990s when Karnataka first proposed setting up hydropower plants on the Cauvery. Fearing that these projects would reduce the flow of water into Tamil Nadu, the State appealed to the Central Government. At the time, Karnataka suggested that if the projects were undertaken by the National Hydroelectric Power Corporation (NHPC), a Central Government entity, Tamil Nadu's water rights would remain unaffected. However, despite the Centre's willingness to allow NHPC to manage these projects, Karnataka ultimately rejected the proposal.

While Karnataka has repeatedly claimed that its hydropower projects will not impact Tamil Nadu's share of Cauvery water, experts argue otherwise. The Tamil Nadu Government has submitted evidence to the Centre demonstrating how these projects could significantly reduce its water supply. Two decades ago, Tamil Nadu had already raised concerns with the Central Government regarding these projects, yet Karnataka has continued its attempts to move forward with them.

Karnataka had planned multiple hydropower projects, including a 345 MW plant in Sivasamudram, a 360 MW plant in Rasimanal, a 400 MW plant in Mekedatu, and a 120 MW plant in Hogenakkal. If these plants are constructed solely under Karnataka's authority, the electricity generated will belong entirely to Karnataka, leaving Tamil Nadu without any share. However, if the Central Government oversees these projects through NHPC, Tamil Nadu would be entitled to a portion of the power. Recognising this, the Central Government previously proposed that NHPC manage the projects, with Karnataka receiving 60 per cent of the generated electricity and Tamil Nadu receiving 40 per cent. Karnataka, however, has continuously opposed this arrangement.

Beyond electricity-sharing concerns, Tamil Nadu has another crucial reason to advocate for NHPC's involvement. The late Rangarajan Kumaramangalam, former Union Minister for Power in the Vajpayee Government, had pointed out that

allowing NHPC to manage these hydropower projects would also ensure precise measurement of water inflows into Tamil Nadu. This, he argued, would help in resolving the long-standing Cauvery water dispute.

The issue was brought before the Cauvery Water Disputes Tribunal, where Karnataka and Tamil Nadu discussed the possibility of NHPC's involvement. The Tribunal, in its final award, stated that any hydropower projects on the Cauvery must not alter or reduce Tamil Nadu's allocated monthly water quota. However, while the Supreme Court upheld the Tribunal's ruling, it did not provide a specific opinion on hydropower projects.

Despite these legal stipulations, Karnataka has been actively pursuing the Sivasamudram hydropower project, even seeking approval from the Central Government. In December 2017, the Union Environment Ministry's Technical Assessment Committee reviewed Karnataka's hydropower project. Given that Tamil Nadu had already challenged the Sivasamudram and Mekedatu projects in the Supreme Court, Karnataka's persistent efforts-along with the Centre's willingness to entertain them-amount to contempt of court.

In 2019, Karnataka completed preparatory work for the Mekedatu Dam Project, submitting a Detailed Project Report (DPR) to the Central Water Commission (CWC). The project, estimated to cost Rs.14,000 crore, proposes a dam capacity of 66 TMC. Karnataka argues that this project would regulate water flow, prevent excess water from flowing into the Bay of Bengal, and benefit both states by ensuring a steady release as per the Supreme Court's 2018 ruling, which mandates that Karnataka release 177.25 TMC annually to Tamil Nadu. However, Tamil Nadu contends that the dam would disrupt the natural flow of the Cauvery, severely impacting its farmers and violating both the Cauvery Water Disputes Tribunal and Supreme Court directives. The project would give Karnataka increased control over water releases, raising concerns that it could manipulate the flow to its advantage.

On February 7, 2025, the Union Government clarified that it has not granted any Inter-State River Water Disputes Act, such projects require the consent of all basin process the DPR, as approval from the Cauvery Water Management Authority (CWMA) from the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change is pending, as the project approval for new dams on the Cauvery, a significant setback for Karnataka. Under the states-especially Tamil Nadu-which has not been obtained. The CWC has yet to remains stalled due to Tamil Nadu's opposition. Additionally, environmental clearance would submerge over 5,000 hectares, including ecologically sensitive areas such as the Cauvery Wildlife Sanctuary.

On behalf of VCK, I demand that the Centre revoke any preparatory permissions granted to Karnataka for construction of dams in Cauvery. Thank you.

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : मैं वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अनुदानों की मांग पर अपने विचार व्यक्त करती हूँ । आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर लोक सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को भी सरकार तक पहुँचाना चाहती हूँ ।

सबसे पहले, मैं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश भर में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए माननीय मंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ । मंत्रालय ने जल संरक्षण, सिंचाई, और स्वच्छता के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिनका सीधा लाभदेश के नागरिकों को मिल रहा है ।

मैं कुछ प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर प्रकाश डालना चाहूंगी । राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 में 25 परियोजनाओं को पूरा किया गया, जिससे अब तक कुल 303 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है । इसके अतिरिक्त, 22,056 करोड़ की 39 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 488 और कुल लागत ₹39,730 करोड़ हो गई है । सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच 305 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता के निर्माण/पुनर्वास के लिए 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है । इसी अवधि में, 750 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता के निर्माण/पुनर्वास के लिए 16 परियोजनाएं पूरी की गई हैं । आज तक, गंगा बेसिन में 6,255 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता के निर्माण और 5,249 किलोमीटर सीवर नेटवर्क बिछाने के लिए कुल 203 सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है । यह प्रगति गंगा नदी को स्वच्छ बनाने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है ।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को 2021-26 के लिए ₹93,068 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरु किया गया है, जिससे लगभग 22 लाख किसानों को लाभ होगा । वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के AIBP कार्यों के माध्यम से 34.63 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के लक्ष्य के मुकाबले 25.80 लाख हेक्टेयर (लगभग 74.5%) सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है । यह योजना हमारे किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है ।

बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) की शुरुआत से लेकर दिसंबर 2024 तक, बाढ़ प्रबंधन घटक के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ₹7136 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की गई है और FMBAP योजना के RMBA घटक के तहत केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों को ₹1258.23 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की गई है । जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (RRR) योजना के तहत, 12वी पंचवर्षीय योजना के बाद से, 22834.692 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 3075 योजनाएं चल रही हैं । मार्च 2024 तक राज्यों को ₹554.279 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की गई है । इसके अलावा, मार्च 2024 तक 2192 जल निकायों के पूरा होने की सूचना मिली है ।

15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन (JUM) की घोषणा के समय, देश के 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों (17%) के पास नल के पानी के कनेक्शन थे । तब से, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 12.19 करोड़ परिवारों को उनके घरों में नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं । अब, 19.36 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 15.45 करोड़ (79.81%) ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति उपलब्ध है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और ईज ऑफ लिविंग' बढ़ा है ।

मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर लोक सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सांगी को रखना चाहती हूँ । मेरे क्षेत्र के अंतर्गत खानपुर, पूसा, और सैदपुर जैसे प्रखंडों में जो बांधी पर सड़कें बनी हुई है. उनकी हालत बहुत ही खराब है । मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इन सड़कों की तत्काल मरम्मत करवाई जाए, ताकि स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके ।

मैं यह भी मांग करना चाहती हूँ कि इन क्षेत्रों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने की निगरानी के लिए एक विशेष योजना शुरू की जाए । इससे परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और वे समय पर पूरी होकर लोगों को लाभ पहुंचा सकेंगी ।

अंत में, मैं गंडक नदी के किनारे पर हो रहे अवैध अतिक्रमण का मुद्दा उठाना चाहती हूँ । नदी के किनारे पर अवैध रूप से घर बनाए जा रहे हैं, जिससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है । मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि इस अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं ।

***m88 श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) :** राजस्थान में खत्म हो जाएगा जल संकट - पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की बरसों पुरानी जल संकट की समस्या जल्द ही समाप्त होने वाली है ।

प्रदेश की डबल इंजन की सरकार तीव्र गति से इस पर कार्य कर रही है ।

राजस्थान के 21 जिलों को पेयजल और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए बनी इस परियोजना का प्रधानमंत्री जनता को सौगात दिए हैं । जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परियोजना के तहत कोटा में कालीसिंध नदी पर बने नवनेरा बैराज का लोकार्पण किया साथ ही बारां जिले में पार्वती नदी पर बनने वाले महलपुर बैराज और कुल नदी पर बनने वाले रामगढ़ बैराज की आधारशिला रखा गया ।

इसके जरिए पूर्वी राजस्थान के जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, ब्यावर, केकड़ी, दूदू, कोटपूतली बहरोड़, खैरथल तिजारा, डीग और जयपुर ग्रामीण को जल संकट से छुटकारा मिलेगा ।

इसके साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हर घर नल के साथ साथ ही जाखम बांध एवं माही बांध से विभिन्न गावों एवं कस्बों में पेयजल के लिये जल को सुनिश्चित किया जाना हैं ।

इसके साथ हीं चम्बल के पानी से चित्तौड़गढ़ के सैकडों गांवों को पानी मिलना तय हुआ हैं । हमारे क्षेत्र में वर्षों से लम्बीत मावली क्षेत्र के बागोलिया बांध को भरने के लिये स्थाई व्यवस्था डबल इंजन की सरकार में हो पाई है ।

रावतभाटा क्षेत्र में ब्राहामणी नदी पर बांध बनाकर अन्य क्षेत्रों जैसे बिसलपुर बांध को भरा जाएगा ।

पूर्व मे राजस्थान मे काँग्रेस की सरकार मे जल परियोजनाओं मे व्यापक भ्रष्टाचार एव अनियमितता रही है, मेरा माननीय जल शक्ति मंत्री से आग्रह रहेगा की जल जीवन मिशन के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाये तथा कार्यो की गुणवता को ध्यान में रखा जाये ।

इसके साथ ही शेष रहे कार्यों को भी वरियता से पूर्ण किया जाये । सिंचाई के लिये जल का बेहतर एवं उचित उपयोग हो इसके लिये नहरों की मरम्मत को गुणवता से किया जाये ।

बांधों का रखरखाव एवं उन पर मॉनिटरिंग भी प्रभावी ढंग से हो ताकी किसी प्रकार की छिजत नही रहे ।

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): At the outset, I on behalf of my Party Jansena and myself I express my sincere appreciation to the Hon'ble Finance Minister and the Union Government for the significant allocation made to the Ministry of Jal Shakti in the Union Budget 2025-26. The allocation of Rs. 99,503 crore to the Ministry is a testament to the government's unwavering commitment to ensuring water security, promoting sanitation, and addressing the critical challenges of water governance in our country.

The substantial provision of Rs. 67,000 crore for the Jal Jeevan Mission (JJM) reflects the government's resolve to achieve the vision of "Har Ghar Jal" by providing functional tap water connections to all rural households.

As on January 2025, 15 crore rural households around 80%-have been covered. With the extension of the mission until 2028, we remain hopeful that this goal will soon become a reality.

Similarly, the continued focus on the Swachh Bharat Mission Grameen, with an allocation of Rs. 7,192 crore, reinforces the government's commitment to rural sanitation and waste management, strengthening the health and dignity of our rural population.

I also wish to highlight the allocations made towards river rejuvenation and interlinking projects. Rs. 2,400 crore for Namami Gange and Rs. 3,400 crore for river interlinking projects will go a long way in addressing pollution, conserving rivers, and optimizing our water resources for agriculture and drinking purposes.

I especially welcome the increased outlay of Rs. 8,260 crore under the Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojana (PMKSY) and the attention given to groundwater management through the Atal Bhujal Yojana.

These steps are crucial to sustaining our agriculture and rural economy, particularly in drought-prone areas.

I would also like to take this opportunity to express my gratitude for the support extended to my home state i.e. Andhra Pradesh, over the past years under these flagship programs. Notably, Andhra Pradesh has made significant strides in JJM, with over 92% of households receiving adequate quantity of water and 90% receiving potable water, as per the Functionality Assessment Report.

During the financial year 2023-24, Andhra Pradesh received Rs. 794 crore as the central share for JJM, with a further allocation of Rs. 2,521 crore in 2024-25. We acknowledge the central government's support, which has been instrumental in advancing rural water supply projects and sanitation efforts in the state.

In this regard, I would like to place certain concerns related to my parliamentary constituency i.e. Machilipatnam, (Krishna District) and my state in general.

It pains me to say that even after 75 years of independence; we are still struggling to provide safe and clean drinking water to every citizen of our country.

However, I truly appreciate that under the visionary Jal Jeevan Mission, our government is committed to ensuring that every household receives safe and clean drinking water.

We are blessed with the Krishna River flowing through our state. Yet, it is unfortunate that nearly 500 TMC of Krishna river water flows into the sea every year, going unutilized.

On the other hand, many assembly segments in my district like

Ganavaram, Gudivada, Pedana, Avanigadda, Pamarru, Penamarulu

Even my district Head Quarters - Machilipatnam,

face drought-like situations year after year. This irony deeply concerns us while precious Krishna River Water flows wastefully, into sea and people in our region suffer from acute water scarcity.

Additionally, Sir, we are also failing to capture and utilize rainwater effectively. My district receives good rainfall during the monsoon, but due to lack of proper infrastructure for rainwater harvesting, this water too is lost.

There is an urgent need for a comprehensive plan and central support to develop rainwater harvesting infrastructure to conserve this resource for drinking and irrigation purposes.

I request the government to kindly consider this seriously.

One of the most important project in AP is the Polavaram Irrigation Project, which is a lifeline for our state.

This project is required to be completed well on time and a close monitoring with timely sanctioning of financial assistance is much requested.

In addition to above, my Hon'ble Chief Minister Shri Chandra Babu Naidu Garu and my Deputy Chief Minister Shri Pawan Kalyan Gaur, have met Union Minister for Jal Shakti and requested the Government of India for additional financial assistance for completing the right and left canals of the project.

Reg. Cleaning of Rivers,

As everyone of us knows here that The Government of India fully committed towards river rejuvenation, reflecting a strong commitment to environmental sustainability.

My Party President And Hon'ble Deputy Chief Minister of AP embraces the same i.e. underscoring a shared vision for ecological preservation.

Many significant rivers, including the Godavari, Krishna, Pennar, Vamsadhara, and Nagavali passes through Andhra Pradesh.

Sir, While the Godavari River has benefited from targeted cleaning initiatives, such as the recent sanctioning of over 288 crore under the National River Conservation Plan,

It is very important to extend similar efforts to other vital waterways

Rivers like the Krishna and Pennar are essential to the state's agriculture, industry, and daily life, yet they face pollution challenges that threaten their health and, by extension, the well-being of communities relying on them.

Therefore, it is my earnest request that comprehensive cleaning projects for these rivers be prioritized, with the provision of necessary financial assistance, to ensure the holistic restoration of Andhra Pradesh's river ecosystems.

These canals are crucial as they are designed with a water transfer capacity of 17,500 cusecs and will benefit vast areas of agricultural land and drinking water supply.

I sincerely urge the Union Government to kindly give due consideration to this request and extend the required support to complete this national project at the earliest.

Reg. Godavari-Banakacherla Interlinking of Rivers Project

Hon'ble President of India in her address (In Para 19 of the Address), early this session has rightly mentioned about the importance of interlinking of rivers.

As we all know water is big concern for every state; Particularly drinking water;

There is a drought like situation in many states during summer;

This has to be taken up very seriously and immediately,

And Hon'ble President has rightly mentioned it in her speech;

I come from Andhra Pradesh and we have understood its importance

one such interlinking project in AP also needs to be taken up

This would provide irrigation to new Ayacut of 3 lakh hectares and stabilizing 9.1 lakh hectares of area;

Importantly, it will provide drinking water to 80 lakh people of Uttarandhra and Rayalaseema districts and 20 TMC for industrial use.

This project links Godavari and Krishna rivers and gives immense benefits.

This interlinking is needed, because

Krishna river does not have reliable inflows due to excessive use by upstream States and full utilization by the river Krishna Basin States

But, Godavari has reliable inflow and its very saddening that nearly around 3000 TMC (average) of water flows into the sea, every year.

It means, 3000 TMC of water is going waste which is unacceptable.

So, to address the irrigation and drinking water needs of whole state of Andhra Pradesh, Krishna Delta, Uttarandhra and Rayalaseema,

Govt. of Andhra Pradesh has proposed to divert Godavari flood waters of 200 TMC at 2 TMC per day from Polavaram to Banakacherla Regulator to overcome drought in the State.

The project proposed in 3 Phases one is Godavari River to Krishna River; second is from Krishna River to Bollapalle Reservoir; and, the third one is from Bollapalle Reservoir to Banakacherla Regulator.

AP has successfully linked Vamsadhara and Nagavali Rivers and now. there is a need to take up Godavari-Banakacherla Link Project.

CM of AP, Shri Chandrababu Naidu, discussed this project with the hon. FM. The Concept Paper of this Project being sent to GOI

So, I appeal to the hon. PM and FM to approve this Project and provide required funds in Grant form to complete this project which makes AP drought-proof State in the country.

Further, given Andhra Pradesh coastal vulnerabilities a consistent financial assistance through schemes like the Flood Management and Border Areas Programme, is much requested.

Once again as we move forward, I urge the Ministry to ensure timely release of funds and address bottlenecks in implementation to maximize the impact of these allocations.

I also request that the state's future needs, especially in the context of our growing population and water challenges, be duly considered.

With this I once again welcome the budgetary allocations for the Ministry of Jal Shakti which is progressive and people-centric.

This reflect the government's vision of providing Clearn water to every household.

On behalf of my Party Jansena, Myself and the people of Andhra Pradesh, I once again place on record our profound gratitude.

Thank you.

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद) : मैं अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी की तरफ से जल शक्ति मंत्रालय के संबंधी प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त करता हूं । आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार ।

जल जीवन मिशन योजना - वर्तमान स्थिति और कमियाँ

केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत हर ग्रामीण घर को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है । इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई खामियाँ सामने आई हैं ।

1. गलत कार्य प्रक्रियाः

कई स्थानों पर पहले गाँव की सड़कों को तोड़कर नल कनेक्शन दिया जाता है ।

फिर पाइपलाइन बिछाई जाती है ।

अंत में जल स्रोत तैयार किए जाते हैं ।

यदि जल स्रोत में पर्याप्त पानी न हो, तो पूरी व्यवस्था विफल हो जाती है और सरकार के करोड़ों रुपये व्यर्थ चले जाते हैं ।

2. अधूरी और अनियमित परियोजनाएँः

कई गाँवों में नल कनेक्शन तो दे दिए गए हैं, लेकिन अभी तक पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई है ।

3. ग्रामवासियों की असुविधाः

बार-बार सड़कें खोदने से ग्रामीणों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

सुधार के लिए सुझाव

1. सबसे पहले जल स्रोतों को विकसित किया जाए, फिर पाइपलाइन बिछाई जाए और अंत में नल कनेक्शन दिया जाए ।

2. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर विशेष समन्वय समितियाँ बनाई जाएँ ।

3. कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया जाए ।

4. असफल ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई हो और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए ।

नदी जोड़ परियोजना - स्थायी समाधान

अध्यक्ष महोदय, पेयजल के साथ-साथ कृषि और उद्योगों के लिए जल संसाधन भी अत्यंत आवश्यक हैं । महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या है । इस संकट का स्थायी समाधान नदी जोड़ परियोजना के माध्यम से किया जा सकता है ।

प्रस्तावित नदी जोड़ योजना

1. पश्चिमी महाराष्ट्र की अतिरिक्त जल मात्रा को गोदावरी नदी में मोड़ने की जरूरत है ।

2. ताप्ती, पैनगंगा जैसी नदियों के पानी को दमणगंगा और पिंजाला नदियों से जोड़कर गोदावरी में लाया जाए ।

3. इससे जायकवाड़ी बांध में जल आपूर्ति बढ़ेगी और मराठवाड़ा में सिंचाई की समस्या हल होगी ।

4. बीड जिले से वडवानी-धारूर मार्ग से मांजरा और तेरणा परियोजनाओं में पानी लाकर धाराशिव, लातूर और अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों की जल समस्या को स्थायी रूप से हल किया जा सकता है ।

सरकार से माँग

1. इस परियोजना के लिए तत्काल निधि स्वीकृत की जाए ।

2. जल संसाधन विभाग केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से इस पर शीघ्र कार्यवाही करे ।

3. भविष्य में जल संकट से बचने के लिए दीर्घकालिक नीति बनाई जाए ।

निष्कर्ष

अध्यक्ष महोदय, अगर इन योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए, तो जल जीवन मिशन और नदी जोड़ परियोजना के माध्यम से देश की जल समस्या को स्थायी रूप से हल किया जा सकता है । सरकार को इस विषय पर प्राथमिकता देनी चाहिए और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, अगर इन योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए, तो जल जीवन मिशन और नदी जोड़ परियोजना के माध्यम से देश की जल समस्या को स्थायी रूप से हल किया जा सकता है । सरकार को इस विषय पर प्राथमिकता देनी चाहिए और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए ।

नार-पार बेसिन से जल आवंटन करते समय ऐसा भेदभाव किया गया है कि गिरना परियोजना के लिए 350 तालन की शर्त को उसी बेसिन के मराठवाड़ा हिस्से के लिए घटाकर 500 तालन कर दिया गया है । मराठवाड़ा के लिए 183 डालमी पानी नार-पार बेसिन से आवंटित किया जा रहा है । उम्मीद है कि पानी का वितरण समान स्तर पर किया जाएगा ।

मराठवाड़ा की जल कमी को पूरा करने के लिए, मराठवाड़ा को मिलने वाले पानी को केंद्र सरकार के स्तर पर बिना किसी भेदभाव के और मराठवाड़ा के लिए जल स्तर की कोई शर्त लगाए बिना समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए ।

धन्यवाद ।

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI):

Thank you for the opportunity to participate in the discussion Hon'ble Speaker

Water is a state subject and hence the Central govt must deal with this issue very delicately. Inter State Council के कई बैठकों में यह पाया गया है कि केंद्र शासन कई बार अपने आदेश को State Govt. पर impose करता है । इससे state govt की implementation और budgeting दोनों पर impact आता है । इस सदन ने मुझे जल संसाधन की Standing Committee का सदस्य होने का अवसर दिया and I am grateful But as a member I noticed many irregularities across depts and different schemes.The Standing committee found that 58% of funds allocated to the Department of Water Resources in 24-25 remained UNUTILIZED. In 23-24, the Atal Bhujal Yojana, allocated ₹1,000 crore, had only about 20% of funds released, with less than 15% of released funds expended. The govt claims 80% project completion and yet has pushed the target date to 2028, raising more concerns of the allocated Rs 67,000 Cr for JJM this year. इन सब बातों से चिंता होती है हमारे नदियों की स्वच्छता को लेकर, क्योंकि National river conservation program से नदी की स्वच्छता की सच्चाई पता चल रही है । This reminds me of: राम तेरी गंगा मैली, पापियों के पाप धोते धोते हमें खुद से पूछना चाहिए क्या हम effective actions ले रहे हैं ताकि पाप कम हो? Recent instances have shown that river water quality assessment is so variable और हो रही है क्योंकि 20% से ज्यादा NABL labs certified नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि पानी गंदा है कि साफ है । यह वहीं बात हो गई कि aeroplane खरीद लिया लेकिt runway नहीं है । Even in last 5 years, Maharashtra has seen completion rate of 25-40% for Community Sanitary Complexes. This is concerning because ऐसे budget cuts दूसरे projects को हानि पहुंचा रही है । मुझे लगता है कि Maharashtra को पता नहीं क्यों वो importance नहीं दिया जा रहा which it deserves. Special Package for Maharashtra has seen no fund allocated. As we speak more than 1,000 Maharashtra ग्राम पंचायत पानी से वंचित हैंHow many farmers from Marathwada and Vidharbha does the govt want to sacrifice their lives for them to take this matter seriously? FMBAP की बात करें तो भी number चौंकाने वाली है Speaker sir NDMA has noted that ₹25,000 करोड़ funds are needed to cope with flood losses and yet a meagre 2450 करोड़ has been allocated for FY 25-26 Moreover, if you want to mitigate floods additional funds should have been allocated for the Maharashtra Resilience Development Programme, funded by the World Bank. I urge the Central Government to intervene and get the World Bank

to allocate more funds, as atleast 10,000crs are required for an effective solution, Even the UNFCCC COP 28 noted the importance of Loss and Damage funds and still India, a signatory of it, is not willing to increase an L&D fund of its own! This will impact flood-prone areas in my Sangli Constituency like Sangli City, Palus taluka and Miraj taluka together with areas of adjoining constituencies. अगर हम Condition Assessment and Management Plan देखें ती लगता है कि अप नदियों की support करने की कोई aspirations ही नहीं 4-5 साल पहले ही इसी plan के तहत 33 rivers के लिए, govt allocated 25,000 Cr, and now when the plan caters to 57 rivers it has a mere 560 Cr Sluggish progress has been observed in the Krishna Koyna Lift irrigation Project which has both AIBP and CADWM components. Although the Mhaisal Lift Irrigation Scheme has seen fruition, a Rs 33.91 Cr terminal installment is yet to be received. A proposal has been sent to Central Water Commission in this regard, and the Ministry is requested to look into the matter and release the amount at the earliest. Similarly, only Rs 14.52Cr of the Rs 67.38Cr has been received under the CADWM component For FY 24-25, a Rs 33.44 Cr was submitted in December 2024 but only Rs 8 Cr has been received, it is requested that this too is looked into and adequate measures are takenThis measures will help my areas of Takari and Tembu as well as Tasgaon, Kavthemankal, Miraj, Khanapur, Atpadi and Jat. Urge the ministry to allocate funds for the newly sanctioned Mhaishal extention and Tembu Extention lift irrigation schemes. As they require funds of close to 3500cr for completion and any augmentation out of AIBP will help in their early completion Farmers had expected that you would look at their plight as such investment could help double their income However, I would appreciate the WRIS system the Ministry wants to make because it is important to have a real-time track of water bodies This will help improve CWC guideline implementation especially for dams like Almatti Recently the ministry had answered how the height increment can potentially submerge Sangli and other areas The budget missed out allocating more funds to tackle the acute shortage in State Committees on Dam Safety and State Dam Safety Organizations under the Dam Safety Act For eg MH has 160 posts to manage 2671 dams! यह कुछ ऐसा हो गया कि मैच में बल्लेबाज़ को बिना बल्ले के भेजा

जा रहा है रन बनाने In the end 1 would recommend launching a Namami Krishna Mission It will include key schemes to enrich, clean, and manage the flood outbreaks from River Krishna अंत में, जैसा कि हम भारत के जल संकट को हल करने के मोड़ पर खड़े हैं, हमें डॉ एम एस स्वामिनाथन के शब्द याद रखने चाहिए ??जल जीवन है, और इसका प्रबंधन मानवता और पर्यावरण की भलाई के लिए आवश्यक है । इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, हमें स्पष्टता, सटीकता और तात्कालिकता के साथ कदम उठाने की आवश्यकता है । हमें एकजुट होकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के जल संसाधनों का प्रबंधन उस सावधानी और दूरदृष्टि के साथ किया जाए, जो वे पूरी तरह से हकदार हैं । क्योंकि अंततः जल सिर्फ एक संसाधन नहीं है; यह जीवन की नींव है । धन्यवाद ।

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): I thank my party as well as my party Leaders for giving me this opportunity to express my views on the demands for grants. I have to state that I come from the tribal dominated constituency in North Maharashtra. This is bordering Gujrat on one side and Madhya Pradesh on the other.

This is a tribal constituency where the river Narmada also flows as well as the river Tapi flows. One may wonder there might be no problems of water in this constituency. One might have an understanding that my constituency is adequately irrigated, surplus supply of water but that's not the reality. The reality is actually more shocking and also disappointing. The truth is that, my Nandurbar constituency is the poorest district in the state of Maharashtra as per recent surveys. Nandurbar needs a separate development model, more funds and extra support from the Central Government for development. It was not like this 11 years ago. There is lot of help needed which I am here to seek. I seek the government's help in this regard in almost all sectors.

There were talks about joining the two rivers in my constituency. It is being objected by people for various reasons. The Joining of rivers seems like a business objective more than practical objective. Because this govt only keeps business as an agenda before launching any policy.

In Nandurbar taluka in my parliamentary constituency, there is a huge drought issue faced by farmers. This is worst during the summers. 35 years ago, one political leader promised an ambitious project for the farmers under the name of tapi-burai project. The drip irrigation project which was sanctioned at 70 crores has now reached 800 crores. Even then the state government offers minimal to negligible funds for this project. I ask the central government to fund this project from its own budget, reignite this project, save lives of thousands of farmers and bring green revolution to the land of north Maharashtra, parts of Gujarat and even Madhya Pradesh. This will also stop migration of farmers and families in search of jobs. If this project is operational, then many villages in Nandurbar tehsil, Sakri tehsil will benefit in my constituency.

Water scarcity problems are causing the suffering of many farmers and families in my constituency. Also, the State Government of Maharashtra is not bothered by this. The State government wants to make Nandurbar and North Maharashtra just like how they have damaged the Marathwada region. From being another statistic in drought prone area in the state of Maharashtra, the Central Government needs to pay special attention to this demand.

Secondly, the Narmada tribunal award had announced 10 TMC water to the state of Maharashtra from the Sardar Sarovar Dam. Unfortunately, since so many years, and after years of litigation, it seems that the state of Gujarat refuses to obey the tribunal's order. I demand from this government that the central government instruct the Gujarat state government to release 10 TMC of water to the state of Maharashtra. This share of water rightfully and legally belongs to the state of Maharashtra.

If the Gujarat Government does not accede to the Tribunal Award then a contempt case should be filed against the government for disobeying the final verdict. Strict action needs to be taken against erring officials and penalties should be imposed as well.

If the water is released then some provisions be made for the tehsil of Dhadgaon and Akkalkuwa and implement minor irrigation projects. This will keep the ground water levels in the constituency intact and the rivers will have water throughout the year. This is because the people of Dhadgaon and Akkalkuwa tehsil have been first asked to relocate because of the dam. these should be the first to receive certain benefits from the same. Right now also many in Manebeli don't have potable water as well.

The central government has on time and again given silly reasons for the failure of the Jal-Jeevan mission. The Central Government keeps clarifying that they are only monitoring authority for JJM and the executing authority is the state, but the Central Government is not doing its supervising as well. The State Government also does not want to share any blame in the failure to implement the scheme. There is a huge scam in Maharashtra regarding this and even in my Nandurbar parliamentary constituency. The works are incomplete, the roads have been dug up, there is no tap, there is no pipes, there is no tank, there is no water, contractors have absconded the work, the works are left incomplete as well and many more issues relating to the scheme.

My question is, is there going to be funds for repair of the roads damaged for the JJM scheme? Is there going to be some additional funds for the completion of the scheme? Is there going to be an addition in the number of villages that will be covered in the scheme without completion of the previous works?

In my Nandurbar lok sabha constituency there is rampant corruption related to the scheme, which needs to be investigated. The local body government which was supposed to implement the scheme has committed several irregularities in the implementation of the scheme and the same needs to be investigated by a committee or judicial inquiry.

I request the Government to grant a package under Atal Bhujal Yojana in my Nandurbar Parliamentary constituency. This would definitely raise the ground water levels in my constituency and solve the oncoming agrarian crisis. I therefore request

some incentives from the Central Government and more funds for projects in Nandurbar.

Thank you once again for letting me speak on the demand for grants.

There was an incident where a certain political leader said that the water of the Holy-river Ganga was potable/drinkable during the Mahakumbh. This statement comes after the National Green Tribunal in the month of January had given warnings that the Ganges is more polluted than ever. This is also when the Central Pollution Control Board has declared that the most parts of Prayagraj the water was unfit for drinking and due to high levels of bacteria. Despite such warnings the political leaders from the ruling party make such abhorring statements and mislead the public. गंगा को मानवता की मां के रूप में देखा जाता है. But they have forgotten to give the mother the respect, express love, show care and offer the importance she deserves. The river ganga keeps suffering because of this Government's poor policies.

Can the government explain how does the rivers of the developed nation remain so clean, with minimal funding, but despite Government spending multi-crores of money Ganga has never remained clean once?

Cleaning of the River Ganga doesn't seem to be the priority of the double engine government? Is it always election agenda?

***m93 श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) :** भारतीय जल संसाधनों के विकास के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय जल शक्ति मंत्री जी की अपार मेहनत और दृष्टि की सराहना करने का अवसर प्रदान करने के लिए मै आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र से जुडी जल सम्बंधित समस्याओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ ।

मैं इस मंच से भारतीय संसद में जल शक्ति मंत्रालय के लिए प्रस्तावित मांगों और अनुदानों पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त कर अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ । इस अवसर पर, मैं सबसे पहले माननीय जल शक्ति मंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रालय द्वारा देश के जल संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए किए गए अभूतपूर्व प्रयासों की सराहना करना चाहता हूँ

। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'राष्ट्रीय जल जीवन मिशन', 'राष्ट्रीय परिदृश्य योजना', 'ग्राम जल योजना' जैसी योजनाएं बहुत ही सराहनीय कदम हैं । इन योजनाओं के जरिए, हर एक व्यक्ति तक स्वच्छ जल पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे हमारे गांवों और दूर-दराज के इलाकों में पानी की किल्लत को हल किया जा सके । इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय ने जल की पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के प्रयासों को भी बढ़ावा दिया है । जो कि न केवल पानी की बचत करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की सुरक्षित उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा ।

हम जानते हैं कि भारत में 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और उनकी सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है । इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) और अन्य सिंचाई योजनाओं के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय ने किसानों के लिए नई संभावनाओं को खोला है, और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए कई योजनाओं को लागू किया है ।

इस मंत्रालय की ओर से उठाए गए ये कदम वास्तव में सराहनीय हैं, और मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों से भारत में जल संकट को हल करने में मदद मिलेगी ।

माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय ने जो कार्य किए हैं, वे न केवल जल संकट से निपटने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की सतत विकास की दिशा में भी एक मजबूत कदम है । मैं इस प्रयास की सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से हमारे देश में जल संसाधनों का प्रबंधन और भी प्रभावी ढंग से किया जाएगा ।

महोदय, इस साल के बजट आवंटन में झारखंड राज्य में जल सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु कुल रु० 99503 करोड़ रूपये की धनराशी का आवंटन किया गया है ।

1. जल जीवन मिशन

2. नमामि गंगे कार्यक्रम

3. अटल भूजल योजना

4. सिंचाई एवं जल संसाधन विकास

5. जल प्रबंधन और शहरी जल आपूर्ति

6. जलवायु परिवर्तन और जल संकट से निपटने के उपाय

7. वित्तीय आवंटन और बजटीय आवश्यकताएँ

वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर मै अपने संसदीय क्षेत्र से सम्बंधित एक अतिमहत्वपूर्ण मांग सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ जिसमे झारखंड राज्य की सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना एक ऐसी पहल है, जिसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है । इस परियोजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना है, जो राज्य की बड़ी आदिवासी और स्थानीय गरीब किसान जनसंख्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

हमारे माननीय मंत्री जी के निर्देशन में इस परियोजना को 2011-12 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्वीकृति दी गई थी । इस परियोजना की कुल लागत 14,959.44 करोड़ रुपये है, और यह किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है । इसके लिए केंद्र सरकार ने अब तक 616.91 करोड़ रुपये की राशि जारी की है, जो इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है ।

यहां तक कि झारखंड की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और इस परियोजना के जरिए राज्य सरकार द्वारा पाइपलाइन के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है । लेकिन, यह कार्य केवल केंद्रीय मदद से ही पूरा किया जा सकता है ।

माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों और समर्पण के कारण, हम आशा करते हैं कि जल्द ही इस परियोजना के लिए 616.91 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी, ताकि 31 मार्च 2025 तक इसे पूर्ण किया जा सके । साथ ही, MOU के अनुसार, AIBP की प्राक्कलित राशि के 60 प्रतिशत केंद्रांश राशि को जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ।

मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में भारत जल संसाधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि उनके प्रयासों से देश के किसान और आम नागरिक जल की समस्या से निजात पा सकेंगे ।

जल संसाधनों का उचित प्रबंधन और संरक्षण देश के विकास और आमजन के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है । इसलिए, 2025-26 के लिए जलशक्ति मंत्रालय की अनुदान माँगों को पूरा समर्थन दिया जाना चाहिए, ताकि जल संकट का समाधान हो सके और जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके । धन्यवाद ।

SHRIMATI PRATIBHA SURESH DHANORKAR (CHANDRAPUR): I express my views Supplementary Demands pertaining to Jalshakti Ministry. There is huge water scarcity in my Chandrapur city. Dhanora and Pipri Barrage work has been approved. You are requested to provide sufficient funds and expedite the work of this Project.

Chandrapur District has many coal mines and due to this natural overburden, many rivers have changed the flow in this District. Therefore, the flood like conditions have been developed in the area near to rivers. Therefore, I request you to pay attention to the depth of the rivers adjacent to the coal mines.

Tenders were floated for Lower Painganga Project but, as of now, the work has been stopped. You are requested to expedite the work.

It is proposed to provide water from the right canal of Gosekhurd Project for irrigation to the Pombhuna and Mul Tehsils. But, due to slow pace of work, the water could not reach to the farmers. In this regard, I urge upon you to complete this work immediately by using your good offices.

The problem of water in the summer is very serious in Maharashtra. But, during monsoon, the rain water causes heavy damages to farms and villages. Atal Bihari Bajpayeeji had proposed the concept of river interlinking to provide water throughout the year. But, the Govt. is not serious about this Scheme. If all the rivers get inter-connected under this Scheme, the water problem will be resolved and the farmers would get enough water for irrigation.

In the rural area, the problem of drinking water and irrigation still persists and that is why

I would like to request you to construct large ponds in rural areas to provide irrigation facilities.

Thank you.

CAPTAIN BRIJESH CHOWTA (DAKSHINA KANNADA): I support the Demand for Grants for the Ministry of Jal Shakti. I would like to begin my speech by quoti

a shloka from the Rig Veda:

"Aps van tara mrutam apsu-bhesha jam?

Which means, "There is nectar in water, there is medicine in water. This verse from the Rig Veda reminds us that water is not just a resource; it is life itself. The recently concluded Kumbh Mela, where millions took a holy dip at the confluence of the Ganga, Yamuna, and Saraswati, underscores the deep reverence that our civilization holds for water.

Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, the Ministry of Jal Shakti was formed in 2019, integrating various water-related initiatives to ensure a holistic approach towards water management, availability, and accessibility of clean water across the country.

Budgetary Allocation:

For the year 2025-26, the Ministry of Jal Shakti has been allocated Rs 99,503 crore, which close to 2% of the total budget, underscoring the government's commitment to addressing water-related issues.

Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS): The DDWS has been allocated Rs 74,226 crore, a substantial increase from the Rs 29,917 crore revised estimate of 2024-25.

Jal Jeevan Mission (JJM): Launched in 2019, JIM aims to provide tap water to all 19 crore rural households. As of January 21, 2025, 15 crore households (80%) have functional tap water connections. In 2025-26. IIM has been allocated Rs 67,000 crore, marking a 195% increase over the revised estimate for 2024-25.

In Karnataka, out of 1,01,31.384 households, 85,03,393 households have been provided with a tap water connection, which is coverage of 83.93%

In my constituency of Dakshina Kannada, out of 3,34,185 households. 2,95,037 households have a tap water connection, which is 88.29% coverage.

Swachh Bharat Mission - Grameen (SBM-G): Focuses on sanitation in rural areas, with an allocation of Rs 7,192 crore for 2025-26.

Department of Water Resources, River Development, and Ganga Rejuvenation:

Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY): Rs 8,260 crore has been allocated, a 25% increase.

River Interlinking Projects: Rs 3,400 crore has been allocated, a 13% increase.

Namami Gange Programme: Rs 2,400 crore has been allocated, a 20% increase.

Atal Bhujal Yojana (ABY): Rs 1,780 crore has been allocated, a significant 197% increase from the previous year.

Achievements of the Government:

80% of rural households now have access to tap water under JJM.

The Namami Gange project has led to a significant improvement in the cleanliness. and rejuvenation of the Ganga.

PMKSY has improved irrigation coverage across India, ensuring water security for farmers.

Demands of the Constituency:

while significant progress has been made, I want to bring to the attention of the House the urgent need for a Multi-Village Drinking Water Supply Scheme for Dharmasthala and 645 other habitations in Belthangady Taluk, Dakshina Kannada District.

Belthangady Taluk comprises 48 panchayats, of which only 17 panchayats have access to multi-village water supply schemes. The remaining 31 panchayats rely

heavily on groundwater sources like borewells and open wells, which are often contaminated with high iron content and deplete during summer.

To address this crisis, a new Multi-Village Water Supply Scheme has been proposed. utilizing the recently constructed Minor Irrigation Department Dam across the Netravathi River at Pajiradka. This project, with an estimated cost of Rs 358 crore, will provide safe and sustainable drinking water to 1.75 lakh residents across 646 habitations**.**

1 urge the Hon'ble Minister to approve this project under the jal Jeevan Mission and facilitate the preparation of a Detailed Project Report (DPR) at the earliest.

Conclusion: Water is the foundation of life, health, and prosperity. Under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. India has witnessed unprecedented progress in water management and conservation. His unwavering commitment to the welfare of the people, particularly in rural India, has ensured that the vision of Har Ghar Jal is becoming a reality.

I strongly support the Demand for Grants for the Ministry of Jal Shakti and urge the government to expedite the approval of essential projects like the one in Belthangady Taluk to truly achieve Har Ghar Jal.

Jai Hind!

***m96 डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे (लातूर) :** जलशक्ति मंत्रालय के Demands for grant पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मुझे खुशी होती हो रही है ।

मैं सरकार का ध्यान इस देश के उन इलाकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जहाँ हमेशा पानी की कमी होती है । मैं महाराष्ट्र के लातूर लोकसभा प्रतिनिधि हूँ जहाँ कुछ दिन पहले रेलवे से पानी लाया गया था और वो भी 300 km दूर से । इस डिपार्टमेंट का काम आगे बढ़ाते समय मंत्री से मेरा अनुरोध है की वो लातूर जैसे कमी पाणी के Area की ओर ज्यादा ध्यान दें ।

अपने देश में बहोत से Area में बाढ़ के कारण काफी नुकसान हर साल होता है और इससे मोटे पैमाने पर जान और माल का नुकसान होता है । मेरी सरकार से गुजारीश है की

जो पाणी बाढ़ में बहता जाता है उस पानी को अगर कम पानी वाले एरिया में Divert कुरके उसका इस्तेमाल कर सके तो उसके जैसा बड़ा काम कोई नहीं होगा । इससे लोगों को पीने का पानी मिलेगा और किसानों को फसल के लिए भी उपयोग होगा । इस मौके पर मैं आपका ध्यान existing it Irrigation Projects है उसकी ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ । उनका maintanance सही होना जरूरी है । बहुत सारा भ्रष्धाचार इसके तहत होता है जिसको रोकना जरूरी है । में इकडे द्वारा नदियों के खोलकिरन की भी मांग करता हूँ । अगर नदियां स्वच्छ रख सकें तो बहुत ही फायदा होगा । हम सब जानते है की बहुत सारी नदियां शहरों का गंदा पानी और Industries के Pollution की वजह से खराब हो रही है । इसके लिए देशभर में people Just education और ठोस उपाय जरूरी है ।

मैं सरकार से माँग करता हूँ की जो सपना बाबासाहेब आंबेडकर तथा अटलजी ने देखा था उसको याद करना होगा और वो सपना था 'नदीजोड़ प्रकल्प? । उसके उपर काम करने की जरूरत है ।

मैं महाराष्ट्र के मराठवाडा एरिया से हूँ जिसके लातूर धाराशिव, नांदेड, बीड जैसे चिन्हों में हमेशा पानी की कमी कम बारिश होने की वजह से है । इन जिलों की और विशेष ध्यान देने की विनती करता हूँ । इन सब इलाकों में पानी की कमी की वजह से काफी नुकसान होता रहा है । इन सब इलाकों में खेती के अलावा कुछ नहीं है । पानी की कमी से खेती के लिए हमेशा परेशानी रही है । इन पूरे इलाकों में Industrial growth रुक चुका है । इस Area के नौजवान उसी वजह से बेरोजगारी से परेशान है और Migrate कर रहे है ।

इन पूरे इलाकों की development के लिए जल्द से जल्द पूरे मराठवाडा Area में नदीजोड़ प्रकल्प चालु करे और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में Budget का provisions करें । Interstate जो debate पानी Distribution की वजह से सालों से चले आ रहे हैं उन्हें भी जल्द खतम करें ।

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : मोदी सरकार ने जल प्रबंधन और ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में जल शक्ति मंत्रालय के लिए अभूतपूर्व 99 हजार 503 करोड़ रूपए आवंटित किए हैं, जो 2013-14 में यूपीए शासन के अंतर्गत मात्र 17 हजार 342 करोड़ रूपए की तुलना में लगभग छह गुना वृद्धि को दर्शाता है । यूपीए शासन के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में जल संसाधन और पेयजल के लिए कुल 17 हजार 342 करोड़ रूपए के संयुक्त आवंटन की तुलना में, वर्ष 2025-26 में केवल पेयजल और स्वच्छता विभाग को ही 74 हजार 226 करोड़ रूपए का अभूतपूर्व आवंटन प्राप्त हुआ है । यूपीए सरकार की जल

संसाधनों के प्रति वित्तीय प्रतिबद्धता बेहद अपर्याप्त थी, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश 2002-03 में मात्र लगभग 2,000 करोड़ रूपए से बढ़कर 2013-14 में 11,000 करोड़ तक ही पहुंचा पाया था । वित्त वर्ष 2025-26 में जल शक्ति मंत्रालय के लिए वर्तमान मोदी सरकार द्वारा आवंटित 99 हजार 503 करोड़ रूपए की तुलना में नगण्य प्रतीत होता है । देश के प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में मोदी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (JM) की शुरुआत की गई, जोकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ग्रामीण सशक्तिकरण और जनकल्याण की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है ।

आज, 15 करोड़ से अधिक परिवारों, यानी भारत की 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को नल के माध्यम से स्वच्छ जल की सुविधा प्राप्त हो चुकी है, जो 2018 में मात्र 3 करोड़ परिवारों की तुलना में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है । इस परिवर्तनकारी प्रभाव और शेष चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 195% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है ।माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों को जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध करवाकर इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया, जिसके फलस्वरूप आज देश में भूजल के स्तर में सुधार हुआ और देश में साफ-सफाई का माहौल बना ।

मैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल जी का आभार व्यक्त करते हुए इस बजट का समर्थन करता हूँ ।

मैं जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र की पानी से संबधीत प्रमुख समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ -

जालोर सिरोही में कम वर्षा के होने से भू-जल स्तर बहुत भारी गिरावट आयी है जिसके कारण दोनो जिले डार्क जोन घोषित हो चुके है । माही नदी का पानी जालोर सिरोही जिले के लिए उपलब्ध कराने की योजना सालो से कागजो में दफन हो कर दम तोड रही है ऐसे में अब किसानो की उम्मीदें भी टूटने लगी है । वर्ष 1966 में राजस्थान सरकार व गुजरात सरकार में हुए समझौते के अनुसार माही बांध का परियोजना का कार्य शुरू हुआ था । खोसला कमेटी की रिपोर्ट 1 सितम्बर 1965 के अनुसार गुजरात राजस्थान के बीच बोर्डर पर कडाणा बांध बनाना प्रस्तावित था । उस समय दिनांक 01 अक्टूबर 1966 को राजस्थान एवं गुजरात सरकार के बीच माही जल बंटवारा समझौता में कडाणा बांध का निमार्ण हुआ था । समझौते

के अनुसार गुजरात के खेडा जिले को कडाणा बांध से पानी तब तक मिलेगा जबतक नर्मदा का पानी नहीं आता है चुकि अब नर्मदा का पानी गुजरात के खेडा जिले को मिल रहा है तो स्वत ही समझौते के अनुसार कडाना और माही बांध के पानी का 2/3 भाग राजस्थान के सिरोही जालोर तय हो चुका है । किसानो का सिंचित पानी कडाणा बांध और माही से पिछले 37 साल में 27 बार ओवरफलो होकर 1.30 लाख एमसीएम पानी समुद्र में बहकर बर्बाद हो गया है । अध्यक्ष महोदय पुरे पश्चिम के राजस्थान के किसानो के तरफ से निवेदन कर रहा हूँ कि कडाणा व माही बांध के ओवरफलो पानी बहकर सुजलाम सुफलाम नहर के मार्फत 37 साल में 27 बार ओवरफलो हो कर जा रहा है उस पानी को जालोर सिरोही के लिए दिया जाए जिसकी फिजकल रिपोर्ट वापकोस कम्पनी गुडगाँव द्वारा तैयार हो चुकी है । अतः राजस्थान और गुजरात के सामुहिक बैठक बुलाकर डिपीआर बनाकर पोजेक्ट को आगे बढाया जाए ।

माननीय सभापित: श्री बापी हलदर ।

SHRI BAPI HALDAR (MATHURAPUR): Hon. Chairperson, I thank you for letting me speak on the discussion regarding the Demand for grants under the control of the Ministry of Jal Shakti. I am grateful to our Hon. Chief Minister Mamata Banerjee, our beloved leader Abhishek Banerjee and the people of our Mathurapur constituency- due to their blessings, I got the opportunity to stand here today in front of this August House. Sir, in the financial year 2025-26, the Ministry of Jal Shakti has been allocated a budget of 99,503 Crore rupees. It is almost the same as the previous financial year's budget allocation. This ministry has two departments- Department of Water Resources, River Development, Ganga Rejuvenation and Drinking Water & Sanitation. Sir, in 2019, the Hon. Prime Minister launched the Jal Jeevan Mission with great fanfare.

देश की140 करोड़ जनता को गारंटी दी गई कि हर एक परिवार को वर्ष 2024 तक शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा । इस गारंटी के साथ माननीय मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हर साल नौजवानों को दो करोड़ नौकरियां मिलेंगी, कालाधन वापस आएगा, महंगाई कम हो जाएगी, अन्य जुमलों के साथ यह भी एक जुमला था ।

In reality, this initiative has failed in achieving its targets. Hon. Finance Minister, while presenting the budget this year, has said that an additional 4 years would be required to achieve the target. In this financial year, 67000 Crore rupees

has been sanctioned in the JJM project, which is approximately 5% less than the last year. This is the current status regarding the fulfilment of the government's promises. Sir, West Bengal is being deprived when it comes to projects such as MGNREGA, Sarva Shiksha Abhiyan, etc. Similarly, the JJM project is also made to face turmoil and deprivation in West Bengal. In the financial year 2024-25, the centre has given only 2528 Crore rupees to the state from the allocated 5089 crore rupees. As we know, due to the lack of financial aid from the central government regarding the MGNREGA project, our Chief Minister Mamata Banerjee paid 100 days of wages to the people of Bengal from the state's own treasury. The central government has also stalled the financial assistance for Awas Yojana. The beloved chief minister of West Bengal has managed to make homes for the people of our state, borrowing money from the state's treasury. Similarly, to take this project forward, she has contributed 4156 crore rupees out of the 4990 Crore rupees decided. There are at least 4 states where less than 60% of families are included under this scheme.

सर, हर घर नल से जल की रिएलिटी यही है । ग्राउंड रिएलिटी यही है कि सिर्फ नल है, जल नहीं है ।This Ministry also launched the Namami Gange Programme with great fanfare. It was a flagship project of the Modi Government.

हमारे देश के प्रधान मंत्री ने वर्ष 2014 में कहा था कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है । माँ गंगा ने अभी भी बुलाया है, लेकिन प्रधान मंत्री बनने के बाद लगता है कि उन्होंने माँ गंगा को बुला लिया है ।

There's only one reason for mentioning all these. A significant portion of the allotted funds has remained unused since 2014-15, with the exception of 2020-21. In the financial year 2024-25, only 69% has been spent from the allotted sum under this project. Whenever the government is unable to spend the allotted sum, we see the pollution in the rivers including the Ganges, reaching a record high. Lately, we read the report of the National Green Tribunal concerning the Kumbh Mela, and the fake promises to decrease the river population are now evident to everyone. Hon. Prime Minister has spoken vastly about the Kumbh Mela but didn't mention a word about how many people died due to Water Pollution or how many people are

suffering from water-borne diseases. नमामि गंगे के नाम पर हजारों-करोड़ों रुपये जो खर्च हुए हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है । इसकी भी जांच होनी चाहिए कि यह पैसा कहां गया? केन्द्र सरकार को यह भी बताना चाहिए कि नदी की सफाई कब तक हो जाएगी?

Swachh Bharat Mission also falls under this project within the purview of the same ministry. Under this project, a chunk of the money allocated for the development of the rural areas remains starkly unused. In the financial year of 2024-25, the money allocated for this scheme was 7192 crore rupees, from which the government could only spend 33%, i.e. 2354 crore rupees. We saw huge advertisements for the Swachh Bharat Mission, but in reality, this work is only known to people like us who reside in rural areas. Initially, efforts were made to construct toilets in exchange for 1000 rupees only. But that was neither healthy nor realistic. Now the government is planning to construct toilets in exchange for 12000 rupees. The state government is supposed to contribute 3000 rupees and the central government is supposed to contribute 9000 rupees. We all know that common people are finding it difficult to live in these current exorbitant market prices. We can understand from the statistics of budget allocation how reasonable and practical it is to build a usable toilet with 12000 rupees. The kind of toilets that are being made with 12000 rupees have such scarcity of space that a person occupying the toilet has to leave his bucket outside. This is the real picture. Through you sir, I want to request the hon. minister to devise a proper, systematic plan to make useable toilets and bring that into action so that the suffering of common people can be alleviated. Certainly, this is the need of the hour. Another important facet of this department is water resources and river development. In my Mathurapur Lok Sabha Constituency, most of the areas are surrounded by rivers. The lives of people in Sundarban are spent amidst water and jungles, and natural calamities push thousands of homesteads and agricultural land slowly towards destruction. We don't have any say on Natural Calamities. But the government must take precautions to alert and protect people. Due to the technological advancements, we can predict the nature of these natural calamities. It's a common practice for the government to announce special packages to aid people who were hit by natural calamities such as floods or cyclones in any part of the country. However, West Bengal has repeatedly

been denied fair compensation, during Amphan or the recent floods. Through you, sir, I want to draw the attention of this house: rivers are reversing their directions due to global warming. As a result of which the river embankment is getting damaged. River dams have broken in different places. I do not know whether the government or the ministry has any plans for the reconstruction of the river dams that are broken due to the change in the course of the river, just as the government arranges for its reconstruction in case of natural disasters. Sir, if the government doesn't have any such plans, the government should immediately adopt a plan for this and should take measures to reconstruct the river dams so that they can ensure the safety of the people living in coastal areas.

माननीय सभापति : आप कृपया कनक्लूड कीजिए ।

SHRI BAPI HALDAR : As an example, I need to cite the river erosion in Gobardhanpur village near Patharpratima, which falls under my constituency, and a hundred acres of agricultural land from many villages are under threat of getting submerged in the riverbed. Cargo ships commute through the Budhiganga River near Mousuni Island in the Sagar assembly constituency. As the navigability of the river decreases, the ship changes its course and moves closer to the banks of the river. As a result, river erosion is increasing. As a result, agricultural land, residential houses, schools and health centres stand the threat of going into the river. Notable in this regard is the Gangasagar Pilgrimage, which houses the temple of Lord Kapil Maharaj, one of the traditional pilgrimage sites of West Bengal and India. Where lakhs of pilgrims gather on the auspicious day of Makar Sankranti and also throughout the year. Gangasagar Mela is the second-largest human fair in India. Our Hon. Chief Minister Mamata Banerjee has repeatedly requested the Central Government to declare Gangasagar Mela as a National Fair. The central government has not yet shown any foresight in that regard. Currently, due to river erosion, Gangasagar and the nearby areas of the Kapil Maharaj Mandir are headed towards destruction. We have seen in recent years that the central government has spent crores of rupees for the beautification of the riverbanks in Kedarnath, Haridwar, and Varanasi. But Gangasagar was deprived because it is situated in West

Bengal. No steps are taken to protect Gangasagar even in the present budget. The beloved chief minister of West Bengal has tried to protect Gangasagar and she has taken measures for its beautification. She has already facilitated the travel of pilgrims by building the Gangasagar bridge over the river Budhiganga. Sir, through you, I request the government to protect Gangasagar in a similar vein to the other pilgrimages. The government should immediately take steps for its beautification. Declare the Gangasagar Mela as a national fair in recognition of the immediate dignity and merit of the Gangasagar. The river erosion in Gangasagar should also be declared as a national sister. The government should announce a special package to protect Gangasagar. In conclusion, through you, I would request the Jal Shakti Ministry to protect the lives in Sundarbans and to protect the river embankments in Sundarbans. They should turn the river-banks into concrete in Ghoramara Island, Gobardhanpur Coastal area, Mousuni Island, Kakdwip, Namkhana, Bakkhali, Raidighi, Goshaba, Basanti, Kultali to provide safety to the people living in this huge expanse of the coastal area. Thank you. Jai Hindi. Jai Bangla.

SHRI BASTIPATI NAGARAJU (KURNOOL): Thank you hon. Chairperson.

I stand here to express my views on demands for grants for the ministry of the Jal Shakti for the year 2025-26. I also thank honourable Prime Minister Sri Narendra Modi, Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman and our honourable Chief Minister Nara Chandrababu Naidu for coming up with a bright and positive budget. I praise them for their far sightedness and vision.

Jal Shakti ministry has been allocated with ₹ 99,503 crores for the financial year 2025-26. This budgetary allocation clearly reflects the Union government's commitment towards solving water problems in our country. I would like to discuss four issues pertaining to my state. Firstly, Jal Jeevan mission has effectively tackled the drinking water crisis in rural areas by providing piped drinking water to numerous households, which has improved health and sanitation in our villages. Though this scheme is being implemented throughout the country at a faster pace, our state Andhra Pradesh could not even touch the national average when it comes to coverage of this scheme.

Due to the negligence of the previous government in our state, we are staring at darkness. I thank the Union Government for extending this scheme till 2028 and allocating ₹67,000 crores for this scheme. This step will help Andhra Pradesh grow stronger.

The second point is regarding Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana which has been introduced to strengthen the irrigation infrastructure in our country, but in Andhra Pradesh, out of eight approved projects only one project could be completed. Though 53 crores have been sanctioned by the union government, since 2019-20 not even a single rupee was released for these projects. I request the union government to release these funds immediately. Similarly, I request the union government to include Andhra Pradesh in Har Khet ko Pani scheme and improve irrigation facilities in our state. Coming to the third Point, Atal Bhujal Yojana has been implemented in states like Rajasthan, Karnataka and Gujarat which improved groundwater levels. That scheme should be implemented in our state as well, especially in Rayalaseema region. Though ₹600 crores have been allocated for this scheme, only ₹76 crores could be utilised till December 2024. Therefore, I request the government to release these funds on time so that we can improve and save our groundwater levels.

In our state Andhra Pradesh our chief minister Nara Chandrababu Naidu is taking ahead our prestigious Polavaram project with a lot of commitment, for which I appreciate our leader Nara Chandrababu Naidu. This project will not only ensure water security for our state but also will result in agriculture revolution. For the financial year 2024-25, Polavaram project was granted ₹ 5,512 crores, whereas for the financial year 2025-26 this has been increased to ₹ 5,936 crores, which is commendable. But there is so much to be done. The union government has allocated ₹12,157 crores for Polavaram Project, but funds are being released at a slower pace and as a result the project is getting delayed. I request the union government to release funds on time. Once we complete the Polavaram project, this will provide irrigation facilities to lakhs of farmers and this will also increase our agriculture produce.

We need robust water planning for the Rayalaseema region as water scarcity is increasing day by day. Thousands of families are migrating to other places from Rayalaseema. In this region only 25% of agricultural land is getting irrigation facilities. Other farmers depend on rainfall for their agricultural needs. As a part of the long-term solution, a plan for Polavaram Banagacherla river interlinking project has been planned. In line with our Prime Minister's vision of Vikasit Bharat by 2047, our chief minister resolved for Swarna Andhra Pradesh by 2047 and as a part of interlinking rivers Godavari, Krishna and Tungabhadra waters will be linked. For this, there is a need to construct a reservoir at Ballapalli in Guntur district and at Banagacherla in Nandyal district, which will become a lifeline for the farmers of Rayalaseema region.

The main objective of this project is to provide drinking water for 80 Lakh people and irrigation facilities to 7.5 Lakh acres of agricultural lands. During the rainy season we can conserve 2 TMCs of water for 100 days. This project will cost ₹ 80,112 crores. We need 40,500 acres of agricultural land and 17,000 acres of forest land for this project. This financial burden cannot be borne alone by the state of Andhra Pradesh, therefore I request the union government to share this burden by allocating additional funds so that this project can be completed on time. This is not something confined to water projects, this is something which pertains to the survival of Rayalaseema.

The NDA government is following the principles of federalism by giving equal importance to all states. I am hopeful that under the leadership of our honourable Prime Minister Narendra Modi, this project will be given priority. Our chief minister Nara Chandrababu Naidu has provided clarity in direction for our state. The Rayalaseema region can only prosper when the union government and state government work collectively. Therefore, I request the union government to provide immediate support for this important water project and bailout the Rayalaseema region from the problem of water scarcity. Let us ensure that our farmers need not stare at clouds for rain. Thank you, sir.

***m100 श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) :** महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र शिवहर और बिहार की जनता की ओर से जल संकट और जल प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं को सदन में रखना चाहती हूँ । वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल संरक्षण और जल आपूर्ति के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं । ?जल जीवन मिशन? के तहत लाखों ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है, जिससे महिलाओं को जल संरक्षण की कठिनाइयों से राहत मिली है । ?नमामि गंगे परियोजना? से गंडक और बागमती जैसी नदियों के प्रदूषण में कुछ सुधार हुआ है । ?अटल भूजल योजना? ने भू-जल स्तर को बनाए रखने में योगदान दिया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देकर कृषि उत्पादन को सशक्त किया है । ?कैच द रेन अभियान? के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया गया है, जिससे जल संकट से निपटने में सहायता मिली है । बिहार में कोसी-मैची योजना के लिए बजट में करोड़ों रुपये का प्रावधान कर बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को राहत देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ ।

महोदय, हर घर नल का जल पहुँचाने में बिहार के विकास पुरूष आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है और उनका यह कार्य बहुत ही सराहनीय है । इसी तर्ज पर केन्द्र सरकार ने भी पूरे देश में इस योजना को लागू किया है । माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने ?जल-जीवन-हरियाली? योजना के तहत जहाँ उन्होंने लाखों घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुँचाया, वहीं भगवान विष्णु की मोक्ष नगरी गया और मगध की पौराणिक राजधानी राजगीर में अपने भगीरथ प्रयासों से गंगा का अमृत जल भी पहुँचाया ।

महोदय, फल्गू नदी, जो वर्षों से सूखी रहती थी, यही इतिहास था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से अब वहाँ 12 महीने गंगा का जल रहता है, उसमें गंगा का पानी रहता है । यह बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है । उसमें पानी होने के कारण अब वहाँ गया में पहाड़ पर भी पेड़ उगने लगे हैं । जो असंभव काम है, वह संभव हुआ है और ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए प्रयासों से हुआ है ।

अब मैं अपने क्षेत्र की बात कर रही हूँ । हालाँकि आज भी मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में जल संकट की गंभीर समस्याएँ बनी हुई हैं । मानसून के दौरान बागमती और गंडक नदियों में बाढ़ से हजारों परिवार प्रभावित होते हैं, जबकि गर्मियों में पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाती है । अभी भी वहाँ पर बाढ़ की बहुत विभीषिका आयी थी, जिसका मैंने पहले सदन में

जिक्र किया था । मैं माननीय जल शक्ति मंत्री से आग्रह करती हूँ कि शिवहर में, जहाँ से मैं चुनकर आती हूँ, शिवहर जिला चारों तरफ से बाढ़ की चपेट में आता है, वह नदियों से घिरा हुआ है । वहाँ तटबंध टूट गया था तो शिवहर में बहुत भयानक बाढ़ आयी थी, बाढ़ नियंत्रण हेतु प्रभावी तटबंध, बराज सह पुल निर्माण और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाए । इसके तहत बागमती नदी पर अदौरी-खोरी पाकड़ और बूढी गंडक पर सरसावां-रामगढ़वा बराज सह पुल निर्माण जरूरी है । इससे जहाँ लाखों किसानों का कल्याण होगा, वहाँ यातायात भी सुगम हो जाएगा ।

महोदय, मेरी माँग है कि बिहार में बाढ़ का संकट समाप्त करने के लिए नेपाल में हाई डैम बनाया जाए ताकि यह जो हर साल बाढ़ की समस्या आती है, उसका निदान हो सके । बाढ़ में किसानों की बहुत सारी फसल खत्म हो जाती है, बहुत सारी क्षति होती है, घर बार असमय बाढ़ में बह जाते हैं, डूब जाते हैं और लोग दाने-दाने को तरसते हैं । जब वहाँ हाई डैम बन जायेगा तो इस समस्या का परमानेन्ट समाधान हो जायेगा ।

भूजल स्तर गिरने से पीने के पानी की समस्या विकराल होती जा रही है, इसलिए जलाशयों, तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए विशेष योजना लायी जाए । किसानों को राहत देने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए और जल के कुशल उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाए । साथ ही महिलाओं और बच्चों की सुविधा के लिए हर घर में नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ।

मैं माननीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि इन आवश्यकताओं पर त्वरित ध्यान देने का कष्ट करें ताकि शिवहर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों, जैसे कोसी क्षेत्र में जल संकट का स्थायी समाधान हो सके ।

महोदय, आपने हमें बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK): Hon?ble Chairman Sir, thank you very much for allowing me to participate in the discussion on Demand for Grants of the Ministry of Jal Shakti for 2025-26. Water is very essential for farming and industry as well as all the human beings. To ensure water conservation, river rejuvenation and to provide clean drinking water, an effective implementation is a common responsibility for all of us. For Jal Shakti Ministry Rs 99503 crore have been allocated in this year?s budget. I hope this would help to take care of water scarcity, ground water recharge, irrigation facilities and clean drinking water in our

country. To boost river linking projects, water table recharge and also to improve sewage system and water treatment, a better and efficient management must be ensured in Maharashtra as well as all over India. A priority should be given to Godavari rejuvenation and better infrastructure development, in view of Maha Kumbh, 2027 at Nashik.

Sir, Maharashtra is agriculture dominated state but, still the irrigation coverage area is mere 23% and it is very less in comparison to the other Indian States. There is a 3000 mm of rainfall every year in Konkan region but, most of the parts of North Maharashtra, Marathwada and Vidarbha region remain dry and face water scarcity.

To tackle this problem, Jal Shakti Ministry should boost the river interlinking projects and also undertake special programmes for balanced redistribution of water resources. If irrigation facilities increase, it would also help to increase farmers? income and help to eradicate water scarcity as well. Sir, to increase irrigation coverage area in Maharashtra through river interlinking, following 4 projects should be declared as projects of national importance and 90% funding should be given by Union Government for these projects.

These 4 projects are, first, Damanganga-Dare-Godawari link for the development of Nasikh having capacity of 5 TMC. Second, Gargi-Vaitarna-Kalbadevi link for development of Sinnar, Shirdi Third, Wainganga-Nalganga link for the development of Vidarbha region and fourth, Nar-Par-Girna link for the development of Jalgaon area to ensure generation of total 12.5 TMC water through these 4 river linking projects.

Sir, for cleaning of Gadavari river, we will have to stop dumping of waste and sewage water into it through 29 small Nallas flowing through Nasik city. We need to control and treat it. All the main sewage line within municipal boundaries should be repaired immediately and new sewage treatment plants should be set up at Makhmalabad and Kamatwade. By using latest technology, modern STP plants should be developed to minimize industrial waste.

The population of Nasik city is increasing rapidly, so the burden on water and sewage treatment plants is also increasing. To solve this problem, the Union Government should sanction funds for effective implementation. To repair and improve main sewage lines, to set up new STP centers at Makhmalabad and Kamatwade, renovation of Godavari and other ghats, and for development of modern STP plant for treatment of polluted water, we need funding worth Rs 903 crore. Through these projects, pollution of Godavari river would be minimized.

Sir, improvement of water pollution of Godvari river, water management for Kumbh Mela and to setting up STP plants, are very important issues and that is why, I would like to request Union Government to provide sufficient funds for this purpose immediately.

Sir, water tables have been decreased by 50% in most of the districts of Maharashtra. To improve implementation of Atal Bhujal Mission, water conservation projects should be expedited. Modern technology should be used for water table recharge. Government should encourage farmers for the cultivation of drought-tolerant crops. Rules and regulations should be framed for water extraction and it should be implemented strictly. Jal Jeevan Mission ensures to provide drinking water to every household but, today only 15 crore households have been benefitted out of it. Water contamination is also a big issue. So, water testing labs should also be set up and an uninterrupted water supply should be ensured. Thank you.

16.00 hrs

SHRI NILESH DNYANDEV LANKE (AHMEDNAGAR): Hon?ble Chairman Sir, Jay Shivray. I would like to thank you and my party leadership for allowing me to speak on Demands for grants of Ministry of Jal Shakti for 2025-26. Mahatma Gandhi has referred water as a natural resource of vital importance and it must be conserved. Following his advice, the Union Government brought Jal Jeevan Mission scheme and Prime Minister of India referred it as a dream project under this scheme, 60% is central and 40% is state government share.

Har Ghar Jal is also a very important scheme of our Prime Minister and a target of providing 55 litre water to every household has been set under this scheme. Around 830 schemes have been sanctioned in my constituency and 972 villages have been covered under this scheme. Officials claimed that out of 830, works of 230 schemes have been completed.

But, the ground reality is different and not even 50 schemes have been completed yet. Approximately Rs. 1338 crore have been sanctioned for 830 schemes. Through Maharashtra Jeevan Pradhikaran for 112 schemes, Rs. 3200 crore have been sanctioned. It means more than Rs. 4538 crore have been sanctioned for my Ahmednagar district. But, a lot of corruption cases came to light and local villagers have sent me written complaints about it. These complaints are about the tendering process, quality of work and payment of bills and corruption is quite visible at first sight. works have been awarded to the ineligible contractors. Bills have been generated of incomplete works. To lay pipes, it is necessary to dig at least 4-5 feet, but pipes have been fitted at the depth of 1 feet only.

I have got photos and videos of these corrupt activities. I have sent a pen-drive and photo copies to Hon?ble Minister too.; They charged for hard surface even when the soil is soft for laying pipelines and in this way, they recovered more amount from Government. The contractors did not purchase the desired quality pipes and a low quality pipes have been used. These corrupt contractors charged full amount for the construction of water tank which is having a capacity of 50 thousand liters in place of 1 lac litre. The work is still incomplete after time lapse but, no action has been taken against defaulters. Their bills are cleared on time.

These kind of corrupt practices came to light at many places like at Aajnuch in Shrigonda Tehsil, Pargaon in Nagar Tehsil, Bhagwangarh in Pathardi Tehsil and in other 146 villages of this region.

In addition to this, at places like Meeri Tisgaon, Godhegaon, Satgaon, Danewadi, Koregaon, Karjat, Koradgaon, Anjanwadi, Malibabhulgaon, Mathani, Adhalgaon, Narayandoh, Tambere, Daradgaon, Shri Kolar, Nighoch etc. rampant

corruption cases are quite visible. When I seeked information?s from Zilla Parishad in this connection, it is found that the works in only 18 villages have been completed. The Government is protecting and supporting corrupt officials and contractors in these cases. They have made an additional provision of Rs. 25 crore for these schemes. If this schemes are completed, why are they making additional provisions?

In my constituency, these schemes are not being implemented in Scheduled Caste and tribal dominated areas . I demand to implement it urgently in these areas too.

Lastly, I would like to request Hon?ble Jal Shakti Minister Shri C.R. Patil, to initiate an enquiry of Jal Jeevan Mission works by appointing a Director level officer and punish the corrupt officials and contractors by registering FIRs against them.

Thank you. Jai Shivray.

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले) : सभापति महोदय, आपने मुझे जल शक्ति मंत्रालय की अनुपूरक मांगों, 2025-26 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । जल शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री जी ने जो पहल की है, वह बहुत अच्छी है । पहले बहुत सारी सरकारें 70 सालों में बनीं, लेकिन आम जनता की तरफ किसी ने भी अपना दायित्व नहीं निभाया । अपना दायित्व बनाते हुए इस बार शक्ति और भक्ति एक साथ ला कर मोदी सरकार ने काम किया है । निश्चित रूप से देश ने शक्ति और भक्ति का एक स्वरूप प्रयागराज में देखा जब महाकुंभ वहां पर आयोजित हुआ । इस जल को प्रवाहित रखने के लिए, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एक ऋषि तुल्य व्यक्ति ने इस देश की कमान संभाली हुई है, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है । जिन्होंने हमेशा ही इस देश के आम नागरिक को मद्देनज़र रखते हुए इन योजनाओं का प्रावधान किया है । सर, जब देश स्वतंत्र हुआ, तब से ले कर आज तक की परिस्थिति आप देखें तो पिछले दस सालों से पहले क्या अवस्था थी? रेगिस्तान से ले कर दूर-दराज़ गांवों में, पहाड़ी इलाकों में पानी की एक बूंद भी मिलना बहुत दिक्कत की बात हुआ करती थी, किल्लत की बात हुआ करती थी । एक माँ की गुहार वे सुन नहीं पा रहे थे, कोई भी शासक उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था । इस अवस्था में निश्चित रूप से इस सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने इस पर अच्छा काम किया और वर्ष 2016 में मंत्री, सारे

मुख्य मंत्रियों को मिला कर, जो भी अलग-अलग विभाग यहां पर थे, वर्ष 2019 में फिर से उनका गठन किया गया और जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया । बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, जो सिर्फ पानी ढोने का काम करते थे । बचपन में मटकी सर के ऊपर रख कर बच्चियां गांव-गांव से, 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर जा कर पानी लाती थीं और शिक्षा के नाम पर उनकी बुरी हालत हुआ करती थी । इस बुरी हालत को बदलने का कुछ काम हो सकता था ।

इस हालत को बदलने के लिए अगर कुछ काम हो सकता था तो वह काम आज हुआ है । उस समय एक घर में भी नल से जल नहीं आया । आज उस घर का नूर बदल दिया गया है । उस परिवार को एक नया आयाम मिला है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ चीजें सदन के समक्ष रखना चाहूंगा । वर्ष 2014 से पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, यह देखने की चीज है । इस देश में कुल 19,36,83,000 घर हैं । वर्ष 2019 से पहले 3,23,62,000 घरों में जल का कनेक्शन हुआ करता था । 16,13, 05,000 घर पानी के कनेक्शन से वंचित थे । आज की स्थिति यह है कि यह मिशन शुरू होने के बाद, अगर हम उसका पूर्ण औसत देखें तो आज 12,29,62,000 घरों में पानी का कनेक्शन जल जीवन मिशन के माध्यम से हो गया है । आज हर घर में नल से जल पहुंच रहा है ।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वर्ष 2019 के बाद 15,00,53,000 घरों में पानी का कनेक्शन देने का रिकॉर्ड काम इस सरकार के माध्यम से हुआ है । ये सब उपलब्धियाँ विपक्ष के लोगों को नहीं दिखती हैं । उन्होंने हमेशा पानी में जहर डालने का काम किया है । उनको हर जगह राजनीति दिखती है । उनको आम आदमी की जरुरतों को भी देखना चाहिए । निश्चित रूप से यह सरकार आम आदमी को नजर में रखते हुए काम कर रही है ।

महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुछ मांगें सदन के समक्ष रखना चाहूंगा । जल है तो कल है और जल ही जीवन है । किसी बड़े आदमी ने कहा था कि अगर दुनिया में कोई वर्ल्ड वार होगा तो वह जल की वजह से ही होगा । इस जल को प्रीजर्व करना और अच्छे तरह से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी हो गया है ।

महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह कोल्हापुर जिला है । हातकणंगले मेरा लोक सभा संसदीय क्षेत्र है । मेरी कॉन्स्टीटूएन्सी कर्नाटक की सीमा से लगी हुई है । अल्माटी नामक एक बहुत बड़ा डैम कर्नाटक में है । इसकी ऊंचाई बढ़ाने का काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है । कर्नाटक सरकार ने उसकी गुहार लगायी है । पहले इस डैम की ऊंचाई 519 मीटर थी । अब इसकी ऊंचाई 524 मीटर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

महोदय, मैं केंद्रीय मंत्री जी और इस सरकार से गुहार लगाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के चाहे कोल्हापुर जिला हो, सांगली जिला हो, सतारा जिला हो, वहां जल समाधि की स्थिति हो जाती है । हमारे यहां वर्ष 2005 में बाढ़ आई, वर्ष 2019 में बाढ़ आई और वर्ष 2021 में भी बाढ़ आई । जब अल्माटी डैम की ऊंचाई 519 मीटर तक बढ़ाई गई, तब से हमारे यहां लगातार बाढ़ आ रही है । इसके माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है । चाहे कोल्हापुर जिला है, सतारा हो, सांगली हो, वहां बाढ़ पीड़ित के इलाके बढ़ रहे हैं ।

महोदय, मेरी मांग है कि उस डैम की ऊंचाई नहीं बढ़ाया जाए । हमारी कॉन्स्टीटूएंसी में पंचगंगा नदी के प्रदूषण का एक बहुत बड़ा मसला है । जल है तो कल है । मेरी कॉन्स्टीटूएंसी में जो पंचगंगा नदी है, वह आज जहर की नदी के नाम से जानी जा रही है । यहां जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करती है, उसमें उस नदी का नाम आ रहा है । जिस प्रकार से आपने नमामि गंगे मिशन के माध्यम से ड्राइव लिया, उसी प्रकार से नमामि पंचगंगा का ड्राइव लेना बहुत जरूरी है । इसके माध्यम से पंचगंगा नदी को पवित्र और शुद्ध बनाने के पहल किया जाए ।

महोदय, मेरी कॉन्स्टीटूएंसी में इचलकरंजी नामक एक शहर है । जब हमारे गांवों में पानी पहुंच रहा है और सरकार उसके लिए पैसा भी दे रही है । इस शहर में टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा हब है । वहां पानी ले जाने के लिए छोटे-छोटे गांवों का विरोध हो रहा है । उसकी वजह से पिछले 10 से 12 सालों से इस शहर में पानी की किल्लत हो रही है । हर एक शहर को स्वच्छ और शुद्ध पानी की जरुरत है ।

महोदय, मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर किसी स्टेट के ऐसे विषय हो, जहां पानी के लिए आपस में ही संघर्ष हो, उसके लिए कोई मार्ग निकालना चाहिए । केंद्र सरकार इसके लिए एक समिति गठित करे । अल्माटी डैम के बारे में भी एक समिति गठित की जाए ।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे: महोदय, मैं एक मिनट में ही अपनी बात खत्म कर रहा हूं । हालांकि मेरी पार्टी का अभी टाइम है ।

महोदय, वहां पानी मिल गया, लेकिन बिजली का बिल भरने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होता है । अगर वहां दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो छोटे-छोटे ग्राम पंचायतों में सही व्यवस्था नहीं होती है । अगर आप सोलर लाइट के माध्यम से पानी की

व्यवस्था कर पाएं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में स्वच्छ पानी मिलने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा । आज बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन एक दूसरी दिक्कत भी आ रही है ।

पानी का कनेक्शन देने के लिए पूरा गांव खोदना पड़ता है, फिर उसका रास्ता नहीं बनता है। रास्ता नहीं बनता तो जब हम सांसद गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पानी तो मिल गया, लेकिन हमारे गांव के रास्ते की हालत बुरी हो गई है । मैं आपसे गुहार लगाता हूं कि इस मंत्रालय और दूसरे मंत्रालय ग्रामीण विकास का कन्वर्जन करके, दोनों को मिलाकर एक व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें पानी भी मिले और गांव का रास्ता भी अच्छी तरह से बने, सड़क अच्छी बने, इसके लिए सरकार पहल करे ।

फ्लड मिटिगेशन प्रोग्राम के लिए 3,200 करोड़ रुपये देश के लिए दिए गए हैं । यह राशि बहुत कम है । हमारे यहां बहुत बाढ़ पीड़ित इलाका है, उसमें से बहुत कम राशि हमारे यहां आएगी । मैं सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि उसको बढ़ाकर पांच हजार करोड़ रुपये किया जाए, जिसके माध्यम से हमारे लोगों को सहायता मिलेगी ।

महोदय, आपने मुझे इस मौके पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं । जय हिंद, जय महाराष्ट्र ।

***m105 श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) :** सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं जब वर्ष 2019 में सांसद बनकर पहली बार आया, तब मेरे क्षेत्र में एक बड़ा जल संकट था । इतिहास गवाह है, मुगल काल की राजधानी फतेहपुर सीकरी रही है ।

16.16 hrs (Kumari Selja *in the Chair*)

अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी हुआ करती थी । वर्ष 1571 से लेकर वर्ष 1585 तक मुगल काल में अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी रही । इतिहास में है कि फतेहपुर सीकरी को अकबर ने क्यों छोड़ा? उसे इसलिए छोड़ा कि वहां पानी की कमी थी, खारा पानी था । अकबर मुगल काल में फतेहपुर सीकरी को छोड़कर चला गया, लेकिन पानी की समस्या का समाधान नहीं किया ।

मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि वर्ष 2019 में जब मैं सांसद बनकर आया, तब 15 अगस्त, 2019 को देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि जल-जीवन मिशन के अंतर्गत अब देश में पेयजल की समस्या का, पानी की

समस्या का ग्रामीण क्षेत्र में समाधान किया जाएगा । मैं भावुकता के साथ कह रहा हूं कि 440 वर्षों की समस्या का समाधान वर्ष 2019 में हुआ । फतेहपुर सीकरी लोक सभा क्षेत्र, आगरा जिला, मथुरा और फिरोजाबाद के लिए 4,000 करोड़ रुपये की योजना देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दी और आज हर घर नल से जल नहीं गंगा जल मिलने के लिए मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र में लगातार काम चल रहा है, मथुरा में भी काम चल रहा है, फिरोजाबाद में भी काम चल रहा है । इतना बड़ा काम देश के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है ।

हमारे यहां क्षेत्र के लोग पूछते थे कि इस समस्या का समाधान कब होगा? मैंने भी भागीरथ को देखा नहीं है, सुना है, पढ़ा है कि गंगा जी को लेकर आए । मेरे क्षेत्र की जनता, मथुरा और फिरोजाबाद की जनता कह रही है कि अगर भागीरथ कोई है, तो वह देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पानी की समस्या का समाधान करके दिखाया ।

जल-जीवन मिशन के अंतर्गत जब यह योजना आई, तब वर्ष 2019 से पहले केवल 3 करोड़ घरों में हर घर के लिए कनेक्शन्स थे । आज 15 करोड़ घरों के अंदर जल-जीवन मिशन के अंतर्गत कनेक्शन्स दिए गए हैं । आने वाले दिनों में सौ फीसदी घरों में कनेक्शन्स पहुंच जाएं, इसके लिए सरकार का अभियान तेजी से चल रहा है । इसका समय वर्ष 2028 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है । मैं देश के प्रधान मंत्री मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वर्ष 2028 तक पूरे देश के अंदर कोई घर ऐसा नहीं रहेगा, जिस घर में हर घर नल से जल नहीं पहुंचे ।

मैं अपने लोक सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी और आगरा जिले की एक गम्भीर समस्या को रखना चाहता हूं । मेरे यहां पांच नदियां है, यमुना है, चम्बल है, किवाड़ है, खारी नदी है और उटंगन नदी है । यमुना नदी में जल बहुत कम है । दिल्ली में केजरीवाल जी जब तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने यमुना की स्वच्छता के लिए कोई काम नहीं किया । हम लोगों को, हमारे किसानों को सिंचाई के लिए गंदा पानी मिलता है । सिंचाई करते-करते उनमें बीमारियां फैल रही हैं ।

दूषित पानी आता है, प्रदूषित पानी आता है, यमुना का पानी स्वच्छ हो जाए, स्वच्छ पानी होकर हमारे नहरों तक पहुंचे । उत्तराखंड में एक डैम बनाने की योजना है, उत्तराखंड में जब वह डैम बने तो आगरा कैनाल के लिए भी यमुना के द्वारा पानी दे दिया जाए, इससे आने वाले समय में हमारे क्षेत्र की सिंचाई की समस्या का समाधान हो जाएगा ।

मेरे यहां चम्बल नदी है । मेरे लोक सभा क्षेत्र में बटेश्वर एक पवित्र स्थान है, भगवान शिव का मंदिर है, यमुना जी वहां बहती हैं । श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री का पैतृक गांव हैं । उनके पैतृक गांव में वह स्थान पर्यटन नगरी के रूप में उभर रहा है । लेकिन चम्बल नदी में बैलेंस पानी नहीं है । राजस्थान के कोटा में बांध बना हुआ है, कोटा के डैम से चम्बल नदी में पानी छोड़ा जाता है । वर्ष 2023 में तीन लाख क्यूसेक जल छोड़ा, अगर डेढ़ लाख क्यूसेक जल छोड़ दिया जाए तो यमुना नदी में बाढ़ आ जाती है । मेरे यहां भी बाढ़ आती है, हर जुलाई-अगस्त के महीने में बाढ़ आती है । हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं ।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि कोटा से बैलेंस पानी छोड़ा जाए । मेरे यहां चम्बल में तीन हजार क्यूसेक पानी आता है । उसे पांच सौ क्यूसेक और बढ़ाया जाए, जिससे मेरे क्षेत्र की सिंचाई की समस्या का समाधान हो जाए । वहां से बैलेंस पानी आए । मेरे यहां उटंगन नदी है । उटंगन नदी राजस्थान से आती है । राजस्थान में भरतपुर के रूपस में पांचना बांध है, पांचना बांध से मेरे यहां नदी आती है, रिहावली में फतेहाबाद के अंतर्गत वह नदी पहुंचती है, वहीं यमुना जी लग जाती है । नदी का नाम है, लेकिन उसमें पानी नहीं है । यह हो सकता है कि राजस्थान से हमें पानी न मिल रहा हो, जो हमारा अधिकार है ।

मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से भी अपील करता हूं । केन्द्र सरकार से भी मांग करता हूं उटंगन नदी में पांचना बांध से हमारा जल दे दिया जाए । जिससे आगरा क्षेत्र के किसानों को भी लाभ होगा, जल स्तर भी ऊपर आए और रिहावली तक वह पानी पहुंचे । रिहावली में एक बांध बना दिया जाए, अगर रिहावली में एक बांध बनेगा तो मेरे क्षेत्र का जल स्तर ऊंचा हो जाएगा ।

माननीय सभापति महोदया, हमारे यहां किवाड़ नदी है, वह बरसाती नदी है । मेरे यहां जगनेर क्षेत्र है, खेड़ागढ़ है, वहां छोटी बंधियां हैं, किसान मजबूर हैं, लेकिन सिंचाई नहीं हो नहीं पाती, उसको भी किसी नदी से जोड़ा जाए । मेरे यहां खारी नदी है, यह भी बरसाती नदी कहलाती है । खारी नदी से सैंकड़ों गांव के किसान खारी नदी से सिंचाई करते हैं । उसमें भी पानी नहीं है । खारी नदी को भी किसी अन्य नदी से जोड़ा जाए, जिससे खारी नदी में भी पानी आ जाए । यमुना, चम्बल, किवाड़, खारी और उटंगन नदी है । उटंगन नदी पर हमारे यहां एक बांध बन जाए, खारी नदी में और पानी आ जाए, लगातार पानी रहे । यमुना का जो गंदा पानी जा रहा है, दिल्ली में यमुना में नाले गिरते हैं, वे नाले बंद हो जाएं । मुझे उम्मीद है, सरकार बदली है, सरकार का मूड बदला है, यमुना स्वच्छ होगी और हमारे आगरा में स्वच्छ जल मिलेगा ।

मेरे यहां करीब 70 गांव हैं जो फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में आते हैं जो राजस्थान की सीमा से लगे हुए हैं । उन गांवों में जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि वहां सिंचाई के लिए ट्यूबवेल नहीं लगा सकते हैं । सिंचाई का कोई और माध्यम नहीं है । एक ही तरीका है, किसी न किसी नदी का पानी दिया जाए या नई नहर बनायी जाए । मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत मेरे यहां एक नहर की व्यवस्था की जाए । यह वह स्थान है, जहां खानवा का मैदान है, जहां राणा संगा और बाबर का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था । मेरे क्षेत्र के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं । माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम किया है, जल जीवन मिशन से हमें गंगा जल मिल रहा है । सिंचाई की समस्या है, जल स्तर को ऊंचा उठाने की है, यह पूरा हो जाए । जब यमुना और चम्बल नदी में पानी रहेगा तो जल मार्ग के द्वारा भी लोग आ-जा सकेंगे । इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, हमारे यहां ताजमहल से लेकर बटेश्वर तक जल मार्ग भी बन सकेगा, उसमें मथुरा भी जुड़ेगा, दिल्ली भी उसमें जुड़ेगा और एक जल मार्ग की व्यवस्था हो जाएगी । बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार ।

***m106 डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) :** माननीय सभापति महोदया, जल ही जीवन है, इसका महत्व हम सभी जानते हैं । लेकिन मौजूदा सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा है । बजटरी एलोकेशन 99.543 करोड़ रुपये है जो बजट का सिर्फ 0.28 परसेंट है जो मेरी समझ से नकाफी है । पानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है । यह बार-बार कई दशकों से कहा जा रहा है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार होगी तो पानी के लिए होगी ।

मैडम, नीति आयोग की एक रिपोर्ट है about water quality index. The report states that nearly 70 per cent of the water is contaminated. इस इंडेक्स में 122 कंट्रीज हैं । उसमें हमारा 120वां नम्बर है । इसका मतलब हमारा पानी इतना खराब है कि हमसे खराब पानी वाले सिर्फ दो मुल्क हैं । इसके बावजूद सरकार इस पर निगाह-ए- करम नहीं कर रही है, जो सबको इफेक्ट कर रहा है । शहरों में लोगों को पानी नहीं मिल रही है । दिल्ली जैसे शहर में एमपीज के घर में पानी नहीं मिल रही है । सिंचाई तो दूर पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है ।

?प्यासे लबों पर पानी का अफसाना रह गया,

नदियां तो थीं, पर रेत का खजाना रह गया ।?

मोदी सरकार ने यह हालत कर दी है ।

मैडम, अगर हम ?जल जीवन मिशन? की बात करें तो the pipes are without water और कहीं नल है तो जल नहीं है । उसकी वजह से रोड का अलग नुकसान हुआ है । ?नमामि गंगे? 20 हजार करोड़ रुपये की स्कीम है । It is only on paper. It is only in advertisements. But the reality is totally different.

Now, I come to the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana. Despite these promises, and despite the irrigation programme, which is on paper, किसान बारिश का इंतजार करते हैं । फ्लड मैनेजमेंट जो बहुत ही क्रुशियल है, अभी हमारे एक सदस्य ने बताया है कि अभी हिमाचल में 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो गया, बिहार में तो हर साल 10 से 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है । उसी तरह से असम में भी होता है । फंड की कमी और ईमानदारी की कमी की वजह से यह सब हम लोगों को झेलना पड़ रहा है ।

मैडम, ?स्वच्छ भारत मिशन? के तहत वर्ष 2014 में शुरू हुआ था कि ?ODF Elimination by 2019?, यह प्रधानमंत्री जी का वादा था । लेकिन, आज जनवरी, 2025 के बाद अभी उसका प्रोग्रेस यह है कि साढ़े छः लाख गाँवों में से ढाई लाख गाँव अभी भी ऐसे हैं, जो ओडीएफ नहीं हो पाए हैं ।

Now, I come to pollution of Ganga. The PAC has noted that still 415 industries situated on the banks of Ganga do not meet the pollution norms. The installed sewage treatment capacity is only 52 per cent, जिसमें से आधे काम नहीं करते हैं । According to Central Pollution Control Board, over 60 per cent of the Ganga?s total length is not even fit for bathing.

The PAC also highlighted that most of the funds, which are allocated, have been spent on *Prachar* or *Prasar*. मोदी जी दिखते हैं, लेकिन नदियां साफ नहीं हो पा रही हैं । यह अफसोस की बात है ।

मैडम, अब मैं आपका ध्यान बिहार की तरफ ले जाना चाहता हूं । वहां तीन प्रॉब्लम्स हैं, groundwater contamination, flood-prone problems and soil erosion, and population density. इसकी वजह से जल शक्ति मंत्रालय ने डिफाइन किया है कि 100 मीटर दूर तक आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं । यह बिहार के लिए बहुत घातक है । मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरी कांस्टिट्यूएंसी किशनगंज और पूर्णिया में जितने नदी-नालें हैं, उतने माननीय मंत्री जी के स्टेट में नहीं हैं । उनको री-लुक करने की जरूरत है । मैं जो कंटेमिनेशन की बात कर रहा था, 31 डिस्ट्रिक्टस में 30 हजार रूरल वॉर्ड्स में कंटेमिनिटेड वाटर है ।

वाटर में फ्लोराइड है, एक्सेसिव ऑयरन है, यहां तक कि उसमें यूरेनियम भी है । उसकी वजह से बच्चे तक को कैंसर हो रहा है । जो इंफैंट्स हैं, उनको कैंसर हो रहा है । रीनल और किडनी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं । इसमें मेरा सुझाव है कि there should be a comprehensive water quality audit and there should be established water treatment facilities. खासकर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और सीमांचल में होना चाहिए । The Mahananda Basin Project should start immediately और लोगों के मशविरे से होना चाहिए । यह नहीं कि फ्लो यहां है और आधा किलोमीटर दूर तक आप लोगों का घर उजाड़ दें ।

Enforce stringent pollution control measures, promote substantial agricultural practices, and enhance water management system; Bihar Water Quality Monitoring Authority should be formed. Rain water harvesting and groundwater recharge project should be aggressively implemented and made compulsory.

महोदया, मुझे आपको बताते हुए अफसोस हो रहा है, मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूं । एक एकड़ में प्रति वर्ष 20 टन टॉपसाइल का नुकसान होता है । जो आंकड़ा है, हमारे यहां हर साल 18 लाख एकड़ खेतिहर जमीन डीग्रेड होती है, जिसमें से बाढ़ के पानी से आठ लाख एकड़ जमीन बर्बाद होती है । इसका नतीजा क्या है? Loss of habitable and landmass, soil degradation, decrease in agricultural productivity, loss of biodiversity, land dispute due to change of river coarse, soil erosion, खासकर नॉर्थ इंडिया, बिहार और सीमाचंल के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए मेरा सुझाव है कि वहां सीमांचल फ्लड टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है । वहां वॉटर क्राइसेज़ हेल्प लाइन बनाने की जरूरत है, ताकि जहां कहीं भी इस तरह की तकलीफें हैं, लोग उनकी मदद ले सकें ।

महोदया, हमारे यहां यानी नॉर्थ बिहार के 38 में से 28 राज्य बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहते हैं, जिसकी आबादी 76 प्रतिशत है । उसकी संख्या लगभग 11 करोड़ है । अगर उसको एरियावाइज देखा जाए, तो हिन्दुस्तान में प्रति किलोमीटर 428 लोग बसते हैं । जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, जहां पर कई नदियां और रिवर बेड्स हैं, वहां प्रति किलोमीटर 1,200 लोग रहते हैं । हम लोगों को यह देखना है कि हम किस तरह से इस समस्या को सुलझा सकते हैं ।

महोदया, एनएमसीजी और जल शक्ति मंत्रालय का निर्देश है कि जो नदियां हैं, उनसे 100 मीटर दूर तक कोई विकास नहीं होना चाहिए । बिहार के 11 करोड़ लोग हैं, वहां एक वर्ग किलोमीटर में 1,100-1,200 लोग रहते हैं, क्या वहां यह संभव है? यह देखते हुए बिहार

सरकार ने बार-बार चिट्ठी लिखी है । वर्ष 2022 में बिहार बिल्डिंग बायलॉज बनाए गए थे । Buffer strip of 25 meters has to be maintained from the outer boundary of the Ganges and 30 metres from other rivers.

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको स्वीकार करें । किशनगंज में कांग्रेस की सरकार के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक एएमयू का तोहफा दिया था । चूंकि वहां एजुकेशनल संस्थान की किल्लत है, बहुत ज्यादा परेशानी है, लेकिन इसकी वजह से वहां पर रोक लग गई है । वहां पर एनजीटी द्वारा यह बताया गया कि आप टेक्निकल टीम से इसका सर्वे करा लें । टेक्निकल टीम ने सर्वे भी किया और उसमें यह पाया गया कि this land neither falls on the floodplain or on the river bed. उसके बावजूद भी वह इनजंग्शन नहीं हट पाया । मेरी आपसे गुजारिश है कि उसको तत्काल हटाने की जरूरत है ।

महोदया, किशनगंज में रमज़ान नदी है । मैंने इसके बारे में यहां पर कई मर्तबा अपनी बात रखी है, लेकिन ब्यूटिफिकेशन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लान सिर्फ कागजों में ही है । यह कहते हैं कि वह दिया गया है, लेकिन आज तक नहीं मिला है । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि बिहार की गंभीरता को देखते हुए, बिहार की गुर्बत को देखते हुए और बिहार की परेशानियों को देखते हुए इन सुझावों पर गौर करना होगा तथा उन पर अमल करना होगा ।

***m107 श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) :** सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने आज जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं अपनी लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास), खगड़िया लोक सभा की जनता, अपने नेता चिराग पासवान की तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं । इसके साथ ही साथ मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जल शक्ति मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री सी. आर. पटिल जी का भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं । इस मंत्रालय को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 53 प्रतिशत ज्यादा राशि का आवंटन किया गया है, जो बढ़कर लगभग 99,503 करोड रुपये हो गई है । मैं इसके लिए मंत्रालय और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं । इस राशि से सरकार हर घर जल का नल और हर खेत में सिंचाई के पानी को सुनिश्चित करने का काम कर रही है । जिस तरीके से सरकार ने ?नमामि गंगे मिशन? के तहत लगभग 3,400 करोड़ रुपये, ?अटल भूजल योजना? के तहत लगभग 2,435 करोड रुपये, ?प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? के तहत लगभग 8,259 करोड रुपये, ?जल जीवन मिशन? के तहत 67,000

करोड़ रुपये और साथ ही साथ ?स्वच्छ भारत मिशन? के लिए 7,192 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं । मैं इसके लिए उनको कोटि-कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं ।

सभापति महोदया, जहां एक तरफ यह मंत्रालय आम लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस देश में जो सनातनी सोच और सनातनी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो नदियों के जल, नदियों के पानी को भी आस्था की तरह देखते हैं, इस मंत्रालय ने नदियों को स्वच्छ करने का काम किया है । एक बड़ी आबादी महाकुंभ में अपने आप को डुबकी लगाकर पवित्र महसूस कर रही है । उसके लिए बड़ा योगदान मंत्रालय की ओर से हुआ है । मैं इसके लिए मंत्रालय को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं । बिहार में 38 में से 19 जिले ऐसे हैं, जो बारिश की कमी से प्रभावित होते हैं । वर्ष 2024 में बाढ़ से लगभग 11 लाख की आबादी प्रभावित हुई है । हम लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए यह बड़ी विडंबना है कि एक तरफ हम लोग बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम लोग सुखाड़ की भी मार को झेलते हैं । इस मंत्रालय को लेकर मैं अपनी खगड़िया लोक सभा क्षेत्र की तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय मेरी खगड़िया लोक सभा क्षेत्र में गोगरी प्रखंड के पैकांत पंचायत के बीरबास और उसके साथ ही साथ गोगरी प्रखंड के सर्किल नंबर एक के बलातारा पंचायत के बड़ी फुलवरिया और लौंगा में कोसी नदी से कटाव की भयावह स्थिति है । उसी तरीके से अलौली प्रखंड के चेरा-खेड़ा पंचायत, उत्तरी बोहरवा, हरदिया और बलुआई में भी भीषण कटाव की स्थिति है । खगड़िया प्रखंड के रहीमपुर दक्षिणी पंचायत के मथार दियारा और सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के घोघसम में कोसी नदी से भयावह स्थिति है ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपये और केंद्र सरकार भी एनडीआरएफ के माध्यम से लगभग 1000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष राहत के लिए बिहार को देने का काम करती है, वहीं जिस तरीके से कटाव और बाढ़ की आपदा है, उसके स्थायी समाधान के लिए किस तरीके से बोल्डर पिचिंग का काम मेरी लोक सभा और बिहार के उन तमाम जिलों में होना है । वहां पर बाढ़ के कारण भारी त्रासदी होती है । मैं उस ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

महोदया, साथ ही साथ मैं एक बड़ी समस्या, जो हमारी लोक सभा और बिहार के कई जिलों में है कि पानी में आर्सेनिक की मात्रा देखी जा रही है । आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने के कारण कैंसर के बहुत ज्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस ओर भी आपका ध्यान जाए और बिहार की बड़ी आबादी की इस समस्या के

स्थायी समाधान के लिए मैं चाहूंगा कि नेपाल के सहयोग से बड़े बांधों का जो निर्माण है, उसे सुनिश्चित कराया जाए ताकि सप्तकोसी हाई डैम और बागमती डैम जैसे प्रोजेक्ट का निर्माण हो सके । इससे न केवल बाढ़ का खतरा कम होगा, बल्कि जल संरक्षण और सिंचाई की सुविधा भी बढ़ेगी । इसके साथ ही साथ बिहार की नदियों का बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम एफएमपी में शामिल करने की मैं मांग करता हूं । केंद्र सरकार से चाहता हूं कि गंडक, कोसी और कमला जैसी नदियों को बाढ़ नियंत्रण जैसे कार्यक्रम में जरूर शामिल किया जाए । बिहार को बाढ़ मुक्त करने के लिए बिहार फ्लड मिटीगेशन प्रोग्राम में भी शामिल करने की मंजूरी देने का काम माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं ।

महोदया, अंत में बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग प्रत्येक वर्ष देखते हैं कि अपनी लोक सभा में लोग किस तरह कतरा-कतरा जोड़ कर अपना आशियाना बनाते हैं और एक झटके में उनका आशियाना खुले आसमान में तब्दील हो जाता है । किस तरीके से एक बड़ी आबादी सड़कों पर छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ बिलखते देखते हैं । यह परिस्थिति बहुत पीड़ा देती है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि सिर्फ राहत से नहीं, बल्कि स्थायी समाधान की जरूरत है। मैं आपसे एक बार गुजारिश भी करूंगा कि एक बार आप मेरी लोक सभा क्षेत्र, जो सबसे पिछड़ी लोक सभा बिहार की है, वहां आप जरूर आएं और वहां की स्थिति देखें । सही मायने में यदि गरीबी और बाढ़ से विचलित होने वाले दृश्य को यदि आपने देखना है और उनकी पीड़ा को महसूस करना है, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर आएं और उनकी पीड़ा में अपना सहयोग करें । मैं केंद्र सरकार से इसलिए मांग करता हूं क्योंकि केंद्र सरकार ने इस बार मेरी लोक सभा और बिहार को बहुत साकारात्मक दृष्टि के साथ योजनाएं दी हैं । जब आप बहुत योजनाएं देते हैं, तो आपकी तरफ उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ती हैं, इसलिए मैं अपनी खगड़िया लोक सभा की तरफ से बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से आपकी तरफ देखते हुए उम्मीद करता हूं कि आप खगड़िया लोक सभा को बाढ़ से और कटाव से मुक्ति दिलाएंगे । यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : महोदया, मैं जल शक्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांग के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मंत्रालय का नाम जल शक्ति मंत्रालय है और इसमें बहुत तरह के विभागों को रखा गया है । जल जीवन मिशन और हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि जल ही जीवन है और आपने इसे मिशन का नाम दिया है । सरकार किस मिशन के तहत काम कर रही है कि पिछली बार 70 हजार करोड़ रुपये जल जीवन मिशन के तहत आबंटन था, जिसमें 50 हजार करोड़ रुपये बचे रह गए थे । क्या जल जीवन का यह मिशन है

कि पैसा बचाओ, खर्च ही न करो? यह बहुत दुर्भाग्य है और मैं माननीय मंत्री श्री सी.आर. पाटिल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम बिहार से आते हैं । वर्ष 2023-24 में, अभी हमारे बिहार के साथी राजेश जी बोल रहे थे, जल जीवन मिशन के तहत बिहार को मात्र 55 करोड़ रुपये की शुरूआती राशि मिली थी और ताज्जुब की बात यह है कि आज तीन साल से यह डबल इंजन की सरकार बिहार में उस 55 करोड़ रुपये को भी खर्च नहीं कर पाई ।

यह किस तरह का जल जीवन मिशन है? यह दुर्भाग्य है । हम औरंगाबाद जिले से आते हैं । औरंगाबाद और गया निश्चित तौर पर सुखाड़ क्षेत्रों में गिने जाते हैं । दक्षिण बिहार में हम लोग आते हैं । वहां पर गर्मी के दिनों में पेयजल की बहुत ही गंभीर समस्या होती है । हमारा वाटर लेवल कहीं-कहीं पर ढाई सौ फीट और कहीं-कहीं पर 500 फीट से भी नीचे चला जाता है । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो । ? (व्यवधान)

माननीय मंत्री जी, जल शक्ति मंत्रालय आपके पास है । मैंने अभी कहा कि औरंगाबाद में ढाई सौ और पांच सौ फीट नीचे वाटर लेवल चला गया है, हम यही आग्रह करेंगे । हमने एक प्रश्न भी किया था, जिसका जवाब पदाधिकारी ने भेजा कि जितनी भी जगह नल लगे हैं, वे लगभग 98 परसेंट चालू हैं । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि एक केंद्रीय टीम गठित कर लें और केंद्रीय टीम को बिहार में भेजकर नल-जल योजना की जो स्थिति है, उससे रूबरू हो लें । कहीं पर 6-6 महीनों से मोटर जली हुई है । उसकी वजह से पंप बंद है । कहीं पर पाइप लाइन टूटी हुई है, जिसकी वजह से पंप बंद है । यह स्थिति है । नल-जल योजना जितने भी वार्डों में है, तकरीबन 50 परसेंट वार्डों में लोग पानी नहीं पी पा रहे हैं । गर्मी का मौसम आने वाला है, इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे यहां बहुत त्रासदी होगी । अत: मेरी आपसे मांग होगी कि जो इतने सारे पैसे बचे रह जाते हैं, हम 543 सांसद हैं, एक लोक सभा में कम से कम 6 विधान सभाएं पड़ती हैं, कम से कम इस गर्मी के मौसम में हर-एक विधान सभा में 50-50 डी.टी. चापाकल ही दे दीजिए, ताकि पैसे का भी उपयोग हो जाए ।

महोदया, हमारी उत्तर कोयल परियोजना बहुत प्रमुख है । इसका कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है । हमारी मुख्य शखा में 211 RD पर CR गेट का निर्माण चल रहा था । पिछले चार-पांच महीनों से यह बंद पड़ी है । हमने जब जानकारी हासिल की, तो उन लोगों का कहना है कि हमने जो काम किया है, उसका पैसा ही नहीं मिला है, इसलिए काम बंद है । चूंकि उत्तर कोयल परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत: माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस परियोजना में विलंब न हो, इसका आप ख्याल रखें और इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए । उत्तर कोयल नहर की चेईं नवादा कैनाल, कोटवारा कैनाल एवं अंगरा कैनाल की

सफाई करना बहुत जरूरी है । मात्र सफाई के कारण नीचे तक पानी नहीं पहुंच पाता है । इन तमाम चीजों की सफाई करा देंगे, तो नीचे तक पानी पहुंच जाएगा ।

महोदया, उत्तर कोयल नहर से ही सब डिस्ट्रीब्यूट्री सोन्डी-2 का कार्य कई वर्षों से बंद पड़ा है । इस काम को जब चालू नहीं करेंगे, तो यह जल शक्ति मंत्रालय किस बात का है? अत: मेरा आग्रह है कि सारे किनारों पर जो काम शेष पड़े हुए हैं, उन्हें चालू किया जाए । हड़ही-सरबहना सिंचाई परियोजना, बटाने नहर सिंचाई परियोजना और बटाने डैम बनकर कई वर्षों से तैयार है । उसकी नहर की शाखा नहीं बनाई गई है । कई सौ करोड़ रुपये लगाकर डैम बना है और वह वैसे ही पड़ा हुआ है । अगर शाखा बन जाएगी, तो लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा । लव दसईन पैइन की योजना भी कई वर्षों से लंबित पड़ी हुई है । बिहार के माननीय मुख्य मंत्री जी वर्ष 2016 में वहां गए थे और घोषणा की थी, लेकिन वह भी अभी लंबित पड़ी हुई है । बांके बाजार प्रखंड अंतर्गत बिहरगांईं पंचायत के ग्राम चौगाईं, टोला में अगर डैम का निर्माण हो जाएगा, तो वहां पर सिंचाई, जल संरक्षण व सुखाड़ इलाके को बहुत बड़ी राहत मिलेगी ।

सभापति महोदया, मैं एक-दो विषय रखकर अपनी बात को विराम दूंगा । औरंगाबाद नगर परिषद से रोजाना लाखों लीटर गंदा पानी नाले से होकर आता है । वहां अदरी नदी पड़ती है, जो औरंगाबाद शहर के बीच से गुजरती है । यह नदी इतनी दूषित हो चुकी है कि वहां पर आना-जाना नामुमकिन हो गया है । वह नदी बीच शहर में पड़ती है । आपके यहां पर स्वच्छता का भी विभाग है । हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि वहां नाले पर एक रिफाइन सीवरेज प्लांट लगा देंगे तो आपका स्वच्छता का जो मिशन है, वह भी पूरा हो जाएगा ।

सभापति महोदया, मदनपुर प्रखंड के दधपी गांव के पास केशहर नदी पर बांध की हालत कई वर्षों से खराब है । हमने उसके लिए पहले भी बोला है । अगर आप उस बांध की मरम्मत करवा देंगे तो वहां पर ऑटोमेटिक सिंचाई होने लगेगी । सिंचाई के लिए बंद पड़े सरकारी ट्यूबवेल्स को अविलंब चालू करवाया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर और ट्यूबवेल्स की व्यवस्था करवाई जाए । अदरी नदी, बरही नदी, रामरेखा नदी, सतनदी, इन तमाम नदियों में जो गाद भरी हुई है, उनकी सफाई करवाई जाए ।

सभापति महोदया, माननीय पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था । मैंने पहले भी कहा था कि नदियों को जोड़ने का जो उनका सपना था, कम से कम उनके सपने को तो इस जल शक्ति मंत्रालय को पूरा करना चाहिए । आप एक-दूसरी नदियों को जोड़ दीजिए । हमारे यहां पर सोन नदी और फल्गु नदी है । फल्गु नदी गया में है । वह मोक्ष

और ज्ञान की भूमि है । वहां पर देश के हर एक राज्य से मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग आते हैं, लेकिन वहां पर पानी नहीं है । फल्गु नदी सोन से तकरीबन 23 मीटर नीचे है । अगर आप सोन नहर का पानी फल्गु नदी में मिला दें तो सूखे से भी राहत मिलेगी और सिंचाई भी होगी ।

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Madam, today we are discussing the vital subject that is Jal Shakti. If you conduct a critical analysis, you will be convinced of a fact. What do the authorities, authentic reports and forecasts reveal? They reveal that India is going to face terrible water scarcity and crisis in the coming years. You may even foresee an explosive situation in this regard. What exactly are the reasons? There are many reasons like depleting groundwater, erratic rainfall, climate change, river pollution, urban water stress in the major cities, inefficient water management and destruction and vanishing of traditional water sources.

Madam, I am not blaming any Government. Whether it is the State Government or the Central Government, one fact remains unchanged, and that is that things do not move fast. This should be taken very seriously.

Take for example, Jal Jeevan Mission in the State of Kerala. I will speak about that only. We are trying to make a milestone in the history of its kind. The target is to reach each household and provide drinking water. The target is to complete it by 2028. Now extension has been given for four years.

What is the present position in Kerala? Kerala is currently at the lowest bottom in India as far as this scheme is concerned. Both the Governments whether it is the State Government or the Central Government are responsible for that. Now, our goal is extended to 2028.

Even within this time, there is no guarantee that things will be all right. We may still lag behind. During this period, there may be different kinds of discussions, like who will do this or who will do that.

For example, in the second phase itself, guidelines from the Central Government have not been given to the Kerala Government. That kind of disputes are continuing there.

Similarly, the State Government now shows helplessness. They are saying that there is no direction from the Government of India. Work is ready to tender, but the tender process is not taking place. They are saying this and improper approach is taken by the Government. Now, there is a terrible financial crisis. The Central Government is not giving their share, and the State Government is also in crisis; they are not providing the State Government?s share either. Those who are entrusted with the work of the JJM are now in a very worried state. They are not doing anything, saying that there is no money and that we are not getting the bill passed. In that way, a kind of controversy is also going on. If we are really honest, funds can be allotted. This kind of issue will have to be eradicated; only then will we be able to attain our goal.

Another thing which I would like to inform you is about road cutting, which is very necessary for the pipeline. There is time constraint, and I do not want to say much about that. Many representations from the State Government are pending, and that is not moving. Not only that, the roads opened for this kind of work are remaining as they are. Restoration is not taking place. The dispute is about who will do it and which department should handle it. The Panchayat?s President and authorities are running from pillar to post. They are not getting money for that. That kind of controversy is continuing. The local bodies are totally complaining about this, and it seems to be a very serious situation in this case.

Madam, we have to think about what exactly we can do. It is a very serious concern. Considering this, war footing level activities should be done. As I mentioned in the beginning, it is a lifeline. Stronger regulation on groundwater use and saving our lakes and rivers is also important. That is also very good. We have written poetry and stories about the river, its beauty, and cleanliness. All the rivers are polluted. That is to be taken as a very serious issue. We have to regain the glory of our lakes and rivers. A regulatory mechanism is necessary for groundwater usage,

as I mentioned earlier. That is also an important issue. These issues will have to be addressed: fund constraints, infrastructure challenges, coordination problems, and bureaucratic and administrative hurdles. All these things will have to be removed. Only then will we be able to attain our goal.

Coming to other matters, a public awareness campaign on how to control water wastage should also be encouraged. We must learn lessons from past experiences. We have had enough schemes: Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), *Har Ghar Jal*, Per Drop More Crop, Watershed Management, Amrut, River Basin Management Programme, R&D, and similar initiatives. As far as R&D is concerned, it is a very important subject with regard to Kerala. I humbly suggest that we must have a national institute for this. There are some institutes. My learned friend, Shri M. K. Raghavan, is sitting behind me. In his constituency, there is CWRDM, which is doing wonderful work. I suggest that we must have a very large institution to tackle R&D matters. Worldwide, such initiatives are ongoing.

Madam, I do not want to take much of your time, but one thing I would like to say is that if we ignore this, the entire mankind, not only mankind but the entire setup of the country, will face serious consequences. We must find ways to save our State from these difficulties. I humbly submit that the Government should take this very seriously and find solutions for it. Thank you very much.

श्री अमरा राम (सीकर) : माननीय सभापति महोदया, आज जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है । पानी एक ऐसी चीज है, जो मनुष्य, खेती, पेड़-पौधों, हर जीवन के लिए आवश्यक है । हमारे देश के 75 सालों की आजादी के बाद भी आज आधा देश बाढ़ से डूबता है और आधा देश अकाल से जूझता है ।

17.00 hrs

महोदया, सरकार ने बहुत बड़ी योजनाओं के नाम घोषित किए हैं । दस सालों के अंदर हम कितना आगे बढ़े हैं, इसका उत्तर जलशक्ति मंत्री जी देंगे और कहेंगे कि पैसे का इंतजाम नहीं है । दस सालों में इस सरकार ने बड़ी-बड़ी कंपनियों के 16 लाख 39 हजार करोड़ रुपये बट्टेखाते लिखे हैं जबकि इससे बाढ़, अकाल, पेयजल की कमी और रोजगार जैसी तमाम

समस्याओं का समाधान हो सकता था । सरकार बड़ी-बड़ी कंपनियों के प्रति तो चिंतित है लेकिन इस देश की प्यासी जनता के लिए चिंतित नहीं है ।

महोदया, जहां तक राजस्थान का सवाल है, इंदिरा गांधी नहर से पेयजल की व्यवस्था होती है । राजस्थान के लोगों को इस केनाल से प्रदूषित पानी गर्मियों में पीने के लिए मिलता है और इस कारण लोगों को आज भी कई असाध्य बीमारियां हो रही हैं । राजस्थान केनाल से ही नहीं, बल्कि 70 प्रतिशत अंडरग्राउंड पानी से लोगों की प्यास बुझाई जाती है । इसके कारण 80 प्रतिशत जगहों पर अंडरग्राउंड पानी समाप्त हो चुका है । राजस्थान में 70 प्रतिशत आबादी को बहुत-सी बीमारियां फ्लोराइड युक्त पानी पीने से झेलनी पड़ रही हैं ।

महोदया, राजस्थान में सबसे ज्यादा समस्या पीने के पानी की है, आप सिंचाई की बात तो छोड़ दीजिए । पीने के पानी के लिए सबसे बड़ी ?जल जीवन मिशन? योजना लाई गई है । राजस्थान ही नहीं देश के हर ग्रामीण क्षेत्र के लिए हर घर में नल से जल देने की योजना लाई गई है । मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि 75 साल की आजादी के बाद गांवों को नल से पानी देने की योजना लेकर आई है । आज भी बड़े शहरों में 30 मंजिल तक पानी नल से पहुंचता है लेकिन गांवों में देश की 80 प्रतिशत आबादी रहती है, क्या वहां नल से जल पहुंचा है? राजस्थान तो सबसे बड़ा समस्या ग्रस्त राज्य है और इसकी प्रगति का स्थान सबसे नीचे है ।

महोदया, चार हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और हर घर में नल से जल देने की बात कही गई है । राजस्थान के गांवों में ?जल जीवन मिशन? योजना लागू की गई है लेकिन एक प्रतिशत भी ऐसे गांव नहीं हैं जहां नल पहुंचाने का काम किया गया हो । नल पहुंच गए हैं तो जल नहीं पहुंचा, इनमें केवल हवा आती है । लोगों के आने-जाने वाली सड़कों को नष्ट करने का काम किया गया है । जहां ड्राई हो गया, वहां ट्यूबवैल नहीं खोद सकते, वहां कनैक्शन्स काटे जा रहे हैं । गर्मी शुरू हो रही है और एक-एक विधान सभा क्षेत्र में दर्जनों ट्यूबवैलों के कनैक्शन्स इस बात के लिए काट दिए गए क्योंकि ?जल जीवन मिशन? के तहत आज तक बिजली बोर्ड को पेमेंट नहीं दी गई । सीकर और झुन्झुनू के लिए ?जल जीवन मिशन? के तहत कुछ गांव बचे हैं । गांवों में तो जल जीवन मिशन योजना लागू कर दी गई है, मेरा जलशक्ति मंत्री जी से निवेदन है कि जिन घरों को छोड़ दिया गया है, उनको इसमें शामिल किया जाए । सीकर और झुन्झुनू में 7900 करोड़ रुपये ?जल जीवन मिशन? के तहत पेयजल देने के लिए स्वीकृत किए गए हैं । माननीय मंत्री जी बताएं कि यह योजना कब शुरू होगी और कब लोगों को पानी मिलेगा? शेखावाटी में सबसे बड़ी समस्या पानी की है ।

महोदया, चोमू विधान सभा क्षेत्र है । बिसलपुर डैम की योजना बनी, अब ईआरसीपी स्कीम बन रही है । जयपुर में चोमू को छोड़कर तमाम क्षेत्र इसमें आ गए हैं । मेरा निवेदन है कि चोमू को बिसलपुर योजना में शामिल किया जाए और लोगों को पानी दिया जाए । सीकर में पानी की स्थिति ऐसी है कि शहरों का पानी, नाली और सीवरेज का पानी आसपास के हाईवे और लोगों तक जाता है । अगर हम स्वच्छता की बात करें, ओडीएफ की बात करें, 335 करोड़ रुपये की योजना बनकर आ गई ।

उससे न केवल गांव नष्ट हो रहे हैं, बल्कि नेशनल हाइवे पर भी तीन-तीन फुट पानी भरता है । आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस जल जीवन मिशन में निश्चित रूप से लोगों को पानी मिले । पैसे की कमी नहीं है । नीयत और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है । वर्षा का जो तमाम पानी है, अगर उसको टेप करके लाया जाए, तो आज भी 87 प्रतिशत जमीन पर सिंचाई हो सकती है । सब को पीने का शुद्ध पानी मिल सकता है । लेकिन न शुद्ध पानी है, न पानी है तथा केवल और केवल घोषणाएं हैं । आप निश्चित रूप से योजना को धरती पर उतारिये । आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

जय हिंद, जय भारत ।

SHRI Y. S. AVINASH REDDY (KADAPA): Madam, Polavaram is a multi-purpose irrigation project envisaged to irrigate lakhs of acres in Godavari district and parts of Uttar Andhra. This project diverts 80 tmc of water to the Krishna River Basin to meet the needs of the people living in Krishna Delta region, and this saving in the Krishna Basin will be utilized for Rayalaseema project from Srisailam Dam. This project provides 24 tmc of water for drinking and industrial needs of Vizag City. All the above benefits can be achieved only if the Polavaram project is constructed as per its original design of 45.72 metres height and 194 tmc of storage capacity.

Recently, the Government of India, with the consent of the present Government of Andhra Pradesh has reduced the project height to 41.15 metres and reduced the storage capacity from 194 tmc to 115 tmc only. The total project cost is reduced to Rs. 30,000 crore from the previously approved amount of Rs. 59,000 crore, which is a loss of grant for Andhra Pradesh to the tune of Rs. 29,000 crore. We strongly oppose this decision, and we urge the Government to construct the project as per its original design of 45.72 metres height and 194 tmc storage

capacity, without which all the objectives of the Polavaram project cannot be achieved. We also request for a quick disbursement of R&R package to all the families displaced and affected by the project. The budget allocation for the project this year 2025-26 is Rs. 5,936 crore. We request the Government to enhance the allocation for the speedy completion of the project.

Around five days ago, the EC was rejected by the Government of India for the Rayalaseema Lift Irrigation project due to gross negligence and lack of persuasion by the present Government of Andhra Pradesh. Apart from allocation to Nagarjuna Sagar and Krishna Delta, there is an allocation of 19 tmc for SRBC, 29 tmc for Telu Ganga, 38 tmc for GNSS, and 15 tmc from Srisailam Dam for drinking water purposes of Chennai. For the above projects from Pothireddypadu head regulator, 7,000 cusecs of water can be drawn when the water level is 854 ft., whereas 44,000 cusecs can be drawn at 880 ft. level during flood days. Madam, our neighbouring State, which is on the left side of Srisailam Dam, is generating power at 798 ft. level. And it has also constructed two lift irrigation projects, Palamuru Rangareddy project and Dindi List Irrigation Scheme, under which 22,000 cusecs of water is being pumped every day at 800 ft. level. Please think, if power is generated at 798 ft. level and if 22,000 cusecs is pumped every day by our neighbouring State at 800 ft. level, when will the water reach 880 level and how will the Greater Rayalaseema project get its share of water? To overcome the above problem, the foundation was laid for the Rayalaseema Lift Irrigation project in the year 2020 by the then CM, Sri Y. S. Jagan Mohan Reddy Garu, and a significant amount of work is completed.

This project is aimed to pump three TMCs of water everyday at 800 feet level for Rayalaseema and Nellore projects and also for Chennai drinking water purpose. Madam, we demand the Government of India to revisit and review and grant permissions for this project without which Greater Rayalaseema projects will be put to severe injustice.

Thirdly, we demand the Government of India to provide financial assistance for Gundrevula project. This project is aimed to stabilise the historical K.C. Canal ayacut and also provide drinking water to western mandals of Kurnool district.

Madam, at present, for 2.65 lakh acres of K.C. Canal ayacut, there is only one dam on Tungabhadra, that is, Sunkesula Dam which has the capacity of only 1.5 TMC. It is nowhere sufficient to irrigate 2.65 lakh acres of land. So, we are requesting the Government to give financial assistance to Gundrevula Project with 15 to 20 TMC capacity so that the K.C. Canal ayacut can be stabilised.

Recently, the NHAI sanctioned a new river overbridge to connect Nandyala of Andhra Pradesh to Kalvakurthy of Telangana State. There is a demand from the farmers to construct a weir, an ayacut along with this bridge. We request the hon. Jal Shakti Minister and the hon. Minister for National Highways to consider this proposal for construction of weir along the river overbridge at Siddheswaram, which would not require any additional land acquisition. All it requires is, change of design and increase in strength.

Madam, we request the National Dam Safety Authority to undertake immediate repairs at Srisailam dam, Nagarjuna Sagar Dam and other important dams of Andhra Pradesh. We request the Government of India to increase the Central support for minor irrigation projects in Andhra Pradesh and also request the Government to increase the allocation of funds under Jal Jeevan Mission for Andhra Pradesh. With these demands, I conclude my speech.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam, on behalf of the All India Trinamool Congress, I rise to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Jal Shakti for the year 2025-26. I would like to express my concern regarding the functioning of the Ministry of Jal Shakti. It was envisioned that this Ministry would be effective in addressing India's multifaceted water challenges, including water scarcity, sanitation and the provision of clean drinking water. Madam, water is the driving force of nature. It is the most precious resource and abundant compound on earth's surface, covering more than 70 per cent of the planet. But India has only four per cent of water whereas it is home to 17 per cent of the world population. Now, it is evident that the ratio of availability and usage is not at the desired level. The solution lies in smart usage. Unfortunately, it has clearly failed in doing so. It is highlighted in the 2018 report published by the NITI Aayog that at least 21 major Indian cities,

including New Delhi, were projected to exhaust their groundwater resources by 2020. If that is the case, I would like to know from the hon. Minister how we are going to move forward from here.

Madam, the Ministry has seen a significant rise in the funds allocated to it. For the financial year of 2024-25, Rs.98,418 crore was given. In the Union Budget, for the fiscal year 2025-26, the Ministry of Jal Shakti has been allocated Rs.99,503 crore. These allocations represent approximately 1.964 per cent of the total Government expenditure, positioning the Ministry of Jal Shakti among the key sectors in terms of budgetary priority.

Madam, despite this, there is a significant underutilization of this fund. So, I would like to ask the hon. Minister the reason for non-utilization of the fund.

The ambitious Har Ghar Jal initiative that aims to provide every rural household with tap water by 2024 has now been extended till 2028. I would like to know from the hon. Minister why the Government needs four years more to fulfil its target. I would also like to highlight an important issue. The Ministry claimed that 78 per cent of Anganwadi centres had access to clean tap water under the Jal Jeevan Mission. However, this was based on a total of 11.11 lakh centres, while the Ministry of Women and Child Development reported that there are 13.87 lakh operational centres as of March 2021. Is there a valid explanation for this glaring mismatch in number? Such differences raise doubt about the accuracy of the Ministry's data and the transparency of its reporting. This means that about 2.75 lakh centres were left out, bringing the actual coverage down to around 70 per cent. The Ministry's focus on large-scale water infrastructure projects, such as river interlinking project, which aims to connect 37 rivers and extensive dam construction, gives rise to various environmental and social concerns. These projects can harm ecosystems, displace communities and lead to loss of biodiversity. I urge the Ministry to focus on sustainable community-based water management instead of large infrastructure projects that could cause long-term damage. ? (*Interruptions*) Madam, my Party has given 15 minutes for me. ? (*Interruptions*) I would like to know from the hon. Minister whether the waters of

the Ganga River in Prayagraj, Uttar Pradesh, during the ongoing Maha Kumbh were completely clean? As per the National Green Tribunal's directives, millions of devotees should have been informed about the quality of the water they were about to dip into. We have all seen the reports showing dangerously high levels of bacteria in the water, making it unsafe for bathing. If the Minister has received this information, I would like to know from the Government what steps the Government is taking regarding cleaning the Ganga Triveni Sangam.

Madam, I belong to the Sundarbans Constituency. The Sundarbans river embankment issue is a major challenge due to the region's fragile ecosystem. The region faced constant threats from cyclones like Amphan, Aila, Bulbul, Yaas and many more. The Government of India sanctioned Rs 2,103.64 crore for FMP schemes, namely Sundarban Embankments Reconstruction Project, Kaliaghai-Kapaleswari-Baghai Basin Scheme etc., The Government of West Bengal submitted a reimbursement project worth Rs. 204.07 crore, but only Rs. 44.15 crore has so far been reimbursed. So, I would like to request the hon. Minister to release the balance amount, that is, Rs. 159.92 crore at the earliest.

I would like to request the hon. Minister to implement the Ghatal Master Plan which is a long-pending demand of the people in the two flood-affected districts ? (*Interruptions*) The dredging of Bhagirathi, Hooghly and Ganga at the upstream of Farakka Barrage to maintain navigability at Kolkata port was the main objective of construction of Farakka Barrage and Ganga Water Treaty, 1996. So, I would like to request the hon. Minister to release the fund.

The three North Bengal districts, namely, Cooch Behar, Alipurduar and Jalpaiguri, which are criss-crossed by more than 50 rivers having their origin in Bhutan, are mainly responsible for erosion and flood.

So, I would like to request the hon. Minister that since the Government of West Bengal has already sent a proposal and requested for sanctioning of fund on 8th August, 2024, you should constitute an Indo-Bhutan Joint River Commission at the

earliest to formulate and recommend flood control works and flood warning system.

Being a representative of Sundarbans, I would like to request the hon. Minister to sanction more fund for construction and maintenance of the entire river embankment of Sundarbans to protect the people of Sundarbans.

Thank you, Madam.

SHRI TAMILSELVAN THANGA (THENI): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. At the outset, I thank you for allowing me to speak on the demands for grants pertaining to the Ministry of Water Resources (Jal Shakti). There is no world without water. Long live Tamil language. Water Resources for the basis of our life, livelihood and development. You have allocated Rs 99, 503 Crore for the Jal Jeevan Mission. If we compare, it is Rs 4,500 Crore less than the last year?s allocation. While speaking in this august House, Hon Finance Minister informed that 98 per cent of the households in India have been provided with potable tap water under the Jal Jeevan Mission. Hon. Prime Minister too was listening to this in this House. You bring several schemes like Jal Jeevan Mission. The Union Government should keenly observe to the fact that which State of this country is implementing the Schemes very effectively. If you talk about Jal Jeevan Mission, it is the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) Government in Tamil Nadu led by *Thalapathi* Thiru M.K. Stalin which has made this Scheme successfully reach 98 per cent of households in the State of Tamil Nadu. When this State Government of Tamil Nadu demands for release of funds, you have been denying to do so. You refuse to provide flood relief assistance. You refuse to release funds meant for education. Similarly for Flood Management and Border Area Programme (FMBAP) you earlier allocated Rs. 450 crore. This year you have further reduced this flood management fund by Rs.50 crore and made it as Rs. 400 crore. Why did you reduce this amount? Will there not be any floods this year? If such a flood comes, will this Government should inform us on how to stop that flood. Air and water are being polluted. Water bodies are polluted. We come to know from the Reports of the Union Government about water pollution, This Biochemical Oxygen Demand test report further about the 1920 samples of water

taken in different places explains how far this water is worst polluted. There is Biochemical Oxygen deficit in 817 places. It means the water pollution is very high in these 817 places. This Union Government after finding this should act swiftly for ensuring the protection of all water bodies. There is very high pollution of water in 311 basins. What are you doing to rectify this? There is depletion of ground water level. If we inspect in 100 districts, there is depletion of ground water table. There are chemicals like fluoride, arsenic and uranium contained in water making it unfit for drinking. I urge the Union Government to devise a Scheme to address this issue. This Government is allocation Rs. 99,503 crore to the Department of Water Resources for the year 2025-26. This Government should also immediately release funds timely and in full to the States like Tamil Nadu which are implementing several Schemes successfully. But so far not even 40 percent of the funds are not released. Why are showing hesitation to release the remaining funds? Union Government should clarify on this. These are the details of rivers which are polluted. You have been allocating huge funds for cleaning Ganga and addressing the issue of pollution in river Ganges. Similarly you should allocate funds for other rivers in the various States of the country. Particularly in Tamil Nadu, people take holy dip like Kumbhmela in rivers like Thamirabharani, Cauvery and Vaigai. Even water is polluted in these rivers. You should allocate funds for cleaning such rivers of Tamil Nadu as well. Hon Prime Minister spoke in this august House even yesterday. He said that more than 60 crore people took holy dip during Mahakumbh in Uttar Pradesh. I want to ask you if 60 crore people take holy dip in a river, will that not be polluted? What is the fate of that river and the quality of that river water? How will you clean it? How long will it take? This situation should not continue. There should be a water management Committee which should look into the issue of Kumbhmela types of holy dip in large numbers in various rivers of the country and submit reports to the different State Governments with a follow-up action in this regard. Similarly in the coastal districts of Tamil Nadu, there is issue of mixing of saline water with in drinking water. There should be coastal management programmes for addressing this issue drinking water becoming saline and water should be protected. In Tamil Nadu, if we talk about a new Scheme, it is

the Combined Water Supply Scheme (CWSS). There are 56 Combine water Schemes through which drinking water is provided to Crores of people of Tamil Nadu. You should provide adequate funds to this Integrated Drinking Water Scheme. Why Union Government is not releasing funds to Tamil Nadu. Under Jal Jeevan Mission, so far, there is a due amount of Rs. 1707 crore to be released by the Union Government for the year 2024-25. This amount is yet to be released to Tamil Nadu. You should release this immediately. Under fund sharing pattern under Jal Jeevan Mission (JJM), should be revised. You have not increased the share of the Union Government. It should be increased. Only then the water resources can be well protected. Similarly, under 19 new Combined water Schemes you should allocate Rs. 21,231 crore to Tamil Nadu. We have given new water Schemes. This Scheme is the need of the hour. Through this Scheme, Crores of people of Tamil Nadu will get integrated drinking water supply. In order to protect our water bodies there should be monitoring of five dams in Tamil Nadu. Cauvery, Kollidam, Vellaru dams should be protected. There should be separate funds allocated for operation and maintenance of these dams. Union Government should understand that it is Tamil Nadu led by Hon Chief Minister *Thalapathi* Thiru M.K. Stalin which is pioneer in implementing successfully the water related schemes of the Union Government without any delay and hence I urge that adequate funds should be allocated Tamil Nadu without further delay. With this I conclude. Thank you.

श्री पुष्पेंद्र सरोज (कौशाम्बी) : महोदया, मैं आज जल शक्ति मंत्रालय की डिमांड फॉर ग्रांट्स का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । कोई विकास के खिलाफ नहीं, बल्कि झूठे दावों, भ्रष्टाचार और जनता के साथ बड़े धोखे के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदया, सरकार दावा करती है कि जल जीवन मिशन के तहत भारत की पानी की समस्या सुलझ गई है । यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाएं, तो एक अलग सच सामने आता है । आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इनके नल में एक बूंद पानी तक नहीं आ पा रहा है । जल जीवन मिशन जो वर्ष 2019 में इस वायदे के साथ शुरू किया गया था कि वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर को जल से नल मिलेगा । अगर यह इतना बड़ा मिशन था, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2024-25 में इसके बजट में जो राशि 70 हजार करोड़ रुपये से आधे से भी कम मात्र 22 हजार करोड़ रुपये क्यों कर दी गई? सरकार दावा करती है

कि उत्तर प्रदेश में 85 परसेंट से ज्यादा ग्रामीण घरों तक जल पहुंच गया है लेकिन महोदया यदि मैं अपने कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे एक दिन मेरे क्षेत्र में आएं । मैं स्वयं उन्हें लेकर जाऊंगा और पानी की समस्या के हालात दिखाऊंगा । वहां एक भी टंकी न पूरे तरीके से बनी है और न ही पाइप लाइन बिछी है । जो पाइप लाइन बिछी भी है, उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि वह फटती चली जा रही है और उससे ऊपर ग्रामीण सड़क बनाने की मेहनत इतने सालों की जो मेहनत चाहे माननीय सांसदों ने की हो या माननीय विधायकों ने की हो, उन सड़कों को खोद दिया गया है ।

महोदया, यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो एक हजार से ज्यादा सड़कें खोद दी गई हैं और मात्र 50 प्रतिशत से कम सड़क आज तक बन नहीं पाई है । वर्ष 2024-25 में जल जीवन मिशन के तहत सैंटर और स्टेट का एक शेयर आधा-आधा बजट एलोकेशन का होता है । उत्तर प्रदेश के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार और भेदभाव किया गया कि सैंटर से वर्ष 2023-24 का अभी भी 4 हजार करोड़ रुपयों का बकाया है और वर्ष 2024-25 में अभी भी 6 हजार करोड़ रुपये बजट का प्राप्त नहीं हुआ है । स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन लाख से ज्यादा सैम्पल्स कंटेमिनेटेड पाए गए हैं । आर्सेनिक और फ्लोराइड जहर जैसे बन चुका है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है । जल जीवन मिशन एक सपना जरूर था लेकिन आज से यह मिशन ?जल झूठ? बनकर रह गया है । इसी तरह से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015 में इस वायदे के साथ शुरू की गई थी कि हर खेत को पानी मिलेगा और कृषि में पानी का बेहतर उपयोग होगा ।

माननीय सभापति महोदया, यू.पी. में हर साल 70 प्रतिशत ग्राउण्ड वॉटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन ग्राउण्ड वॉटर रिचार्ज के लिए इस सरकार ने कोई ठोस व्यवस्था अभी तक नहीं की है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र की कुछ मांगें हैं, जो मैं सरकार से करना चाहूंगा, जिनमें कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं, जैसे महाराजपुर से सिया माइनर कैनाल; रामपुर, केटवा से बसियारा माइनर कैनाल; बाघराय से कमासिन से चकवाडा माइनर कैनाल । बकुलाही नदी, जो रायबरेली से निकलती है और मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर जाती है, वह कुंडा और बाबागंज में भयंकर बाढ़ लेकर आती है । उसमें हजारों एकड़ खेत डूब जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है और इसके कारण वहां के किसान कर्ज में डूब जाते हैं । इसका एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए, यह मैं सरकार से मांग करूंगा ।

पूर्वांचल और बुंदेलखण्ड में अमृत सरोवर योजना में जितने तालाब खोदे गए हैं, आज तक उनमें एक बूंद भी पानी नहीं है ।

माननीय सभापति महोदया, ?नमामि गंगे? का जो सपना इस सरकार ने दिखाया था, इसमें दस सालों में 20,000 करोड़ रुपये लगे और फिर भी ?राम तेरी गंगा मैली? है । इन्होंने पिछले दस सालों का जो बजट प्रस्ताव रखा है तो मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि दस सालों में से बस दो बार ?नमामि गंगे? के बजट को यूटीलाइज्ड किया गया और इस सरकार में उस बजट का आठ बार अंडर यूटीलाइज्ड रहने का रेट रहा है ।

माननीय सभापति महोदया, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में साफ दिखाया गया है कि ?नमामि गंगे? योजना में धीमी गति से काम हो रहा है । प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को एप्रूव करने में देरी हो रही है, इसके इम्प्लीमेंटेशन की रफ्तार बहुत धीमी है । सबसे बड़ा धोखा यह रहा कि बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रचार-प्रसार में खर्च किया गया, लेकिन धरातल पर इसकी वास्तविकता कुछ और है ।

कल हमने प्रधान मंत्री जी का भाषण सुना । मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कुम्भ में मरने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की, लेकिन कल प्रधान मंत्री जी ने उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कहा ।

सभापति महोदया, अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि वह गंगा, जो पाप धोने आयी थी, आज वह सरकारी पापों से भर गयी है । 20,000 करोड़ रुपये का प्रचार भी हो गया, पर गंगा की हालत और बिगड़ गयी ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

***m115 श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) :** माननीय सभापति महोदया, मैं इस सम्मानित सदन में जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए खड़ी हूँ । यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत प्रशासनिक दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि जल संसाधनों के प्रबंधन और जल संरक्षण में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है । जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जैसी योजनाओं से जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में व्यापक सुधार किया गया है ।

माननीय सभापति महोदया, महाराष्ट्र में जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई है । माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना के माध्यम से हजारों गाँवों में जल संरक्षण की नई मिसाल

कायम की है । इस योजना के तहत भूजल स्तर में सुधार हुआ है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है । विशेष रूप से विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं ।

माननीय सभापति महोदया, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण भारत को हर घर नल से जल देने की योजना बनाई गई थी । वर्ष 2025 तक महाराष्ट्र में 88 प्रतिशत से अधिक घरों में नल कनेक्शंस उपलब्ध कराए गए हैं, जो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है । जल गुणवत्ता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई गई है और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं । गंगा नदी की स्वच्छता के साथ-साथ महाराष्ट्र की अन्य प्रमुख नदियों, जैसे गोदावरी, कृष्णा, भीमा और पंचगंगा के पुनर्जीवन पर भी केन्द्र सरकार का विशेष ध्यान है । मोदी सरकार में बाढ़ नियंत्रण और जल संचयन के लिए जलाशयों और बांधों के रख-रखाव को प्राथमिकता दी गयी है । इस योजना के तहत किसानों को जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं । महाराष्ट्र में इस योजना के तहत 8,260 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिससे किसानों की जल संबंधी आवश्यकता को पूरा किया जा सके । ?हर खेत को पानी? योजना के तहत नई सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है और आधुनिक ड्रिप सिंचाई तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जलगांव में गंभीर जल संकट के समाधान हेतु लोअर तापी प्रमुख सिंचाई परियोजना पर पाडसरी डैम को लगभग 25 वर्ष पूर्व स्वीकृत दी गई थी । यह परियोजना 32,328 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता प्रदान करने के साथ-साथ लाखों नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में सहायक होगी ।

महाराष्ट्र सरकार ने अब तक 874.05 करोड़ रुपये इस परियोजना पर खर्च किए हैं, लेकिन अब भी 2,014 करोड़ रुपये की लागत लंबित है ।

जल शक्ति मंत्रालय ने 22वीं आईसीसी बैठक 23, अप्रैल, 2024 में इस परियोजना को मंजूरी दी थी ।

महाराष्ट्र सरकार ने 31 मई, 2024 को इस परियोजना को पीएमकेएसवाई योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है । इस परियोजना को 2,888.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ निवेश की मंजूरी प्रदान की गई है, लेकिन यह परियोजना अब तक अधूरी पड़ी है । सीमित वित्तीय संसाधनों और धीमी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण हर वर्ष केवल नाममात्र का बजट आवंटित किया जाता है । इस देरी के कारण किसानों को फसल

उत्पादन में नुकसान उठाना पड़ रहा है और नागरिकों को भी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है । अतः मैं सरकार से यह प्रमुख मांग करती हूँ कि इस परियोजना को शीघ्र ही पीएमकेएसवाई योजना में शामिल किया जाए और आवश्यक निधि तुरंत जारी की जाए ।

जलगांव जिले में 99.98 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक पाइपलाइन जल आपूर्ति पहुँच चुकी है, जो केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है । यह डेटा दर्शाता है कि योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रहा है, लेकिन वित्तीय बिलों के भुगतान में देरी और कार्यों की धीमी गति के कारण कई विकास कार्य अधूरे रह गए हैं ।

माननीय सभापति महोदया, केंद्र सरकार की योजनाएँ प्रभावी हैं, लेकिन उनका समयबद्ध और सुचारु रूप से क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है । मैं जल शक्ति मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों से आग्रह करती हूँ कि लंबित वित्तीय भुगतान तुरंत जारी किए जाएँ, ताकि ठेकेदारों और श्रमिकों को समय पर भुगतान मिले और कार्य तेजी से पूरा हो सके । प्रगति धीमी होने वाली परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाए और अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए । जल आपूर्ति योजनाओं को तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए जाएँ, ताकि जनता को जल्द से जल्द लाभ मिल सके । ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु नियमित निगरानी तंत्र विकसित किया जाए।

प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल साहब के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय की विभिन्न योजनाएँ जल संकट से निपटने में मील का पत्थर साबित हो रही हैं । लेकिन हमें इस कार्य को तेज़ गति से पूरा करना होगा । मैं इस सदन से अनुरोध करती हूँ कि जल शक्ति मंत्रालय के अनुदानों की मांगों को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाए, ताकि देश और महाराष्ट्र की जल आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके ।

धन्यवाद ।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Thank you, Chairperson, for giving me the opportunity to participate in this discussion. Jal Jeevan Mission, a flagship programme of the Government, aims at providing clean and sustainable drinking water to every rural household in India.

While we appreciate the vision and commitment behind this initiative, its execution in many States, including Kerala, remains deeply concerning. Jal Jeevan Mission has been allocated Rs. 67,000 crore in 2025-26, which is five per cent

lower than the Budget Estimate of 2024-25. In 2024-25, the Revised Estimate of this Scheme is only Rs. 22,694 crore, as opposed to a budget allocation of Rs. 70,163 crore. This is the lowest expenditure on this Scheme in any year since 2020-21.

In Kerala, the coverage of Jal Jeevan Mission is the lowest, with only 54 per cent of households having access to tap water. The Mission, which was supposed to ensure piped water access to every rural household by 2024, has faced severe delays in execution.

Nearly half of the project remains incomplete, mainly due to slow tendering process and approvals. This bureaucratic delay has delayed infrastructure development.

The slow pace of implementation has had a direct impact on local communities. Roads that were dug up for laying pipelines have been left unfinished for months, even years, causing significant economic losses and posing serious safety hazards. Accidents due to unfinished roads and trenches are becoming more common.

Instead of improving quality of life, the Mission's poor execution is creating new infrastructure challenges. Since the Scheme's funding structure mandates that 50 per cent of the cost be borne by the Centre, 25 per cent by the State Governments, 50 per cent by the local bodies and 10 per cent by the beneficiaries, Members of Parliament have a minimum role over its execution. This has led to States renaming, and implementing the project under different local schemes, which reduces Central Government involvement, and scrutiny. The States like Kerala purposefully try to evade the Centre?s role in this project. They try to implement these projects as their own by avoiding the Members of Parliament.

As a Central Government project, MPs have the right to monitor the Jal Jeevan Mission project. The Government of Kerala has even published a book consolidating Jal Jeevan Mission work in 140 Assembly Constituencies, exempting

Central Government?s contributions and the MPs' concern, owning it as their own project.

Across many States, people are receiving tap connections, but no water flows through them. In some cases, the taps are yet to be fitted. Issues of water crisis have been raised in Parliament multiple times. A common issue regarding Jal Jeevan Mission has been the lack of water at the source. The Government reports an increase in household tap connections, but having taps does not mean having water. The data may suggest rapid progress, but what matters to people is whether water actually reaches their homes.

Madam, another major issue is the quality of water being supplied. The Functionality Assessment Report 2022 revealed that States like Kerala, Sikkim and Tripura have over 40 per cent of households receiving water that does not meet quality standards. Safe drinking water is not just about access, but also about reliability. The Standing Committee on Water Resources also highlighted several issues, including inadequate water quality testing, unhygienic storage facilities, and insufficient testing labs. It is not enough to just provide connections. We must ensure that the water supplied is clean, regular, and safe for consumption.

The financial constraints are another major hurdle. Many States have struggled to meet their share of funding due to cost overruns and delays in statutory approvals. The Standing Committee has pointed out that difficult terrains, scattered rural populations, and adverse climatic conditions often slowdown progress. As a result, Kerala and several other States have been unable to fully implement Jal Jeevan Mission at the desired pace. If the Centre claims to have Jal Jeevan Mission as one of its major schemes, that they boast about, then they should also take responsibility and accountability for ensuring that the scheme is properly implemented, taking into consideration the diversities and complexities of implementation of the scheme across regions.

Finally, if we truly want Jal Jeevan Mission to be a success, we need urgent corrective measures. I urge the Government to prioritise source sustainability to

ensure that every tap connection is backed by a dependable water source. Kerala, with its lowest Jal Jeevan Mission coverage, must receive special attention to address gaps in implementation. Furthermore, the Centre must work closely with the States to address financial bottlenecks, accelerate fund releases, and strengthen infrastructure.

This Mission is not just about numbers on the dashboard, it is about ensuring every citizen gets access to safe and sustainable drinking water. Water is the most fundamental human need. The people of Kerala, and indeed all of India, deserve not just tap connections, but running water which is clean, and accessible every day.

I urge the Government to take immediate, and decisive steps to bridge the implementation gap in the Jal Jeevan Mission as water security is not a privilege but a right. Thank you, Madam.

SHRI GURMEET SINGH MEET HAYER (SANGRUR): I thank you hon. Madam Chairperson for giving me the opportunity to speak on Demands for Grants under the control of Ministry of Jal Shati for the year 2025-26.

Ma?am, it has been said in Guru Granth Sahib that water is an essential element in life and due to water, there is greenery and prosperity in life around us. So, water is indispensable for life. As far as Punjab is concerned, our state was irrigated by five rivers earlier. The word Punjab means ?land of five rivers?. Two rivers are now located in Pakistan after division of India in 1947. Three rivers remained in Punjab. But, the waters of Punjab?s rivers were over-exploited. Our river-water was given to even those states that should not have been given our river-water under Riparian State law.

Secondly, we had to make India self-sufficient in production of foodgrains. We ushered in the Green Revolution. We had to over-exploit the under-ground water resources in Punjab. For paddy cultivation, lot of water was needed. So, due to over-exploitation of ground-water resources, condition has deteriorated in Punjab.

Madam Chairperson, I want to place 4-5 important points pertaining to Punjab. When Punjab was divided and Haryana came into existence, it created problem for Punjab. As per 1954 Yamuna river-water agreement, 2/3 rd of Yamuna river?s water was supposed to be granted to Punjab. However, after Haryana came into existence, it was not mentioned as to how much river-water will be given to Punjab. I urge upon the Central Government to reconsider the provisions of this treaty and Punjab? s share of river-water should be given to our state.

Second matter pertains to my constituency Sangrur as well as Punjab. The embankment of river Ghaggar from Khanauri to Makror Sahib has eroded. As a result, in 2023, floods were rampant in this area. From Makror Sahib to Karail, the 17 kilometres stretch needs to be widened. An embankment needs to be built here so that thousands of acres of land of farmers can be saved from destruction. So, I urge upon the hon?ble minister Sir to do the needful in both the states.

Thirdly, Punjab became the first state to complete government?s Jal Shakti mission in 2022. Pipes were laid, boring was done and water reached the houses of people via taps. But, that water is not worth drinking. Today, in every second or third house of Punjab, cancer patients are there. The underground water in Punjab is badly contaminated. I urge upon the Central Government that for the region of Malwa and my area, including Sangrur, Dhuri, Barnala, Malerkotla, Sunam etc., provision should be made for providing Bhakra Canal water to these areas. This is essential for providing clean drinking water to people of these areas.

Fourthly, Madam, there are dams in Kandi region. They are 30 years old dams. A lot of silt has accumulated in these dams. It leads to flooding. Extra water flows into Pakistan. The need of the hour is to de-silt these small dams. The State Government has sent proposals for the same to the centre. Three projects have been approved but five other projects are still pending with the Centre. I urge upon the hon. Minister Sir to give the approval for the remaining projects at the earliest. Silt can be used for the construction of highways in Punjab and excess flood water will

no longer flow into Pakistan. Nowadays, fertile top soil is being used for construction of highways in Punjab.

The ?Pradhan Mantri Krishi Sinchaai scheme? is there. For renovation and extension of canals, Punjab had been asked to submit its proposal. We have sent a proposal of Rs. 1163 crores to the Centre. 10 years have passed but the entire amount has not yet been given to Punjab. Only a partial amount has been given to Punjab. Full money should be paid to Punjab.

The Standing Committee on Water Resources has taken cognizance in its tenth report that the underground water of Punjab is badly contaminated. Punjab?s name has been included in the list of seven such states. We withdraw ground water at the rate of 27.80 bcm but the recharge of ground water is only 18.84 bcm. So, Punjab was added in the list of Atal Scheme. Money was to be provided to Punjab. But, Punjab has not yet been given this amount. An official notice should be given to us that Punjab has been included in this scheme.

Hon. Madam Chairperson, I do hope that the problems of drinking water and other water related issues of Punjab will be solved by the Central Government. Thank you.

SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR): Hon. Chairman, Vanakkam. I wish to speak briefly on the Demands for Grants pertaining to the Ministry of Water Resources. There is a Tamil proverb which says that even if the temple is small in area, the bell sound should be bigger than normal. In the same way, those in the Government are talking big and doing nothing. Their activities are in that fashion. I am not saying this with any bias. This is the actual state of affairs prevalent in this country. This Government has failed on three counts. They failed miserably. I do not have any hesitation to say so. They have failed to protect the water resources of India without water being wasted. This is utter failure on the part of Union Government. They have also failed to use water for our benefit. Thirdly, they have miserably failed to protect our water bodies and water resources including ground water from being polluted. Therefore, this Government, I must say, is just functional on mere words

with no concrete and appropriate action in protecting the interests of our country. I want to cite an example. Flood and drought are perennial issues. Losses due to floods and drought are to the large extent. Why cannot you link the rivers of Mount Himalayas to compensate this loss? Why cannot you link the rivers of south India? There was a Scheme to link the rivers of our country. There was a Scheme called as Garland Canal Scheme. I fail to understand why this Scheme could not be completed? They say that they do not have funds. Is it true that they do not have funds? This Government wants to waive-off the loans to the tune of Rs. 25 lakh crore taken by corporates like Adani and Ambani. If this Government had collected that loan, it would have been easily implemented the interlinking of Himalayan rivers. It would have interlinked the rivers of our country. It would have made our arid lands fertile. They did not do this. That is why I say that this Union Government has miserably failed. Ground water table has gone down so deep to a dangerous level. It has been polluted as well. There is no policy to streamline this or to implement corrective measures in this regard. Chemical discharges are polluting the rivers of the country. River Yamuna has become the worst polluted as we cannot even stand on the shore of this river. No river including Ganges is pure without being polluted. They gave assurance with the slogan ?Truth alone can Triumph? for cleaning Ganges within a particular period of time. Whether they have fulfilled this assurance? No, they failed. They just betray the people of this country by mere words and no action is visible concretely on ground. This is the ground reality. I want to talk about industrial effluents. Who is to be blamed for discharge of effluents from Industries? Is it the industry which is the culprit? Is that the labourer to be blamed for this debacle? No. It is the Government which gave permission for these Industries is to be blamed. Even a drop of water in this land should not be polluted. There is a gap in the planning of such a Scheme and its execution. There is a sharing pattern of funds for these water related Schemes. At the time of giving permission to set-up industries in Textile hubs, if the integrated schemes are implemented in preserving water, theissue of water pollution would have been very well addressed. They should have ensured that not even a single drop of water will be polluted. But the Union Government failed to do so. Similarly, sea water should

be made drinkable. Priority should be given to desalination plants to convert saline water to drinking water. They have not shown any concern towards this aspect of preservation of water as well. There are ways to do it efficiently without any loss. Not only on three counts, have they failed on many counts. I have a long list of the failures of this Government. Finally, I want to say this Parliament should have more number of sittings in a calendar year. This can ensure availability of more time for the MPs belonging to the Opposition parties to speak on different issues. What is the loss for this Government in this regard? Why it is not doing so? I want to warn about this dangerous trend where this Government is just disallowing the democracy to function in its normal course.

Thank you.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): The Ministry has been allocated Rs. 99,503 crore in BE 2025-26. This marks a meagre increase over Rs. 98,714 crore allocated in BE 2024-25. I stand to oppose this because the Ministry had faced severe under-utilisation of funds in 2024-25 with the Revised Estimate being 48 per cent lower than the allocation at just Rs. 51,558 crore. The Department of Drinking Water and Sanitation has been allocated Rs. 74,226 crore in 2025-26. This is a reduction in allocation compared to Rs. 76,570 allocated in BE 2024-25. This trend of under-utilisation has persisted with only 74 per cent utilisation in 2020-21; 72 per cent utilisation in 2021-22; 88 per cent utilisation in 2022-23; and only 31.47 per cent funds utilised till January in 2024-25.

In Jal Jeevan Mission, the allocation has been reduced from Rs. 70,162 crore in BE 2024-25 to Rs. 67,000 crore in 2025-26. The scheme has also seen limited utilisation in 2024-25 with only 31.35 per cent funds utilised till February 2025. While the Jal Jeevan Mission may declare victory on paper, the ground reality tells a different story. Reports from Maharashtra?s Solapur, Aurangabad, Palghar, and Palghani districts reveal persistent water shortages. In drought-stricken Bundelkhand in UP, people across multiple districts are still desperately searching for water. The Government?s tall claims mean little when taps remain dry and basic survival remains a daily battle.

Regarding the Swachh Bharat Mission, again the Government can boast success. I will give examples how these funds have been utilised. In 2020-21, 49 per cent of the allocated Rs. 9,994 crore was utilized. In 2021-22, 31 per cent of the allocated Rs. 9,994 crore was utilized. In 2022-23, 68.5 per cent of the allocated Rs. 7,192 crore was utilized. In 2023-24, 94.6 per cent of the allocated Rs. 7,192 crore was utilized. In 2024-25, 32.7 per cent of the allocated Rs. 7,192 crore utilized. Even more concerning is from 2020-21 to 2022-23, less than 50 per cent of funds allocated by the Centre to States for Swachh Bharat Mission has been released. Under Solid Waste Management, over four years, that is, 2021 to 2025, only 4,96,610 villages have been covered out of a total target of 9,81,827, which is a shortfall of nearly 50 per cent. Under Liquid Waste Management, since 2020-21, only 4,25,625 villages have been covered out of a total target of 8,30,345.

I will now come to the specific issues of Telangana. My Government has long been demanding the national status for the Palamuru-Rangareddy Lift Irrigation Scheme under the Ministry of Jal Shakti.

18.00 hrs

Moreover, the DPR has been pending for appraisal with the Central Water Commission. The Government of Telangana has submitted a proposal to the Ministry of Jal Shakti for the linking of Godavari with Musi River. This is said to provide 5 TMC of water to Musi River. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Mr. Owaisi, just a minute.

We have a very long list of Members who wish to speak on the subject, and if the House agrees, we can extend the time till 8 pm.

SEVERAL HON. MEMBERS: Agreed.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Owaisi, please continue.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Madam, it is said to provide 5 TMC of water to Musi River facilitating its cleaning and the project would also supply 15 TMC drinking water to

Hyderabad Urban Region. This proposal is currently pending with the Ministry. The State Government has been requesting for the sanction of Rs. 7,400 crore in financial assistance for the project under AMRUT 2 as a special project. But alas, I do not know why this Government hates the Telangana people by not sanctioning this.

And the most important point is that Andhra Pradesh is violating the bifurcation water sharing ratio. They are taking 75 per cent as compared to 66 per cent, and Telangana is getting only 25 per cent as compared to 34 per cent. ? (*Interruptions*)

I am concluding, Madam. In February, 2024, the Telangana Assembly had passed a resolution not to hand over component of Srisailam and Nagarjunasagar to KRMB. The same has been communicated to the Ministry of Jal Shakti. Unfortunately, the Government has not shown any interest.

Madam, may I point to this Government that under Article 21, water is a fundamental right as interpreted by the Apex court under Right to Life. Yet by Government?s own data which says that 21.9 per cent of the rural households still lack potable water; all the districts are plagued by high arsenic and uranium; and numerous rivers are biologically dead. Women in Maharashtra and Bundelkhand still walk miles for water and are forced to scoop murky water from the bottom of wells and ponds. For every single day that this Government fails to fulfil its mandate, it is, in no simpler words, violating the fundamental rights of millions of citizens. Maybe, I think the Mughals are to be blamed for this also. Thank you, Madam.

SHRI BASAVARAJ BOMMAI (HAVERI): Madam, I thank you very much even though it has been a little late in giving me an opportunity to speak on the Demands of Grants of the Jal Shakti Department. Thank you once again, Madam.

I must congratulate our hon. Prime Minister and Jal Shakti Minister for one simple reason that even though water is in the Concurrent List, a lot of responsibilities have been taken by the Government of India since 2017, especially

with the kind of society we are living in where even after more than 75 years of our Independence we are not able to give minimum quality drinking water to our people.

Yes, it is a challenge. Water problem is a dynamic problem. It is no more a static problem. If there is good rain, the underground is charged and water is there in rivers, ponds, everywhere. If rain is not there, then the next year itself can be a drought year.

18.03 hrs (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

With great experience, *jeeva jala*, the lifeline of our entire world is water. However, the fundamentals are not very clear. For example, to whom does water belong? Does it belong to an individual, an institution, a Government or a society? This question is yet to be answered throughout the world. Hence, there are disputes, and there are a lot of dispute solutions from Helsinki Award to our Inter-State Water Dispute Act.

Therefore, the next question that automatically arises is this. Is water problem a local problem or a global problem?

For example, our nation was under a green category about 30 years back. Now, India has come into an ?orange? category. If there is a neglect of water, which we think is a natural resource, unless and until the natural resource becomes a national resource, both conservation of water and utilization of water have to be balanced, along with recycling and reutilization of water. All these years, we have been concentrating only on the storage of water, to build dams and different kinds of storages. We have focused solely on the augmentation of water.

Sir, we never thought of utilizing distribution and managing the water. The time has come now. It is already late for this country to think as a whole. The time has come now to look into the management of water. How is the water managed that is stored? How is it distributed? A lot of wrong concepts are also going around. Many States, organizations, and even political parties and politicians, despite being

taught in our high schools regarding the water cycle, tend to forget. Many leaders speak as if water is going waste to the sea. If sweet water does not go to the sea, only the salt water will rise because of the heat, and come down as water vapour, as rain. Thirty per cent of the sweet water should go to the sea. When the first droplets of sweet water go up, along with that, salt water also goes up. Then there will be rainfall. It is a magnificent water cycle. This is just an introduction.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude in two minutes.

SHRI BASAVARAJ BOMMAI : I have been waiting since morning. You have to give me exemption; otherwise, I will just keep quiet. Please give me time to speak, Sir.

Sir, it is a very serious matter. I am trying to draw the attention of the Government. I congratulated the present Government because drinking water was not a priority in the past. Our hon. Prime Minister, at Red Fort, announced the Jal Jeevan Mission. Enough allocation has been made. This year, out of the total budget allocation of Rs. 99,503 crore, Rs. 74,000 crore is reserved for drinking water. That shows the importance this Government has given to drinking water. Out of that, JJM has got Rs. 67,000 crore. What is the result? Before JJM was there, there was a huge gap between water supply in the villages, in urban areas, and among poor sections. Now, there are a total of 19 crore rural households. Up to January 21st, 2025, 15 crore households have been given water supply. This is the greatest achievement after Independence. जो नामुमकिन था, उसको मोदी जी ने मुमकिन बनाया । इसलिए लोग बोलते हैं ? मोदी है तो मुमकिन है । Along with that, we have taken care of Swachh Bharat. This year, they have given Rs. 7,192 crore. I do not want to elaborate on that.

Sir, I will come straight to the point because you are in a hurry. The greatest loss to the country, both as a livelihood and finance, is because of one Act we have been following since independence and that is the Interstate Water Dispute Act. This Interstate Water Dispute Act has created more disputes than solving the disputes. Section 3 of this Act clearly says that if there is a dispute between two States, and one of the States goes to the Central Government, a tribunal has to be formed.

Tribunals are there in Punjab water dispute, in southern States like Karnataka, Tamil Nadu, Andhra, and in Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and other places. It is really a shame. We are all sitting here but the disputes have not been solved for over 50 years. The Tribunals have been working for 30 years or 40 years but the disputes have not been solved. It is bringing a real bloodbath among States, and there is a huge financial loss. A scheme, which was worth Rs.20 crore, has reached Rs.20,000 crore now. Who is going to pay for this? It is justice denied, not justice delayed. It is a criminal waste. Therefore, I just don't want to talk about the problems. I want to highlight the solution also.

Sir, in 2012, as a Water Resource Minister, in the conference, I had made a proposal. There are judges sitting in tribunals whose age is 83 or 84 years. They have been sitting for the last 20 years with all the facilities in Delhi. All the States have to come to Delhi. What a legal penalty the States are paying! I proposed that there should be a water tribunal or only one single tribunal, headed by a sitting Supreme Court judge, and within six months, the interstate water disputes should be resolved.

Sir, I am just coming to my State. My State, Karnataka, is a mid-riparian State. ऊपर वाले स्टेट से भी हमारा झगड़ा है और नीचे वाले से भी झगड़ा है । लोग डिस्पियूटेड स्टेट कहकर के बुलाते हैं । लेकिन हमारा हालत यह है कि ऊपर वाला स्टेट भी हमें पानी नहीं देता है और नीचे वाले हमें स्टोर करने के लिए नहीं देते हैं । We have got disputes. I am giving one small example of Upper Krishna dispute. The tribunal had given an order on 30.12. 2010. We are now in 2025. Fifteen years have passed. It has not been notified. What an injustice!

Our good friend from Maharashtra was quoting Almaty Dam case in which the height was to be raised from 519 metres to 524 metres. It is not our proposal. It is our right and the Tribunal has upheld our right. They said that we can raise the height up to 524 metres.

Regarding flooding, the CWDC?s independent report is there that the flooding will not happen in the State of Maharashtra because of the height of the Almaty. In

fact, Almaty will give a better justice to the lower riparian areas of Telangana and Andhra Pradesh. Our senior friend has raised the dispute between Telangana and Andhra Pradesh. It is Section 15 in the Andhra Pradesh State Reorganization Act. It is between them. But it is affecting us because it has not been notified. Similarly, we have been denied our rights in Mekedatu. I urge the Government of India to take initiative and advise the CWMA, which is sitting on it for the last six years, to take a decision quickly.

Lastly, there is the issue of Mahadayi, everything is over. The Tribunal?s order is there. But they are not giving the environmental clearances. Sir, the State has been suffering from all directions. As regards Cauvery-Mahanandi interlinking, we have been denied our rights, Sir.

The NWDA is up to it. I urge the Government of India to give justice to our Karnataka State.

Lastly, I would like to talk about the interlinking of Bedti-Varada. It is there in the first national prospective interlinking plan. The NWDA has approved it, still nothing is happening. I want the Government of India to take up the interlinking of Bedti-Varada at the earliest.

Sir, I am really happy that this Government, under the leadership of Narendra Modi Ji, has given a new direction to the concept of drinking water, and because of that, most of the villages are getting a good surface water, otherwise they would have gone to bore wells. Due to the surface water and clean water, health of the villages is improving and performance of the villages is improving. I thank the leadership of Narendra Modi Ji and Patil Ji who are doing a wonderful job. But as far as the inter-State water problem is concerned, they have to think seriously and give solutions. अगर मोदी है, तो मुमकिन है, तो इंटर-स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी सॉल्व हो जाएगा । इस विश्वास पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं । धन्यवाद ।

श्री मोहम्मद हनीफ़ा (लद्दाख) : धन्यवाद सर । जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल-जीवन मिशन प्रोग्राम मरकज़ी सरकार ने वर्ष 2019 में शुरू किया था और इन सालों में काफी हद तक इस पर काम चला है और चल रहा है । आज करीब देश के बहुत सारे घराने कवर कर दिए गए हैं ।

सर, जल-जीवन मिशन के तहत जो हर घर नल पहुंचाना था, इसमें काफी हद तक लद्दाख में भी काम हुआ है, लेकिन इसमें मसला यह है कि जल-जीवन मिशन के तहत हर घर नल तो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इन नलों में पानी कैसे पहुंचाया जाए, यह लद्दाख, खासकर बालाई इलाकों के लिए बहुत बड़ा मसला है । इस स्कीम के तहत जो काम हो रहा है, उसमें उन्हीं सोर्सेज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सोर्सेज़ पहले वहां हुआ करते थे ।

सर, चूंकि लद्दाख में मौसमी हालात, माहौल व ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी के सारे सोर्सेज़, जो बर्फ और ग्लेशियर पर मुदस्सिर हैं, वे बंद होने की कगार पर हैं । जितने भी सोर्सेज़ हैं, वे ग्लेशियर और बर्फ पर मुदस्सिर हैं ।

सर, यही ग्लेशियर्स और बर्फबारी पिघलकर चश्मे और नाले-नदियों की सूरत में नीचे बहते हैं । जब बर्फबारी ही नहीं हो रही है, तो चश्मे और नदी-नालों में जो पानी है, वह खत्म होने की कगार पर है ।

सर, पिछले 10-15 सालों से क्लाइमेट चेंज की वजह से लद्दाख में बर्फबारी बहुत कम हो रही है । लद्दाख में चाहे पीने का पानी हो या इरीगेशन पर्पज़ के लिए हो, ज्यादातर बर्फबारी पर ही मुदस्सिर होता है, क्योंकि यहां बारिश बहुत कम होती है ।

सर, पिछले कई सालों से लद्दाख में जो मौसमी हालात तब्दील हो रहे हैं, उसके बाद लद्दाख के बहुत सारे इलाकों में खुश्कसाली की तरफ जा रहे हैं । बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जहां पिछले कई सालों से पहले ही खुश्कसाली की सूरतेहाल बनी हुई है । यहां के किसान पानी की किल्लत की वजह से काफी परेशान हैं । सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि पिछले 30-40 सालों से जो किसान मेहनत करके प्लांटेशन लगा रहे हैं, वे लगकर तैयार भी हुए हैं । वह प्लांटेशन तैयार है और माहौलियात के लिए भी यह काफी जरूरी है, लेकिन पानी न मिलने के कारण ये प्लांटेशन सूखने की कगार पर हैं ।

पानी न मिलने की वजह से आज ये प्लांटेशन सूखने की कगार पर हैं । किसानों ने पूरी जिंदगी जो मेहनत की है, वह सब आज बर्बाद हो रही है । कारगिल जिले का एक बड़ा इलाका है, जिसे सोध इलाका कहा जाता है । सोध वह ब्लॉक है, जहां के लोग सबसे ज्यादा मुतासिर है । पिछले कई सालों से यहां पर खुश्कसाली जैसे सूरत-ए-हाल बने हुए हैं । जहां कभी दो फसलें हुआ करती थीं, वहां आज एक भी फसल नहीं हो पा रही है ।

सभापति महोदय, कई सालों पहले कारगिल में जो निचले इलाके हैं, वहां सर्दियों में दो से तीन फीट बर्फ जमा हुआ करती थी, लेकिन आज वहां पर मुश्किल से छः इंच भी बर्फ जमा नहीं होती है । इस साल भी बर्फबारी बहुत कम हुई है । जहां दिसम्बर में बर्फबारी होना शुरू

हो जाती है और फरवरी तक वहां पर बर्फबारी जमा रहती है, वहां इस साल में फरवरी तक भी बर्फ नहीं पड़ी है । इस साल भी खुश्कसाली होने का इम्कानात है । इस वजह से इस साल भी इम्कानात है कि इन इलाको में बर्फ से ख़ुश्कसाली से सुरत-ए-हाल बनेगा, जिससे यहां के किसान काफी परेशान होंगे ।

सभापति महोदय, खासकर मैं जिस इलाके की बात कर रहा हूँ, सोध इलाका हेडक्वार्टर से भी बहुत नजदीक है । इस इलाके में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है । वहां पर खेती भी पानी पर ही डिपेंड है और जानवर भी डिपेंडेंट है । खुश्कसाली की वजह से पिछले कई सालों से चारे का भी मसला है । उसके लिए सरकार को मुआवजा देना पड़ता है ।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिए सरकार से मांग करता हूँ, चूँकि लद्दाख यूटी है और यह होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है । मैं होम मिनिस्ट्री से गुजारिश करता हूँ कि लद्दाख के इन इलाकों के लिए एक स्पेशल सर्वे टीम बनाई जाए और उस टीम के तहत वहां प्रोजेक्ट बनाकर इन इलाकों के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए । इन गांवों में जल्दी से जल्दी पानी पहुंचाने की कोशिश की जाए । अगर वहां पर जल्दी से जल्दी पानी नहीं पहुंचेगा तो वहां की जो पब्लिक है, वह पलायन करने पर मजबूर हो जाएगी ।

MD. RAKIBUL HUSSAIN (DHUBRI): Hon. Chairperson Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak about the Demands for Grants relating to the Ministry of Jal Shakti.

While in 2025-26, the Ministry of Jal Shakti has been allocated Rs. 99,503 crore, the budget does not account for the issues that are faced by the people of my State, Assam. Therefore, I dedicate my allocated time to speak about the issues that they face and what has not been covered in the budget provided to the Ministry of Jal Shakti.

Let me start by mentioning a few words in my own language about the Brahmaputra, from the Bard of Assam, the renowned Assam *Gaurav*, Bharat Ratna, late Dr. Bhupen Hazarika.

Luitor boliya baan toi koloinu dhapoli meliso, hir hir xobode
kaal roop dhori loi,
Kaknu bare bare khediso,
Luitor buku henu bam hoi gol ,

Gobhirota henu kixu nuhuwa hol
Baan toi xeye heno oloiya boliya hoi
Duipaare uposi poriso
Baan toi tighil nighilaabi
Axare kothiya nutuabi
Xisu bodh bhaona naapaatibi
Ghoror xaalote xogunok bohuwai
Moronor xobaah naapaatibi
Paanir paarote jonom aamaar
Paanir pitri xokti aamaar
Xei xoktire baanok rodhim
Xohoxro haatere dupaar baandhim
Tor ei xoktik kaarhi kaarhi aani tokei
Aamaar bhrityo korim.

Dr. Bhupen Hazarika often addressed the Brahmaputra River as the *Luit*, as most of us in Assam do. It stands as the lifeblood of Assam, intertwining itself with the very essence and identity of its people.

According to the Assam State Disaster Management Authority?s daily flood reports in 2022, 5-14 districts report significant erosion daily, thereby making it a silent yet devastating crisis, including my Parliamentary Constituency, Dhubri.

For Majuli in Assam ? the world?s largest inhabited river island ? erosion is an existential threat that already its area was reduced from 1000 square kilometres to around 500 square kilometres. If this trend continues, Majuli could disappear by 2040, thereby raising urgent concerns about the future of its displaced population.

Sir, ?*Aapda Prabandhan*? or ?Disaster Management? कह देने से हमारे असम राज्य की याद आती है, क्योंकि असम की one of the many problems, सर्वप्रथम मुख्य समस्या बाढ़ और मिट्टी कटाव है । असम के लोग बाढ़ की समस्या को किसी तरह से सहन कर लेते है, जबकि बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है । बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर आपकी जमीन और घर रह जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो मिट्टी कटाव की समस्या है, हम दिल्ली में बैठकर सोच भी नहीं सकते है कि यह कितनी भयानक समस्या है? मैं पहले भी कह चुका हूं कि असम में ब्रह्मपुत्र और इसके साथ जुड़ी हुई कम से कम 33 सहायक नदियों में किस प्रकार से मिट्टी कटाव होता है, हम यहां बैठकर उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं ।

सर, हम दिल्ली को बार-बार यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिल पायी है । ब्रह्मपुत्र असम की जीवन रेखा है और इस ब्रह्मपुत्र से असम के लोगों का जन-जीवन लगा हुआ है । हम ब्रह्मपुत्र का विषय पहले भी कई बार उठा चुके हैं कि यह नदी नहीं है, यह नद है । यह ब्रह्म का पुत्र है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र असम की जीवन रेखा है । ब्रह्मपुत्र या सहायक नदियों का जो स्वभाव है, वह हिन्दुस्तान की बाकी नदियों से नहीं मिलता है । ब्रह्मपुत्र और इसके सहायक नदियों में जब मिटटी का कटाव होता है, आप सोच नहीं सकते हैं, तब एक ही बार में 1000-1000 बीघा जमीन ब्रह्मपुत्र में समा जाती है । 100-100 बीघा जमीन के मालिकों की जमीन ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों में समा जाने के कारण एक ही दिन में वे लोग रास्ते पर आ जाते हैं । जब इन लोगों की जमीन और घर खोकर भटकना पड़ता है, तब दिल्ली में आने पर कुछ लोग इन्हें घुसपैठिया बोलते हैं ।

इसीलिए मैं माननीय सभापति जी के माध्यम से केंद्र सरकार को अनुरोध करना चाहता हूं कि यह इरोजन, मिटटी कटाव की समस्या क्या है? इस समस्या को समझने के लिए एक बार इस मुद्दे को नजदीक से समझना होगा । इस समस्या को जमीन के स्तर पर समझने के लिए विशेषज्ञों और एक ऑल पार्टी प्रतिनिधिमंडल के साथ स्पॉट पर यात्रा करने की आवश्यकता है । बाढ़ और मिट्टी कटाव जैसी समस्या का समाधान करना केवल एक राज्य सरकार के बस की बात नहीं है । इस समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण अर्थात् राष्ट्रीय नजरिए से देखने की आवश्यकता है । इसीलिए मैं माननीय सभापति महोदय जी के माध्यम से केंद्र सरकार को गुजारिश करना चाहता हूं कि असम की बाढ़ और मिटटी कटाव की समस्या को राष्ट्रीय समस्या घोषित किया जाये ।

Through the Chair, I request the Government of India to declare the flood and erosion problems of Assam as a national problem.

Sir, it is time that the Government recognizes that a separate and dedicated Centrally-funded River Erosion Management Programme must be introduced to identify, map, and prioritize erosion-prone areas, including my Parliamentary Constituency, Dhubri and across Assam, and other affected States. Moreover, the Brahmaputra Board, which is responsible for river management in Assam, must be strengthened through increased financial support.

Erosion is not just an environmental issue but it is a humanitarian crisis that has forced lakhs of people into perpetual displacement, pushing them into economic

insecurity and landlessness.

As a State that bears one of the heaviest burdens of erosion and flooding, Assam deserves a comprehensive, long-term solution rather than piecemeal projects that fail to address the root cause.

I urge this House to strongly recommend that the Government take immediate action to safeguard the land, livelihoods, and people of Assam by allocating appropriate Budget for flood and erosion management before this crisis worsens further.

Thank you, Sir.

DR D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Hon Chairperson Sir, Vanakkam. I must say those who die due to water-borne diseases are large in number as compared to the people who die in wars around the world. We should also look at an important aspect that 97.5 per cent of water flows into sea. Only 2.5 per cent of water is available for human consumption. Out of this, if we exclude water in glaciers of Himalayas and ground water, then only a meagre 1 per cent of the total water is available for human consumption. We should think as to how we use this 1 per cent of water that is available in a judicious manner.

We are worshipping our perennial rivers as Gods. We should also think whether, in the name of worshipping these rivers, we can pollute them. Governments have a key role to play in equitable distribution of this 1 per cent of available water among all human beings. With that in mind this Government brought Jal Jeevan Mission (JJM) to provide water to all the people in equal manner. A target was set by this Government to provide potable tap water to all the households in India by 2024. Now this target has been extended to the year 2028. During the year 2024-25, an amount of Rs 70,000 Crore was allocated for this Scheme. An amount of Rs. 67,000 has been allocated for this Scheme for the year 2025-26. There is a reduction of allocation by Rs. 3000 Crore. But it is a matter of concern that out of the total allocation only Rs 22,000 Core could be spent last year.

In the revised Budget the remaining amount has been marked as unspent. As a result, there is a big financial burden on the State Governments.

The sharing pattern of JJM is 50:50 between the Union and the State Governments. But during last year only 31 per cent of funds were released by the Union Government. Although water pipes have been fixed in many places, due to non-availability of bore-wells, there is no water supply through these pipes. Union Government claim that they have given drinking water to the people of this country. But it is pitiable to say there is no supply of drinking water through these pipes. Union Government claims that drinking water facility has been provided almost 100 per cent in 2.5 lakh villages of the country. But statistics give a different picture. Only 1.5 lakh villages have been provided with drinking water facility. I urge upon you that in order to address this shortcoming, the funds allocated for this Scheme should be completely utilized by releasing it to the fullest extent. In my Viluppuram parliamentary constituency, the ground water table has gone down drastically. Viluppuram district is one among the districts of Tamil Nadu where there is scarcity of drinking water. They tried a Scheme to convert sea water into drinking water. This was renamed as Integrated Drinking Water Scheme of Tiruvannamalai and a proposal was made for providing drinking water to more than 2500 villages at a cost of Rs 2060 Crore. Only when the Union Government releases adequate and necessary funds to this Scheme, we can provide uninterrupted drinking water to the people living in Viluppuram and Kallakkurichi districts. Therefore, I urge upon the Union Government to release funds under JJM without any further delay to Tamil Nadu.

Experts suggest desalination plants as an alternative to address the problem of drinking water scarcity. There are several Schemes in this regard. We have a long coastal line for our country. We have to utilize the sea resources to best possible extent. But what are we doing? We have started polluting the sea water as well. Due to the effluents flowing into sea, it becomes dead and hence it is Dead Sea. If it is Dead Sea, we cannot make use of that sea water. Not only the sea life is affected, we are just digging our own grave. Besides increasing the efforts of desalination of sea

water making it drinkable, we should also protect the underwater flora and fauna of the sea. It is necessary that we should prevent the sea being polluted in different ways. I urge upon the Union Government to act in this regard as well.

Swach Bharat Mission-Clean India Programme is another scheme under this Ministry. We had set targets for making India open defecation free. We devised several programmes in this regard. But the fund allocated for construction of toilets under this Scheme is very insufficient. As per the price rise, this amount of assistance should be increased. Only then we can implement this Scheme with a conviction to reach its core objectives. With this I conclude. Thank you.

श्री अनुराग शर्मा (झाँसी) : महोदय, मैं बुंदेलखंड से आता हूं । बुंदेलखंड के बारे में जैसे पूरे सदन को, पूरे देश को पता है कि हमारे यहां अक्सर सूखा ही पड़ता है और प्रकृति की ऐसी मार रही है कि बुंदेलखंड हमेशा सूखे की चपेट में ही रहा है । मैं बुंदेलखंड की ओर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी को, आदरणीय जलशक्ति मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर किसी ने हमारी सदियों की पीड़ा सुनी और किसी ने बुंदेलखंड को आशीर्वाद दिया है तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिया है । नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने सबसे बड़ा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट शुरू किया । अटल जी का महान सपना था कि दो नदियों को जोड़ा जाए । अगर उसको पूरा करने की किसी ने चेष्टा की, किसी ने हिम्मत की तो हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी की सरकार ने की । मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि केन-बेतवा नदी का जुड़ाव होने वाला है और आदरणीय प्रधान मंत्री जी को सदियों तक हमेशा हिन्दुस्तान तथा बुंदेलखंड याद रखेगा, क्योंकि बुंदेलखंड के लोगों की पहली बार प्यास बुझने वाली है । यह 42 हजार करोड़ रुपये की परियोजना है, जिससे 10 लाख, एक लाख, दो लाख नहीं, बल्कि 10 लाख हेक्टेयर सिंचित होगा, 60 लाख लोगों के घरों में जल पहुंचने की व्यवस्था होगी । उसके काम की शुरुआत हो चुकी है और डैम भी बनना शुरू हो चुका है । बुंदेलखंड में पहली बार ?हर घर जल योजना? के माध्यम से पानी पहुंचना शुरू हो चुका है । हम लोगों का यह सपना भी नहीं था, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बुंदेलखंड की कोई प्यास बुझायेगा । आज प्रधान मंत्री जी की वजह से बुंदेलखंड की प्यास बुझना शुरू हुई है । हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, क्योंकि उन बच्चों के लिए पहली बार जिंदगी में नल से जल आना शुरू हुआ है और वह भी स्वच्छ जल आना शुरू हुआ है । हम कभी जल के बारे में नहीं सोचते थे और आज उन्हीं नलों से स्वच्छ जल आना शुरू हुआ है ।

मेरे यहां कुछ बड़े-बड़े कार्य हो रहे हैं । आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने अभी हमको बीडा (BIDA), नोएडा जैसे बनाने के लिए, 36 हजार हेक्टेयर में दिया है । उसकी वजह से झांसी में पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है । मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमको 75 मिलियन क्यूसिक पानी चाहिए । अगर उसके लिए कुछ व्यवस्था केन्द्र सरकार की ओर से हो जाएगी तो उससे बुंदेलखंड को बड़ा लाभ होगा । बुंदेलखंड में हमेशा पलायन हुआ है । बुंदेलखंड के किसान छोड़ कर चले गये । हमारे युवा छोड़ कर गये, क्योंकि हमारे यहां उनको नौकरियां नहीं मिलती थीं, किसान भाइयों को काम नहीं मिलता था । आज उनको काम भी मिलना शुरू हो रहा है और पहली बार इंडस्ट्रीज़ आने की व्यवस्था की गई है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र की कुछ विशेष डिमांड्स भी हैं । जाखलौन से जो कैनाल निकलती है, उस लिफ्ट कैनाल को सोलर एनर्जी के माध्यम से चालू किया जाता है । इसी तरह से, एक ड्राई और डार्क क्षेत्र टहरौली है, जहाँ लगभग एक लाख की आबादी है । यह बेतवा नदी का किनारा भी है । इससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर पारीछा डैम है । यदि वहाँ पर लगभग 350 करोड़ रुपए में लिफ्ट कैनाल की परियोजना दी जाएगी, तो इन एक लाख घरों में स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था भी हो जाएगी । अगर इसे सोलर एनर्जी के साथ जोड़कर इसमें सोलर पम्प लगाने की व्यवस्था कर दी जाएगी, तो मेरे यहाँ के बहुत-से गांव, जैसे बिजना, टहरौली, रणवारा, टोड़ी फतेहपुर, परसा, बनुहा, गाहता पूरी तरह से संरक्षित और सिंचित हो जाएंगे । इन गांवों से लोगों का पलायन रुक जाएगा ।

हमारे यहाँ की एक-दो डिमांड्स और हैं । अगर हमें माननीय मंत्री जी का थोड़ा और स्नेह मिल जाए, तो बहुत अच्छा होगा । माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से मेरे यहाँ जल संरक्षण में बहुत अच्छा काम हो रहा है । बुंदेलखंड के लोगों के बारे में सोचा जाता था कि यहाँ के लोग ज्यादा झगड़ालू हैं, लेकिन वहाँ की महिलाओं ने, मेरी दीदियों ने जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किये हैं । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा माननीय राष्ट्रपति जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ की शारदा बंसकार जी और गीदा देवी जी को राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित किया गया । मेरे यहाँ की ये जल सहेली दीदियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं । इसलिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि जल संरक्षण के क्षेत्र में जितनी भी दीदियाँ काम कर रही हैं, इन लोगों के लिए जनभागीदारी में कुछ मानदेय देने की व्यवस्था हो जाए, तो ये आगे और भी काम करेंगी । आज इनकी वजह से, हमारे यहाँ के 216 गांवों में जल संरक्षण का काम शुरू हो चुका है ।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पुराने काल में, बुंदेलों और चंदेलों ने छः हजार बावड़ियाँ और ताल बनवाये थे । यदि केन-बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट में इनकी साफ-सफाई का

कार्य भी शुरू हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा होगा । मेरे यहाँ 4 बड़े डैम्स हैं । अगर इन चारों डैम्स में साफ-सफाई और डी-सिल्टिंग के काम हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा होगा । यदि पहुज नदी, राजघाट, पारीछा, सुकमा दुकमा डैम में डी-सिल्टिंग का काम हो जाएगा, तो बुंदेलखंड में, विशेष रूप से, झांसी और ललितपुर में बहुत फायदा मिलेगा ।

अंत में, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि जाखलौन कैनाल से ललितपुर डैम को जोड़ने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए का आवंटन हो जाए, तो उससे गोविंदसागर डैम हमेशा भरा रहेगा ।

आपने मुझे बोलने का पर्याप्त समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । इसके साथ ही, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने बुंदेलखंड की प्यास बुझाने का महत्वपूर्ण काम किया है, इसके लिए उनको हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है ।

महोदय, जल संचय से पूरे देश को, पूरी दुनिया को और यहाँ तक कि पूरी सृष्टि को बचाने का सवाल है । लेकिन इस दिशा में जो काम होना चाहिए, वह काम सरकार नहीं कर रही है । इसलिए मैं सरकार के इस अनुदान की माँगों के खिलाफ बोल रहा हूँ । सरकार को यह करना चाहिए था कि देश के अन्दर जितनी भी छोटी-बड़ी नदियाँ हैं, उनमें जल की उपलब्धता के आधार पर जल संचय के लिए बैराज अथवा छोटे या बड़े बांध का निर्माण कराना चाहिए था, लेकिन इसमें सरकार की दिलचस्पी नहीं है ।

सरकार केवल उन योजनाओं का चयन करती है, जिन योजनाओं के लिए, कहा जाए कि जरूरत के हिसाब से चयन करती है । स्थानीय लोगों की जरूरत के हिसाब से उनकी जरूरत नहीं है । बिहार में बागमती परियोजना है, मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट में लोगों का इसके लिए भारी विरोध है । लेकिन, सरकार अड़ी हुई है कि बांध बनवाना है । नर्मदा नदी पर सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ानी है, स्थानीय किसान इसका विरोध कर रहे हैं । लेकिन, सरकार को इसको ऊंचा करना है ।

संपूर्ण बिहार को, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, मध्य बिहार के आठ जिले, जिनके 60 प्रखंडों की खेती, करीब 42 लाख एकड़ जमीन उस परियोजना से सिंचित होगी । हम लोग सोन नदी में इंद्रपुरी जलाश्य बांध बनाने की मांग कर रहे हैं । सरकार इस पर कोई

ध्यान नहीं दे रही है । नहरों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण है । हमारे भोजपुर जिले के दक्षिणी इलाके में सहार, संदेश, चरपोखरी, पीरो, इत्यादि की मरम्मत पर ध्यान नहीं है ।

हमारे जिले का उत्तरी इलाका शाहपुर, बड़हरा, मुफसिल, बिहिया आदि में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है । गंगा नदी से बाढ़ में भारी तबाही मचती है । वहां नदी से अगर नहर की निकासी की जाए, तो एक पूरा इलाका सिंचित होगा । अगर सोन नदी में कदवन जलाश्य या इंद्रपुरी जलाश्य बन जाता है, तो करीब 42 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी । यह जलाश्य न सिर्फ बिहार, बल्कि झारखंड को भी यह अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा ।

इसलिए, हमारी सरकार से मांग है कि सरकार इंद्रपुरी जलाश्य का निर्माण कराए और गंगा नदी से नहर की निकासी हो । इस पर बहुत बड़ा खर्चा नहीं है । जितने सरकारी नलकूप हैं, सब के सब बेकार पड़े हैं, उनको चालू करवाया जाए ।

महोदय, जल संचय हो तो जल पर अधिकार किसका हो, ऐसा एक माननीय सदस्य ने कहा है । पहला अधिकार पीने वालों का होना चाहिए । प्यासों की प्यास बुझाने के लिए जल का उपयोग होना चाहिए । दूसरा अधिकार खेती के लिए किसानों का होना चाहिए । तीसरा अधिकार कल-कारखानों का होना चाहिए । लेकिन, पिछले 10-11 वर्षों में हम लोग देख रहे हैं कि यह प्राथमिकता उलट दी गई है । इसको ठीक-ठाक किया जाए । कल-कारखानों को ज्यादा पानी दिया जा रहा है । कल-कारखाने ही नदियों को दूषित कर रहे हैं, नदियों में कचरा गिरा रहे हैं, जिनकी सफाई की जरूरत है ।

महोदय, दूसरी बात यह है कि हमारे बिहार में कहा जा रहा है कि 97 परसेंट घरों में ?नल से जल? चला गया है । यह सच्चाई से परे है । 97 परसेंट घरों में नल का पानी नहीं गया है । बिहार में जब ?हर घर नल? योजना शुरू हुई, तो इन लोगों ने पूरे बिहार की गलियों को कोड़ दिया । उनको कोड़ दिया, बनी-बनाई सड़कों को तोड़ दिया । पक्की पीसीसी को तोड़ दिया । पाइप डाला, लेकिन पानी नहीं आया । इस पर 36,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिला । उस समय हम लोग देख रहे थे कि पानी नहीं आ रहा है, बच्चे पाइप निकालकर उससे फोफी बजा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं । पश्चिमी चंपारण में हमने देखा कि एक पाइप खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुसाया गया है । ? (व्यवधान) किसी तरह से आनन-फानन में योजना को पूरा किया गया है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री सुदामा प्रसाद : वहां पानी नहीं चल रहा है । ? (व्यवधान) 97 परसेंट यह योजना फेल है । ? (व्यवधान) कोई संसदीय समिति बनाकर इसकी जांच कराई जाए । ? (व्यवधान) ऊपर से सरकार कह रही है, ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BATHINDA): I thank you, Hon. Chairman Sir. A lot of Hon. Members have spoken here and emphasized that water is vital for life. I hail from an agriculture-based State. Water is the life and soul of farmers of Punjab. Irrigation water is needed for production of foodgrains. Our economy is dependent on it. The future of vast number of families is dependent on agriculture.

I oppose the Demands for Grants under the control of the Ministry of Water Resources for the year 2025-26. The budget allocation this year is Rs. 99,503 crores. In 2024-25, it was Rs. 98,724 crores. Out of this amount, Rs. 644 crores were granted to Punjab in the last 5 years. It is hardly 0.65% of the total budget. It means, hardly 125 crores were given to Punjab each year. Punjab provides 40% foodgrains in the Central pool for people of the country. We have hardly 2% of country?s land but we provide 40% foodgrains to the country. The amount given annually to Punjab is peanuts. This is a very sad state of affairs.

As per the report of the Ministry, 78 per cent of our groundwater blocks are in critical condition. Eighteen out of 23 districts are over-exploited. We are extracting 65 per cent more, over and above what we can possibly do. But despite this, the Government gives nothing for a 150-year-old irrigation network, which needs urgent repair.

Why money has not been provided to us to repair and upgrade our 150 years old canal systems so that water can be saved?

Punjab is the only State where Riparian principle regarding sharing of river-water was not followed. The earlier Congress Govts. unjustly gave our water to our neighbouring States. Our rights were denied to us. This country has suffered due to

politics of vote. Our rightful share of river-water was given to neighbouring States due to vote-politics. Our farmers do not have sufficient water for irrigation. Clean drinking water is a casualty in Punjab.

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर) : महोदय, इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई?? (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: औजला साहब,... @ कीजिए ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Madam, please address the Chair. Do not see anywhere. Please address the Chair.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Instead of speaking for the rights of Punjab, you are siding with Members like Bittuji. Why should river-waters of Punjab be given unjustly to neighbouring States? ? (*Interruptions*)

इस कांग्रेस पार्टी ने ही पंजाब का पानी? (व्यवधान) दूसरे सूबों को दे दिया ।? (व्यवधान) आज यह बीजेपी की पार्टी, जब हमारे पास पानी नहीं होता है तो कहते हैं कि एसवाईएल बनाओ और हरियाणा को पानी दो । जब इतनी बड़ी बाढ़ आ जाती है तो रातों-रात डैम खोलकर सारे पंजाब में आफत कर देते हैं और वहाँ पर फ्लडिंग हो जाती है । बीबीएमबी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हमारे एक मेंबर ने पंजाब के पानी की हिफाजत करने के लिए था । इस भाजपा की सरकार ने हमारे मेंबर को हटा दिया । आपको पता है कि वर्ष 2023 में जुलाई के महीने में रात के अंधेरे में सारे डैम्स को खोल दिया और हजारों गाँवों में रात में पानी भर गया, लोग अपनी जान बचाकर भागे, न उनकी फसल बची, सवा लाख एकड़ फसल पानी से तबाह हो गई । The flood waters destroyed our standing crops and washed away our cattle. Punjab suffered a huge loss. But the Central Govt. did not give even a single rupee as compensation.

Sir, due to river Ghaggar, Punjab suffers a lot during annual floods. In 2023, the embankments of river Ghaggar were breached at 108 places. Major floods hit the State of Punjab last year.

पिछले साल मेजर फ्लडिंग हुई, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं दिया । ये यह जरूर कहेंगे कि राज्य सरकारों को करना होता है । हमारी राज्य सरकार तो ऐसी... है, हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि मरी हुई मुर्गी, बकरी का भी मैं मुआवजा दूँगा । वह मरी हुई फसल का तो क्या दे, मुर्गी, बकरी का तो क्या दे, हमने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा । न राज्य सरकार को परवाह है

और न ही सेंटर की सरकार को परवाह है । पंजाब के लोग कहाँ पर जायें, यह आज मैं इन दोनों से पूछना चाहूँगी ।

इसी तरह जब पानी कम होता है तो कहते हैं कि दूसरे राज्यों को दे दो, जब पानी ज्यादा हो जाता है तो डैम खोलकर हमारे यहाँ फ्लड कर देते हैं । एक तरफ पंजाब इरीगेशन की मार झेलता है, दूसरी तरफ इसका नाम तो पंजाब है, लैंड ऑफ रिवर्स, लेकिन पानी का इतना बुरा हाल है कि पंजाब का कोई शहर या गाँव नहीं होगा, जहाँ स्वच्छ पानी हो । मैं बठिंडा से आती हूँ । इस मंत्रालय की अपनी रिपोर्ट बताती है कि वहाँ का पानी इतना पॉइजनस है कि It is not fit for human consumption. उसके बावजूद, जहाँ वह पानी मानव के उपयोग के लिए फिट नहीं है, उससे जानवरों तक को कैंसर हो रहा है । अभी कोई माननीय सदस्य कैंसर एक्सप्रेस की बात कर रहा था, वह कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन मेरे निर्वाचन क्षेत्र से होकर जाती है । वह पानी इतना पॉइजनस है कि वह बहुत लोगों की जान लेता है । आपके पास गंगा एक्शन प्लान होगा । गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन पंजाब का पिछले 10 सालों में बजट में नाम तक नहीं आया है ।

सर, मैं आज आपसे अपील करना चाहती हूँ कि हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, जो हर साल तकरीबन एक मीटर ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है और पानी नहीं रहेगा तो पंजाब नहीं रहेगा, आप 5 हजार करोड़ रुपये का फंड दीजिए । हमें अपनी नहरों और खालों को मजबूत करने के लिए, कैनाल्स की मजबूती के लिए तीन हजार करोड़ का फंड दीजिए । मेरे निर्वाचन क्षेत्र और मालवा में जो पोटेबल वाटर नहीं है, उस वाटर की साफ-सफाई के लिए कोई ऐसा अर्जेंट प्लान बनाइए और फंड दीजिए । इसी तरह हमारा बीबीएमबी में जो मेंबर आपने हटा दिया है, वह मेंबर वापस बीबीएमबी के बोर्ड में डालिए । माइक्रो इरीगेशन के लिए फंड दीजिए ताकि पंजाब अपना पानी बचा सके । धन्यवाद ।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to participate in the Demands for Grants discussion under the control of the Ministry of Jal Sakti.

The biggest project of this Government after the formation of this Ministry is the Jal Jeevan Mission. Everybody now accepts that the Jal Jeevan Mission has become a big failure due to the mismanagement of this project. The Standing Committee critically evaluated the failure of this project in States like West Bengal, Rajasthan, Madhya Pradesh, Kerala, and Jharkhand. This Government is only

concentrating on publicity. The slogan, ?*Har Ghar Jal*?, is turning into ?*Har Ghar Vayu*? through pipelines, and that is all that is happening. For the proper implementation of this project, water source development is very important, as is the development of treatment plants and distribution. All these three aspects have seen significant failure under this Government, especially in the State of Kerala. Even though the Union Budget has extended the Jal Jeevan Mission?s deadline to the year 2028, the project in Kerala will remain incomplete unless the State mobilizes Rs. 17,250 crore by the year 2028. That is the truth. The sluggish project could come to a standstill if the State fails to clear outstanding dues of Rs. 4,500 crore to project contractors by March 31st this year. Due to this negligence and financial mismanagement in Kerala, only 57 per cent of the targets have been met as of February, and by this month, nearly 32.40 lakh families in the State are still waiting for water supply under the Jal Jeevan Mission. That is the reality. However, the Government have kept elected representatives like MPs away from the deliberations. This also should be rectified. My serious suggestion to this Government is that they should either fully fund the scheme and take full control of the implementation or at least adopt a 90 to 10 funding ratio, as is being done currently in the North-Eastern States.

Regarding the National Dam Safety Authority, I must point out some important issues here. It is very unfortunate that despite the Dam Safety Act coming into force on 30th December, 2021, the National Dam Safety Authority (NDSA), which is the crucial body constituted under the Act for ensuring the safe and secure operation of specified dams, has not become fully functional. As per the Demands for Grants, the National Dam Safety Authority was allocated Rs. 25 crore in the previous year, which has now been raised to Rs. 9.41 crore. In the present budget, it has been allotted Rs. 23.91 crore. However, nothing has taken place from the side of the NDSA. I would request that full utilization of the allocated amount be ensured for the better functioning of this organization.

According to Section 9(1), read with the second schedule, the duties of the NDSA are prescribed. These main duties include maintaining standards of dam

safety and preventing dam failure-related disasters by implementing the policies made by the National Committee.

Secondly, the NDSA should resolve any issues between the States? dam safety organizations or between a State dam safety organization and any owner of a specified dam in that State. Thirdly, it should maintain a national-level database of specified dams, including any serious distress conditions that may be notified. Fourthly, it should maintain relations with State dam safety organizations and the owners of specified dams for the standardization of dam safety-related data and practices, as well as provide related technical or management assistance. These are the main duties of the NDSA. However, the NDSA has not taken any steps in this direction, as mandated under the provisions, even after one year of coming into operation. Therefore, I am respectfully urging this Government that the NDSA should be competent enough to discharge its duties vested under the Dam Safety Act in connection with the Mullaperiyar dam in my constituency. This dam falls within the definition of a specified dam as defined under Section 2(x) of this Act. According to the court verdict on 8th April, 2022, the responsibilities and duties assigned by the hon. Supreme Court to the Supervisory Committee have gradually merged with the NDSA. However, neither the Government nor the authority has taken any steps to place the Mullaperiyar Dam under the control and surveillance of the NDSA in accordance with this Act.

19.00 hrs

In a Question answered on this floor, the hon. Minister has replied that the responsibility for comprehensive safety audit is not the duty of NDSA. It is quite unfortunate. It is the duty of NDSA. As per Section 16 of the Act read with proviso to Section 24(1), it is clear that the duty of NDSA is to keep perpetual surveillance, carry out inspection and monitor the operation and maintenance of a specified dam located in one State and operated by another State. So, it is the duty of NDSA.

In conclusion, I would like to mention that we are passing this kind of legislation for resisting disasters like dam breaking, but the biggest disaster like dam

failure will happen if we do not take precautions. Mullaperiyar is the biggest threat for the Kerala State. ? (*Interruptions*)

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI (SALEM): Sir, I object to this. ? (*Interruptions*)

ADV. DEAN KURIAKOSE : *The New York Times* pointed out that it will be a big disaster in which five million people will be the victims. ? (*Interruptions*)

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI: Sir, there is no danger to the Mullaperiyar dam. ? (*Interruptions*)

ADV. DEAN KURIAKOSE: It is not for debate. ? (*Interruptions*) It is a fact and a reality. ? (*Interruptions*)

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI: Sir, this is absolutely misleading. ? (*Interruptions*)

ADV. DEAN KURIAKOSE: The NDSA is having a definite role to solve these issues. ? (*Interruptions*) Hence, I am requesting here that the NDSA has to be strengthened. ? (*Interruptions*) Unfortunately, the NDSA has never visited this particular dam. ? (*Interruptions*) So, in this discussion on the Demands for Grants, I am humbly requesting to resolve this issue amicably for the safety of Kerala. ? (*Interruptions*)

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI: Sir, as regards the Mullaperiyar dam, the Supreme Court has said that the dam is safe. ? (*Interruptions*)

ADV. DEAN KURIAKOSE: We are ready to provide enough water for Tamil Nadu. ? (*Interruptions*) Safety is the only concern of Kerala. ? (*Interruptions*) Everybody has accepted it. ? (*Interruptions*) Hence, I would humbly request you to solve this issue. ? (*Interruptions*) Thank you. ? (*Interruptions*)

***m134 श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) :** सभापति महोदय, आपने हमें वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, जल ही जीवन है, यह हम सब जानते हैं । इसके बिना हम जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते । आज पूरे देश में जल संकट बना हुआ है ।

सभापति महोदय, भारत सरकार जल संसाधनों के संरक्षण, स्वच्छ जल, हर घर नल से जल और नदियों की साफ-सफाई, बाढ़ नियंत्रण आदि तमाम दावे करती है लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद भी धरातल पर वास्तविकता यह है कि आज भी देश में पीने योग्य स्वच्छ पानी का अभाव, भूजल में हो रही भारी गिरावट, जल प्रदूषण, हर साल आने वाली बाढ़ और शहरों के गंदे नालों से बहने वाले पानी और औद्योगिक कचरे को बगैर मानक ट्रीटमेंट के नदियों में बहाया जाना, आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है ।

महोदय, उत्तर प्रदेश सहित देश के करीब 20 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में मीठे पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य कई हानिकारक तत्वों का पाया जाना आज एक गंभीर चिंता का कारण बना हुआ है, जो फसलों, भोजन एवं पानी के माध्यम से लोगों के शरीर में पहुंच रहा है । देश के हर व्यक्ति को स्वच्छ एवं पीने योग्य पानी मिल सके, इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ।

महोदय, हमारा लोक सभा क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां के दोनों जिले आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आते हैं । वहां गांवों में जल शक्ति मिशन के तहत पानी की पाइपलाइन्स बिछायी जा रही है । इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे गांवों में खुदाई करके रास्ते को खराब कर दिया गया है, जिससे जगह जगह तमाम गड्ढे हो गए हैं, जिन्हे अभी तक भरा नहीं गया है । अभी भी यहाँ के कई गांवों में जल जीवन मिशन (हर घर नल से जल योजना) का कार्य शुरू नहीं हो सका है । इस मिशन के तहत बिछाई गयी पाइपलाइनों की मरम्मत और रख-रखाव ठीक से नहीं हो रहा है ।

महोदय, वर्तमान बजट में उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोई विशेष पैकेज की व्यवस्था नहीं की गई है जबकि मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली राप्ती नदी में लगभग हर साल बाढ़ आती है । इससे वहां के किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है, सैकड़ों गाव जलमग्न हो जाते हैं । बड़ी-बड़ी सड़कों के कट कर पानी में बह जाने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है । जगह-जगह बंध टूट जाने के कारण लोगों के घर नदी में समा जाते हैं और लोग बेघर हो जाते हैं । इससे लोगों की जान तक चली जाती है ।

सभापति महोदय, किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन की व्यवस्था नहीं है । उनके लिए नलकूप की व्यवस्था करायी जाए । हमने कई बार इस मुद्दे को सदन में पहले भी उठाया है, पर स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है ।

महोदय, राप्ती नदी के दोनों किनारों पर नए बांध बनाने, बांधों की मरम्मत करने और जहां जरूरत हो वहाँ बाधों को ऊँचा करने के साथ-साथ राप्ती नदी की गहराई से सफाई करने की जरूरत है । साथ ही भारत सरकार द्वारा एक टीम बनाकर उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती और बलरामपुर सहित देश के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराकर उनका स्थायी समाधान किए जाने की जरूरत है । बाढ़ के कारण होने वाले भारी जान माल के नुकसान के लिए उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए । बाढ़ के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को कम से कम 20 से 25 लाख रुपये सहायता अनुदान के रूप में दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए । साथ-साथ एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ । अभी हाल ही में मेरे लोक सभा क्षेत श्रावस्ती के जनपद बलरामपुर में विधान सभा बलरामपुर की ग्राम सभा चूल्हा भारी के पुरवा केवलपुर में लगी पानी की टंकी का लोकार्पण उत्तर प्रदेश सरकार के जलशक्ति मंत्री द्वारा किया गया था और लोकार्पण के कुछ ही दिन बाद पानी टंकी पूरी तरह से ढह गयी । जल शक्ति मंत्रालय बहुत बड़े दावे करता है, अगर इसी तरीके से देश की स्थिति रहेगी, तो जो लोग सोचते हैं कि उन्हें पानी स्वच्छ मिलेगा, सरकार पीने के पानी की व्यवस्था कर रही है, वह कैसे हो पाएगा?

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक संसद सदस्य को कम से कम दो हज़ार हैंडपंप देने की ज़रूरत है ।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ ।

जल है तो जीवन है और जीवन है तो कल है और हवा के बाद अगर किसी भी प्राणी मात्र को जीना है तो उसके लिए जल की अत्यंत आवश्यकता है । व्यक्ति हो या पशु-पक्षी हो, उनको भी पानी की बहुत आवश्यकता, जीवन जीने के लिए है ।

महोदय, मैं इस सम्मानित सभा के समक्ष जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ । जल संसाधन प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और हमारी नदियों के संरक्षण के लिए यह मंत्रालय अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । आज मैं मंत्रालय की प्रमुख पहलों, उनकी उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए इन अनुदान मांगों के समर्थन में अपनी बात रखती हूँ ।

रामजल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से पूर्वी राजस्थान के जिलों को जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना की शुरुआत की गई है । यह परियोजना चंबल बेसिन के भीतर जल के अंतर्बेसिन स्थानांतरण की परिकल्पना करती है, जिससे 2.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और 13 जिलों में पेयजल और औद्योगिक जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी । माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में 46,300 करोड़ मूल्य की इस परियोजना की आधारशिला रखी थी । इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ ।

वर्ष 2019 में शुरू किया गया जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर नल का जल उपलब्ध कराना है । इस मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन जो अप्रैल 2024 तक बढ़कर 75.97 पर्सेंट हो गया है । जिसमें आठ राज्य और तीन संघ प्रदेशों को 100 पर्सेंट कनेक्शन दिए गए हैं ।

महोदय, इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 67,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट से 195 प्रतिशत अधिक है । यह दर्शाता है कि सरकार जल को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है । जल संकट को गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठा गए हैं । पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) एक माइलस्टोन प्रयास है, जिसका उद्देश्य चंबल नदी से पूर्वी राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी लाना है । इससे राज्य भर के करोड़ों लोगों को लाभ होगा । यह परियोजना न केवल शहरी और ग्रामीण आबादी को पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, बल्कि कृषि भूमि के विशाल क्षेत्रों के लिए सिंचाई सुविधाएँ भी प्रदान करेगी । ईआरसीपी जीवन को बदल देगी । हमारे कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करके खाद्य सुरक्षा को बढ़ाएगी, जो हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है ।

महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सुरक्षित पेयजल कार्यक्रम के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 1.36 लाख बच्चों की मृत्यु को रोका जा सकता है । वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है । राजस्थान में प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में सूर्य की रोशनी उपलब्ध है और यहाँ विशाल खुले स्थान हैं, जिनका उपयोग वर्षा जल संचयन, छत पर जल संग्रह प्रणाली और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है ।

महोदय, जल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग- उपग्रह मानचित्रण, रिमोट सेंसिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग जल संरक्षण, प्रबंधन और वितरण के

लिए बेहतर समाधान प्रदान कर सकता है । ये प्रौद्योगिकियां वास्तविक समय में जल गुणवत्ता की निगरानी करने में भी मदद कर सकती हैं ।

महोदय, स्वच्छता जल संसाधन प्रबंधन का अभिन्न हिस्सा है । वर्ष 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत वर्ष 2019 तक देश के सभी गाँवों को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया । अब मिशन के दूसरे चरण में सरकार सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रतिबद्ध है ।

महोदय, वर्ष 2025-26 के बजट में SBM-G के लिए 7,192 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है । आज 96 प्रतिशत गाँवों ने ODF Plus का दर्जा प्राप्त कर लिया है और 73 प्रतिशत गाँव ODF Plus मॉडल के रूप में विकसित हो रहे हैं । यह दर्शाता है कि हमारी सरकार न केवल जल आपूर्ति बल्कि स्वच्छता पर भी उतना ही ध्यान दे रही है ।

महोदय, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण से खुले में शौच की प्रथा में कमी आई है, जिससे जल स्रोतों की स्वच्छता में सुधार हुआ है । आगामी वित्तीय वर्ष में मंत्रालय की योजना है कि जल जीवन मिशन के तहत शेष बचे घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाएं । इसके अलावा, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा की सहायक नदियों के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा । रामजल सेतु लिंक परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय और तकनीकी संसाधनों का प्रावधान किया जाएगा ।

माननीय सभापति महोदय, जल शक्ति मंत्रालय की ये पहलकदमियाँ हमारे देश के जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । इन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन से न केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल की उपलब्धता में सुधार होगा, बल्कि स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में वर्तमान में भूजल स्तर को बढाने हेतु जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, विश्व बैंक वित पोषित पूर्णत: अनुदान आधारित भूजल प्रबंधन योजना राज्य के 16 जिलों के 38 ब्लॉक्स की पूर्ण चिन्हित 1129 ग्राम पंचायतों को पायलट आधार पर चिन्हित किया जा रहा है । यह योजना देश के 7 राज्यों सहित राजस्थान में 1 अप्रैल, 2020 से 5 वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 2025 तक क्रियान्वित की जा रही है । योजना का उद्देश्य समुदाय आधारित जल सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से समुदाय को जलृ प्रबंधन के मामले में स्वालम्बी बनाता है । जन समुदाय आधारित भूजल प्रबंधन में ग्राम पंचायत क्षेत्रीय जिला सुरक्षा योजनाओं में प्रस्तावित जल भाग एवं जल आपूर्ति कार्यो को केन्द्र और राज्य सरकार के

सहयोगी विभागों की जल केन्द्रित कार्य योजनाओं के कन्वर्जनस के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है । योजना की विशिष्ठ पहलू यह है कि 'परिणाम के लिए कार्यकम' योजना पायलट आधार पर लागू की गई है । अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन से जन समुदाय में भूजल प्रबंधन को अपनाने एवं बेहतर परिणाम मिलने के अवसर बढ रहे हैं । ग्राम जल स्वच्छता समिति अटल भूजल योजना क्रियान्वयन में सरकार का विभागों एवं जन समुदाय के मध्य मुख्य सेतू का कार्य करना है ।

महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगी । अटल भूजल योजना में विगत 4 वर्षों में क्रियान्वयन के आंकलन पर आरम्भिक परिणाम यह दर्शाता है कि राज्य के 6 जिलों के 8 ब्लॉक्स में 189 गाम पंचायतों में भूजल स्तर की गिरावट में कमी आई है । इससे भूजल में सुधार भी होगा ।

महोदय, अंत में मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से कहना चाहती हूं कि जल की समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं को उठानी पड़ती है । आज हर घर में नल से जल आ रहा है । मैं उन सभी बहनों की तरफ से बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहती हूं । हमारी हर बहन सिर पर मटके रखकर दूर से पानी लाती थी और घरों में तीन-चार मंजिलों से पानी लेकर आती थी । उनकी तरफ से मैं सरकार का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद करती हूं ।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सभापति महोदय, धन्यवाद । जिस देश ने नदियों को सिर्फ नदी समझा, भगवान नहीं माना, वहां नदी अच्छी भी रही, उस नदी ने दुनिया को जीवन भी दिया और उस देश ने उस नदी को अपने जीवन के लायक बनाया । जिस देश ने नदियों को भगवान मान लिया, वह नदी उस देश में मैली हो गई । यमुना, गंगा, कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सप्तकोशी, मेची, सोन आप जितनी नदियों का नाम लेंगे, हिंदुस्तान की वे नदियां स्नान करने के लायक नहीं है ।

सभापति महोदय, हमारे देश में 90 प्रतिशत बीमारियां पानी के चलते हो रही हैं । हमारे यहां आर्सेनिक और आयरन वाला पानी है । यह देश पांच सौ साल पुरानी कब्र को खोदेगा, लेकिन यह देश स्वच्छ पानी पर, स्वच्छता पर काम नहीं करेगा, यह देश हवा पर काम नहीं करेगा, यह देश आर्सेनिक और आयरन पर काम नहीं करेगा । आप दूसरे देश में जाइए, वहां मिनरल वाटर नहीं के बराबर मिलेगा । वहां की नदी, वहां का पानी बिल्कुल साफ मिलेगा, क्योंकि वहां हिंदू, मुसलमान नहीं हैं, वहां जात-पात नहीं है, वहां पर मणिपुर नहीं है,

वहां पर साउथ-नार्थ नहीं है । वहां एक कंट्री है और कंट्री के लिए काम किया जाता है, वहां पर इकोनॉमी के लिए काम किया जाता है ।

महोदय, जो बाढ़ आती है, यह प्राकृतिक प्रकोप नहीं है, यह मैन मेड डिजास्टर है । मैं कोसी नदी वाले क्षेत्र से आता हूं । मेरे इलाके में 13 नदियां हैं । जल-नल योजना, नमामि गंगे कार्यक्रम, जल शक्ति योजना, अटल भूजल योजना, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत काम हो रहा है । अटल जी ने नदी जोड़ने की बात कही थी । नरेन्द्र भाई मोदी जी ने कहा कि गंगा मैया ने मुझे बनारस बुलाया है । आज 11 सालों में दिल्ली की यमुना साफ नहीं हुई । दिल्ली में यमुना के नाम पर कितने चुनाव हो गए? गंगा सफाई के नाम पर प्रधान मंत्री जी तीन बार बनारस के प्रधान मंत्री हो गए । यदि आप बनारस के पानी को जाकर देखेंगे तो वहां की गंगा इतनी प्रदूषित है, जिसके बारे में आप कह नहीं सकते ।

बिहार के बक्सर से लेकर पटना और पटना से लेकर पूरा का पूरा जो इलाका है, उसमें तीन हिस्सा डिजास्टर से प्रभावित है, हमारा तीन हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है । फरक्का एक तरफ है, तो भीम नगर बैराज दूसरी तरफ है । कई बार यह चर्चा हुई कि फरक्का बैराज को नवीनीकरण करके चौड़ा किया जाएगा । कोसी सबसे विकराल नदी है । नदी पहले वरदान होती थी, अब वह नदी अभिशाप बन गई है । नदी हमारे लायक नहीं है, नदी जिंदगी को समाप्त कर रही है । एक तरफ जल जमाव है, तो दूसरी तरफ बाढ़ है । जब हम नदी के गाद की सफाई की बात करते हैं तो आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं । 80 प्रतिशत नदी और कैनाल का पक्काकरण नहीं हुआ है । बड़े कैनाल को छोटे कैनाल में ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

महोदय, डैम बनाने की बात की जाती है, जहां पर तीन हजार मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा । नेपाल द्वारा इस बार 6 लाख 61 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया । यदि यह 7 लाख क्यूसेक पार कर गया होता तो कोसी, सीमांचल का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचता । 7-8 लाख क्यूसेक पानी गया तो हम लोग डूब गए । नेपाल के पानी का पूरा का पूरा प्रेशर भीम नगर बैराज पर पड़ा हुआ है । भीम नगर बैराज कभी भी टूट सकता है, लेकिन इसकी चिंता नहीं है । हमें हाई डैम बनाने पर जोर देना चाहिए । मैं अब पॉइंटवाइज कुछ बात कहूंगा ।

महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, हमारे इलाके के तीन हिस्से बाढ़ से प्रभावित है, एक तरफ हमीदनगर है, उत्तर कोयल परियोजना जो बनकर तैयार है, लेकिन औरंगाबाद और जहनाबाद में पानी नहीं जा रहा है । जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और उसको समझने की

जरूरत है । जहानाबाद और अरवल में पानी हमीदनगर पुनपुर परियोजना के तहत मिलना था, जिसे स्वर्गीय जगदेव बाबू लाए, लालू जी और नीतीश जी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया । अरवल, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद में आज तक पानी नहीं गया, इस पानी को पाइप के द्वारा नालंदा ले जाने की बात हो रही है ।

महानंदा बेसिन की स्थिति क्या है? महानंदा बेसिन परियोजना बहुत ही गलत परियोजना ली गई है । यदि बड़ा बांध बन गया तो महिनहारी, बारसोई, बायसी, अमौर और रौटा के दस लाख किसान बर्बाद हो जाएंगे । कोसी मेची लिंक परियोजना के बारे में एक रिक्वेस्ट करूंगा, डीपीआर के मुताबिक परियोजना कार्य करेगी, लेकिन कोसी मेसी परियोजना की स्थिति बहुत बुरी है । मैं आग्रह करना चाहूंगा, कोसी मेची परियोजना में जब तक सिलटिंग नहीं निकालिएगा, जल जमाव बना रहेगा, जब तक पक्कीकरण नहीं करेंगे, आप काम ठेकेदार को देंगे ।

नल जल योजना में नब्बे प्रतिशत पूर्णिया, कोसी और मधेपुरा के बारे में बताना चाहता हूं । मैं इसकी लिस्ट दे देता हूं, आप आर्डर कर दीजिए । आप से रिक्वेस्ट है कि नल जल योजना के तहत नब्बे प्रतिशत गरीब के घर में पानी नहीं गया है । जल नल योजना की जांच जेपीसी के द्वारा कराएं, जो काम ठेकेदार ने किया है, उसकी इनक्वायरी कराएं । धन्यवाद ।

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा (सिक्किम) : सभापति महोदय, जल शक्ति मंत्रालय के डिमांड फॉर ग्रांट्स के डिस्कशन पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद । सबसे पहले जल शक्ति मंत्रालय के माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं । जिस तरह से भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय को प्रायोरिटी दिया है, इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स लेकर आए हैं । मुझे लगता है कि जल शक्ति मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक विजन को आगे बढ़ा रहे हैं । माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा मिशन रहा है । हर घर नल से जल पहुंचाने का जल जीवन मिशन है, इसके इम्पलीमेन्टेशन के लिए 67 हजार करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया है, इसका यूटिलाइजेशन सही रूप में हो जाएगा तो हर घर के नल में जल पहुंचेगा । इसमें एक ही मिशन, एक ही पॉलिसी, भारत इतना डाइवर्स कंट्री है कि हमारे ज्योग्रॉफिकल एरिया में विभिन्न जगहों पर प्रॉबल्म्स रहता है ।

मैं एक हिमालयी राज्य से आता हूं, ज्यादातर जितने भी स्प्रिंग होते हैं, जितनी भी धारा होती है, उसी के पानी से हम आजीवन चलाते हैं । जितने भी ड्रिंकिंग वॉटर के सोर्सेज होते हैं, ये ज्यादातर 90 परसेंट स्प्रिंग वॉटर से ही होता है । अभी एक प्रॉबल्म आया है, हम दिशा की मीटिंग करते हैं, जब कंस्टीट्यूएंसी में लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो

हमें समझ आता है कि जल जीवन मिशन का इम्पलीमेन्टेशन अच्छे से हुआ है, इसके लिए पानी का टैंक बना दिया गया, पाइप लेइंग ठीक से हो गया । घरों में नल भी पहुंचा दिया, लेकिन पानी का जो पेरिनिएल सोर्स होना चाहिए, अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पेरिनिएल सोर्स नहीं रहा । लीन पीरियड में ज्यादातर धारा सूख जाती है, इसकी वजह से पानी नहीं रहता है ।

इसको रिजुविनेट करने के लिए धारा विकास और स्प्रिंग से डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, उसको जल शक्ति मंत्रालय पहाड़ी इलाकों में ज्यादा फंड देकर कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि जितने भी स्प्रिंग्स हैं, जितनी भी धाराएं हैं, उनको हम रिजुविनेट कर सकें । लीन सीजन में भी उसमें पानी आए और वह पैरेनियल सोर्स ऑफ वाटर बने । अभी 50 प्रतिशत से ज्यादा धाराएं सूख चुकी हैं । इस इश्यू के लिए हम दूसरे मंत्रालय से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहां-जहां भी जिस गाँव में, जैसे सिक्किम में भी हमारे रेन शैडो एरियाज हैं, वहां स्प्रिंग वाटर भी नहीं होता है । वहां पीने का पानी बहुत दूर से लेकर आना पड़ता है । ग्लेशियर लेक और जितने भी बड़े-बड़े रिवर्स हैं, वहां से लेकर आना पड़ता है । उसमें ज्यादा खर्च होता है । ?जल जीवन मिशन? में कॉस्ट इफेक्टिव डीपीआर बनाने के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास ज्यादा कॉस्ट का डीपीआर बनाने के लिए भेजा जाता है तो उसको खारिज कर दिया जाता है । इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल जीवन मिशन के ऊपर भी हमारी पार्लियामेंट्री कांस्टिट्यूएंसी सिक्किम के जितने भी रेन शैडो एरियाज हैं, जहां पानी का ज्यादा अभाव है, वहां पर ग्लेशियर लेक से पानी लाने के प्रोजेक्ट में सहयोग किया जाए ।

सर, ?स्वच्छ भारत मिशन? में, हमें कहते हुए गर्व और खुशी होती है कि सिक्किम ने हमेशा टॉप किया है । ?स्वच्छ भारत मिशन? में जब ओडीएफ आया तो उसमें भी फर्स्ट किया । वर्ष 2023 में ओडीएफ प्लस में भी सिक्किम ही पहला राज्य था, जो ओडीएफ प्लस हुआ था ।

अभी प्लास्टिक मैनेजमेंट की बात आई है । सिक्किम में हमने कई सालों से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर रखा है । वहां अभी दो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट पदमसेन और योक्सॉन में अच्छी तरह से संचालित हो रहे हैं । वे अपना ओन सोर्स रेवेन्यु बनाते हैं । ? (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं एक मिनट ज्यादा लूंगा । इसको सारे देश में रिप्लिकेट किया जा सकता है । इस तरह के जो भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको सुविधा के लिए उनको थोड़ा ऑनरेरियम देकर ट्रेंनिंग के लिए लिया जा सकता है ।

महोदय, जो रिवर मैनेजमेंट और फ्लड मैनेजमेंट की बात है, रिसेंटली वर्ष 2023 में सिक्किम में एक बड़ा फ्लैश फ्लड हुआ था । अचानक गल्फ हो गया । ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से फ्लैश फ्लड हुआ था । उसकी वजह से सिक्किम को बहुत नुकसान झेलना पड़ा । आज भी वहां रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है । उसने कई सारे रोड्स वाश-आउट कर दिए थे । उसने कई सारे ब्रिजेज वाश-आउट कर दिए थे । आज भी उन सबके रिपेयरिंग का काम चल रहा है । जीएलओएफ मिटिगेशन के लिए इस बजट में बताया गया है कि पिछले साल 150 करोड़ रुपये का प्रावधान चार स्टेट्स के लिए और हिमालयन राज्यों के लिए किया गया था । मुझे लगता है, मैं मंत्रालय से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 150 करोड़ रुपये कहीं भी जीएलओएफ मिटिगेशन के लिए पर्याप्त नहीं होगा । हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मंत्रालय से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस राशि को बढ़ाया जाए और जीएलओएफ मिटिगेशन के लिए तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी अधिक फंड का प्रावधान किया जाए । बिहार और असम में जो फ्लडिंग होती है, वह भी कहीं न कहीं जीएलओएफ से जुड़ा हुआ है । आज जितने भी ग्लशियर लेक्स हैं, वे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतने ज्यादा एक्सपैंड हो गए हैं कि वे कभी भी भारत में एक आपदा बनकर आ सकते हैं । हम इसके लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं ।

महोदय, जितने भी तिस्ता और रंगीत के बेसिन्स हैं, उनको भी रिजुविनेट करने का प्रयास किया जाना चाहिए । हमारे सारे टाउन्स तिस्ता और रंगीत रिवर बैंक्स में ही हैं । उनके प्रोटेक्टिव काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और मंत्रालय को थोड़ा ध्यान देना चाहिए । मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

***m138 श्री जयन्त बसुमतारी (कोकराझार) :** महोदय, मैं आज अपनी पार्टी की ओर से जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर हो रही चर्चा के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में देश ने बहुत प्रगति की है । हर विभाग में उल्लेखनीय काम हुआ है । जल शक्ति मंत्रालय भी उनमें से एक है । जब इरादे ईमानदार होते हैं, तो उपलब्धियां निश्चित होती हैं । इस वर्ष जल शक्ति मंत्रालय को 99,503 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जबकि यूपीए सरकार ने वर्ष 2013-14 में 17,342 करोड़ रुपये दिए थे । आज मोदी जी की सरकार ने 99,503 करोड़ रुपये की कुल राशि आवंटित की है । वर्ष 2013-14 से छः गुना ज्यादा धनराशि दी गई है । मैं आशा करता हूं कि इस धनराशि से हमारे देश में जल संसाधन पर जितना भी काम होना है, निश्चित तौर पर वे काम होंगे ।

जल जीवन मिशन ? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते पांच सालों से एक ऐसी स्कीम चलाई गई है, जिसने आम लोगों की जिंदगी को काफी प्रभावित किया है । खासकर महिलाओं के जीवन में खुशहाली आई है और होठों पर मुस्कान ला दी है । इस योजना के लॉन्च होने के बाद इसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल कर रख दी है । करोड़ों लोगों के घरों में सीधे नल से जल पहुंच रहा है । पीने के पानी के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं की रोज की जिदंगी में बदलाव आया है । उत्तर पूर्व के राज्यों को भी इस योजना का बहुत लाभ मिला है । पहले स्कूल तथा आंगनवाड़ियों में पीने के पानी का अच्छा इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से बच्चों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था । आज वहीं यह साबित हो गया है, जहां-जहां स्कूल्स, कॉलेजेज़ या आंगनवाड़ियों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीने का पानी उपलब्ध है, वहां पर बच्चों और लोगों के स्वास्थ्य में भारी सुधार हुआ है ।

स्वच्छ भारत मिशन ? स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए इस मिशन के माध्यम से देश में साफ-सफाई और बीमारियों से मुक्ति में बहुत सहायता मिली है । सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 02 अक्टूबर, 2014 को ?स्वच्छ भारत मिशन? की शुरुआत की थी । इस मिशन को राष्ट्रवादी अभियान यानी जन आंदोलन के रूप में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना था । ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2014 से 2019 के दौरान बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन, घरेलू स्वामित्व और सामुदायिक स्वामित्व वाले शौचालयों का निर्माण हुआ है । इस योजना से पूरे देश में सफाई और स्वच्छता में बहुत सुधार हुआ है । आज कहीं भी खुले में शौच करने का चलन नहीं रहा है और लोगों की मानसिकता में भी बहुत सुधार हुआ है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी से आह्वान करना चाहता हूं कि बाढ़ और भूमि कटाव दोनों बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जो पूर्वोत्तर के सभी राज्य, खासकर असम और मेरे संसदीय क्षेत्र कोकराझार में तो भूमि कटाव से आधे से अधिक खेती योग्य जमीन बह चुकी है और किसानों को हर साल भारी नुकसान होता है । बोडोलैंड में भूटान से आए हुए पानी के साथ-साथ बड़े-बड़े पत्थर और सिल्ट आती है, जिससे खेती योग्य जमीन भी खत्म हो रही है और किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है ।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि पूर्वोत्तर में हर वर्ष आने वाली बाढ़ और भूमि कटाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और यहां के लोगों के पुनर्वास के लिए और अधिक उपाय किए जाएं । आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी ।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : सभापति महोदय जी, मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्य इतनी देर तक बैठकर जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं । मैं सदन की सहमति चाहता हूं, अगर आप सभी सहमत हैं, तो हम नौ बजे तक सदन चलाएंगे । हमने आठ बजे के बाद सबके लिए डिनर भी अरेंज किया है । आप सभी डिनर पर आमंत्रित हैं ।

माननीय सभापति : अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय 9 बजे तक बढ़ाया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

माननीय सभापति : ठीक है ।

SHRI PHANI BHUSAN CHOUDHURY (BARPETA): During the discussion on the Demands for Grants of the Jal Shakti Ministry, I would like to speak on some problems faced by our state. Hon'ble Chairman Sir, please don't press the bell.

I will conclude within 5 to 7 minutes because if you press the bell, my concentration might get distracted. Hon'ble Chairman Sir, the total land area of our state is 78,438 square kilometres. The National Flood Commission, after conducting a survey, has stated that Assam's 31,500 square kilometres are flood-prone area, which means that 39.5% of Assam's land is flood-prone.

The total flood-prone area of our country is 10.2%, while 39.5% of our state are flood-prone. If we compare the average of our country, Assam's flood-prone area is four times higher than that of the entire country. These figures show how serious the problem of flood is for the state of Assam. The number of villages in Assam is 26,395. In 2022-23, the number of flood-affected villages were 11,227. In 2023-24, the total number of affected villages were 3,094. In 2024-25, 7,747 villages were affected by devastating floods.

Hon'ble Chairman Sir, we have 64 lakh households in Assam. Among these households, in 2022-23, the total number of affected households were 1,08,444. These figures show how many people have been terribly affected by the furious

floods in Assam. If we look at the death toll, we will find that during the period 2019-24, a total number of 880 people lost their lives in floods. Altogether, 9,901 houses have been completely damaged in Assam floods, and the number of houses that have been partially damaged are 1,38,441. All these figures depict how badly our state has been affected by floods.

I would like to speak a few words on erosion as well. Since 1950, Assam has lost over 4.27 lakh hectares of land to riverbank erosion, which means 7.47% of the total land of Assam has been washed away due to erosion. If we look at this grim picture, we will find that, on average, 8,000 hectares of land are being washed away by floods in Assam every year.

Sir, I will take 2 minutes. It may be mentioned that a survey was conducted on the river Brahmaputra during the period 1912-1928. At that time, the total area of the river Brahmaputra was 3,817 square kilometres. In 1963, 1967, and 1975, when surveys on the Brahmaputra were conducted, it was found that the total area of the river Brahmaputra was 4,850 square kilometres. Again, in 2006, another survey was conducted, which showed the total area of the river Brahmaputra as 6,080 square kilometres. All these figures contribute only to the Brahmaputra River's widening, and its overall size increase. Erosion has caused the widening of the river Brahmaputra by 2,210 square kilometres. In fact, the size of the river Brahmaputra has increased by 15 kilometres.

I am very happy to say that in the last Budget, the Hon'ble Finance Minister made certain announcements, and I quote, "Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River and its tributaries originating outside India. We will provide assistance to Assam flood management and related projects." We thank the Hon'ble Finance Minister. We want a permanent solution to Assam's flood and erosion problems. We all give the slogan, "Modi Hai to Mumkin Hai." So we hope that under the leadership of Prime Minister Modi Ji, there will be a permanent solution to Assam's perennial problems of flood and erosion. We have full faith in the Hon'ble Prime Minister Modi Ji. Assam has received many benefits from the Modi Government. The Congress, despite being in power for so many years, could

do nothing. If we compare the Congress rule and BJP's rule at the Centre, we will find a vast difference between the two. That is why I request the government under the leadership of Modi Ji to solve Assam's flood and erosion problems permanently.

With these words, and thanking you for giving me an opportunity to speak, I conclude. Thank you.

***m141 श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) :** माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2025-26 के लिए जलशक्ति मंत्रालय को 99503 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया है, जो पिछले बजट से अधिक है, लेकिन फिर भी कम है । जल संसाधन विभाग को 25277 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । जिसमें प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8260 करोड़ रुपये, नदी जोड़ो परियोजना के लिए 3400 करोड़ रुपये और नमामि गंगे परियोजना के लिए 2400 करोड़ रुपये शामिल हैं । लेकिन देश भर के रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट को देखा जाए तो यह फंड कम है ।

माननीय सभापति महोदय, देश भर की नदियों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया था । अपने कार्यकाल में यह निर्णय लेते हुए भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । जबकि देश भर की नदियों के पानी को समुद्र में गिरने की बजाय डायवर्ट करके यूज़ किया जाए तो मुझे लगता है कि कृषि सिंचाई एवं पीने के पानी की समस्या दूर हो सकती है । लगभग 30 प्रतिशत पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है । आज देश भर में नदियों की हालत देखी जाए तो एक भी नदी का पानी पीने के लायक नहीं है और यूज़ करने के लायक नहीं है ।

राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाली महानगर पालिका, नगर पालिका और जिला परिषद् द्वारा नदियों को स्वच्छ रखने का कार्यक्रम हाथ में लिया जाए, तो मुझे लगता है कि नदियों का प्रदूषण दूर हो जाएगा । नदियों का पानी स्वच्छ रखने के लिए आगे चलकर जन आन्दोलन की आवश्यकता है ।

महोदय, मोदी जी के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के लिए हर घर जल-स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का मिशन 2019 में शुरू किया गया था । यह योजना 2024 तक पूरी करनी थी तथा 19 करोड़ लोगों के घर में स्वच्छ जल देने का कार्यक्रम था । यह योजना राज्य सरकारों के नियंत्रण में काम करती है और इस योजना का DPR जब बनाया जाता है, तो गलत ढंग से DPR बनाया जाता है । उसमें एस्टीमेट कॉस्ट, टंकी की कॉस्ट को शमिल नहीं किया जाता है । यह योजना आज पूरी तरह से असफल हुई है

। मुझे लगता है कि यह योजना केवल ठेकेदारों की जिम्मेदारी पर चलती है । राज्य सरकारों की उदासीनता के कारण यह योजना असफल हुई है । इसमें जितना फंड राज्य सरकारों को दिया गया है, उसका पूरी तरह से ऑडिट होना चाहिए और इस योजना को गलत ढंग से अमल करने वाले अधिकारियों व ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए ।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत पवना, इंद्रायणी, मुळा, मुठा और उल्हास नदियाँ आती है, लेकिन ये नदियाँ पूरी तरह से प्रदूषित हैं । पिंपरी, चिंचवड़ महानगर पालिका ने पवना और इंद्रायणी नदी सुधार हेतु एक DPR बनाकर राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को भेजा है । इसमें पवना रिवरफ्रंट विकास परियोजना का प्रस्ताव तैयार कर अपने कोष से 343.66 करोड़ रुपये आवंटित करने का भी आश्वासन दिया है । इसका प्रस्ताव राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय को राज्य सरकार के माध्यम से भेजा है, लेकिन आज तक इसको मंजूरी नहीं मिली है । इंद्रायणी नदी सुधार हेतु अमृत-2 योजना के अंतर्गत 526 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है और यह अंतिम मंजूरी हेतु केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है । मुझे लगता है कि इसे जल शक्ति मंत्रालय मंजूरी दे, तो यह जल्द ही पूरी हो जाएगी ।

महोदय, इंद्रायणी नदी का उद्गम स्थान मेरे चुनाव क्षेत्र से होता है और यह नदी देहु आलंदी तीर्थ क्षेत्र से गुजरती है । जब वारी पंढरपुर तक चलती है, तब अपनी मन की बात में प्रधान मंत्री जी ने इसका उल्लेख भी किया था । मुझे लगता है कि देहु आलंदी के वारकारी, जो इसमें स्नान करते हैं और पानी का आचमन करते हैं, इस हेतु जल्दी से जल्दी यह प्रस्ताव मंजूर किया जाए । मैं आशा करता हूँ कि इंद्रायणी नदी सुधार हेतु अमृत 2 में दिए गए प्रस्ताव को जल्दी से जल्दी मंजूरी दी जाएगी ।

महोदय, अतः मैं यह मांग करता हूँ कि पवना और इंद्रायणी नदी संरक्षण योजना को केंद्र सरकार शीघ्र मंजूरी प्रदान करें, जिससे हम अपनी नदियों को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और समृद्ध पर्यावरण सुनिश्चित कर सकें । धन्यवाद ।

SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE (SHIRDI): Hon. Chairman Sir, thank you very much for allowing me to speak on Demands for Grants of Jalshakti Ministry for 2025-26. This year, total allocation made is Rs. 99503 crore and it was around Rs. 98714 crore during 2024-25.

I think, considering the talent and competence of Hon. Minister Shri C.R. Patil ji. This is very less budget allocation for the Ministry and the Union Govt. must look into it. The total allocation for Jal Jeevan Mission is also very less.

Sir, I would like to draw your kind attention towards various issues pertaining to my Lok Sabha constituency, Shirdi. Water scarcity is a prominent issue in Shirdi. People have to fight for each drop of water. There is no water available for farming here. Niti Aayog had explained in last year?s report that 60 crore people in India are facing drinking water scarcity problem and demand for water would be doubled till 2030. Around 2 lac people are loosing their lives due to contaminated water every year and this is a matter of grave concern for all of us.

Most of the parts of India are drought ridden but on other side, some rivers have more water. We have sufficient rain ever year but we lack in rain water harvesting and water management. This rain water flows to drains and create water scarcity. To tackle this problem, interlinking of river is a welcome step. River Basins and ravines of Mula, Pravara, Godavari and Tapti river in Sahyadri mountain range should be interlinked. These rivers have their origin in this area and river water flows towards west Konkan region. We can stop and store this water in reservoirs and dams and prevent it from flowing into sea.

In this regard, a detailed action plan should be fixed at local level and it should be implemented effectively.

Sir, I want to raise a serious concern about Jal Jeevan Mission Scheme. Some MPs talked about its success. But the reality is very different. I want to flag the irregularities and corruption under this Scheme. This Scheme is being implemented even in those areas where no water source is available. It would be shown completed on paper but, without developing any water bodies.

Govt. should undertake a survey of these works because rampant corruption is everywhere. They are only spending public money which is siphoned off. I would request Hon. Minister to take it seriously.

It is pertinent to mention here that most of the Gram Panchayats are financially weak and they are not in a position to pay electricity bills. No village can ensure water supply without electricity and this is reality. So, Union and State

Govts. should come forward to pay these electricity bills for uninterrupted water supply in villages.

There is a small town called Kopargaon in my constituency and it is still deprived of water connections. The villagers are leaving this town. So, the Govt. should take an initiative to secure water supply here. You can draw water from the dams in Nashik district. British Era canals are there in this area and they should be repaired immediately.

One big dam is also there but people have many concerns about it. These concerns should be addressed immediately. Irrigation facilities should also be made available. These are some geographical problems too and ground leveling is needed. So, the concerned officers should look into it.

Left and Drip irrigation is also important and it should also be promoted by the Ministry.

Sir, equal water distribution should be done by the Govt. 8TMC water has been diverted towards other regions and hence, farmers in my area are facing irrigation problems. A Committee has been constituted in this connection and I hope this Committee would look into it.

The Union Govt. should take water scarcity issue seriously and take necessary steps immediately.

Thank you.

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, मैं जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए अवसर दिए जाने पर आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । सबसे पहले मैं अपने प्रयागवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, माननीय जल शक्ति मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र खासकर प्रयागराज में अभी जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, माननीय जल शक्ति मंत्री माननीय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष भूमिका रही, जिनके कारण यह आयोजन सफल हुआ है । निश्चित रूप से हम इस बात की भी सराहना करना चाहते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय तमाम

परियोजनाओं के माध्यम से इस देश को विकसित देश बनाने के क्रम में आगे बढ़ रहा है । अभी हम कांग्रेस के साथी की बात सुन रहे थे । वे कह रहे थे कि जल शक्ति मंत्रालय का बजट और ज्यादा होना चाहिए था, इसका बजट कम है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जब वर्ष 2013-14 में यूपीए की सरकार थी, उस समय जल शक्ति का मंत्रालय का बजट करीब 17,342 करोड़ रुपए था । इस बार का जो बजट पेश हुआ है, वह निश्चित रूप से एक गुना, दो गुना नहीं, बल्कि 6 गुना से ज्यादा है । इस बार के बजट में 99,503 करोड रुपए आवंटित हुए हैं । इसके लिए हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहेंगे । निश्चित रूप से हमारे कई साथियों ने इस बजट पर चर्चाएं की हैं, लेकिन हम आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां कुंभ के आयोजन से पहले जल शक्ति मंत्रालय ने कई बड़े-बड़े कार्य किए हैं, ताकी संगम, त्रिवेणी, गंगा का जल स्वच्छ रहे, उसके लिए रिवर फ्रंट बनाया गया, जो कि दारागंज से होते हुए नागवासुकी, नागवासुकी से होते हुए सीधे रसूलाबाद घाट तक और हमारे यहां गऊघाट से लेकर, हमारे भाई, उज्ज्वल रमण सिंह जी भी यहां उपस्थित हैं, उनके क्षेत्र में भी, नैनी साइड में अरैल से लेकर पूरे डीपीएस तक रिवर्स फ्रंट का निर्माण हुआ, जो निश्चित रूप से जल मंत्रालय का यह सराहनीय कदम रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में ग्राम सभा ढोकरी, लीलापुर कला, लीलापुर खुर्द, मलखानपुर, कोटवा, जमुनीपुर बेलवार, डुबावल, ककरा और पट्टी वैरिसाल, छिवैया, मुरार पट्टी और अगर हम दूसरे इलाके में जाएं तो हमारा जो लवायन कलां का क्षेत्र डेल्टा का क्षेत्र है, वहां लगभग हजारों बीघा जमीन असिंचित रहती है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह मांग करना चाहता हूं कि अगर वहां पर लिफ्ट कैनाल का निर्माण हो जाए तो वहां के किसानों को बड़ा फायदा होगा । निश्चित रूप से वहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

20.00 hrs

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि हमारे यहां बदरा, सोनोती और मुंशी का पुरवा में जो रिवर फ्रंट बनाया गया है, वहां हर बार बाढ़ आ जाती है जिससे वहां बांध बनाने की आवश्यकता महसूस होती है ।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे यहां उत्तरी विधान सभा में द्रोपदीघाट, नेवादा, गंगानगर, बेली कछार, राजापुर कछार, न्योराबाद कछार, कमलानगर, नयापुरवा, महदौरी, रसूलाबाद, अशोकनगर, मऊ सरैया, शिवकुटी, सादियाबाद, गोविन्दपुर, सलोरी आदि घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं । यहां लाखों की आबादी है, हर साल बाढ़ आने से लोगों को पलायन करना पड़ता है, स्कूल और कॉलेजों में शरण देनी पड़ती है । अगर वहां बांध का निर्माण हो जाएगा तो यहां के लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी । आने वाले कुंभ में हम इसका फायदा भी उठा सकते हैं ।

मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां खासकर फाफा मऊ विधान सभा में सीताकुण्ड, मण्डारा, मुबारकपुर कछार, सराय जयराम, नरहा झिगहा, सुल्तानपुर पूरेघासी, चफरी, ककरा, करेसर आदि क्षेत्र हैं जो जलमग्न हो जाते हैं । मेरी मांग है कि यहां पर ऐसी व्यवस्था हो ताकि फसलों का नुकसान न हो ताकि लोगों को पलायन न करना पड़े । वहां बांध का निर्माण हो ।

माननीय सभापति जी, हमारे यहां भकरी कछार है, जो लीलापुर से होते हुए जाता है, वहां कुछ दूर तक तो बांध बना हुआ है लेकिन अगर पूरा बांध निर्मित हो जाएगा तो हर साल जो कटान होता है और 100, 200 या 300 मीटर मिट्टी कटती चली जा रही है, नहीं होगा । इससे आने वाले समय में वहां के गांवों को एक संकट उत्पन्न हो सकता है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि इन मांगों पर विचार करके इन्हें पूरा करने की कृपा करें । धन्यवाद ।

SHRI ISHA KHAN CHOUDHURY (MALDAHA DAKSHIN): Hon. Chairperson Sir, today I would like to bring to your attention some salient features with regard to the Government's Jal Shakti Ministry?s current Budget regarding flood and erosion control.

There are four schemes for flood and erosion control in the Budget, namely flood, flood management programmes, Flood Management and Border Areas Programmes, and the river basin management. These particular schemes deal with embankment protection and flood control.

I want to compare the effectiveness of this year's Budget by comparing the current Budget allocation of the Narendra Modi-led NDA Government to the Budget allocation during the time of the last UPA Government.

Here are some vital conclusions. First, despite a 12-year gap, this year's NDA Government's flood and erosion control Budget allocation of Rs. 800 crore is actually Rs. 298 crore less than what the UPA had allocated in 2013-2014 during its last term, which was an amount of Rs. 1,098 crore. This is not just a reduction. It is a deliberate cut in funds in absolute terms, on river and coastal flood control and embankment spending throughout our nation.

Second, the cost of disaster mitigation has skyrocketed due to inflation and in the last decade our nation is facing more natural disasters, more floods and more erosion due to the worsening impact of climate change. Yet, against all logic, the Modi Government has slashed flood and erosion control budgets, instead of increasing them. Factoring in inflation, this amount of Rs. 1,098 crore that the UPA Government allocated in 2013 is worth nearly Rs. 2,000 crore today, but instead of increasing investments in disaster management, the NDA Government has cut it down to a meagre Rs. 800 crore. This is a let-down of vulnerable communities, especially in States like Assam and West Bengal where the people lose their homes, farm lands and their entire villages to riverbank erosion and floods every year.

Hon. Chairperson, Sir, I will now move to my State of West Bengal. Here are the most important facts about West Bengal. First of all, about 42.5 per cent of West Bengal is flood-prone, which makes it one of the most flood-affected States in the country. Flood satellite maps estimate the total flood-affected area in West Bengal at 19.69 lakh hectares with the most affected districts being Purba Barddhaman, Murshidabad, Purba Medinipur, Hooghly, and Maldah.

Secondly, I would like to share some numbers provided by the Ministry of Jal Shakti to an Unstarred Question in the Rajya Sabha, from 2023. The following numbers were in response to the year-on-year count of the total financial losses incurred by West Bengal due to flood and erosion. The following are the losses incurred:- in 2017, it was Rs. 17,000 crore; in 2018, it was Rs. 54 crore; in 2019, it was Rs. 1,269 crore; in 2020, no data available; and in 2021, it was Rs. 16,079 crore.

These are not just numbers; these figures represent the destruction of farmland, agricultural crops, fisheries, homes, roads and schools, community hospitals, mosques and temples washed away as land is eroded, and literally falls into the Ganges and its tributary rivers. These figures represent only some of the crushing losses on the livelihood of West Bengal farmers, labourers, and families. What these figures do not show is the effect on landless families who then become landless refugees, without a permanent home. The consequences of floods are short-term and economic recovery is possible, but the effects of the slow river bank erosion are of permanent nature, where the entire socio-economic structure is damaged and the affected population has to move, settle and create a livelihood somewhere else.

Thirdly, the Farakka Barrage, a Central project built in the 1970s to divert water flowing into Bangladesh into our Bhagirathi and Hooghly rivers to maintain Kolkata port navigability, is directly responsible for worsening erosion crisis in the districts of Malda and Murshidabad, where my Parliamentary Constituency of Malda Dakshin lies. The presence of the Barrage causes the build-up of 64 crore tonnes of silt to accumulate annually and this has changed the course of the Ganges and has resulted in devasting erosion to both these districts.

After the construction of Farakka Barrage, more than 350 km of fertile land has been completely swallowed by the Ganges in Malda district, and 500 sq.kms of fertile land has been wiped out in Murshidabad district, displacing lakhs and lakhs of people. During the UPA regime, from 2005 onwards, the Centre took direct responsibility for anti-erosion measures caused by the barrage ? 40 kms upstream into Malda and 80 kms downstream into Murshidabad from the Farakka Barrage itself. Under the UPA Government's, the budget allocation was Rs. 214 crore in 2013-14 for the Farakka Project. The current NDA Government has abandoned this policy which is shown in this year's small allocation of only Rs. 69 crore.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI ISHA KHAN CHOUDHURY : Sir, while the Centre boasts of providing West Bengal with Rs. 1,051.96 crore under the Flood Management Programme

component of FMBAP, let us dissect the reality. Out of 17 projects sanctioned for West Bengal, only four have received funds, amounting to a meagre Rs. 42.80 crore, which is less than one per cent of the promised allocation. This is a drop in the ocean when compared to the devastation endured by the people of West Bengal. What about the remaining 13 projects? Where is the timeline for their completion? Funds are announced for optics, but not disbursed in time; projects are sanctioned but they never see the light of the day.

In conclusion, in the Finance Minister's Budget Speech, she states that the Budget continues the NDA Government's ?continued efforts to secure inclusive development? and that the Government wants the growth of all regions of India through ?Sabka Vikas?. However, the budget allocation of the Jal Shakti Ministry for flood control and erosion measures across the nation paints a different picture with a seeming indifference and neglect towards millions of people who face the destructive power of river erosion. The facts are clear and the numbers undeniable.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairperson Sir, I rise to strongly oppose Demand 62 and 63 in the Demands for Grants of the Ministry of Jal Shakti as it is a non-performing Ministry. Sir, what is the purpose in providing grants to this Ministry when they are not utilizing the funds? Hon. Jal Shakti Minister, Patil Ji, what is the purpose of providing grant by this House to your Ministry when you are not utilizing the funds? Sir, I will substantiate it. The total Demands for Grants under Demands 62 and 63 for the financial year 2025-26 is Rs.99,503 crore. What is the budget allocation for the financial year 2024-25? It is Rs.98,714 crore.

Hon. Chairperson, Sir, you may kindly see that the Revised Estimate goes to show that the total money, which was spent, was Rs.51,558 only. That means, 48 per cent lower than that of the budget allocation, which is the money spent by this Ministry during the year 2024-25.

Coming to the Jal Jeevan Mission budget proposals 2025-26, Rs.67,000 crore have been allocated and granted by this House as Demand for Grants. It is five per cent lower than that of the Budget Estimate of 2024-25. Sir, the Budget Estimate

2024-25 is Rs.70,163 crore. The Revised Estimate goes to show Rs. 22,694 crore. That means the budget allocation is Rs.70,163 crore out of which your Ministry has spent just Rs.22,694 crore on Jal Jeevan Mission. That is the lowest expenditure since the implementation of scheme in the year 2021. What is the purpose of granting money or granting finance to your Ministry if you are not able to spend? I will come to each and every provision. I know there is the paucity of the time. Kindly see the report of Comptroller and Auditor-General of India and Audit Accounts for the financial year 2021-22. Kindly see Demand 62 for Jal Jeevan Mission. The total money sanctioned is Rs.16,485 crore out of which the total disbursement is just Rs.4,972 crore. That means 69 per cent saving.

Coming to the Swachh Bharat Abhiyan, there is 74 per cent saving, and in Jal Jeevan Mission Gram, there is 79 per cent saving. This 79 per cent saving means they have only utilised 21 per cent of the money. That means non-utilisation of the money granted by the Parliament, which in turn means, the Ministry is not performing. That is why, I am saying that I strongly oppose the Demands 62 and 63.

Sir, I am talking about the CAG report. There is an observation also in the report. I am not going to read the observation. The justification given by the Ministry has not been accepted by the Comptroller and Auditor-General of India because the money has not been spent. There are so many reasons because one of the reasons is that the States are not able to give their share. That means they have to spend the money. This is regarding the Demands for Grants.

Sir, I was the Minister for Water Resources for five years in the State of Kerala. During my time in the year 2007-2008, we had formulated a water policy towards which I would like to draw the attention of the hon. Minister. The right to safe drinking water is a Fundamental Right enshrined in Article 21 of the Constitution. The right to have safe drinking water does not mean the right to have tap water. You are giving focus to the right to have tap water. It is not at all possible. There is no doubt about it. So, you have misconceived the issue. You have to ensure the availability of safe drinking water. The right to access water is to be ensured. Instead of ensuring right to access to water, you are giving a chance to the right to

give tap water. Is it possible? The target was 2024. Now it has been extended to 2028. The main problem is unavailability of potable water. The second problem is the quality of the water. You have to address these two issues. Instead of addressing these two issues, you are going for the tap water.

Sir, this is going to be an engineering project. This is going to be a big misappropriation. Most of the Members from Kerala has already stated that Rs. 4,500 crore are in arrears for the contractors. All the roads are in dilapidated state. It is everywhere. It is going to be a project which is not up to the expectation. Kindly have a review on this issue because there is no water. The source of water has to be made. Water transmission has to be made. Treatment plant has to be made. This is simply digging the roads, putting the pipes, and giving a tap connection, but there is no water. In place of water, you are getting only air. What is the meaning? That means this Jal Jeevan Mission project is a good, innovative project, but unfortunately, it has become an engineering project. The person, who will be benefited, will be the contractors and other partners. Nothing else is going to happen. I am making sure, please keep it on record. You kindly have a review. I am saying this out of my experience.

There is one more point regarding the Members of Parliament. Mr. Patil Ji, what is the role of the MPs? Is it a Centrally-Sponsored Scheme? I am sure this is a 200-page booklet published by the Kerala State Government. This is a Centrally-Sponsored Scheme in which 50 per cent of the contribution is from the Central Government, and only 25 per cent contribution is of the State Government, 15 per cent is the contribution of local bodies, local panchayats and 10 per cent is the contribution of the beneficiary. The Chief Minister is there. The Water resources Minister is there. All the 140 MLAs are there. Each and every legislative constituency is well explained. This is a Centrally- Sponsored Scheme. There is not even a mention that this is a Centrally- Sponsored Scheme. The MPs have no role. You go through the booklet. You kindly review it. Last time also, I have said this. You are saying that this is a Centrally-Sponsored Scheme and 50 per cent contribution is from the Centre. But unfortunately, the Members of Parliament has

no role in the implementation, in the formulation or even in the review. Nothing is there. So, I would like to request the hon. Minister to kindly review the Jal Jeevan Mission. It shall not remain as a project. Otherwise, it shall become a failed project. So, a review has to be done. Appropriate changes have to be made so that the money is utilised for the poor people. This will benefit the common people.

With these words, I conclude. Thank you very much

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Sir, I too strongly oppose this Demand raised by this Jal Shakti Ministry. It is because this Ministry is not able to handle properly even the flagship programme. So, that is very evident. What was the aim? The Jal Jeevan Mission's aim was to provide functional household tap connections to provide 55 litres per capita per day, bringing water to all rural households in the country by 2024. But nothing has happened. Now, the scheme has been extended to 2028. But at this rate, I doubt, even by 2028, nothing is going to happen because in the last year, out of Rs. 70,000 crore allotted for this particular project, Rs. 50,000 crore was not spent. I do not know what is happening with this Ministry. It is not happening not only in Kerala, but also throughout the country. I request the Ministry and the hon. Minister, who is here, to do a proper review of this project throughout the country. In all States, what is happening? Only pipeline is being laid. Nobody knows where the source is. Nobody knows where the tank is. Only pipes are being laid. All the panchayat roads have been dug up and now the people are asking us to provide the MP funds to repair these roads. No repair work is being done. The whole thing is in a mess. So, I would request the Ministry that it has to do a complete review of this flagship program.

Sir, due to paucity of time, I am going straight to another very important thing. Under the repair, renovation and restoration of water body scheme, I would like to draw your attention to Vembanad Lake. The Vembanad Lake is India's longest lake. It stretches over 96 kilometres, encompassing an area of approximately 230 square kilometres. This vast water body traverses multiple districts of Kerala, including Alappuzha, Kottayam and Ernakulam, serving as a lifeline for the State's ecology and economy. The lake's unique mix of salt water and freshwater fosters a thriving

ecosystem, supporting diverse flora and fauna. Notably, it hosts the renowned Nehru Trophy boat race also, attracting enthusiasts worldwide.

The degradation of Vembanad Lake is not a localised issue. It reflects broader environmental and public health concerns that warrant national attention. There is microplastic contamination; there is biodiversity loss; and there are pathogenic threats. The lake?s pollution levels have led to the proliferation of harmful bacteria, including Vibrio species associated with diseases such as cholera. The Thanneermukkom Bund is a double-edged sword. Constructed in 1974, the Thanneermukkom Bund was designed to prevent salt water intrusion into the Kuttanad lowlands, the Rice Bowl of Kerala, facilitating agriculture. However, it has disrupted the natural salinity gradient leading to ecological imbalances such as the proliferation of invasive species like water hyacinth and a decline in fish population.

The imperative for national intervention is integrated water resources management, pollution control initiatives, ecological restoration projects, community engagement and education, scientific monitoring and research. I request that the degradation of Vembanad Lake is a clarion call for immediate action. This crisis transcends regional boundaries reflecting broader environmental and public health challenges that our nation is confronted with. I request that a Vembanad Lake Authority should be created. There are a lot of funds lying there unspent. A Vembanad Lake Authority should be constituted and sufficient funds should be granted for the restoration of Vembanad Lake.

Our Tamil Nadu friends are here. Adv. Dean kuriakose had mentioned it. We have no quarrel with our Tamil Nadu friends. The Mullaperiyar Dam is 130 years old. It warrants urgent attention. Our only request is this. We have no problem in sharing this water with Tamil Nadu. We have been giving it for the last 130 years almost free. We are not taking any money. We would like to have the security aspects being very properly considered by the Central Government. The Central Government should call the leaders of both the States and discuss and settle this matter once and for all. This is because if something happens, it is not going to be

the issue of Kerala or Tamil Nadu issue. The whole world will blame the country. More than 50 lakh people are going to be affected. So, please considerer it. We want the Prime Minister himself to intervene in this matter. Call and settle it amicably. We have no problem in sharing water with Tamil Nadu. Our erstwhile Chief Minister Shri Oommen Chandy coined a slogan saying ?water for Tamil Nadu, and security for Kerala?. So, it is always water for Tamil Nadu first. We are taking the security aspect second only.

So, I most humbly request that the Water Resources Minister should take the lead. The Prime Minister should intervene and settle this matter once and for all. So, I strongly again oppose this Demand because the Ministry has not been functioning efficiently.

Thank you.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : महोदय, सदन में आज जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है । सदन के साथियों ने इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने-अपने विचार रखे हैं । जल है तो कल है और जल है तो जीवन है । हम तो उस मारवाड़ के इलाके से आते हैं, जहाँ जल को घी से भी ज्यादा संजोकर रखा जाता था । लोग पाँच-पाँच, सात-सात किलोमीटर दूर से मटकी से, घड़े से महिलाएँ पानी लाती थीं । आज भी बड़े-बड़े तालाब वहाँ बने हुए हैं । बहुत बड़ी समस्या पानी को लेकर जल शक्ति मंत्रालय की है और पीने के पानी के साथ-साथ सिंचाई के पानी की व्यवस्था की बात सभी लोगों ने कही है । वर्ष 2025-26 का जो जल शक्ति मंत्रालय का बजट है, वह 99,503 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2024-25 के 98,714 करोड़ रुपये से थोड़ा सा ही ज्यादा है । इसमें और ज्यादा बजट लेना चाहिए । निश्चित रूप से आज आवश्यकता देश के अंदर है ।

माननीय सभापति : आप ज्यादा देने की डिमांड कर दीजिए । आप माँग कर दीजिए ।

श्री हनुमान बेनीवाल : महोदय, अगर बेरोजगारी को खत्म करना है तो हर खेत तक सिंचाई का पानी आप लेकर चले जाओ, बेरोजगारी 80 प्रतिशत खत्म हो जायेगी । राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में पेयजल की कमी और सरकारी योजनाओं के बावजूद लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है । दूसरी तरफ भूजल में यूरेनियम और आर्सेनिक सहित विभिन्न संदूषकों के कारण बढ़ रहा प्रदूषण चिंता का विषय है ।

वर्ष 1984 में हमारे राजस्थान के 236 में से 203 ब्लॉक सुरक्षित स्थिति में थे, क्योंकि उस वक्त 35 प्रतिशत पानी का दोहन होता था । सरकार आंकड़ों व समाचार पत्रों के अनुसार 30 वर्षों के बाद भूजल दोहन 114 प्रतिशत बढ़ गया है । अब मात्र 12 प्रतिशत ब्लॉक ही सुरक्षित बचे हैं । इसलिए मंत्री जी मैं आपसे विशेष आग्रक करूँगा कि आप राजस्थान की तरफ विशेष रूप से ध्यान दें ।

सभापति जी, हमारे राजस्थान का बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है यानी सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता ज्यादा है और भारत की दो तिहाई कृषि भूमि सूखाग्रस्त है । आपने वर्ष 2015-16 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की, उसका दायरा बढ़ाया जाए और अटल भूजल योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए । नदियों और नहरों में बढ़ता प्रदूषण बहुत बड़ी चिंता का विषय है । करोड़ों रुपये बजट खर्च होने के बावजूद और कानून होने के बावजूद नदियों में प्रदूषण नहीं रुक रहा है । पंजाब से राजस्थान आने वाली नहरों में अपशिष्ट और फैक्ट्रियों के दूषित जल से नागौर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर इलाके जहां लुधियाना की फैक्ट्रियों का अपशिष्ट उनके अंदर पड़ता है, उससे कैंसर ट्रेन के नाम से एक ट्रेन चलती है । वहां जो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं, उनकी तरफ आप विशेष रूप से ध्यान दें । लोगों को कैसे शुद्ध पानी पिलाया जाए, आप इसकी व्यवस्था कीजिए ।

महोदय, हमारा राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र है । राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है । यहां लोग जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं । कृषि का विकास सिंचाई पर निर्भर है लेकिन सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है । कोटा, हनुमान गढ़, गंगानगर और कुछ इलाकों को छोड़ दें, तो सारे इलाके वर्षा पर निर्भर हैं । राजस्थान में कुल सतही जल का मात्र 1.16 प्रतिशत जल उपलब्ध है और 61.11 प्रतिशत हिस्सा मरुस्थल है । जनवरी 2024 के प्राप्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमारे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर और जल संसाधन विभाग में इंदिरा गांधी नहर और जल संसाधन विभाग के अधीन मात्र 39 लाख 43 हजार 155 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है जबकि हमारे नागौर सहित पश्चिमी राजस्थान की बात करूं तो हम केवल और केवल बारिश पर निर्भर हैं ।

महोदय, ERCP की तर्ज पर बनी WRCP परियोजना की बात करूंगा । मैं जल शक्ति मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ की हमारे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए ERCP योजना बनी । हमने सदन में मामला उठाया और खूब आंदोलन किए गए । जिसे आपने और राजस्थान सरकार ने संशोधित करके PK, ERCP नाम दिया, अब राजस्थान सरकार ने उसका नाम राम सेतु लिंक परियोजना किया है । क्या भारत सरकार इसके लिए 90 प्रतिशत राशि देगी या नहीं, यह उल्लेख नहीं हुआ? आपने जो राजस्थान और मध्यप्रदेश

के मध्य एमओयू करवाया है उससे राजस्थान और एमपी को कितना कितना पानी मिलेगा, इसे भी आप क्लीयर करें?

दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के नागौर व डीडवाना -कुचामन जिले के साथ पश्चिमी राजस्थान के तमाम जिलों के लिए जिनके लिए ईआरसीपी पेयजल और सिंचाई पश्चिमी राजस्थान नहरी परियोजना विकसित की जाये, एक राष्ट्रीय परियोजना आप बनाये यह मेरी मांग है ।

राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौता को लेकर दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के सीएम की केंद्रीय मंत्री श्री सी.आर. पाटिल जी से मुलाकात हुई है, इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान के शेखावाटी अंचल के किसानों को जल्द ही यमुना जल का लाभ मिल सकेगा, मैं सदन के माध्यम से जल शक्ति मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ की आप जब इस चर्चा का जवाब दे तो यह जरूर बताये की यमुना जल समझौते के परिप्रेक्ष्य में जल समझौते में जल संसाधनों के समुचित वितरण, अंतरराज्यीय जल समझौतों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर क्या प्रगति हुई या वो समझौता केवल दिखावा मात्र था ?

पंजाब से मिले राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा जल- महोदय, मैं आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्री जी का ध्यान दिनांक 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी- व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे को लेकर हुए समझौते की तरफ आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूँ की राजस्थान को अब भी 0.60 M.A.F. पानी नहीं मिल रहा है और पंजाब सरकार जब इस समझौते को समाप्त करने के उद्देश्य से विधेयक लेकर आई तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विशेष संदर्भ संख्या 1 / 2004 में रावी- व्यास जल के संबंध में पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम 2004 को गलत माना इसलिए मेरी मांग है की केंद्र हस्तक्षेप करके राजस्थान को पंजाब से उसके हिस्से का पूरा जल दिलवाये । राजस्थान बार-बार आपको लोक सभा सीटें दे रहा है । इस बार गड़बड़ हो गयी । मैं इधर हो गया तो 11 इधर आ गए । अगर मैं उधर होता तो इन 11 को भी वहां अपने साथ ले आता और 25 हो जाते

माननीय सभापति : कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री हनुमान बेनीवाल : एक मिनट और दीजिए ।

रामगढ़ बांध और अतिक्रमण ? सभापति महोदय, आज सदन के माध्यम से जल शक्ति मंत्री जी का ध्यान राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित रामगढ़ बांध की तरफ आकर्षित करते

हुए यह बताना चाहता हूँ की रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र का गला घोंटा गया है, पर राजस्थान सरकार को यह नजर नहीं आ रहा है, न जिम्मेदार अफसरों को, हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी रामगढ़ बाँध के बहाव क्षेत्र में बनाये गए फार्म हाउस, रिसोर्ट, होटल हटाई नहीं जा रही है इस पर आप ध्यान दें । इनको आप धराशायी करें और पीने के पानी की व्यवस्था करें ।

JJM और राजस्थान- राजस्थान में पूर्व की सरकार के समय में तो जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार हुए । पूर्व के मंत्री के घर पर ईडी और सीबीआई की रेड हुई । आपने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे उन सबको सलाखों के पीछे डालेंगे और सीबीआई से पूरे मामले की जांच करवाएंगे ।

माननीय सभापति : पूर्ववर्ती सरकार का मतलब?

श्री हनुमान बेनीवाल : राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री के घर पर ईडी की रेड हुई और आपने यह कहा कि आप हमें वोट दो, हम जांच करवाएंगे, लेकिन वह जांच आगे नहीं बढ़ी है, सवा साल से मामला वहीं पर अटका है ।

माननीय सभापति : कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, आप इनकी जांच कराएं । इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट्स पर 900 करोड़ रुपये से अधिक राशि के टेन्डर कर दिए । राजस्थान में तो अभी जल स्वराज अभियान के एक मंत्री हैं । वे भी भ्रष्टाचार में लिप्त ऑफिसर्स की फील्ड पोस्टिंग दे रहे हैं ।

सभापति महोदय, मैं आपसे यही मांग करूंगा कि आपके दल की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं आना चाहिए । आप जांच कराइए । मेरी मांग है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन में हुए तमाम घोटालों की जांच आप सीबीआई से करवाएं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : धन्यवाद ।

श्री चन्द्र शेखर ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : चन्द्र शेखर जी, आप अपना भाषण शुरू कीजिए । आपका समय शुरू हो गया है ।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : सभापति जी, धन्यवाद ।

सभापति जी, मैं अपने कॉलेज के जीवन से शुरू करूंगा । जब हम डीएवी पीजी कॉलेज, देहरादून में पढ़ने जाते थे तो मैं और मेरे साथी सचिन, सुबोध, फिरोज मोटरसाइकिल से कॉलेज जाते थे, ज्यादातर भीगते हुए जाते थे । वहां तो बारिश अच्छी लगती थी । लेकिन, जब बारिश बाढ़ का रूप ले लेती है तो वह स्थिति भयानक हो जाती है । बहुत सारे लोग अपने घरों में सो नहीं पाते, बहुत लोगों के तो घर उजड़ जाते हैं ।

सर, मैं यह भी कहूंगा कि भारत की आज़ादी के 75 सालों के बाद भी अगर सबको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है तो यह हम सबके लिए शर्म की बात है । सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए था । यह बुनियादी चीज है । इसमें किसी व्यक्ति का कोई जोर नहीं है, यह कुदरत की देन है । अगर लोगों को हम साफ पानी भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो हमने लोगों के बारे में क्या सोचा है?

सर, मेरे लोक सभा क्षेत्र में बहुत सारे गांव बाढ़ से प्रभावित हैं । हर बार योजना बनती है, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है । इनमें मालन नदी, कोटा वाली नदी, गंगा का बाढ़ क्षेत्र, छोईया नदी, शाहपुर कुच्छयान, लाहक कलां, रामपुर चाढ़ा, पितमगढ़, गौसपुर, बौराकी, रानीपुर, हामिदपुर, माखन, सादात, बूढ़ावाला, तुकमापुर, भवानीपुर, चमरावाला, जग्गुवाला, तौफिक़वाला प्रमुख हैं । जब कानपुर को पानी की आवश्यकता होती है और रामगंगा में कालागढ़ डैम से पानी छोड़ा जाता है, तब उससे भी हमारे यहां बाढ़ आती है । उन गांवों में मनोहरवाली, भूतपुरी, मुबारकपुर, गांवड़ी, घोषियावाला, सातनगर, भनोटी, रामसावाला, हाफिज़ाबाद, बिहारीपुर, तिपड़जोत, मुकरपुरी, बेरखेड़ा, सिपाहियोंवाला, मिलक, कोप्पा, नत्थादोई, मनधोरा, नंदगांव और नयागांव हैं । वहां जमीन कट जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है । वहां न ही लोगों को मुआवजा मिलता है और न लोगों को नींद आ पाती है । जब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, तब तक हमारे लोक सभा क्षेत्र नगीना के लोगों का भला नहीं हो सकता है ।

सर, गंगा और यमुना की सफाई कब होगी? सरकार ने गंगा और यमुना की सफाई के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन दोनों नदियां अभी भी गंदी हैं । इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? गंगा और यमुना को साफ और अविरल बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे?

फैक्ट्रियों का गंदा पानी उनमें जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार कहती है कि फैक्ट्रियों से गंगा और यमुना में गंदा पानी नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा हो

रहा है । इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं ।

गंदे पानी को साफ करने वाले प्लांट कब तक बनेंगे? गंगा और यमुना के किनारे कई ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने थे, लेकिन अब तक वह काम पूरा नहीं हुआ है । उसमें देरी के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी?

सीवर का पानी यमुना में क्यों मिल रहा है? दिल्ली और आस-पास के शहरों में लाखों लीटर गंदा पानी यमुना में बहाया जाता है । सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

गंगा नदी के जीव-जंतुओं की रक्षा कैसे होगी? गंगा में पायी जाने वाली डॉल्फिन्स और अन्य जीव संकट में हैं । इनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और उनका क्या असर हुआ है?

?नमामि गंगे? योजना सफल हुई है या नहीं हुई है? सरकार कहती है कि ?नमामि गंगे? योजना सफल हुई है, लेकिन इसकी जमीनी सच्चाई कुछ और है । क्या सरकार इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराएगी?

यमुना की सफाई के लिए बनी योजनाएं क्यों फेल हो रही हैं? यमुना एक्शन प्लान और अन्य योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च हुए, लेकिन कोई खास असर नहीं दिख रहा है । क्या सरकार इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराएगी?

नदी किनारे बनाए जा रहे रिवरफ्रंट से गंगा को नुकसान हो रहा है । गंगा किनारे बनाए जा रहे रिवरफ्रंट से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है । क्या सरकार इस विकास और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए कोई नयी नीति बनाएगी?

गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों में अवैध रेत खनन, अवैध निर्माण क्यों नहीं रुक रहा है, जिससे नदी और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है । सरकार इसको रोकने के लिए क्या कर रही है?

बाढ़ से प्रभावित गांवों के लोगों का क्या होगा? गंगा व यमुना के किनारे बसे हुए कई परिवार हर साल बाढ़ और कटाव से प्रभावित होते हैं । क्या सरकार इनके पुनर्वास के लिए कोई ठोस योजना बनाएगी?

यहां जायसवाल साहब बैठे हैं । बिहार का क्या हाल होता है, ये जानते हैं । वहां तीन-तीन महीने तक लोग परेशान होते हैं ।

गंगा के किनारे जैविक खेती क्यों नहीं बढ़ रही है? गंगा के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गयी थी, लेकिन उसका असर कम दिख रहा है । सरकार इस योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए क्या करेगी?

महोदय, नदियों के संरक्षण के नाम पर कई योजनाएं बनीं, लेकिन उनके नतीजे साफ नहीं दिख रहे हैं । यमुना नदी को बचाने के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है । क्या सरकार ऐसा कोई अभियान चलाएगी ताकि लोग यमुना बचाने में योगदान कर सकें? सर, हर घर को साफ पानी कब मिलेगा? सरकार ने हर घर में नल से जल देने का वादा किया था, लेकिन अभी भी कई गांवों में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं । क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि सभी को साफ पानी और सुरक्षित पानी मिले? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन बिछाने में देरी क्यों हो रही है? कई इलाकों में पाइपलाइन अधूरी पड़ी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है । सरकार कब तक सभी जगह पानी की पाइपलाइन का काम पूरा करेगी? हैंडपंप और कुएं क्यों खराब पड़े हैं? गांव और कस्बों में लगे कई हैंडपंप और कुएं खराब हैं, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हो रही है । सरकार उनकी मरम्मत और देखभाल के लिए क्या कर रही है? गंदे पानी से बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? कई जगह गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं । सरकार गंदे पानी को साफ करने और बीमारियों रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? शहरों में गटर का पानी सड़कों पर क्यों बह रहा है? कई शहरों में सीवर लाइनें जाम हैं और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है । क्या सरकार सीवर व्यवस्था सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी, योजना बनाएगी?

सर, पीने के पानी का नल खराब हो गया है, उससे बड़ी गंभीर बीमारियां हो रही हैं । लेकिन सरकार का ध्यान इसकी तरफ नहीं है । पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? कई जगह पाइप लाइन लीक हो रही हैं । हज़ारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है । क्या सरकार इस बर्बादी को रोकने के लिए कोई योजना बना रही है?

गिरते भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए क्या सरकार कोई संरक्षण नीति ला रही है? पानी और स्वच्छता की योजनाओं में पारदर्शिता कब आएगी? सरकार ने कई योजनाएं शुरू की थीं, लेकिन उसके नतीजे स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं । क्या सरकार इन योजनाओं की पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चत करेगी? सर, अंत में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि पाइपलाइन से पानी आएगा, लेकिन कैनाल बंद कर रहे हैं । सर, भूजल का स्तर गिर जाएगा और फिर आप बजट भी कम कर रहे हैं । सर, प्रधान मंत्री का लोक सभा क्षेत्र काशी, मैंने अखबार की कटिंग पढ़ी, उसमें लिखा है कि मेहमानों को पानी पूछने में शर्म आती है । यह हालात प्रधान मंत्री जी के क्षेत्र में हैं । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री गोरखपुर से हैं । वह क्षेत्र

बरसात में पूरा डूब जाता है । ? (व्यवधान) सर, उत्तर प्रदेश में नेपाल का पानी आता है । लखीमपुर खीरी, पीलीभीत आदि पूरा एरिया डूबता है । इस समस्या से निजात दिलाने के लिए परमानेंट सॉल्युशन होना चाहिए । इसके नाम पर पैसों का हेर-फेर कर के काम नहीं चलेगा ।

धन्यवाद ।

SHRI GOVIND MAKTHAPPA KARJOL (CHITRADURGA): Sir, I would like to speak a few words. I would like to place some issues before the House and thereby seek approval of Central Assistance for the Upper Bhadra Project of Karnataka, through your kind self, from the hon. Prime Minister and also from the hon. Minister of Jal Sakti.

?हे भोजनेन् जीवतम् भवतु, बिना जलन्तो: सर्वम् ही नश्यत् ।?

One can live without food, but without water, everything perishes. The farmers of the drought-prone area of central Karnataka have been deprived of irrigation facilities for more than five decades. After five decades of struggle, the Upper Bhadra Project is being implemented in the State of Karnataka, which creates an *atchkat* of 2,25,000 hectares in the drought-prone area of central region of Karnataka through micro irrigation with an intent to fill approximately 367 tanks in the command area. The command area spreads in Chikkamagaluru, Chitradurga, Tumkuru and Davanagere districts. The project was started in the year 2008 and the works are under progress.

In the Union Budget for the year 2023-2024, an amount of Rs. 5,300 crore had been announced as Central Assistance for the Upper Bhadra Project. I sincerely extend my gratitude for announcing Rs.5,300 crores as Central Assistance.

Hon. Chairperson, Chitradurga district is my Lok Sabha constituency. Majority of the people in my district are poor, small and marginal farmers. This region is deprived of irrigation facilities. Around 30 to 40,000 people from each taluk are migrating to big cities such as Bangalore, Davanagere, Hubli and Goa in search of their livelihood. Their farm fields are left uncultivated as a result there is no crops grown. When such a situation was there during the year 2019 -2023, when our government was in power, we had allocated Rs. 7,200 crores for taking up relief measures in this region. However, the ruling Congress government is not giving even a single rupee to address the problems of the people, So, all the developmental

works are stalled in this area. Our farmers are agitating over there for fulfilling their demands.

Hence, through you, I would like to request our hon. Prime Minister and also Hon?ble Minister for JAL Shakti to come forward and take necessary measures to help the people of my region. Rs. 5,300 crores were announced for Upper Bhadra canal Project in the Union budget for the year 2023-24. I urge upon the Union government to release the amount immediately under the Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojana (PMKSY) and Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP).

The government of Karnataka has not allocated any funds for the irrigation schemes in the state for the last two years. As a result, all the works have been stopped. I would like to draw the attention of the Union government with regard to the Upper Bhadra project, which falls under in my Lok Sabha constituency itself. Sir, Rs. 2400 crores that has to be paid to the Contractors. Since the amount is not paid to the contractors, all of them have stopped their works in the proposed projects in midway and they have no way but to migrate to other places.

Hon'ble chairperson, through you I want to draw the kind attention of the Union government to the fact that the water in this area contains more Fluoride, Nitrate and Iron contents, which are causing health hazards among the farmers and poor people. Underground water has become poisonous as it contains dangerous level of Fluoride. As a result of which our people are suffering from various health issues.

Hence, I urge upon the Union government and Hon?ble Minister of Jalshakti to take immediate steps to release the amount of Rs. 5,300 crores immediately that was announced in Union budget 2023-24.

Thank you.

DR. BACHHAV SHOBHA DINESH (DHULE): Hon. Chairman, Sir, thank you very much for allowing me to speak on Demands for Grants of Jal Shakti Ministry for 2025-26. I would also like to thank our Leader Shri Rahulji Gandhi. Protection

and conservation of water resources is very important. Sir, I would like to share this information regarding water conservation and irrigation projects under PM Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) in my State Maharashtra. In my Lok Sabha constituency Dhule, thee is an acute water scarcity and drinking water was supplied once a week in Dhule city last year. It was supplied through Tapti pipeline and now water is being supplied twice a week. This pipeline is 40-year-old pipeline and this is in bad condition. So, it leaks continuously and water supply also get disturbed. This 40 kilometre pipeline should be replaced immediately and for replacement work, Rs. 225 crore should be provided through PMKSY. There is a dam called Akkalpara and this dam is like a boon for Dhule district. But this dam have water just 65 per cent of its maximum capacity. The remaining 35 per cent water flows away. If we want to store 100 percent water, we would have to acquire 200 hectare land in that area and we need Rs. 500 crore for land acquisition. This fund should be given from PMKSY. I will help to ensure availability of water for drinking and irrigation purposes.

Sir, at least 10 per cent water of Akkalpara Dam must be reserved as a drinking water for Dhule city. For the locals of Shinkheda and Nandurbar, Prakasha Burai lift irrigation scheme is very important. This project would ensure availability of drinking and irrigation water for more than 28 villages and also provide irrigation facility to 7025 hectare of land. This project would help for the overall development of farming and horticulture in this area. But, it needs funding of Rs. 793 crore and hence, I request you to provide it through PMKSY.

Haranmall Dam is located in Satana Tehsil and it is quite useful for drinking and irrigation water in that area. But, 12 km long right side canal work is still pending. So, it should be started immediately by providing Rs. 37 crore from PMKSY.

Sir, Kelzar Dam is built on Aram river near Satana. It is also known as Gopalsagar Dam. But the canal needs to be extended through the villages like Shardeyash and Satmane and an extended DPR should be presented as early as possible.

Zodge village in Malegaon Tehsil is a well-known market place and it is located on Mumbai-Agra Highway. This village is facing water scarcity problem. Jal Jeevan Mission work is underway since last two years. This water scarcity problem is everywhere in my constituency and people are facing hardships.

So, I would like to request you to initiate an enquiry of the Jal Jeevan Mission works. Rs. 25 crore should be provided for different works in Dhule rural, Shinkheda. Rs. 198 crore should be given for Malegaon rural and Satana from PMKSY. Sufficient funds should be given under Amrit Yojana for urban areas.

I request you to kindly look into it seriously and provide relief and assistance for distressed people of my constituency Dhule. Thank you.

***m151 श्री चंदन चौहान (बिजनौर) :** सभापति महोदय, आपने मुझे जल शक्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह बहुत अभूतपूर्व है कि 99,503 करोड़ रुपये का वर्ष 2025-26 के अंदर एलोकेशन हुआ है । 10 वर्ष पूर्व जब यूपीए की सरकार थी, तब 17,342 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ था । उसकी तुलना में 6 गुना बजट को बढ़ाना सरकार की गम्भीरता को दिखाने का काम करता है । आने वाले समय में वर्ल्ड के अंदर पानी को लेकर जो चैलेंजेज़ हैं, उसको लेकर सरकार बहुत चिन्तित है । जल-जीवन मिशन के अंदर 67 हजार करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया । स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 7,192 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया और जल संसाधन को लेकर पीएमकेएसवाई, नदी संयोजन, नमामि गंगे और अटल भूजल को लेकर 25,277 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया । यह कहीं न कहीं सरकार की गम्भीरता को दिखाने का काम करती है ।

इस वर्ष कुम्भ का आयोजन किया गया । इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसका सफल आयोजन किया । हम इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं ।

हर घर नल, हर घर जल योजना का सभी साथियों ने जिक्र किया । आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन उसको धरातल पर उतारकर उस पीड़ा को समझना कि कैसे हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचे और जीवन में बीमारियों से लड़कर जीवन को सुलभ बनाने के लिए

इस भावना को बढ़ाने के लिए 15 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया, यह भी एक अभिभूत करने वाला कार्य है ।

स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से 2019 में ओडीएफ की स्थिति, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से गांव में परिवर्तन करने का काम किया । भारत की पवित्र नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया, नमामे गंगे के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं । वर्ष 2025-26 में 24 सौ करोड़ रुपये आबंटित किया गया जो पिछले वर्ष के मुकाबले बीस प्रतिशत अधिक है ।

मान्यवर, हमारा देश किसान आधारित है । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में लगभग साठ हजार करोड़ रुपये का निवेश पीएमकेएसवाई के अंतर्गत किया गया है । त्वरित सिंचाई का लाभ, एआईबीपी के तहत 63 परसेंट योजनाएं इसके अंतर्गत की गई हैं । वर्ष 2025-26 में 8260 करोड़ रुपये जल प्रबंधन और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा ।

हमारे लोक सभा क्षेत्र में गंगा माँ का आशीर्वाद मिला हुआ है । गंगा माँ का वह आंचल और पूरे देश और विश्व का सबसे अच्छा क्षेत्र है, जहां दोआब की जमीन है, सबसे मोस्ट फर्टाइल लैंड है । जब मौसम की मार पड़ती है या बाढ़ की समस्या आती है ।, हमारे यहां बाढ़ प्रबंधन सीमा क्षेत्र है । हमारे यहां जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा में सोलानी नदी के पास पुरकाई खादर में तटबंध के लिए प्रदेश सरकार के साथ मिलकर रिसर्च का काम चल रहा है । आईआरआई रूड़की ने रिसर्च पूरी कर ली है, इससे दादोपुर, रजकलापुर, बदौली, बदौला, शेरपुर, बड़ेवाला, चमरावाला, अहमदवाला, जिंदावाला गांव पीड़ित रहते हैं । मीरापुर विधान सभा तौफीर हो, महाराजनगर हो, खैरनगर हो ।

बिजनौर में नदी के बायें तट पर ग्राम जहानाबाद, बेला, सेहतमाली से जनपद अमरोहा और रसूलपुर तक एक तटबंध की आवश्यकता है । मैं आपके माध्यम से इसकी मांग माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं । बिजनौर बैराज घाट पर नमामि गंगे की योजना मिले तो बहुत लाभकारी होगा । बिजनौर खादर के अनेक गांव हैं । हर साल गंगा नदी के कटान के कारण मुबारकपुर, टीप, फतहपुर, सीमली, सीमा, मीर्जापुर, कोहरपुर और गंज की सीमाओं में इसके लाभ की आवश्कता है ।

हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह नल है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि नल आज भी वह पानी का वेस्ट होने से बचाने का काम करता है । सभी सदस्यों को हैंड पम्प ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दिलाएं, चाहे सांसद निधि आधा कर दें । आने वाले समय में यह पानी बचाने का काम करेगा ।

श्री सनातन पांडेय (बलिया) : सभापति महोदय, आपने मुझे जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, धन्यवाद ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात तीन मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री सनातन पांडेय : सभापति महोदय, मन की बात हो लेने दीजिए । पिछले सत्र में ही मैंने एक आशंका व्यक्त किया था कि जल जीवन मिशन योजना इस देश की भ्रष्टतम योजनाओं में से एक होगी । मैंने पिछल सत्र में कहा था । मैं जहां से चुनकर आता हूं, उसका नाम बलिया है । बलिया में तमाम आपकी कंपनियां काम कर रही हैं । उन्होंने अपने काम को छोटे-छोटे पार्ट में छोटे-छोटे ठेकेदारों को दे रखा है । उन ठेकेदारों के पास ग्रमीाण इलाके के लोग काम किए हुए हैं और सात महीने से उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है, होली भी मुहर्रम की तरह से बीत गया ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन कंपनियों पर नकेल कसा जाए । हमारे गांव इलाके या क्षेत्र के लोग काम किए हैं, उनको समय से मजदूरी दिया जाए ।

दूसरी तरफ आपने कहा है कि 80 प्रतिशत लोगों तक हमने जल की व्यवस्था कर दी है तो मंत्री जी यह बिल्कुल ... है । यह सत्य से परे नहीं है । आपने 20 प्रतिशत लोगों तक भी पानी पहुंचाने का काम नहीं किया है ।

महोदय, मेरी शंका है कि आपकी सरकार ने ... को काम दिया । उसमें अपनी कंपनी ... को भी काम देने का काम किया । मैंने तभी अपनी शंका जाहिर की थी कि वो कंपनियों जो चुनाव से पहले आपको चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में एक हजार करोड़ रुपये दे सकती है तो मैं उससे कैसे उम्मीद करूं कि चुनाव में जब आप सत्ता में होंगे तो वे कंपनियां ईमानदारी के साथ काम करेंगी ।

माननीय सभापति : इन कंपनियों के नाम को एक्सपंज कर दिया जाए ।

श्री सनातन पांडेय : महोदय, मेरी शंका उस समय भी थी और आज भी है ।

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि समय बार-बार नहीं आता है । यह कोई जरूरी नहीं है कि मैं कल सदस्य रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन सरकार इस तरह का रोजगार करना बंद कर दे ।

आपने भी संगम में स्नान किया है । संगम में गंगा नदी में स्नान करने के लिए सभी लोग गए थे । गंगा नदी में बेतवा, यमुना, काली नदी और रामगंगा नदी भी मिलती है । अगर यमुना नदी का जल दिल्ली में स्वच्छ नहीं है तो यह जल प्रयागराज में कैसे स्वच्छ हो गया? इसका

मतलब देश की ... आपने प्रदूषित जल में 100 करोड़ लोगों को स्नान कराने का काम किया है । इसके लिए आप ... के भागी हैं । इस ... का जवाब आपको कल देना पड़ेगा । आने वाले दिनों में विपक्ष सदन में पक्ष में होगा और आप विपक्ष में बैठने का काम करेंगे । मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं । ? (व्यवधान)

***m155 डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** सर, भारत के संविधान का आर्टिकल-28 कहता है कि किसी की धार्मिक भावना पर कोई क्वैश्चन नहीं हो सकता है । यदि सनातन पांडेय जी को ब्राह्मण होकर भी संगम अच्छा नहीं लगता है तो यह उनका विषय है । हमारे लिए संगम महत्वपूर्ण है । ? (व्यवधान) हम गंगा और यमुना को पवित्र मानते हैं । यदि उनको ब्राह्मण होकर अच्छा नहीं लगता है तो वे अपनी राजनीति देखें । ये हमारी भावना को नहीं भटका सकते हैं । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Any unparliamentary words used against any religion or caste or creed should be expunged.

? (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे : सर, इसको एक्सपंज कीजिए ।

माननीय सभापति: सब निकाल दिया जाएगा ।

SHRI M. MALLESH BABU (KOLAR): Hon. Chairperson, Sir, thanks for giving me the opportunity to discuss the Demands for Grants under the control of the Ministry of Jal Shakti for the year 2025-26.

As we know, water plays an important and vital role in people?s life. As it is very much essential for daily domestic activities, it is also important for agriculture and allied activities like irrigation, enabling crop production, and food security of not only human lives but also animal lives. Jal Jeevan Mission launched in 2019 aims to provide functional tap water connections to all rural households by 2024. The hon. Finance Minister has announced that the total budget outlay for Jal Jeevan Mission has been enhanced to Rs. 67,000 crore for 2025-26 and the Mission is extended until 2028, which is a welcome move. Today over 15 crore households, representing 80 per cent of India?s rural population, have functional tap connections, a monumental leap from just three crores in 2018.

Coming to my parliamentary constituency, Kolar, 2,72,456 households would be benefitted by the Mission. Kolar lies just 60 kilometres from Bengaluru and for more than a century its legendary gold mines fuelled not only Karnataka?s treasury but also strengthened the very foundations of India?s economic backbone. Before and after Independence, Kolar?s wealth helped build this nation, funding progress, economic development, and the aspirations of the nation. But today, the legacy of its gold is history, and in its place, a stark reality looms. The same land that once flowed with prosperity now thirsts for something as fundamental as water. Kolar has given gold to this nation; today, it asks only for water. Kolar is popularly known as the land of silk, milk, mango, and tomatoes, which are being exported to various countries. The district is also known for having large number of tanks, numbering 2,479 tanks.

21.00 hrs

Here, the farmers are purely dependent on groundwater where borewells are sunk up to 1,500 feet depth since we do not have any perennial sources for agriculture and allied activities. The entire district is facing a threat of groundwater depletion thereby classifying the entire district as ?over exploitation of groundwater?.

In view of this, the Karnataka Government has implemented KC-Valley and HN-Valley projects thereby releasing the treated sewage water from Bangalore to the tanks in Kolar and Chikkaballapur districts to improve the groundwater levels. This has resulted in various health issues among women and youths and even indirect effects on crops.

The Yethinahole project is under implementation since 2007-2008 with an estimated cost of Rs. 23,000 crore to provide clean and pure water to Bangalore Rural, Chikkaballapur and Kolar districts. The project is being delayed due to various reasons.

Since, Kolar and Chikkaballapur districts are adjoined with Andhra Pradesh, I would urge the Ministry of Jal Shakti and Prime Minister, Modi ji to intervene and

allocate a minimum quantity of water during the excess flow at Almathi Dam diverting Krishna River water which has been flowing in the adjoining districts of Andhra Pradesh, namely Annammai and Chittoor districts.

With these words, from my Party, Janata Dal Secular, I am concluding my speech on the Demands for Grants of the Ministry of Jal Shakti for 2025-2026, and I support it. Thank you.

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 2025 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

21.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, March 20, 2025/Phalguna 29, 1946 (Saka).

_____

@ Expunged as ordered by the Chair.